



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 595]
No. 595]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 21, 2007/वैशाख 31, 1929
NEW DELHI, MONDAY, MAY 21, 2007/VAISAKHA 31, 1929

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2007

का.आ. 789(अ).—मेघालय के अचीक नेशनल वालंटियर काउंसिल (एएनवीसी) और हन्नीवट्रेप लिब्रेशन काउंसिल (एचएनएलसी) नामक संगठनों को विधिविरुद्ध घोषित किए जाने के लिए पर्याप्त कारण विद्यमान होने अथवा न होने के संबंध में न्याय-निर्णयन के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. रवीन्द्र भट्ट की अध्यक्षता में गठित अधिकरण को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4 (1) के अधीन भेजे गए संदर्भ के संबंध में पारित उनके दिनांक 14-5-2007 के आदेश को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4(4) के अनुसरण में आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री एस. रवीन्द्र भट्ट की अध्यक्षता में गठित विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण की रिपोर्ट

संदर्भ : गृह मंत्रालय की दिनांक 16 नवम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1974(अ)

1. दिनांक 16-11-2006 की एक अधिसूचना के द्वारा केन्द्र सरकार ने यह घोषणा की कि, अन्य बातों के साथ-साथ, उसका यह मत है कि विनिर्दिष्ट कारणों से अचीक नेशनल वालंटियर काउंसिल (जिसे इसमें इसके बाद "एएनवीसी" कहा गया है) तथा हन्नीवट्रेप नेशनल लिब्रेशन काउंसिल (जिसे इसमें इसके बाद "एचएनएलसी" कहा गया है) तथा उनके द्वारा स्थापित अन्य निकाय विधिविरुद्ध संगठन हैं। केन्द्र सरकार की यह भी राय थी कि एएनवीसी तथा एचएनएलसी की गतिविधियां भारत की संप्रभुता तथा अखण्डता के

लिए हानिकारक हैं तथा यदि इन पर तत्काल अंकुश एवं नियंत्रण नहीं लगाया गया तो वे फिर से संगठित तथा शस्त्रों से सुसज्जित हो जाएंगे, अपने कौडरों का विस्तार करेंगे, परिष्कृत हथियार जुटा लेंगे, आम नागरिकों तथा सुरक्षा बलों के जीवन को नुकसान पहुंचाएंगे तथा अपनी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को तेज करेंगे। तदनुसार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (जिसे इसमें इसके बाद "अधिनियम" कहा गया है) के अंतर्गत इस अधिकरण की स्थापना की गई।

2. इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार गठित इस अधिकरण के समक्ष यह मामला 19-12-2006 को आया। धारा 4(2) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिकरण ने 12-2-2007 को अचीक नेशनल वालंटियर काउंसिल (जिसे इसमें इसके बाद "एएनवीसी" कहा गया है) तथा हन्नीवट्रेप नेशनल लिब्रेशन काउंसिल (जिसे इसमें इसके बाद "एचएनएलसी" कहा गया है) को कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसका जवाब 12-2-2007 को दिया जाना था। केन्द्र सरकार को यह निदेश दिया गया कि वह इन संगठनों को उनके पतों पर नोटिस तामील करे तथा राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्रों तथा उस क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रचलित समाचार पत्रों में भी नोटिस को प्रकाशित करे। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार को इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में इसका समुचित प्रचार करने का निदेश दिया गया। निदेशक, गृह मंत्रालय, केन्द्र सरकार ने एएनवीसी तथा एचएनएलसी दोनों को नोटिसों की तामिली तथा इनके प्रकाशन के अनुपालन का उल्लेख करते हुए एक शपथ-पत्र दायर किया। इस शपथ-पत्र के अनुसार, 30-12-2006 और 4-1-2007 को स्थानीय समाचार पत्रों सहित चार अलग-अलग समाचार पत्रों में प्रकाशन के माध्यम से नोटिसों की तामिली की गई। इन नोटिसों का तीन क्रमिक तारीखों अर्थात् 29, 30 और 31 दिसम्बर, 2006 को विभिन्न भाषाओं, अर्थात् खासी, गारो, जैतिया तथा अंग्रेजी में आकाशवाणी द्वारा प्रसारण किया गया। नोटिसों को मेघालय के सभी जिलों में उपायुक्तों के कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर भी चिपकाया गया। न्यायालय ने अधिकरण के

रजिस्ट्रार द्वारा दायर की गई अनुपालन रिपोर्ट, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि नोटिस 12-2-2007 को विभिन्न तरीकों से तामील कर दिया गया तथा प्रकाशित कर दिया गया, को रिकार्ड में लिया। इसी दिन एएनवीसी ने अपने वकील के माध्यम से अधिकरण के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज की।

3. अधिकरण ने विभिन्न पक्षकारों से अपने शपथ-पत्र तथा अपने दस्तावेज दायर करने की अपेक्षा की। एएनवीसी ने अपनी आपत्तियां दायर कीं, तथापि एचएनएलसी की ओर से कोई आपेति अथवा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। 28 मार्च, 2007 की कार्यवाहियों में इन तथ्यों पर ध्यान दिया गया तथा केन्द्र सरकार के वकील ने शपथ-पत्र दायर करने के लिए समय मांगा। मेघालय राज्य ने शपथ-पत्र दायर कर दिए थे। तत्पश्चात्, यह मामला आगे की कार्यवाहियों के लिए शिलांग में 12, 13 और 14 अप्रैल, 2007 के लिए नियत कर दिया गया। तब तक मेघालय राज्य और केन्द्र सरकार ने अपने शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिए थे।

4. 28, 29 मार्च, 2007 तथा 2 अप्रैल, 2007 को नई दिल्ली में बैठकों के बाद अधिकरण ने 12, 13 एवं 14 अप्रैल, 2007 को शिलांग में बैठकों की ताकि गवाहों के साक्ष्य दर्ज करने में आसानी हो सके। “शिलांग टाइम्स” तथा स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों में काफी प्रचार किया गया; इन समाचार पत्रों की कतरनों की प्रतियां रिकार्ड का भाग हैं। मेघालय राज्य की ओर से गवाहों अर्थात् सीडब्ल्यू-1 से सीडब्ल्यू-16 तक साक्ष्यों तथा आपत्तिकर्ता, एएनवीसी के कुछ गवाहों, अर्थात् आरडब्ल्यू-1 से आरडब्ल्यू-3 तक के साक्ष्य 12 अप्रैल, 2007 से 14 अप्रैल, 2007 के बीच शिलांग में दर्ज किए गए। इन गवाहों के शपथ-पत्र शिलांग में कार्यवाहियों के दौरान प्रस्तुत किए गए। अधिकरण ने, केन्द्र सरकार की ओर से दिए गए साक्ष्य तथा इसके गवाहों की जिरह को 19 अप्रैल, 2007 को नई दिल्ली में दर्ज किया। एएनवीसी की ओर से और साक्ष्य, अर्थात् आरडब्ल्यू-4 तथा आरडब्ल्यू-5, 20 और 23 अप्रैल, 2007 को दर्ज किया गया। आरडब्ल्यू-5 की गवाही तथा जिरह 24, 25 और 26 अप्रैल, 2007 को दर्ज की गई।

5. इस मामले को, इच्छुक पक्षकारों की ओर से अंतिम सुनवाई के लिए शिलांग में दो दिनों, अर्थात् 6 मई, 2007 तथा 7 मई, 2007 के लिए सूचीबद्ध किया गया। बहस 9 मई, 2007 को नई दिल्ली में पूरी हो गई। पूरी कार्यवाही के दौरान एएनवीसी का प्रतिनिधित्व हुआ। एचएनएलसी अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं हुई।

केन्द्र सरकार का पत्र

6. केन्द्र सरकार से प्राप्त पत्र निम्न प्रकार पठित है :

“राजपत्र अधिसूचना

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2006

का.आ. 1974 (अ)—यतः, मेघालय के अचीक नेशनल वालंटियर काउंसिल (जिसे इसमें इसके पश्चात् ‘एएनवीसी’ कहा गया है) ने हिंसा छोड़ने पर सहमत होने तथा अपनी मांगों को पूरा करने

के लिए भारत के संविधान के दायरे में वार्ता करने की इच्छा व्यक्त करने के बावजूद जबरन धन वसूलना जारी रखा है;

और, यतः, केन्द्रीय सरकार की राय है कि मेघालय की हन्नीवट्रेप नेशनल लिब्रेशन काउंसिल (जिसे इसमें इसके बाद ‘एचएनएलसी’ कहा गया है) मेघालय को भारत संघ से अलग करने के अपने उद्देश्य की खुलेआम घोषणा कर रही है।

और, यतः, केन्द्रीय सरकार की पुनः राय है कि एएनवीसी तथा एचएनएलसी दोनों,—

- (i) अपने संगठन के लिए निधियां एकत्रित करने के उद्देश्य से आम लोगों को डराने-धमकाने, जबरन धन वसूली तथा लूट-पाट की कार्रवाइयों में लिप्त हैं;
- (ii) जबरन धन वसूली तथा डराने-धमकाने की कार्रवाइयों को जारी रखने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य विद्रोही गुटों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं;
- (iii) आश्रय तथा अपने काडरों के प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए कुछ पड़ोसी देशों में शिविर स्थापित किए हुए हैं; और यतः, केन्द्रीय सरकार का यह भी मत है कि —
 - (i) एएनवीसी वर्ष 2004 में चौबीस हिंसक घटनाओं, वर्ष 2005 में छः हिंसक घटनाओं तथा वर्ष 2006 (31 अगस्त, 2006 तक) में एक हिंसक घटना में संलिप्त रही है।
 - (ii) एएनवीसी की हिंसा की इन वारदातों में वर्ष 2004 में 12 व्यक्ति (4 सुरक्षा बल कार्मिक सहित) तथा वर्ष 2005 में एक व्यक्ति मारा गया।
 - (iii) एचएनएलसी वर्ष 2004 में एक हिंसक घटना में, वर्ष 2005 में चार हिंसक घटनाओं में तथा वर्ष 2006 (31 अगस्त, 2006 तक) में दो हिंसक घटनाओं में शामिल रही।

और, यतः, केन्द्रीय सरकार का यह भी मत है कि उपरोक्त कारणों से एएनवीसी और एचएनएलसी और उनके द्वारा गठित अन्य निकाय विधिविरुद्ध संगम हैं।

और, यतः, केन्द्रीय सरकार का यह भी मत है कि अचीक नेशनल वालंटियर काउंसिल (एएनवीसी) और हन्नीवट्रेप नेशनल लिब्रेशन काउंसिल (एचएनएलसी) की उपरोक्त गतिविधियां भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता को विच्छिन्न करने के लिए आशयित हैं और यदि इन पर तत्काल नियंत्रण न किया गया तो ये संगठन पुनर्संगठित होंगे, पुनः शस्त्रों से लैस होंगे, अपने कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाएंगे, अत्याधुनिक हथियार प्राप्त करेंगे, भारी संख्या में नागरिकों और सुरक्षा बलों की हत्या करेंगे और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को तेज करेंगे।

अतः, अब, विधिविरुद्ध गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, अचीक नेशनल वालंटियर काउंसिल (एएनवीसी) और हन्नीवट्रेप नेशनल

लिब्रेशन कार्डसिल (एचएनएलसी) को इनके सभी गुटों, विंगों और मुख्य संगठनों सहित विधिविरुद्ध संगम घोषित करती है।

केन्द्रीय सरकार का यह भी मत है कि अचीक नेशनल वालंटियर कार्डसिल (एएनवीसी) और हनीवट्रेप नेशनल लिब्रेशन कार्डसिल (एचएनएलसी) को इनके सभी गुटों, विंगों और मुख्य संगठनों सहित तत्काल प्रभाव से विधिविरुद्ध संगम घोषित करना आवश्यक है, और तदनुसार धारा 3 की उप-धारा (3) के प्रस्तुत द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, निदेश देती है कि यह अधिसूचना उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किए जा सकने वाले किसी आदेश के अधधीन सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 11011/49/2006-एनई III]

नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव "

इस पत्र के साथ भेजा गया संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार पठित है :

"विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 5 के अंतर्गत गठित अधिकरण को प्रस्तुत किए गए अचीक नेशनल वालंटियर कार्डसिल (एएनवीसी) तथा हनीवट्रेप नेशनल लिब्रेशन कार्डसिल (एचएनएलसी) के लक्ष्यों/उद्देश्यों तथा हिंसक गतिविधियों के संबंध में संक्षिप्त सार

1. अचीक नेशनल वालंटियर कार्डसिल (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'एएनवीसी' कहा गया है) तथा हनीवट्रेप नेशनल लिब्रेशन कार्डसिल (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'एचएनएलसी' कहा गया है) को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के उपबंधों के तहत 16 नवम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1974 (अ) के तहत विधिविरुद्ध संगम घोषित किया गया था। पूर्व में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4 की उप-धारा (1) के अंतर्गत, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता में गठित विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण को एक पत्र भेजा गया था तथा विद्वान अधि-करण ने अपने दिनांक 12-5-2005 के आदेश के तहत, भारत सरकार द्वारा जारी की गई दिनांक 16-11-2004 की अधिसूचना की पुष्टि की।

2. एएनवीसी का गठन दिसम्बर, 1995 में हुआ था और इसका उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, 'अचीक लैंड' नामक एक नया राज्य बनाने के लिए गारो हिल्स को मुक्त कराना, गैर-जनजातीय लोगों का आगमन और गारो लोगों का शोषण रोकना, गारो लोगों की जीवन-दशाओं को सुधारना एवं उनके रीति-रिवाजों तथा परम्पराओं को बचाना, गारो लोगों के बीच एकता लाना और संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद् को सुदृढ़ बनाना था। इस संगठन ने 23 जुलाई, 2004 से प्रारंभ से छः माह के लिए 'अपने अभियान को निलंबित रखने' के संबंध में भारत सरकार तथा मेघालय सरकार के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए थे जिसे समय-समय पर बढ़ाया गया है तथा इस समय यह 23 जुलाई, 2007 तक वैध है। इस करार पर हस्ताक्षर किए जाने से यह संगठन हिंसा छोड़ने के लिए राजी हो गया है तथा इसने अपनी मांगों को पूरी किए जाने के लिए भारत के संविधान के ढांचे के अंतर्गत बातचीत करने

की अपनी इच्छा व्यक्त की है। यद्यपि इस करार पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से मेघालय की गारो पहाड़ियों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार हुआ है तथा मेघालय में एएनवीसी नेतृत्व सरकार के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक प्रतीत होता है किन्तु एएनवीसी काडर जबरन धन वसूली तथा 'कर' वसूली की कार्रवाई में लगे हुए हैं। एएनवीसी का स्वयं भू अध्यक्ष दिलाश मराक तथा स्वयं भू कमान्डर-इन-चीफ जेरोम मोमिन प्रत्यक्ष रूप से शांति प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए हैं। दिलाश मराक अपने समर्थकों के साथ बंगलादेश में ठहरा हुआ है तथा अपना व्यवसाय चला रहा है। एएनवीसी द्वारा यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) के साथ भी सम्पर्क रखे जाने की सूचना है।

3. एचएनएलसी की स्थापना 1992 में हुई थी और इसका उद्देश्य हनीवट्रेप लोगों को भारत सरकार के अधिकारवादी शासन से मुक्त कराना, खासी लोगों और मेघालय की अन्य जनजातियों को शोषण से बचाना, स्थानीय संस्कृति को बचाए रखना और सामाजिक बुराइयों को मिटाना था। यह संगठन खासी समाज को विभाजित करने के किसी भी प्रयास के विरुद्ध लड़ने के लिए भी प्रतिबद्ध है। यद्यपि एचएनएलसी ने विगत में किसी बड़ी हिंसा की कार्रवाई का सहारा नहीं लिया है तथा वर्ष 2004 के बाद से इस संगठन द्वारा हिंसा में काफी कमी आई है फिर भी यह संगठन विशेष रूप से शिलांग घाटी में जबरन धन वसूली, अपहरण एवं व्यपहरण-जैसी कार्रवाइयों को जारी रखे हुए हैं। इस संगठन ने गैर जनजातीय लोगों को राज्य से बाहर चले जाने की अपनी धमकी भी छोड़ दी है। एचएनएलसी, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) तथा नेशनल सोशलिस्ट कार्डसिल ऑफ नागालैंड (इसाक/मुइबाह), एनएससीएन (आई/एम) के साथ भी संबंध बनाए हुए है। एनडीएफबी के साथ एचएनएलसी का संबंध चिंता का विषय है क्योंकि यह संगठन विस्फोट करने में एनडीएफबी से सुविज्ञता प्राप्त कर सकता है। एचएनएलसी नियमित रूप से गणतंत्र दिवस तथा स्वतंत्रता दिवस का बहिष्कार करने का अह्वान करती रही है। यह लोगों से राष्ट्रीय दिवसों का विरोध करने के लिए इन दिनों में बंद रखने के लिए भी कहती रही है।

3.1 एएनवीसी का प्रभाव गारो हिल्स के तीन जिलों तथा पश्चिमी खासी जिले की कोल बेल्ट के क्षेत्रों में फैला है। इसकी मौजूदा संख्या 250 होने का अनुमान है जिसमें से 150 तूरा, पश्चिम गारो हिल्स जिले तथा पूर्वी गारो हिल्स जिले तथा दक्षिणी गारो हिल्स जिले में अभिहित क्रमशः समन्दा एवं जेन्ना में हैं। इस संगठन के पास कुल 150 हथियार होने का अनुमान है जिनमें 50-60 ए के सीरीज रायफल, 3 लाइट मशीन गन, 5 स्टेनगन, 50 पिस्टल/रिवाल्वर, 35 राइफल और 25 शॉट गन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इनके पास 200 ग्रेनेड हैं।

3.2 एचएनएलसी प्राथमिक रूप से मेघालय की खासी पहाड़ियों में सक्रिय हैं। इसके कुछ शिविर बंगलादेश में हैं। एचएनएलसी के काडरों की संख्या 100 होने का अनुमान है। इस समय इस संगठन के पास कुल 75 हथियार होने का अनुमान है जिनमें लगभग 30 ए के सीरीज रायफल, 02 लाइट मशीनगन, 20 कार्बाइन एवं स्टेनगन और 20 राइफल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इनके पास 80 हथगोले हैं।

4. हिंसा की स्थिति

4.1 वर्ष 2004, 2005 और 2006 (31-08-2006 तक) के दौरान एनवीसी क्रमशः चौबीस, छः और एक हिंसक घटना में शामिल थी। एनवीसी द्वारा की गई हिंसा की इन घटनाओं में वर्ष 2004 और 2005 में क्रमशः 12 व्यक्तियों (4 सुरक्षा बल कार्मिकों सहित) तथा 1 व्यक्ति की मृत्यु हो गई। वर्ष 2004, 2005 और 2006 में (31-8-2006 तक) एचएनएलसी क्रमशः एक, चार और दो हिंसक घटनाओं में शामिल थी। इन घटनाओं में किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई।

5. एनवीसी और एचएनएलसी को 'विधिविरुद्ध संगम' की घोषणा को जारी रखने का औचित्य

5.1 उपरोक्त पैराओं में दिए गए अनुसार एनवीसी और एचएनएलसी की निम्नलिखित गतिविधियों की पृष्ठभूमि में विधिविरुद्ध गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत एनवीसी और एचएनएलसी को 15 नवम्बर, 2006 से दो वर्ष की और अवधि के लिए विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया जा रहा है ताकि इन दोनों संगठनों को फिर से संगठित होने का अवसर न मिल सके :

- (i) हिंसा का त्याग करने के लिए सहमत होने और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए भारत के संविधान के ढांचे के भीतर बातचीत करने की इच्छा व्यक्त करने के बावजूद एनवीसी द्वारा मेघालय के व्यवसायों से जबरन धन वसूली एवं कर वसूली जारी रखना;
- (ii) मेघालय को भारत से पृथक् करने के एचएनएलसी के उद्देश्य की खुले तौर पर घोषणा की गई है;
- (iii) एचएनएलसी द्वारा अपने संगठन के लिए निधियां एकत्र करने के लिए नागरिकों को डराना एवं लूट-खसोट करना जारी है;
- (iv) लूट-खसोट तथा डराने-धमकाने की कार्रवाइयों को अंजाम देने के लिए एचएनएलसी तथा एनवीसी दोनों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य विद्रोही संगठनों के साथ संपर्क बनाए रखना;
- (v) अपने काइरों के आश्रय एवं प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए एनवीसी तथा एचएनएलसी दोनों के द्वारा बंगलादेश में शिविर बनाए रखना।

5.2 विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3 की उप-धारा 3 के परन्तुक के अनुसार यदि केन्द्र सरकार का यह मत है कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जिनसे इन संगठनों को 'विधिविरुद्ध' घोषित किए जाने संबंधी अधिसूचना का विस्तार आवश्यक हो जाता है तो यह लिखित में कारणों को अभिव्यक्त करते हुए निदेश दे सकती है कि अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी। एनवीसी एवं एचएनएलसी की गतिविधियां लगातार जारी हैं और ऐसा महसूस किया गया है कि यदि अधिसूचना के विस्तार में विलंब हुआ तो ये संगठन स्थिति का नाजायज फायदा उठा सकते हैं। तथा अलगाववादी, विध्वंसक एवं हिंसक गतिविधियों के लिए अपने कार्यकर्ताओं को लामबंद कर सकते हैं। इससे इन संगठनों

के नेताओं को भारत की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाली विदेशी ताकतों के साथ मिलकर खुलेआम राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का मौका मिल जाएगा। ऐसी स्थिति में पुलिस तथा सुरक्षा बलों के लिए उनके द्वारा पकड़े गए उग्रवादियों को कैद में रखना और उन पर अभियोजन चलाना मुश्किल हो जाएगा। अतः उन पर दो वर्ष की और अवधि के लिए प्रतिबंध लगाने संबंधी अधिसूचना को इसके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से विस्तारित करना आवश्यक समझा गया है। तदनुसार, गृह मंत्रालय द्वारा 16 नवम्बर, 2006 को एनवीसी तथा एचएनएलसी तथा उनके गुटों, विंगों एवं प्रमुख संगठनों को "विधिविरुद्ध संगम" घोषित करने संबंधी अधिसूचना सं. का.आ. 1974(अ) जारी की गई।

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के संगत उपबंध

7. विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (जिसे इसमें इसके बाद "अधिनियम" कहा गया है), धारा 2 (ण) तथा 2 (त) के माध्यम से इस बात को परिभाषित करता है कि "विधिविरुद्ध संगम" तथा "विधिविरुद्ध क्रियाकलाप" क्या हैं। "विधिविरुद्ध क्रियाकलाप" को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है :—

"2(ण) किसी व्यक्ति अथवा संगम के संबंध में "विधिविरुद्ध क्रियाकलाप" से तात्पर्य उस व्यक्ति अथवा संगम द्वारा की गई किसी ऐसी कार्रवाई (चाहे किसी कृत्य के द्वारा अथवा मौखिक अथवा लिखित शब्दों द्वारा संकेतों अथवा स्पष्ट चित्रण द्वारा अथवा अन्यथा) से है,—

- (i) जिसका उद्देश्य किसी भी आधार पर भारत के किसी भू-भाग का समर्पण करना अथवा भारत के किसी भू-भाग को संघ से अलग करना अथवा इसका समर्थन करना अथवा दावा करना हो अथवा जो किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के सनूह को इस प्रकार के समर्पण अथवा अलगाव के लिए उकसाती हो; अथवा
- (ii) जो भारत की प्रभुसत्ता तथा प्रादेशिक अखंडता को अस्वीकार करती है, उस पर प्रश्न खड़ा करती है, उसे विघटित करती है अथवा उसे विघटित करने से अभिप्रेत हो; अथवा
- (iii) भारत के विरुद्ध विद्रोह फैलाती है अथवा विद्रोह फैलाने से अभिप्रेत हो;"

विधिविरुद्ध संगम को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है:

"2 (त) "विधिविरुद्ध संगम" से आशय किसी ऐसे संगम से है,—

- (i) जो अपने उद्देश्य के लिए कोई विधिविरुद्ध गतिविधि चलाता हो अथवा जो किसी विधिविरुद्ध गतिविधि चलाने के लिए व्यक्तियों को प्रोत्साहित करता हो अथवा उसकी सहायता करता हो अथवा जिसके सदस्य इस प्रकार की गतिविधि चलाते हों; अथवा
- (ii) जो अपने उद्देश्य के लिए कोई ऐसी गतिविधि चलाता हो जो भारतीय दंड संहिता (1860 की 45) की धारा

153 क अथवा धारा 153 ख के अंतर्गत दंडनीय हो अथवा जो इस प्रकार की कोई गतिविधि चलाने के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रोत्साहित करता हो अथवा उनकी सहायता करता हो; अथवा जिसके सदस्य इस प्रकार की कोई गतिविधि चलाते हों;

परन्तु यह कि उप-खंड (ii) में की कोई बात जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लिए लागू नहीं होगी;”

8. अधिनियम की धारा 3(1) केन्द्र सरकार को, यदि उसका यह मत हो कि कोई संगठन (एसोसिएशन) विधिविरुद्ध है अथवा बन गया है, राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा उसे विधिविरुद्ध घोषित करने की शक्ति प्रदान करती है। केन्द्र सरकार को ये आधार विनिर्दिष्ट करने होते हैं जिनके कारण वह एसोसिएशन विधिविरुद्ध है [धारा 3(2)]। धारा 3(3) में यह उल्लेख किया गया है कि धारा 3 (1) के तहत जारी की गई कोई अधिसूचना तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि धारा 5 के अंतर्गत गठित अधिकरण इस घोषणा की पुष्टि न कर दे और आदेश राजपत्र में प्रकाशित न हो जाए। धारा 3(3) के परन्तुक में यह अधिनियमित है कि यदि केन्द्र सरकार का यह मत हो कि ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हैं जिनकी वजह से उस एसोसिएशन को तत्काल प्रभाव से विधिविरुद्ध घोषित करना आवश्यक है तो वह अधिसूचना, धारा 4 के तहत किए गए किसी आदेश के अध्यक्षीन, राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

9. केन्द्र सरकार को; धारा 3(1) के अंतर्गत अधिसूचना जारी करने के साथ-साथ, यह न्याय निर्णय करने के लिए इस अधिकरण के पास भेजना होता है कि क्या एसोसिएशन को विधिविरुद्ध घोषित करने का पर्याप्त कारण है अथवा नहीं। अधिनियम के तहत गठित अधिकरण में, धारा 5 के अधिदेश के अनुसार, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शामिल करना अपेक्षित होता है। धारा 4(3) के परन्तुकों के अनुसार अधिकरण को इस बात की जांच करनी होती है तथा निर्णय लेना होता है कि क्या संबंधित एसोसिएशन को विधिविरुद्ध घोषित करने का कारण है अथवा नहीं तथा यथाशीघ्र और किसी भी हालत में धारा 3(1) के तहत अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख से छः माह के भीतर रिपोर्ट देनी होती है। अधिकरण धारा 3(1) के अंतर्गत इस घोषणा की पुष्टि कर सकता है अथवा इसे रद्द कर सकता है। अधिनियम की धारा 9 में यह उल्लेख है कि अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यक्षीन, अधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, जहां तक संभव हो, दावों की जांच के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में निर्धारित प्रक्रिया की तरह होगी।

एचएनएलसी से संबंधित साक्ष्य एवं सामग्रियाँ

10. मेघालय राज्य ने दस्तावेजी साक्ष्य के अतिरिक्त 9 गवाहों के शपथपत्र प्रस्तुत किए। एचएनएलसी के विधिविरुद्ध एसोसिएशन होने की घोषणा के संबंध में धारा 3(1) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के समर्थन में इन 9 गवाहों से भी अधिकरण के समक्ष पूछताछ की गई। यह साक्ष्य, इस संबंध में केन्द्र सरकार के साक्ष्य का समर्थन करता है। केन्द्र सरकार ने सीडब्ल्यू-17, श्री आर.आर. झा, निदेशक, पूर्वोत्तर, गृह मंत्रालय के साक्ष्य पर भरोसा किया।

11. सीडब्ल्यू-1, श्री फ्रेडरिक रॉय खरकांगर, उपायुक्त, जैतिया हिल्स जिला, जो 10-5-2005 से कार्यरत हैं; ने सीडब्ल्यू-1/1 के रूप में 17-3-2007 को उनके द्वारा दायर शपथपत्र प्रदर्शित किया। उन्होंने यह बताया कि एचएनएलसी जैतिया हिल्स जिलों में सक्रिय थी; पूर्व अधिसूचनाओं द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद जिले में एचएनएलसी के सदस्य विधिविरुद्ध गतिविधियों में लिप्त थे। एचएनएलसी के बड़े नेता बंगलादेश में छिपे हुए हैं तथा सीमा पार से अपनी गतिविधियाँ चला रहे हैं। इनमें आमतौर पर जनता तथा विशेष रूप से व्यवसायी वर्ग को डराना-धमकाना तथा उनका अपहरण करना शामिल है। उन्होंने यह भी बताया कि भय की वजह से मनोरोग से पीड़ित व्यक्ति मामलों की रिपोर्ट नहीं करते हैं। गवाह ने यह भी बताया कि एचएनएलसी के पूर्वोत्तर रुख्यों के नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एनएससीएन (आई/एम)), नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) आदि जैसे अन्य प्रतिबंधित संगठनों के साथ संबंध एवं सम्पर्क हैं। गवाह ने बताया कि इस प्रतिबंध से, कुछ सीमा तक एचएनएलसी की गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिली।

12. साक्ष्य देने वाले गवाह सीडब्ल्यू-2 श्री हेमलिंग ननगफुह, पुलिस अधीक्षक, जैतिया हिल्स जिला, जोवाई थे; उन्होंने ईएक्स. सी डब्ल्यू-2/1 के रूप में रिकार्ड में लिए गए दिनांक 17-3-2007 के शपथपत्र पर अपने हस्ताक्षरों की शिनाख्त की। उन्होंने 25 जनवरी, 2005 की एक घटना का उल्लेख किया जब अपेक्स बैंक, खलीहरियात से 93 लाख रु. की राशि लूटी गई जिसमें एचएनएलसी काडर शामिल थे तथा जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 395/397 के अंतर्गत पी. एस. मामला सं. 7(1)05 दर्ज किया गया। उन्होंने दिनांक 25 मार्च, 2005 की एक घटना के बारे में बताया जिसमें उम्लावंग वार परसाह कोयला खान से किसी मोन बाह प्रधान का अपहरण कर लिया गया तथा एचएनएलसी को फिरोती की राशि का भुगतान करने के बाद उसे रिहा कर दिया गया था। उन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 364/34 के अंतर्गत पी. एस. मामला सं. 24(3)05 के संबंध में एफआईआर की प्रति प्रस्तुत की। गवाह ने दिनांक 25 मई, 2005 को किसी राजू शर्मा के अपहरण की घटना के बारे में भी बताया जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 448/364/326/34 के अंतर्गत एफआईआर, जोवाई पी.एस. मामला सं. 65(5)05 दर्ज किया गया। गवाह के अनुसार, चूंकि फिरोती की राशि का भुगतान नहीं किया गया, इसलिए अपहृत व्यक्ति की हत्या कर दी गई। गवाह ने 8-1-2006 को मूलबर से किसी बशेम्भा पाठव उर्फ कमान्डो उर्फ बहदुह उर्फ बहनाह पाठव की गिरफ्तारी तथा एके-47 के चीन में बने 10 भरे हुए करतूसों की बरामदगी का भी उल्लेख किया। उसे भारतीय दंड संहिता तथा शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न मामलों से संबंधित 4 अन्य मामलों में भी स्पष्ट रूप से शामिल पाया गया। गवाह ने वर्ष 2005-2006 के दौरान जैतिया हिल्स जिलों में छः एचएनएलसी काडरों के समर्पण के बारे में भी बताया, अर्थात् 10-5-2005 को बिना शस्त्रों के जोवाई पुलिस थाने में फरलोक सिरक्रेम उर्फ फेर द्वारा समर्पण किया गया; टारसन लिम्बा ने 10-5-2005 को पुलिस थाना डावकी में आत्मसमर्पण किया, होपबोर्न उर्फ बहुरित ने 20-1-2006 को चीन में बनी एक 9 एमएम पिस्टल, दो मैग्जीन तथा 10 राउंड कारतूस के साथ जोवाई पुलिस थाने में समर्पण किया; हमबाद बियम ने 4-2-2006 को एक देशी रिवाल्वर के साथ जोवाई पुलिस थाने में समर्पण किया; निलन

स्टेन ने 4-2-2006 को एक देशी रिवाल्वर के साथ जोवई पुलिस थाने में समर्पण किया तथा दियामसलोन मेनर ने 16-7-2006 को बिना हथियार के जोवई पुलिस थाने में समर्पण किया।

13. गवाह ने बताया कि इस जिले में एचएनएलसी तथा एएनवीसी सक्रिय हैं किन्तु एचएनएलसी अधिक सक्रिय है। उनका आरोप है कि विधिविरुद्ध संगठनों का मुख्य समर्थक एनएससीएन (आई/एम) बंगलादेश में स्थापित है तथा उन काडरों को प्रशिक्षित करने के लिए शस्त्रों एवं गोलाबारूद की आपूर्ति करता है जिनका मूल उद्देश्य भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को खतरा पहुंचाना तथा एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग करना है। मेघालय कॉर्पोरेटिव अपैक्स बैंक लिमिटेड के पत्र की प्रतियां तथा दिनांक 20-3-2006 के आदेश, जिसमें मेघालय निवारक नजरबंदी अधिनियम, 1995 के अंतर्गत बंशेम्भा पाठव की निवारक नजरबंदी का निदेश दिया गया, की प्रति उनके शपथपत्र के भाग के रूप में प्रस्तुत की गई।

14. सीडब्ल्यू-3, श्री भलंग धर, उपायुक्त, ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट ने अगला बयान दिया। उन्होंने प्रदर्श सीडब्ल्यू-3/1 के रूप में दिनांक 17 मार्च, 2007 को अपना शपथपत्र प्रस्तुत किया। शपथपत्र में उन्होंने एचएनएलसी की गतिविधियों का लगभग वही स्वरूप दोहराया जो सीडब्ल्यू-1 तथा सीडब्ल्यू-2 ने अपने बयानों में कहा था। उन्होंने आगे कहा कि एचएनएलसी ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट में सक्रिय है और इसके शीर्षस्थ सरगना बंगलादेश में छुपे हुए हैं। उनके अनुसार एचएनएलसी ने अन्य प्रतिबंधित विद्रोही गुटों जैसे यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा), नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैण्ड (एनडीएफबी), एनएलएफटी, एनएससीएन आदि के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर लिए हैं गवाह ने अधिकरण द्वारा रिकार्ड किए गए अपने बयान में लोगों में डर व्याप्त होने के बारे में बताया तथा यह भी बताया कि एचएनएलसी अवैध शस्त्र क्रियाकलापों, लूट-खसोट, अपहरण तथा एक मामले में हत्या में लिप्त है। गवाह ने यह भी बताया कि एचएनएलसी का मुख्य निशाना जिले का व्यापारी समुदाय है। उन्होंने एचएनएलसी के संबंध अन्य प्रतिबंधित संगठनों के साथ होने के बारे में बताया।

15. श्री एडीसन रॉय माथोह, पुलिस अधीक्षक, ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट ने सीडब्ल्यू-4 के रूप में बयान दिया। उन्होंने अपने द्वारा 17 मार्च, 2007 को सीडब्ल्यू-4/1 के रूप में निष्पादित किया गया शपथपत्र दिखाया। इस गवाह ने अनेक घटनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने दिनांक 9-7-2005 को किसी माणिक डे के अपहरण उसकी मौसिनराम थाने के तहत गांव टाइला में रखे जाने तथा दिनांक 10-7-2005 को पीड़ित को बचाने के लिए लॉबाह गांव में घर पर छापा मारने, एचएनएलसी आतंकवादियों द्वारा गोलीबारी करने, जवाब में गोलियां चलाने तथा एक काडर की मृत्यु के बारे में उल्लेख किया। उन्होंने बयान दिया कि दूसरा काडर सदस्य भाग गया जबकि अपहृत व्यक्ति को बचा लिया गया। उन्होंने मौसिनराम पुलिस थाने में दर्ज 2005 के मामला सं. 12(07) का उल्लेख किया और उस प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति अधिकरण के रिकार्ड के लिए दी। इस गवाह ने बताया कि अनेक हथियार जैसे रिवाल्वर, 9 एमएम जिंदा गोलाबारूद के तीन राउंड चीन में बनी एक हथगोला डीबीबी एल बंदूक। (रूपांतरिक), एक राईफल बैरल सं. 405 डब्ल्यूयूसीएफ तथा इस्पात

का एक ट्रैगर आदि बरामद किए गए। गवाह ने यह भी बयान दिया कि एचएनएलसी ने 14-8-2005 तथा 15-8-2005 को 24 घंटे के बंद का आह्वान किया और लोगों से स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग न लेने के लिए कहा। समाचारों की प्रतियां भी फाइल की गईं। गवाह ने दिनांक 22-9-2005 की एक घटना का उल्लेख किया जिसमें किसी प्रतुल चंद्र डेका को एक गोली के साथ जो शायद बारिक से छुपकर चलाई गई थी, एक नोट मिला जिसमें 3 लाख रुपए की मांग की गई थी तथा एचएनएलसी के एक काडर पीसफुल रिकी सोहतन को गिरफ्तार किया गया था। इसके फलस्वरूप थाना लबान में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 384/506/34 के अंतर्गत 2005 का मामला सं. 53(09) दर्ज किया गया तथा 28-11-2005 को एक आरोप पत्र दायर किया गया। आरोप पत्र की एक प्रति रिकार्ड में दी गई है। इसी प्रकार उन्होंने 23-12-2005 की एक घटना के बारे में उल्लेख किया जिसमें किसी तीलांग थांगखियू को गिरफ्तार किया गया, गोलाबारूद के 7 राउंड से भरे हुए मैग्जीन सहित 9 एमएम का पिस्तौल बरामद किया गया जिसके फलस्वरूप रिंजाह थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 121(क)/120, सशस्त्र अधिनियम की धारा 25(1क) तथा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के अंतर्गत 2005 का मामला सं. 75(12) पंजीकृत किया गया। उसके फलस्वरूप 6-7-2006 को आरोप पत्र दायर किया गया। उस आरोप पत्र की एक प्रति अधिकरण के रिकार्ड के लिए दी गई है। इस गवाह ने आगे एचएनएलसी द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह का बहिष्कार करने के लिए 25-1-2006 से 26-1-2006 तक 24 घंटे के बंद के आयोजन के बारे में बताया। उन्होंने बयान दिया कि एचएनएलसी ने दिनांक 14-2-2006 को एक प्रेस विज्ञापन में कहा कि वह भारत के संविधान को स्वीकार नहीं करेगा। गवाह के अनुसार, दिनांक 26-3-2006 को मावलाई, शिलांग के किसी आईबोर मारवीन को एचएनएलसी के संदिग्ध काडर द्वारा गोली मार दी गई। इसके फलस्वरूप भारतीय दंड संहिता की धारा 320 तथा सशस्त्र अधिनियम की धारा 25(1क)/27(2) के अंतर्गत पुलिस थाने में मामला सं. 16(3)/06 दर्ज किया गया। एक एफआईआर की प्रति अधिकरण की फाइल के लिए दे दी गई है। यह बताया गया कि एचएनएलसी ने एक प्रेस विज्ञापित जारी की है जिसमें कहा गया है कि यह सशस्त्र संघर्ष जारी रखेगा और 1-6-2006 को इसने प्रेस विज्ञापित के माध्यम से एक चेतावनी जारी की कि यह शिलांग नगर निगम के चुनावों में भाग लेने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। गवाह ने बयान दिया कि 6-7-2006 को पुलिस ने हिल्स स्टार होटल, पुलिस बाजार शिलांग से एचएनएलसी के एक काडर कमफेर फ्रैंकली साईम को गिरफ्तार किया जो एचएनएलसी के कैप में एक रसोई के रूप में कार्य कर रहा है और उसके कब्जे से प्रतिबंधित एचएनएलसी से संबंधित कुछ अपराध को सिद्ध करने वाले दस्तावेज बरामद और जब्त किए गए जिसके फलस्वरूप शिलांग सदर पुलिस थाने में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10/13 के तहत मामला सं. 128(07) दर्ज किया गया।

16. सीडब्ल्यू-4 ने बयान दिया कि 2006 के स्वतंत्रता दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर एचएनएलसी ने हन्नीवट्टेप लैण्ड में भारतीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का विरोध करने के लिए 24 घंटे का बंद का आह्वान किया जो 14-8-2006 को शाम 6 बजे से 15-8-2006 को शाम 6 बजे तक प्रभावी था और लोगों से ऐसे

समारोह में भाग न लेने के लिए कहा। इस आह्वान के कारण लोगों में डर पैदा हो गया और समारोह के दौरान लोगों का सामान्य जीवन अस्त-व्यस्त हो गया। 1-9-2006 को पुलिस को मैसर्स रेडियो इलेक्ट्रीकल, मॉरवार, शिलांग के श्री राहुल जसरारिया से सूचना मिली कि 29-8-2006 को शाम 3.30 बजे उसे एक व्यक्ति का फोन आया था जिसने खुद को एचएनएलसी का एक काडर बताया और उसे 5-9-2006 तक 10,00,000 रुपए (दस लाख रुपए) देने का निदेश दिया जिसके फलस्वरूप पुलिस थाना लम्डीन गजरी में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 384/511 के तहत 2006 का मामला सं. 109 (9) पंजीकृत किया गया।

17. गवाह ने बयान दिया कि एचएनएलसी काडरों का एक दल डमक्रेम गांव में आश्रय ले रहा था और इसलिए दिनांक 20-9-2006 को शाम लगभग 5.00 बजे पुलिस ने गांव में छापा मारा। गवाह के अनुसार, इस अभियान में मुठभेड़ हुई क्योंकि एक घर के अन्दर से पुलिस बल पर गोलियां चलाई गई थी। पुलिस ने आत्मरक्षा में गोलियां चलाई और मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ के दौरान, एक काडर मारा गया तथा मौलाई इयूरिथेप शिलांग के एक अन्य काडर श्री वानपिसशंगाई डिमपैप उर्फ बाह जोप (19 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया गया। श्री वंस्टमोरलैण्ड लैमिन (35 वर्ष) का भी एचएनएलसी के आतंकवादियों को शरण देने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ में मारे गए एचएनएलसी के काडर की शिनाख्त श्री बंकिट खोंगजी उर्फ लीट के रूप में की गई। उसे पहले 27-9-2001 तथा 23-1-2002 को अवैध रूप से हथियार रखने के लिए गिरफ्तार किया गया था। घटनास्थल और गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों के कब्जे से निम्नलिखित सामग्री जब्त की गई अर्थात् :-

- (i) एक मैग्जीन सहित रूपांतरित स्टेगन
- (ii) एक मैग्जीन सहित कारबाइन
- (iii) जिन्दा गोलाबारूद के 9एमएम के 40 राउंड
- (iv) वर्गीकृत गोलाबारूद के 8 खाली केस

इसके फलस्वरूप सशस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-क) (1-ख)/27 के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 353/307/120(ख)/121/121(क)/123 के तहत पिनुरसला पुलिस थाने में 2006 का मामला सं. 14(09) दर्ज किया गया।

18. सीडब्ल्यू-4 ने यह भी उल्लेख किया कि दिनांक 25-9-2006 को सुबह लगभग 9.00 बजे पुलिस ने एचएनएलसी के एक दुर्दांत काडर मौलाई सिलाईकारिआहु, शिलांग स्थित श्री टॉम जोन्स रिंजाह के घर पर छापा मारा और उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके घर की तलाशी लेने पर, श्री बिशन नोनारूम को संबोधित एचएनएलसी के लेटर हैड पर लिखा गया कि डिमांड नोट बरामद किया गया जिसमें 5,00,000 रुपए (पांच लाख रुपए) की मांग की गई थी जिसके फलस्वरूप मौलाई पुलिस थाने में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10/13 के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 384/511 के तहत 2006 का मामला सं. 44(9) दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि एचएनएलसी ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट में सक्रिय है, जिसकी बंगलादेश के साथ लंबी अंतराष्ट्रीय सीमा रेखा

है; क्योंकि एचएनएलसी के शीर्ष काडर बंगलादेश में छुपे हुए हैं जहां से वे अपने विधिविरुद्ध आपराधिक एवं राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप चलाते हैं। संगठन के काडर अंतराष्ट्रीय सीमा पर से शीर्षस्थ सरगनाओं के अनुदेशानुसार व्यापारी समुदाय के सदस्यों को डिमांड नोट जारी करके निधियां जुटाने में लिप्त हैं। उसके अनुसार, विशेष रूप से उल्लिखित घटनाओं के अलावा, कम से कम 10 अन्य सूचित नहीं की गई घटनाएं हैं, लोग डर की वजह से सभी घटनाओं की सूचना नहीं देते हैं। उन्होंने बताया कि एचएनएलसी द्वारा की जाने वाली अवैध गतिविधियों में लूटे-खसोटे, अपहरण, हत्या एवं डराना-धमकाना शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पिछले प्रतिबंध की वजह से एचएनएलसी की गतिविधियां कुछ हद तक काबू में रही।

19. अधिकरण द्वारा जिस अगले गवाह का बयान लिया गया वह था सीडब्ल्यू-5, फ्रीमैन खारलिनेडोह, उपायुक्त, जिला वैस्ट खासी हिल्स। उन्होंने प्रदर्श सीडब्ल्यू-5/1 के रूप में अपने दिनांक 17-3-01 के शपथपत्र को पढ़ाया और प्रस्तुत किया। उनके अनुसार, एचएनएलसी तथा एएनवीसी वैस्ट खासी हिल्स में प्रचलनात्मक है और सूचना मिली है कि वे विभिन्न गुप्त स्थानों पर बड़ी संख्या में अवैध शस्त्र तथा गोलाबारूद रख रहे हैं ताकि वे भारत की संप्रभुता एवं भूभागीय अखण्डता को अव्यवस्थित और भंग कर सकें। यह भी बताया गया कि दोनों संगठनों के सदस्य अवैध रूप से धमकी देकर धन इकट्ठा करते हैं जो जारी है और एएनवीसी तथा एचएनएलसी के काडरों द्वारा अभी भी व्यापारियों से धन लूटा जा रहा है। एचएनएलसी के काडर नोंगजरी अंबेर, नोनीलाम, परमावदार तथा मावीत क्षेत्रों में अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। उन्होंने अपने शपथपत्र की विषयवस्तु को दोहराया तथा यह भी कहा कि ये संगठन कोयला समृद्ध क्षेत्रों में विभिन्न अवैध क्रियाकलापों में लिप्त हैं और व्यापारी समुदाय दोनों संगठनों का मुख्य निशाना है। गवाह ने कहा कि दोनों संगठनों के काडर भारत के बाहर बंगलादेश में आश्रय लेते हैं। उनके अनुसार प्रतिबंध की वजह से संगठनों के कार्यकलापों को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सका। जब एएनवीसी के अधिवक्ता द्वारा जिरह की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने 15 जनवरी, 2007 को ही उपायुक्त के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था।

20. सीडब्ल्यू-6, डाल्टन पी भरक, पुलिस अधीक्षक, जिला वैस्ट खासी हिल्स नोंगस्टोइन ने एएनवीसी तथा एचएनएलसी दोनों के संबंध में बयान दिया। उन्होंने प्रदर्श सीडब्ल्यू-6/1 के रूप में दिनांक 17-3-2001 के अपने शपथपत्र को पढ़ाया और प्रस्तुत किया। एएनवीसी के संबंध में साक्ष्य यह था कि इसके काडर छः घटनाओं में शामिल थे जिनमें उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्होंने ऐसी घटनाओं के बारे में एफआईआर दर्ज किए जाने के बारे में उल्लेख किया। एएनवीसी के अधिवक्ता द्वारा जिरह के दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें युद्धविराम बंदोबस्त के तहत संयुक्त मॉनीटरिंग ग्रुप के तंत्र के बारे में मालूम था और इस बात से इंकार किया कि उनके द्वारा अपने शपथपत्र के अनुलग्नक में उल्लिखित नाम एएनवीसी सदस्यों के नहीं थे। उन्होंने तीन व्यक्तियों का नाम लिया और कहा कि उनकी स्वीकारोक्ति के अनुसार वे एएनवीसी के सदस्य थे। जहां तक एचएनएलसी का संबंध है, उन्होंने आरोप लगाया कि इसने अपना सशस्त्र संघर्ष जारी रखा हुआ है ताकि वह भारत की संप्रभुता और

भूभागीय अखण्डता को अव्यवस्थित कर सके और इसके पास बड़ी मात्रा में शस्त्र तथा गोलाबारूद हैं। उन्होंने यह भी बताया कि एचएनएलसी के काडर नोंगजरी अंबेर, नोंघीलाम, पोरमावदार तथा मावीत क्षेत्रों में अपनी गतिविधियां चलाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि दोनों संगठन व्यापारी वर्ग से धन लूटते हैं और डकैती, चोरी, पुलिस दलों पर हमला करने में संलिप्त हैं। एचएनएलसी का एनएससीएन (आई/एम) तथा एनएलएफटी के साथ प्रत्यक्ष गठजोड़ एवं संपर्क है। वे संगठन एचएनएलसी के काडरों को प्रशिक्षण देकर उनकी सहायता करते हैं और अन्य राज्य में सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण जीवन को भंग करने में इसकी सहायता करते हैं। गवाह ने अपने बयान में एक घटना के बारे में भी उल्लेख किया जिसमें दो काडर सदस्य एक मुठभेड़ में मारे गए थे तथा एक को 2006 में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने अपने शपथपत्र के साथ लगी सूची में उल्लिखित दो मामलों के समर्थन में बयान दिया। पहला मामला दिनांक 22-6-2006 की एक घटना से संबंधित था जिसमें एचएनएलसी के काडरों ने होंघीलाम गांव में पुलिस दल पर हमला किया था जिसकी वजह से दोनों तरफ से गोलियां चलाई गईं और एचएनएलसी के दो अज्ञात संदिग्ध काडरों की मौत हो गई तथा शेष भाग गए। इस घटना में जीवित गोला बारूद के छह राउंड सहित एक कारबाइन, 32 गोलाबारूद के पांच राउंड सहित एक रिवाल्वर तथा अन्य अपराध सिद्ध करने वाले दस्तावेज बरामद हुए। मोंकीरवाट पुलिस थाने में सशस्त्र अधिनियम की धारा 27 तथा यूए(पी) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 333/307/353 के तहत मामला सं. 13(6)06 के लिए एक एफआईआर दर्ज की गई। दूसरी घटना यूए(पी) अधिनियम की धारा 10/11, के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 120(ख)/387 के तहत मोंकीरवाट पुलिस थाने में मामला सं. 26(11)06 से संबंधित थी। 18-11-06 को नोंगजरी गांव के मॉर्निंग हाइशह के धर पर छापा मारा गया तथा एचएनएलसी के वित्त सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए हुए एचएनएलसी के दो डिमांड नोट बरामद किए गए। गवाह ने रिकार्ड में अपना शपथपत्र देते समय अधिकरण के सामने प्रमुख जिरह के दौरान इन आरोपों को दोहराया।

21. सीडब्ल्यू-7 के सांके फोर्ड खोंगवीर, उपायुक्त, री-भोई जिला ने अगला बयान दिया, उन्होंने प्रदर्श सीडब्ल्यू-7/1 के रूप में दिए गए दिनांक 17-3-2007 के शपथपत्र का समर्थन किया। अगले गवाह सीडब्ल्यू-8 के रूप में श्री जैनल रिमाई, पुलिस अधीक्षक थे उन्होंने भी अपने दिनांक 17-3-07 के शपथपत्र का समर्थन किया जो प्रदर्श सीडब्ल्यू-8/1 के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इन दोनों गवाहों ने कहा कि एचएनएलसी री-भोई जिले में सक्रिय है और इसके काडर विधिविरुद्ध क्रियाकलाप करते हैं जिनकी सूचना इसके काडरों द्वारा डर पैदा करने के कारण नहीं दी जाती। सीडब्ल्यू-7 ने अन्य दलों जैसे उल्फा, एनडीएफबी, केएनवी (कबी नेशनल वालंटियर) आदि के साथ एचएनएलसी के संबंधों का उल्लेख किया।

22. सीडब्ल्यू-8 ने सूची (प्रदर्श सीडब्ल्यू-8/2) के रूप में सामग्री प्रस्तुत की। जिसमें विशिष्ट घटनाएं दी गई थी। 8-6-2005 को किसी कलेंडरसन वानियांग उर्फ मार्मेट उर्फ वैट ऑफ द फिनांस विंग ऑफ एचएनएलसी को उमजरसी गांव के निकट जंगल से गिरफ्तार किया गया तथा उससे एचएनएलसी के वित्त सचिव द्वारा

हस्ताक्षरित एक डिमांड नोट बरामद किया गया जिसमें 50,000 रुपये की मांग की गई थी। इसके फलस्वरूप उसे गिरफ्तार किया गया तथा अन्य अनेक व्यापारियों को डिमांड नोट वितरित करने के बारे में पता चला तथा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 120(ख)/121/121 के तहत नोंगपोह पुलिस थाने में मामला सं. 45(6)03 दर्ज किया गया। उन्होंने 11-6-05 की एक अन्य घटना के बारे में भी उल्लेख किया जो एचएनएलसी के वित्त विंग काडर सुमरलैंड खारमुजाई उर्फ हैप जैप द्वारा पुलिस अधीक्षक री-भोई के समक्ष आत्मसमर्पण करने से संबंधित थी तथा एचएनएलसी के लैटर हैड पर इसके अध्यक्ष जूलियस डोरफांग तथा इसके वित्त सचिव इआनेह स्वेम शाईला द्वारा हस्ताक्षरित एक प्राधिकार पत्र सौंपा गया था जिसमें उसे उन लोगों के साथ बातचीत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था जिनके खिलाफ डिमांड नोट जारी किए गए थे। उन सभी फर्मों की सूची जिन्हें डिमांड नोट वितरित किए जाने थे तथा मांगी गई राशि सोहपेटनेंग यूथ स्पोर्ट यूथ क्लब की रसीद बुक बरामद की गई। यह बताया गया कि एचएनएलसी ने 15 अगस्त, 2006 तथा 26 जनवरी, 2007 सहित राष्ट्रीय दिवसों पर बंद का आह्वान किया था। इसके कारण डर पैदा हो गया जिससे समारोहों में लोगों की स्वतंत्रता बाधित हुई। गवाह ने अपनी सूची में अंत में कहा कि आसूचना रिपोर्टों के अनुसार, एचएनएलसी के काडर अपने हथियार भंडार को पुनःवर्गीकृत और सुदृढ़ करने के लिए असम में अन्य संगठनों से गार्नर सहायता मांगते हैं।

23. श्रीमती रीबैका वानेसा सुचियांग, मेघालय सरकार की आयुक्त एवं सचिव ने सीडब्ल्यू-9 के रूप में अपना बयान दिया। उन्होंने सीडब्ल्यू-9/1 के रूप में अपने दिनांक 17-3-2007 के शपथपत्र की पहचान की। गवाह ने बयान दिया कि एचएनएलसी मेघालय में ईस्ट खासी हिल्स वैस्ट खासी हिल्स, जैतिया हिल्स तथा री-भोई जिलों में सक्रिय है। एचएनएलसी का मुख्य उद्देश्य एक पृथक राज्य बनाना है जो भारत संघ का हिस्सा न हो। गवाह ने कुछ घटनाओं के बारे में बयान दिया जिनमें एचएनएलसी सक्रिय रूप से शामिल था। 2005, 2006 तथा 2007 के गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान एचएनएलसी ने 24 घंटे के बंद का आह्वान किया और लोगों को समारोहों में भाग न लेने देने की धमकी दी। आम जनता ने परेशानी होने की आशंका से समारोहों में भाग नहीं लिया। गवाह ने बयान दिया कि एचएनएलसी खासी एवं जैतिया हिल्स में सक्रिय है जिसकी बंगलादेश के साथ लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। उन्होंने बयान दिया कि एचएनएलसी के शीर्षस्थ सरगना बंगलादेश में छुपे हुए हैं और वहीं से अपनी गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। गवाह ने बयान दिया कि एचएनएलसी के अन्य विद्रोही गुटों जैसे एनएससीएन, उल्फा, एनडीएफबी तथा एनएलएफटी के साथ अच्छे संबंध हैं तथा यह इन गुटों से प्रशिक्षण प्राप्त करता है।

24. गवाह ने बयान दिया कि एचएनएलसी मुख्यतः व्यापारी समुदाय को अपना निशाना बनाता है और लूट-खसोट में संलिप्त है। वर्ष 2005 में एचएनएलसी काडरों को गिरफ्तार किया गया तथा वर्ष 2006 में भी उनमें से 21 को गिरफ्तार किया गया। वर्ष 2005 में 1 ए के राईफल, एक 303 राईफल, 2 शॉटगन, 1 पिस्तौल, 1 रिवाल्वर, 30 गोलाबारूद, 1 खाली मैग्जीन, 1 हथगोला बरामद किया गया तथा

वर्ष 2006 में 3 कारबाईन, 1 पिस्तौल, 3 रिवाल्वर, 31 गोलाबारूद, 2 खाली मैगजीन बरामद की गई। गवाह ने विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित अधिसूचनाओं की प्रतियां प्रस्तुत की जिनके द्वारा दोनों संगठनों को विधिविरुद्ध घोषित किया गया था। ये अधिसूचनाएं 16-11-2006 की हैं। उन्होंने उन हिंसक/विधिविरुद्ध गतिविधियों और 2005-2006 के दौरान की गई गिरफ्तारियों की भी सूची दायर की जिनमें एएनवीसी के कांडर लिप्त थे।

25. श्री आर. आर. झा, निदेशक, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने सीडब्ल्यू-17 के रूप में बयान दिया। उन्होंने प्रदर्श सीडब्ल्यू-17/1 के रूप में प्रस्तुत अपने दिनांक 29-3-2007 के शपथपत्र की पहचान की। गवाह ने कहा कि एचएनएलसी का उद्देश्य हनीवट्रेप लोगों को भारतीय शासन के प्राधिकार से मुक्त करना, खासी जनजाति और मेघालय की अन्य जनजातियों की शोषण से रक्षा करना, स्थानीय संस्कृति का अनुरक्षण और सामाजिक बुझाई को दूर करना है। यह गुट इस बात पर जोर देता है कि सशस्त्र संघर्ष उसका अधिकार है। गवाह ने बताया कि यह संगठन लोगों को राष्ट्रीय समारोहों में भाग लेने से मना करता है, इन अवसरों पर बंद आयोजित करता है। लोग मुश्किल में पड़ जाने की प्रत्याशा में इन समारोहों में नहीं जाते। गवाह ने यह भी बताया कि यह संगठन विशेषकर खासी-जैतिया क्षेत्रों के कोयला सेक्टर से लूट खासोट, जोर-जबरदस्ती जैसे विधि विरुद्ध कार्यकलापों में संलिप्त है। यह संगठन व्यापारी समुदाय से लूट खासोट करने, अपने लिए धन एकत्र करने हेतु लोगों को लूटने, डराने-धमकाने और अपहरण के कार्यों में लगा है। इसने शस्त्र एवं गोलाबारूद प्राप्त करने के लिए पूर्वोत्तर के अन्य प्रतिबंधित विद्रोही गुटों से संपर्क बना रखे हैं। एचएनएलसी के शीर्ष नेता बंगलादेश में ठहरते हैं। वे शिविर आयोजित करते हैं जिनमें प्रशिक्षण शिविर भी शामिल हैं। गवाह ने प्रमुख जिरह में बताया कि सरकार ने अपनी पहले की अधिसूचना द्वारा एचएनएलसी पर जो प्रतिबंध लगाया था उससे केन्द्र सरकार विद्रोह-रोधी अभियानों के तौर पर प्रभावी कार्रवाई कर सकी है। ऐसा ही मामला एएनवीसी से संबंधित पहले प्रतिबंध का है। प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन संगठनों के अभियानों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में कोई अन्तराल न हो और उन्हें पुनः संगठित होने से भी रोका जा सके।

एएनवीसी के बारे में मेघालय राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए सक्षय

26. सीडब्ल्यू-10, श्रीमती रोबेक्का वनेस्सा सुचियांग, आयुक्त एवं सचिव मेघालय राज्य सरकार, राजनीतिक विभाग, शिलांग ने मेघालय राज्य की ओर से बयान दिया। उन्होंने अपने दिनांक 17-3-2007 के शपथपत्र का प्रदर्श सीडब्ल्यू-10/1 के रूप में प्रस्तुत किया। गवाह ने बताया कि एएनवीसी लोगों को तंग करके आमराधिक कार्यकलापों में लगा रहता है और विशेषकर गैर-जनजातीय व्यापारियों से लूट खासोट, जोर-जबरदस्ती करता रहता है। एएनवीसी व्यापारियों से धन की जबरन वसूली के लिए भी ताकत का इस्तेमाल करती है। यह डरा-धमकाकर गारो हिल्स में व्यापारिक गतिविधियों पर कब्जा करने का प्रयास कर रही है। उनकी गतिविधियां पश्चिम, पूर्व और दक्षिण गारो हिल्स के तीन जिलों तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि इसका

कांडर पश्चिम खासी हिल्स में भी सक्रिय है। एएनवीसी तुरा और गारो हिल्स में अन्य स्थानों में डरा-धमकाकर व्यापारियों से जबरन धन की वसूली करती है। एएनवीसी के वरिष्ठ नेता पूर्वी गारो हिल्स में कोयला व्यापारियों को उनके एजेंटों से, विभाग से किसी अधिकार, के बिना, बहुत अधिक दरों पर पी-फॉर्म और डीएमआर चालान खरीदने को मजबूर करते हैं। गारो हिल्स में कुछ टोल-गेट अप्रत्यक्ष रूप से एएनवीसी द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। संगठन के सदस्यों द्वारा अवैध तौर पर अप्रत्यक्ष रूप से धमकी देकर धन इकट्ठा करने का कार्य गुप्त रूप से अभी भी किया जा रहा है। गवाह ने बताया कि 14 जनवरी, 2005 को हुई एक घटना से यह स्पष्ट हो जाता है कि एएनवीसी कांडर अपने स्वयं के निहित स्वार्थ के लिए लोगों को आतंकित करते हैं। लोग इनके विरुद्ध रिपोर्ट करने से डरते हैं। गवाह के अनुसार युद्धविराम करार के बाद राज्य सरकार ने एएनवीसी से अवैध गतिविधियां छोड़ देने तथा सभी हथियार और गोलाबारूद सौंप देने का अनुरोध किया। ये इस समय तुरा में एएनवीसी के संपर्क कार्यालय में रखे गए हैं। आसूचना रिपोर्टों से स्पष्ट होता है कि एएनवीसी के शीर्ष नेताओं के बंगलादेश से संबंध हैं और उन्होंने यहां सुरक्षित आवास बना लिए हैं। उन्होंने अपने शस्त्र एवं गोलाबारूद बंगलादेश में छुपा रखे हैं। एएनवीसी ने गारो पहाड़ियों के तीन जिलों में कई डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रोड्स पर जबरदस्ती नियंत्रण किया हुआ है। उन्होंने प्रत्येक कोयला डीलर के लिए यह अनिवार्य बना दिया है कि वह उनको टूकों कोयला दान करे।

27. सीडब्ल्यू-10 ने बयान दिया कि एएनवीसी के 10 सदस्यों ने मई, 2005 एवं अक्टूबर, 2005 तथा अप्रैल, 2006 में हथियारों सहित शिविर छोड़ दिए थे। शिविर छोड़ने वालों ने पूर्वी एवं दक्षिणी गारो पहाड़ियों में अचीक नेशनल लिबरेशन फ्रंट आर्मी (एएनएलएफए) एवं पश्चिमी खासी पहाड़ियों में अचीक नेशनल यूथ (एएनवाई) नामक दो संगठन बनाए। गवाह ने यह भी कहा कि शिविर छोड़ने वालों सहित एएनवीसी के 13 कांडर 2005-06 में गिरफ्तार किए गए थे और उनसे 2 ए के राईफल्स, 1 एसएलआर, 3 पिस्तौल, 3 रिवाल्वर, 139 गोलाबारूद, 12 ग्रेनेड एवं 7 खाली मैगजीन बरामद की गई थीं। प्रमुख जिरह के दौरा, उन्होंने बताया कि एचएनएलसी तथा एएनवीसी दोनों के उत्पन्न, एनएलएफटी, एनडीएफबी और एनएससीएन (आई/एम) जैसे प्रतिबंधित/विधिविरुद्ध संगठनों से संबंध हैं। पूर्वतर्ती अधिसूचनाओं के तहत लगाये गए प्रतिबंध के परिणामस्वरूप लोगों में विश्वास की बहाली हुई, इन संगठनों की गतिविधियों पर अंकुश लगा जो कि कुल मिलाकर भारतीय भूभाग के बाहर के क्षेत्रों तक सीमित रह गयी हैं।

28. गवाह ने जिरह की गई। उसने कहा कि न्यायाधिकरण में उसका हलफनामा दर्ज किए जाने से पहले राज्य मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया; कोई अनुमोदन अपेक्षित नहीं था क्योंकि इसमें मंत्रिमंडल द्वारा नीति संबंधी निर्णय लेना शामिल नहीं था। ए एन वी सी अभियान के निलम्बन के लिए मेघालय सरकार, भारत सरकार तथा एएनवीसी के बीच हस्ताक्षरित, एक त्रिपक्षीय करार था। आरंभिक निलम्बन 6 महीनों की अवधि के लिए था इसे बार-बार बढ़ाया गया। अभियान के निलम्बन के विस्तार तथा करार की वैधता को मेघालय राज्य सरकार की सहमति प्राप्त नहीं थी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। करार के पक्षों ने एएनवीसी द्वारा मूल नियमों के पालन पर संतुष्टि जाहिर की। जिरह के दौरान, गवाह ने कहा कि एएनवीसी का उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष के जरिए राज्य का दर्जा प्राप्त करना है और मौजूदा क्षेत्रीय एकता का विरोधी और विच्छिन्नता वाला अथवा भारत की संप्रभुता तथा एकता को प्रभावित करने वाली कोई गतिविधि गैर-कानूनी है। मेघालय राज्य के पास एएनवीसी के सदस्यों की एक सूची है, जो अन्य (एवमेव सम्पूर्ण?) नहीं है। आरंभिक सूची में 105 नाम थे और बाद वाली सूची में 202 नाम निहित हैं। एक प्रश्न के उत्तर में, गवाह ने कहा कि एएनवीसी द्वारा कब्जे में लिए गए हथियारों को एक तटस्थ स्थान पर रखा जाना चाहिए लेकिन उन्हें तुरा में एएनवीसी के सम्पर्क कार्यालय में रखा गया। उन्होंने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि अभ्यर्पित एवं संयुक्त हिरासत में रखे गए हथियारों तथा लापता वस्तुओं के व्यौर के सम्बन्ध में विसंगतियाँ थी। अभियान के निलम्बन को शासित करने वाले मूल नियमों के अनुसार, एएनवीसी काडरों को निरस्त होना चाहिए; लेकिन कुछ हथियारों सहित घूमते हैं। एएनवीसी काडरों में से भगोड़े भी हैं। एएनवीसी के परिसर में संयुक्त अभिरक्षा में समझे जाने वाले लापता हथियार तथा ऐसे भगोड़ों की मौजूदगी, एएनवीसी की मंशा की अविश्वसनीयता की ओर संकेत करती है।

29. जिरह के दौरान सी डब्ल्यू 10 ने अभिसाक्ष्य दिया कि एएनवीसी काडर तीन जिलों नामतः पूर्वी गारो हिल्स, पश्चिमी गारो हिल्स तथा दक्षिणी गारो हिल्स के व्यापारियों, दुकानदारों, उद्योगपतियों तथा ठेकेदारों से जबरन धन वसूली करते हैं। वे फिरौती के लिए अपहरण करते हैं। जिसमें हाई-प्रोफाइल अपहरण भी शामिल हैं। वे लोगों में भय उत्पन्न करते हैं। एएनवीसी के निशाने पर बहुधा गैर-आदिवासी रहे हैं; उन्होंने सभी व्यापारियों/ट्रेडरों पर 2000 रुपये से एक लाख रुपये तक वार्षिक कर भी लगाया और 15 दिसम्बर, 2006 तक सभी भुगतान कर देने को कहा। एएनवीसी ने 202 काडरों की एक सूची दी थी जिसमें से केवल मात्र 120 काडर नामजद शिविरों में रहते हैं; शीर्ष नेता नामित शिविरों में कभी नहीं रहते। इस संगठन ने मात्र 16 हथियार जमा किए थे। शेष हथियार अभी भी उनके कब्जे में हैं। एएनवीसी कोयला व्यापारियों तथा अन्य लक्ष्य समूहों से चन्दा वसूली द्वारा जबरन धन वसूली में लगा हुआ है। भगोड़ों ने एके-47 राइफलों, सेल्फ लोडिंग राइफलों, मैग्जीनों तथा चीनी हथगोलों के साथ इस संगठन को छोड़ दिया। भगोड़ों के दो विभिन्न ग्रुप थे; उन्होंने एएनएलएफ, एएनवाई नामक विभिन्न संगठन बनाए जिनका मूल आधार पश्चिमी खासी हिल्स में था, एएनवीसी का इन संगठनों पर कोई नियंत्रण नहीं है। एएनवीसी गारो हिल्स में सक्रिय हैं और इसका उद्देश्य अपनी वित्तीय क्षमताओं को बढ़ाना है। इसके काडर लोगों में भय उत्पन्न करते हैं। एएनवीसी सामाजिक तथा सांस्कृतिक पुलिस-व्यवस्था एवं विवादों को निपटाने में भी शामिल रहा है।

30. श्री पामु सम्मत कुमार, उपायुक्त, पश्चिमी गारो हिल्स जिला, तूरा, मेघालय, ने सी डब्ल्यू-11 के रूप में अभिसाक्ष्य दिया। उन्होंने दिनांक 17-3-2007 को एक्स.सी. डब्ल्यू-11/1 के रूप में अपना हलफनामा दिया। इनके अनुसार, एएनवीसी पश्चिमी गारो हिल्स जिले में अपनी गैर कानूनी गतिविधियों को सक्रिय रूप से चलाते हैं। उन्होंने बताया कि एएनवीसी सशस्त्र संघर्ष द्वारा ग्रेटर गारो

लैण्ड की रचना करना चाहता है; व्यापारी समुदाय इसका मुख्य निशान है। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड (आईएम), [इसके बाद "एनएसीएन (आई एम)", यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम "उल्फा" तथा नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैण्ड ("एनडीएफबी")] सहित अन्य गैर-कानूनी संगठनों से इसके संबंध हैं जो इसे हथियार और असला सप्लाई करते हैं। एएनवीसी का मुख्यालय बंगलादेश में है जहां से यह नियमित रूप से अपना कार्य चलाता है। गवाह ने अपनी मुख्य जांच में अभिसाक्ष्य दिया कि एएनवीसी उनके जिले में सक्रिय है। इसका उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष द्वारा एक अलग गारोलैण्ड हासिल करना है। उन्होंने बताया कि काडरों के सीमा पार अन्य प्रतिबंधित संगठनों के साथ अच्छे रिश्ते हैं। एएनवीसी अपहरण, जबरन धन वसूली, हत्या और लोगों को डराने जैसी गैर-कानूनी गतिविधियों में लगा हुआ है। वे उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो उनकी दृष्टि से सहायता नहीं करते। गवाह ने जो बयान दिया कि बहकाए हुए युवाओं को ऐसी हिंसक एवं गैर-कानूनी गतिविधियों में हिस्सा लेने से विमुख करने में प्रतिबन्ध का फायदेमंद प्रभाव रहा।

31. जिरह के दौरान, गवाह ने अभिसाक्ष्य दिया कि गारो पश्चिमी गारो हिल्स में रहते हैं। एएनवीसी को गारो समुदाय के किसी वर्ग का समर्थन प्राप्त नहीं है। मूल नियमों के उल्लंघन के उदाहरण एवं मामले हुए हैं जिनमें विभिन्न पक्षों के बीच अभियान के निलम्बन के समझौते के बाद हिंसा शामिल है। पांच मामलों को छोड़कर, बहुत से अन्य मामले भय की मनःस्थिति के कारण सूचित नहीं किए गए। गवाह ने अभिसाक्ष्य दिया कि हिंसक कार्यों की सूचना पुनरीक्षा समिति को दी गई ताकि पहचान पत्र जारी करने तथा पदनामित शिविरों में रहने वाले एएनवीसी काडर के संबंध में अन्य सम्बन्धित मुद्दों का समाधान करने में राज्य के समन्वयन को सुकर बनाया जा सके। बैठक का प्राथमिक उद्देश्य हिंसा को शपथपूर्वक त्यागने में हितों के लिए परामर्श देना तथा समझना है और न कि सीधे ही सम्मत मूल नियमों के उल्लंघन को निर्दिष्ट करना। उन्होंने कहा कि यही कारण था कि बैठकों में जबरन धन वसूली आदि की मांगों को उजागर नहीं किया गया। गवाह ने दिनांक 28-8-2005 की एक घटना का वर्णन किया जिसमें एएनवीसी के संयुक्त सचिव ने कुछ काडर सदस्यों के साथ, मूल नियमों का उल्लंघन करते हुए जिला मजिस्ट्रेट के चैम्बर में जबरन प्रवेश किया और इसके काडर सदस्य नकली वंशपूषा में थे। गवाह ने बताया कि एएनवीसी के नाम का प्रयोग करने वाले कुछ अन्यो की संभावना बहुत कम है क्योंकि उन्हें इसके परिणामों का भय है। गवाह ने यह भी माना कि एएनवीसी में भगोड़े थे।

32. श्री जेरी फिशर के. मरक, पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी गारो हिल्स, तूरा, मेघालय ने सी डब्ल्यू-12 के रूप में अभिसाक्ष्य दिया। उन्होंने दिनांक 17-3-2007 को एक्स. सी. डब्ल्यू-12/1 के रूप में अपना हलफनामा प्रस्तुत किया। गवाह ने कहा कि एएनवीसी एक प्रतिबन्धित संगठन है और गैर-कानूनी गतिविधियाँ चलाता है। उन्होंने कुछ घटनाओं का वर्णन किया। 15-2-2006 को एएनवीसी काडरों को कलाईचार बाजार में देखा गया जब उन्होंने व्यापारिक समुदाय के सदस्यों से धन की मांग करनी शुरू कर दी। उन्होंने टीर काउंटर से 3000 रुपए की मांग की और उस दिन 1000 रुपए लिए। इसकी प्राथमिकी महेन्द्रगंज थाने में भा.द.स. की धारा 384 के अंतर्गत

मामला सं. 6 (2) 2005 दर्ज हुई। गवाह ने एक अन्य घटना का उल्लेख किया जो 17-2-2005 की घटी थी, जब एएनवीसी काडर, अर्थात् श्री कोचोल के. मरक डर्फ अमदस डर्फ रिक्शन को अपेक्षित शेष धनराशि वसूलते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। इसके परिणामस्वरूप इसके खिलाफ महेन्द्रगंज थाने में भा.द. सं. की धारा 384 के अंतर्गत मामला सं. 6(2) 2005 के रूप में एक प्राथमिकी दर्ज की गई। वर्णित तीसरी घटना श्री तोनांग डी. संगमा, एक काडर सदस्य से जुड़ी है जो लाटरीग्रे ट्राई जंक्शन पर एक स्कूटर से आया और शिकायतकर्ता श्री दुक्रान्त एम. संगमा को अम्पति बाजार के सभी टीएर काउंटरों से प्रत्येक से 200 रुपये वसूलने को कहा। शिकायतकर्ता ने प्रत्येक काउंटर से 200 रुपये एकत्र करके उसे 1800 रुपये दे दिए। इसकी प्राथमिकी महेन्द्रगंज थाने में भा.द. सं. की धारा 384 के अंतर्गत मामला सं. 8(2)05 के रूप में दर्ज की गई।

33. गवाह ने एक घटना का वर्णन किया जिसमें श्री वाडिंग के. मरक, महसविच (एएनवीसी) ने गारो हिल्स जिला परिषद (जीएचएडीसी) के सदस्यों को जीएचएडीसी के अंतर्गत आने वाली हाटों/बाजार से महसूल इकट्ठा करने हेतु अपने मुख्तार अभ्यर्थियों को आबंटन करने के लिए धमकी दी थी; उसने तुरा म्युनिसिपल बोर्ड के अधिकारियों को एएनवीसी अभ्यर्थियों के नाम से नगरपालिका के महसूल एकत्रण ठेके सुरक्षित रखने के लिए भी मजबूर कर दिया। नीलामी के लिए निर्धारित दिन एएनवीसी के सदस्य मौजूद थे तथा आम जनता डर के कारण वापस लौट गई। एएनवीसी काडरों ने आम जनता के दिमागों में आतंक की मन:स्थिति पैदा कर दी है। गवाह ने 5-4-2006 की एक घटना का जिक्र किया, जब अपराह में 11 बजे, एएनवीसी काडरों नामतः रामके बी. मरक, चोन्बार च. मोर्मिन तथा चार्ली संगमा ने यूथ-हास्टेल तुरा में एक लकड़ी की छड़ी से अपने साथी दाम्बिल सी. मरक पर हमला कर दिया जिसके परिणामस्वरूप उन्हें गहरी चोटें आईं और उसकी मौत हो गई। अभियुक्त छोटे हथियारों समेत भाग गए; उन्हें गिरफ्तार किया गया और दिनांक 14-4-2006 को तुरा थाने में भा.द. सं. की धारा 302/201 के अंतर्गत मामला सं. 39 (4) 06 के रूप में प्राथमिकी दर्ज की गई। गवाह ने लोगों में आतंक की मन:स्थिति उत्पन्न करने वाली एएनवीसी काडरों की उपस्थिति दर्शाने हेतु कुछ अन्य घटनाओं का वर्णन किया। स्थानीय लोग भय के मारे कोई वक्तव्य नहीं देते। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा हालातों को देखते हुए जिले में वर्तमान स्थिति को बेहतर बनाने हेतु कम से कम अन्य दो वर्ष की अवधि के लिए इए संगठन पर आगे प्रतिबंध लगाना जरूरी है।

34. सी डब्ल्यू-12 ने अभिसाक्ष्य दिया कि पश्चिमी गारो हिल्स में एचएनएलसी तथा एएनवीसी दोनों ही सक्रिय हैं; फिर भी, बाद वाला अधिक सक्रिय है। एएनवीसी का उद्देश्य सशस्त्र विद्रोह के जरिए गारोलैंड को हासिल करना है। वे जबरन धन वसूली, आपराधिक अभिभ्रान्त तथा जनता को परेशान करने जैसी गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त हैं; वे अभिभ्रान्त के द्वारा गारो हिल्स के व्यापार को हथियाने का प्रयास कर रहे हैं। एएनवीसी काडरों के खिलाफ मामले दर्ज हैं। बहुत से मामले डर के कारण सूचित नहीं किए जाते। गवाह ने बताया कि 2005-2007 के दौरान, 3 एएनवीसी काडर सदस्यों को गिरफ्तार किया गया लेकिन उनसे कोई अधिार बरामद नहीं किए गए। व्यापार

समुदाय एएनवीसी के निशाने पर है तथा उनके (एएनवीसी) प्रतिबंधित एसोसिएशनों के साथ संबंध हैं। एएनवीसी अपने कामियों को शस्त्रों का प्रशिक्षण दे रहा है और काडर नकली वेशभूषा पहनते हैं। मुख्य जांच के दौरान, उन्होंने एएनवीसी द्वारा प्रकाशित एक्स सी. डब्ल्यू-12/2 तथा सी डब्ल्यू-12/3 दीवार कैलेन्डर एवं टेबल कैलेन्डर प्रस्तुत किया; पहले वाले में इसके काडरों के नामों के ब्योरे सहित फोटो तथा प्रतिरूप हैं, जिन्हें युद्ध करते हुए अथवा युद्ध की वेशभूषा में, समूहों में तथा प्रशिक्षण देते हुए भी दिखाया गया है। सी डब्ल्यू-12/3 को चिह्नित कर दिया गया; यह गारो में "आर्मी फोर्मेशन अचिक नेशनल वालंटियर काउंसिल" नामक शीर्षक से एक दस्तावेज की प्रति है; गवाह के द्वारा इसका अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया गया तथा सी डब्ल्यू-12/4 के रूप में चिह्नित किया गया। इन्हें एएनवीसी की ओर से आपत्तियों के बिना चिह्नित किया गया।

35. गवाह ने साक्ष्य दिया कि एक नोडल अधिकारी एएनवीसी के नेताओं के साथ सम्पर्क बनाए रखता है। यह नोडल अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक स्तर का होता है। एएनवीसी के वरिष्ठ नेताओं को छोटे अग्नेयास्त्रों को रखने की अनुमति है, परन्तु वे इन्हें सार्वजनिक स्थानों पर नहीं ले जा सकते, उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए ऐसा करने की अनुमति है। एएनवीसी अन्य प्रतिबन्धित संगठनों से निपटने में पुलिस के साथ सहयोग नहीं करता। एएनवीसी व्यापार समुदाय से मांग करता है और गारो हिल्स में प्रत्येक जिस की बिक्री पर कर लगाता है। एएनवीसी ने डीटीएच (डायरेक्ट टू होम) घ्रादिकिणी पर प्रतिबंध लगा दिया है जिससे तुरा में सभी व्यक्ति प्रभावित हुए हैं। एएनवीसी जिले में केबल आपरेशन के व्यापार को नियंत्रित करता है। एएनवीसी ने तुरा में सूखी मछली की बिक्री पर 5 रुपये प्रति किलो कर भी लगा दिया है। लोग भय की मन:स्थिति के कारण घटनाओं की सूचना देते हुए डरते हैं।

36. श्रीमती रेनिल्ला डी. मरक, आईएस, उपायुक्त, दक्षिणी गारो हिल्स ने सी डब्ल्यू-13 के रूप में अभिसाक्ष्य दिया। उन्होंने दिनांक 17-3-2007 को एक्स सी डब्ल्यू-13/1 के रूप में अपना हल्फनामा प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि एएनवीसी एक गैर-कानूनी संगठन है जिसके शीर्ष नेता बंगलादेश में छुपे हुए हैं और वही से कार्य करते हैं। व्यापारिक समुदाय को डिमांड नोट जारी करके संगठन के काडरों का धनराशि वसूल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जबरन धन वसूली से फंड इकट्ठा करना उनकी प्रमुख गतिविधियों में से एक है। एएनवीसी ने अन्य पूर्वोक्त राज्यों के दूसरे प्रतिबन्धित विद्रोही समूहों जैसे एनएससीएन (आईएम), उल्फा, एनडीएफडी के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित किए हैं। गवाह ने अपनी मुख्य जांच के दौरान अभिसाक्ष्य दिया कि दक्षिण गारो हिल्स में एचएनएलसी तथा एएनवीसी दोनों ही सक्रिय हैं, लेकिन एएनवीसी अधिक सक्रिय है। उनका उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष के जरिए गारोलैंड सृजित करना है। एएनवीसी जबरन धन वसूली, हत्या करने तथा आम जनता को अभिभ्रान्त करने जैसी गैर-कानूनी गतिविधियों में सम्मिलित है। जबरन धन वसूली के लिए गैर-आदिवासियों तथा स्थानीय व्यापारियों को निशाना बनाया जाता है। लोग डर के मारे सारी घटनाओं को सूचित नहीं करते हैं। गवाह ने यह भी बताया कि एएनवीसी द्वारा अभिभ्रान्त के कारण, तुरा में दुकानदार तुरा के नगरपालिका क्षेत्र में निवासियों को डीटीएच उपकरण की

बिक्री नहीं करते। केवल व्यापार पर भी एएनवीसी का नियंत्रण है लेकिन दुकानदार इस धमकी को खुले रूप से प्रकट नहीं करते हालांकि वे मानते हैं इसके परिणामस्वरूप समस्या है। गवाह ने जिरह के दौरान अभिसाक्ष्य दिया कि 2006 में हिंसा की कुछ घटनाएं हुईं, नॉंगलबिन्ना में कोयला व्यापारियों से जबरन धन वसूली की सूचनाएं दी गईं। उन्होंने यह भी कहा कि टटके हल्फनामे में प्राथमिकी, एएनवीसी के भगौड़े से संबंधित है।

37. श्री हेईमाउं टोई, एमपीएस, पुलिस अधीक्षक, दक्षिणी गारो हिल्स जिला, बाघमारा ने सीडब्ल्यू-14 के रूप में अभिसाक्ष्य दिया। उन्होंने दिनांक 17-3-2007 को एक्स सी डब्ल्यू-14/1 के रूप में अपना हल्फनामा प्रस्तुत किया। उन्होंने 2-5-2005 की एक घटना का वर्णन किया जिसमें एएनवीसी के काडरों ने अपनी पिस्तौलों से गोली चलाई। मैं, वासा डी. संगमा तथा तीन अन्य व्यक्तियों ने श्री चिप्सोन मरक तथा जोहुरुल इस्लाम पर 9 एमएम पिस्तौल से गोली चलाई जिससे पीड़ित व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में, पुलिस ने उनके छिपने के ठिकाने पर छापा मारकर उनके कब्जे से जिंदा 9 एमएम असला तथा तीन चीनी हथगोले बरामद किए। इसकी प्राथमिकी बाघमारा थाने में धारा 25(1)(ए) शस्त्र अधिनियम के साथ पठित भा.द. सं. की धारा 307/326 के अंतर्गत मामला संख्या 20(5) 2005 के रूप में दर्ज की गई। गवाह ने अभिसाक्ष्य दिया कि एएनवीसी काडर लोगों को आतंकित करते हैं, जो पुलिस की शिकायत करने से डरते हैं क्योंकि आतंकवादी धन के साथ-साथ उनके हथियार भी रखते हैं। उन्होंने बयान दिया कि एएनवीसी तीसरे पक्ष को शामिल करके व्यापारिक समुदाय से जबरन धन की वसूली कर रहा है। यह संगठन गारो हिल्स में सभी व्यापारिक गतिविधियों को हथियाने की कोशिश कर रहा है। काडर के सदस्य अपहरण, हत्या तथा पुलिस के साथ मुठभेड़ जैसे विभिन्न अपराध करते हैं; उनका मुख्य उद्देश्य जबरन धन की वसूली करना है। लोग भय के कारण पुलिस को सूचित नहीं करते हैं। गवाह ने बताया कि एएनवीसी के पूर्वोत्तर के अन्य प्रतिबन्धित विद्रोही समूहों के साथ संबंध हैं। एएनवीसी का मुख्यालय बंगलादेश में है और वहां से इस संगठनको चलाया जाता है। गवाह ने कहा कि दक्षिणी गारो हिल्स बाघमारा जिले में एचएनएलसी तथा एएनवीसी सक्रिय हैं, एएनवीसी अधिक सक्रिय है। एएनवीसी जबरन धन वसूली, अभिद्रास तथा लोगों में आतंक फैलाने में सम्मिलित है। भय के कारण लोग घटनाओं की सूचना नहीं देते हैं। एएनवीसी के चार काडर सदस्यों को गिरफ्तार किया गया क्योंकि वे गैर-कानूनी गतिविधियों में संलिप्त थे, और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और एएनवीसी व्यक्तियों के किसी अन्य काडरों से हथियार बरामद नहीं किए गए हैं। एएनवीसी व्यापारी वर्ग और नोकमा यानि ग्राम के प्रधान को भी धमकी देता है। गवाह ने आगे अभिसाक्ष्य दिया एएनवीसी सरकारी कर्मचारियों को भी धमकी देता है। इसके काडर नॉंगलबिन्ना के कोयला क्षेत्र में व्यापक रूप से सक्रिय हैं। एएनवीसी के एचएनएलसी के साथ संबंध हैं; बंगलादेश में भी इसके अड्डे हैं। एएनवीसी काडरों के पास पहचान पत्र हैं, जिनकी प्रतियां रिकार्ड में रखी जाती हैं। एएनवीसी काडर अपनी कई तरह की पहचान रखते हैं और वे प्रायः अपना नाम बदलते रहते हैं। वे अक्सर नई भर्ती करते हैं। गवाह ने अभिसाक्ष्य दिया कि एएनवीसी के काडरों को नामजद शिविरों में रखा

जाता है गवाह ने दस्तावेजों के सामने रखे जाने पर (दिनांक 8-12-2005 की मासिक समीक्षा बैठक) कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि दक्षिणी गारो हिल्स के पूर्व पुलिस अधीक्षक ने एएनवीसी को, नामजद शिविरों से छः एएनवीसी भगौड़ों के ठिकानों की सूचना देकर पुलिस की सहायता करने का अनुरोध किया था। उन्होंने बताया कि एएनवीसी तथा इसके काडर हथियार नहीं रख सकते, यद्यपि हथियार बरामद किए गए।

38. श्री ओनेसिमस पासी, एमपीएस, पुलिस अधीक्षक, पूर्वी गारो हिल्स, विलियम नगर ने सीडब्ल्यू-15 के रूप में अभिसाक्ष्य दिया और दिनांक 17-3-2007 को एक्स सी डब्ल्यू 15/1 के रूप में अपना हल्फनामा प्रस्तुत किया। गवाह ने कहा कि एएनवीसी काडर जबरन धन वसूली में संलिप्त हैं; वे कोयला व्यापारियों, गेट आपरेटरों तथा अन्य व्यवसायियों से धन की मांग करते हैं। उन्होंने गारो हिल्स के तीन जिलों में बहुत से परिषद् गेटों को जबरन नियंत्रण में ले लिया। लोगों की हमदर्दी बटोरने के लिए वे जबरन वसूली गई रशि से वाहनों, एम्बुलेंस की खरीद करते हैं और उन्हें लोगों को दान कर देते हैं। एक बार रोगजंग की मदर्स केवर सोसायटी को एक मारुती वेन एम्बुलेंस दान की गई और सोसायटी के एक कार्यकारी सदस्या श्रीमती सुर्धा एम. संगमा को यह वाहन सौंप दिया गया। जब यह पता लगा कि एएनवीसी के काडरों द्वारा वाहन का प्रयोग अपनी जघन्य और गैर-कानूनी गतिविधियों को चलाने के लिए किया गया था, तो तुरा के पेसत ए. संगमा के नाम पर खरीदे गए इस वाहन को बाद में पुलिस ने जब्त कर लिया। इसे यूएलए (पी) अधिनियम की धारा 11/13 के अंतर्गत मामला सं. 11(4) 05 के रूप में रोजंगेंग थाने में दर्ज किया गया। 8-8-2006 को एएनवीसी काडरों को दसम गांव में सेना कर्मियों द्वारा गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से दो 9 एमएम पिस्तौलें जिन्दा कारतूसों सहित जब्त की गईं। शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-ए)(1-बी) के अंतर्गत मेण्डीपाघर थाने में मामला सं. 34(8)06 के रूप में मामला दर्ज किया गया। गवाह ने आगे साक्ष्य दिया कि एएनवीसी काडर आरक्षित वन से वृक्षों को अवैध रूप से काट गिराने और उन्हें समान्दा प्राप्ता मार्ग से हटाने में संलिप्त हैं। वे बहुत सी हत्याओं में भी शामिल हैं तथा लोग भय के कारण रिपोर्ट नहीं करते। गवाह ने अभिसाक्ष्य दिया कि पूर्वी गारो हिल्स में एएनवीसी तथा एचएनएलसी सक्रिय हैं, लेकिन दोनों में से एएनवीसी अधिक सक्रिय है। यह अपहरण, हत्या, अपावर्तन में शामिल हैं तथा इन सबसे जनता में भारी भय उत्पन्न किया है। ये काडर हत्याओं में शामिल हैं तथा विलियम नगर थाने में भा.द. सं. की धारा 302/201 के अन्तर्गत विभिन्न प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। पूर्वी गारो हिल्स में उन प्रतिबन्धित संगठनों के मुख्य समर्थक हैं—उल्फा, एनडीएफबी, (बीएससीएन) (आईएम), इन संगठनों की प्रमुख सहायता हथियारों का प्रशिक्षण एवं सप्लाई है। इन्होंने अपनी मुख्य जिरह में कहा कि एएनवीसी का मूल उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष के जरिए भारतीय संघ के बाहर एक अलग प्रभुसत्ता वाला राज्य प्राप्त करने का है। एएनवीसी तथा इसके कर्मियों के कई मामले हैं। भय के कारण सभी घटनाओं की सूचना नहीं दी जाती है। एएनवीसी की गैरकानूनी गतिविधियों में जबरन वसूली, अपहरण एवं हत्याएं शामिल हैं। वे प्रतिबन्धित हथियार रखते हैं और स्वतन्त्रता दिवस तथा गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय उत्सवों को मनाने,

अनुपालन करने पर प्रतिबंध लगाते हैं। वे व्यापारी वर्ग तथा उनके आदेशों के अनुरूप न चलने वाले लोगों को अपना निशाना बनाते हैं।

39. गवाह ने, जिरह के दौरान अभिसाक्ष्य दिया कि एएनवीसी के तीन नामजद शिविर हैं और इनमें से एक उनके जिले में स्थित है। बहुत से कांडर वास्तविक रूप से शिविर में नहीं रहते हैं। इन शिविरों से भगोड़े हैं। गवाह ने आगे बताया कि कांडर, व्यापारी वर्ग को निशाना बनाते हैं, कई अवसरों का बहिष्कार करते हैं और इनके कई प्रतिबन्धित विद्रोही समूहों के साथ सम्पर्क हैं।

40. श्री मिनेरम, आईएएस, उपायुक्त, पूर्वी गारो हिल्स विलियम नगर, मेघालय ने सी डब्ल्यू-16 के रूप में अभिसाक्ष्य दिया। उन्होंने 17-3-2007 को एक्स सी डब्ल्यू-16/1 के रूप में अपना हल्फनामा प्रस्तुत किया। गवाह ने अभिसाक्ष्य दिया कि एएनवीसी पूर्वी गारो हिल्स में सक्रिय रूप से गैर-कानूनी गतिविधियों में संलग्न है। इसके शीर्ष नेता बंगलादेश में छुपे हुए हैं। वे सीमा पार से अपनी गतिविधियों को चलाते हैं। इस संगठन के कांडर, व्यापारी समुदाय को डिमांड नोट जारी करके धन वसूल करने की गतिविधियों में लगे हुए हैं। उनके पूर्वोत्तर राज्यों के उल्फा, एनएससीएम (आईएम), एनडीएफबी जैसे अन्य प्रतिबन्धित समूहों के साथ अच्छे संबंध हैं। अपनी मुख्य जांच में गवाह ने अभिसाक्ष्य दिया कि पूर्वी गारो हिल्स, विलियम नगर में एचएनएलसी तथा एएनवीसी दोनों सक्रिय हैं लेकिन एएनवीसी अधिक सक्रिय है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य संशस्त्र संघर्ष के जरिए एक अलग राज्य प्राप्त करना है। वे लूटपाट, अपहरण, हत्या तथा अन्य असामाजिक गतिविधियों में शामिल हैं; वे गतिविधियां लोगों को राष्ट्रीय त्योंहारों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने से रोकती हैं। भय तथा प्रतिकूल परिणामों के कारण अधिकांश घटनाओं की सूचना नहीं दी जाती। गवाह ने आगे कहा कि एएनवीसी कांडर जिले में कार्य करते हैं परन्तु उनके शीर्ष नेता अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के पार बंगलादेश में हैं। एएनवीसी व्यापारी समुदाय, पुलिस तथा आम जनता को अपना निशाना बनाता है।

41. गवाह ने जिरह के दौरान अभिसाक्ष्य दिया कि अन्तिम बार एएनवीसी ने बन्द का आह्वान तथा स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस समारोहों का बहिष्कार वर्ष 2004 में किया था। गवाह ने आगे कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है तथा यह बताने में असमर्थ है कि एएनवीसी कांडरों के साथ संयुक्त बैठकें कहाँ आयोजित की गईं। गवाह इस बात से सहमत नहीं थे कि एएनवीसी पर प्रतिबंध लगाने का वास्तविक प्रयोजन अथवा उद्देश्य इसे मुख्य राजनैतिक गतिविधियों में शामिल होने तथा हिस्सा लेने से रोकना है।

42. आर. आर. झा निदेशक, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, सी डब्ल्यू-17 ने भी एएनवीसी के बारे में बताया; उन्होंने ई एक्स. सी डब्ल्यू-17/2 के रूप में दिनांक 29-3-2007 का अपना शपथ-पत्र दाखिल किया। गवाह ने यह स्पष्ट किया कि एएनवीसी का गठन 24 सितम्बर, 1996 को इसके पूर्ववर्ती अर्चीक लिबरेशन माटीग्रिक आर्मी (एएलएमए) से हुआ था। एएनवीसी का उद्देश्य मेघालय के गारो हिल्स के तीन जिलों, अर्चिचमी खासी हिल्स और री-भोई जिलों को शामिल करके एक अलग गारोलैंड राज्य बनाना है। इस मांग से खासी और गारो के मध्य शत्रुता बड़ी है। अपने इस उद्देश्य को पूरा

करने के लिए वह गृह राज्य के जन पदाधिकारियों को भयभीत करता रहा है, और जबरन धन-वसूली, अपहरण के जरिए धन राशि बढ़ाता रहा है और इकैतियों तथा बुरदराज के क्षेत्रों में अपना आधार स्थापित करने में संलग्न रहते हुए अन्य प्रतिबन्धित समूहों के साथ भी अच्छे संबंध बनाता रहा है। गवाह ने एडीशनल सॉलीसीटर द्वारा की गई प्रमुख जांच में यह बताया कि पूर्व अधिसूचना द्वारा एचएनएलसी पर प्रतिबंध लगाने से केंद्रीय सरकार विरोधी कार्रवाई के लिए प्रभावी कदम उठाने में सक्षम हुई है। यही स्थिति एएनवीसी से संबंधित पूर्व प्रतिबंध के मामले में है। प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लगाया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संगठनों की कार्रवाइयों को प्रभावी ढंग से रोकने में कोई कमी न रह जाए और उन्हें पुनः संगठित होने से भी रोका जा सके। गवाह ने ईएक्स-सी डब्ल्यू-17/3 के रूप में दिए गए अन्य शपथ पत्र की भी पहचान की जिसके साथ 1996 में बनाए गए एएनवीसी के संविधान की प्रति संलग्न थी।

43. गवाह ने अपनी जिरह के दौरान यह बताया कि यह गारो भाषा बोलता, लिखता/पढ़ता या समझता नहीं है। उसने यह बताया कि उसने एएनवीसी संविधान का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा है। एएनवीसी का अपना संविधान है। गवाह ने यह बताया कि 11-7-2006 को हुई बैठक में केंद्रीय सरकार ने एएनवीसी से यह कहा था कि वह अपने कांडरों की एक संपूर्ण सूची प्रस्तुत करे। एएनवीसी ने 202 कांडरों की एक सूची मुहैया करवाई; इनमें से 120 शिविरों में रहते थे। केंद्रीय सरकार के अनुमान के अनुसार हथियारों की संख्या 150 से ज्यादा है परन्तु केवल 16 हथियारों की सूची उपलब्ध कराई गई थी।

एएनवीसी की ओर से साक्ष्य

44. श्री राफेस सीधुच. माराक आर डब्ल्यू-1 के रूप में पेश हुए। (उन्होंने ई एक्स. आर डब्ल्यू-1/1) के रूप में 12-4-2007 के अपने शपथ-पत्र की पहचान की। गवाह ने यह बताया कि वह यूनाइटेड अर्चीक पीस फोरम जिसे इसके बाद "यूपीएफ" कहा गया है) का संयुक्त सचिव है जो गारो हिल्स के लगभग सभी वर्च नेताओं का प्रतिनिधित्व करता है। गवाह ने यह बताया कि यूपीएफ में दस सदस्य हैं। उसने यह बताया कि संगठन का प्रमुख उद्देश्य सोसायटी के नेताओं की नियमित बैठकें करके गारो हिल्स में शांति को बढ़ावा देना है। गवाह ने यह भी उल्लेख किया कि एएनवीसी यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता रहा है कि क्षेत्र में शांति बहाल हो। उसने यह भी बताया कि उसके संगठन ने एएनवीसी और सरकार के बीच अस्थायी युद्धविराम जारी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसकी जानकारी के अनुसार, एएनवीसी ने कभी भी किसी को नहीं धमकाया या जबरन धन-वसूली के जरिए धन की मांग नहीं की। उसने यह भी बताया कि एएनवीसी शान्तिपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता के जरिए अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। गवाह ने अपनी प्रमुख जांच में यह उल्लेख किया कि एएनवीसी का उद्देश्य है गारो लोगों के लिए राज्य का दर्जा प्राप्त करना और यूनाइटेड अर्चीक पीस फोरम का उद्देश्य है मेघालय सरकार और एएनवीसी के बीच शांति को बढ़ावा देना। उसने आगे बताया कि एएनवीसी ने किसी को नहीं धमकाया अथवा किसी से धन की मांग नहीं की। गवाह ने यह उल्लेख किया कि यदि गारो लोगों का अलग राज्य होगा तो उससे शांति को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि

मौजूदा सामाजिक राज्य में विभिन्न जनजातियाँ और लोग शामिल हैं और यह गारो लोगों की प्रकृति के अनुकूल नहीं हैं क्योंकि मौजूदा ढाँचे में गारो जाति के लोग विकास में अपना उचित हिस्सा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। गारो लोगों के हित के लिए एएनवीसी पर प्रतिबंध हटा लिया जाना चाहिए।

45. जिरह में, गवाह ने यह उल्लेख किया कि उस घटना की जानकारी है जिसमें 30-9-2005 को गारो हिल्स में पुलिस द्वारा गोलाबारी की गई थी; उस घटना के बाद सरकार और सभी वर्गों के बीच मतभेद समाप्त करने के प्रयास किए गए थे। इसमें रोमन कैथोलिक्स, पेंटेकोस्टल चर्च और अमेरिकन बैप्टिस्ट वर्गों जैसे चर्च समूहों के विभिन्न वर्गों की भागीदारी शामिल थी। उसने यह बताया कि चर्च और संबंधित सेवाओं ने एएनवीसी और अन्य समुदायों के सदस्यों के बीच शांति स्थापित करने का भरसक प्रयास किया। उसने यह उल्लेख किया कि एएनवीसी की लोगों को धमकाता नहीं है और लोगों से जबरन धन-वसूली नहीं करता। एएनवीसी और यूएपीएफ की तीन अवसरों पर गारो हिल्स, ऑडिटोरियम तूरा में शांति स्थापना की पहल करने हेतु बैठक की गई और उसके संगठन का मुख्य उद्देश्य है शांति को बढ़ावा देना। गवाह ने अपनी जिरह में यह भी बताया कि एएनवीसी अपने क्षेत्र अर्थात् बिशप कैपस एरियर, तूरा, गारो हिल्स में सक्रिय नहीं है। उसने बताया कि 30-9-2005 की घटना के परिणामस्वरूप कुछ बच्चों की मृत्यु पुलिस की गोलीबारी के कारण हुई थी। उसने बताया कि एएनवीसी संवर्गों के पास कोई हथियार नहीं है और उसे इस बात की जानकारी नहीं है इन्होंने हथियार कहाँ छिपा रखे हैं।

46. श्री रेकनंग एस. संगमा और डब्ल्यू-2 के रूप में पेश हुए। उन्होंने ई एक्स आर डब्ल्यू-2/1 के रूप में 16-11-2006 का अपना शपथ-पत्र प्रस्तुत किया। गवाह ने यह उल्लेख किया कि वह गारो हिल्स लेबर यूनियन का सचिव है जिसका मुख्यालय तूरा में है और लेबर यूनियन के लगभग हजार सदस्य हैं। गवाह ने यह बताया कि उसकी लेबर यूनियन के सदस्यों से लगातार बातचीत होती रही है जो अधिकांशतः गैर-जनजातीय हैं और उन लोगों को किसी भी वजह से धमकाए या डराए जाने के लिए एएनवीसी के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है। उसने यह भी उल्लेख किया कि एएनवीसी गारो हिल्स में रह रहे लोगों के हितों को बढ़ावा दे रहा है और वे गारो हिल्स में रह रहे लोगों की हालत में सुधार लाने के लिए एक अलग राज्य चाहते हैं।

47. गवाह ने अपनी जिरह में यह उल्लेख किया कि यूनियन के सदस्यों की संख्या लगभग एक हजार है। यूनियन में शामिल होते समय नए सदस्यों से 100 रुपए पंजीकरण शुल्क लिया जाता है। यूनियन एक पंजीकृत संगठन है, पदाधिकारियों का चयन हाथ उठाकर मतदान द्वारा किया जाता है न कि गुप्त मतपेटियों द्वारा। गारो हिल्स में काम करने वाले लोगों और मजदूरों द्वारा झेली जाने वाली समस्याओं में मजदूरी निर्धारण संबंधी विवाद, जन प्रतिनिधियों के साथ गाली-गलौच, संघर्ष, पारस्परिक विवाद और बाहरी क्षेत्रों, खास तौर पर सीमा पार से मजदूरों का आगमन आदि शामिल हैं। अधिकांश सदस्य गैर-जनजातीय हैं; यदि एएनवीसी यूनियन के गैर-जनजातीय सदस्यों को कोई धमकी

देता है तो उसकी सूचना संबंधित सदस्यों द्वारा यूनियन को दी जाती है। एएनवीसी की संलिप्तता के परिणामस्वरूप लूटपाट, जुआ खेलने और शराब पीने की घटनाओं में कमी आई है। गवाह ने यह भी बताया कि उसे एएनवीसी की गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। एएनवीसी संवर्ग के सदस्य उस क्षेत्र का दौरा करते हैं जहाँ अक्सर वह रहता है और उनके पास कोई हथियार नहीं होता। उसे एएनवीसी को वित्तपोषित किए जाने के स्रोतों के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

48. श्री परमन आर. माराक आर डब्ल्यू-3 के रूप में पेश हुए। उन्होंने ई एक्स आर डब्ल्यू-3/1 के रूप में 16-11-2006 का अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया। गवाह ने यह बताया कि वह गारो हिल्स ट्रेडर्स यूनियन, तूरा का अध्यक्ष है जिसका उद्देश्य है क्षेत्र के व्यापारियों के हितों को बढ़ावा देना और रक्षा करना। उसने यह बताया कि संगठन जनजातीय तथा गैर जनजातीय लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। एएनवीसी ऐसी किसी भी गतिविधि में संलिप्त नहीं रहा है जो गारो हिल्स में रह रहे व्यापारियों के विरुद्ध हो। गवाह ने यह बताया कि एएनवीसी के संवर्गों ने न तो धन की मांग की है और न ही व्यापारियों को धमकाया या परेशान किया है। गवाह ने यह बताया कि उसका चयन यूनियन के अध्यक्ष के रूप में ऐसी प्रक्रिया से किया गया जिसमें सदस्य मतदान हेतु अपने हाथ उठाते हैं, चयन गुप्त मतदान के जरिए नहीं किया जाता। यूनियन की गतिविधियों से मुख्यतः यह सुनिश्चित किया जाता है कि व्यापारियों और उसके सदस्यों का कल्याण हो। यूनियन पंजीकरण शुल्क के रूप में 200 रुपए प्रति सदस्य एकत्रित करती है और उसके लगभग एक हजार सदस्य हैं। ट्रेडर्स यूनियन की गतिविधियों का उद्देश्य है कठिनाई के समय में इसके सदस्यों की सहायता करना और किसी विपत्ति अथवा आपात स्थिति में परिवार के सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। यूनियन के लगभग 50 प्रतिशत सदस्य गारो हैं और शेष गैर जनजातीय हैं। गवाह ने यह बताया कि व्यापारियों के समक्ष प्रायः बहुत समस्याएँ नहीं आती; कभी-कभार शराब के नशे में धुत युवकों के कारण समस्या का सामना करना पड़ जाता है। जब कभी भी ऐसी सूचना प्राप्त होती है, यूनियन मौके पर पहुंचती है और परेशानी पैदा करने वाले ऐसे व्यक्तियों को समझाती है। गवाह ने यह बताया कि उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि एएनवीसी ने प्रस्तावित प्रतिबंध की अधिसूचना पर कोई आपत्ति दर्ज की है अथवा नहीं।

49. गवाह ने अपनी जिरह में यह बताया कि उसे एएनवीसी की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों की कोई जानकारी नहीं है। उसे पदाधिकारियों के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है; उसने काफी समय से अपने क्षेत्र में एएनवीसी संवर्गों को नहीं देखा है। संगठन के किसी भी सदस्य ने एएनवीसी द्वारा धन की मांग किए जाने या धमकाए अथवा परेशान किए जाने का उल्लेख नहीं किया है।

50. श्री वांडिंग के. माराक, महासचिव, एएनवीसी आर डब्ल्यू-4 के रूप में पेश हुए। उन्होंने ई एक्स आर डब्ल्यू-4/1 के रूप में 13-4-2007 का अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया। गवाह ने यह बताया कि एएनवीसी का गठन 20-2-1995 को किया गया था और वह 1998 से महासचिव हैं। संगठन का उद्देश्य है अलग गारो लैंड राज्य बनाना जिसमें मेघालय का गारो हिल्स जिला और प्रमुखतः गारो द्वारा

बसाए गए क्षेत्र (मेघालय के पश्चिमी खासी हिल्स और रिमोई जिले, असम के पोलपाड़ा और कामरूप जिला) शामिल है। गवाह ने यह बताया कि गारो लोगों का एक पृथक् राज्य होना चाहिए ताकि ये राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नृजातीय एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में अपना भविष्य स्वयं निर्मित कर सकें। गवाह ने यह बताया कि एएनवीसी ने प्रथमतः छः माह के लिए कार्रवाई को स्थापित करने के लिए भारत सरकार और मेघालय सरकार के साथ एक समझौता किया। कई अवसरों पर बैठकें आयोजित की गईं : 17-1-2005 में बैंक में एएनवीसी ने यह स्पष्ट किया कि इसके संघर्ष का कोई भी सदस्य विधिविरुद्ध गतिविधियों में संलिप्त नहीं था और पुलिस को चाहिए कि वह जबरन धन-वसूली के लिए एएनवीसी के नाम का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करें। गवाह ने यह बताया कि वे नए संघर्षों की भर्ती नहीं कर रहे हैं। दिनांक 18-7-2005 की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि निर्धारित शिविरों में संघर्ष के सदस्यों की पूरी सूची, फोटो और पते तथा इनके पास मौजूद हथियारों की सूची प्रस्तुत की जाएगी। हथियार आत्मरक्षा के लिए रखे गए थे। युद्धविराम की अवधि छः माह के लिए और तदुपरांत अगले एक साल के लिए बढ़ा दिया गया था तथा सूची उपलब्ध कराई गई और हथियारों को संयुक्त अभिरक्षा में रखा जाता है।

51. गवाह ने यह बताया कि एचएनएलसी और एएनवीसी विधिविरुद्ध संगठन नहीं है, एएनवीसी उल्फा और एएनएलएफ, एलएईएफ जैसे अन्य छोटे-छोटे समूहों के साथ संलिप्त नहीं है। गवाह ने यह बताया कि छोटे समूह गारो हिल्स में हत्या, जबरन धन वसूली, अपहरण, मांग नोट देने आदि में संलिप्त हैं। उसने यह भी बताया कि इसका कोई भी शीर्ष नेता बंगलादेश में नहीं रहता और वे गैर-कानूनी गतिविधियाँ नहीं चला रहे हैं। वास्तव में एएनवीसी अनेक सामाजिक गतिविधियाँ भी संचालित करता है जैसे कि उसने सुनामी राहत निधि में स्वेच्छा से अंशदान दिया और ग्रामवासियों को 2 एम्बुलेंस भी दान में दी हैं।

52. गवाह ने अपनी जिरह में यह बताया कि गारो लोग एक अलग राज्य के हकदार हैं क्योंकि उनके साथ मेघालय में अन्य जनजातियों के मुकाबले भेदभाव किया गया है। एएनवीसी ने केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के अपने संघर्ष के 202 सदस्यों की सूची सौंपी। संघर्ष को शुभचिन्तकों और अलग गारो लैण्ड राज्य की इच्छा करने वाले गारो लोगों की सहायता के जरिए बनाए रखा जाता है। एएनवीसी के पास आप्र का कोई अलग स्रोत नहीं है; इसकी सहायता नियमित आधार पर लोगों/शुभचिन्तकों के अंशदान से की जाती है। गवाह ने इस बात से इंकार किया कि एएनवीसी बड़ी मात्रा में हथियार रखता है और उनके हथियार संयुक्त अभिरक्षा में रखे जाते हैं। हथियार आत्मरक्षा के लिए रखे जाते हैं और वे सभी इथिओपिया तस्करों से प्राप्त किए गए थे; आर डब्ल्यू-4 ने इस बात से इंकार किया कि हथियार बंगलादेश से प्राप्त किए गए थे या पुलिस, अर्द्ध सैनिक बलों अथवा सेना से छीने गए थे। गवाहों ने इस बात पर सहमति जताई कि हथियारों की एक सूची राज्य सरकार को दी गई थी जिसमें एलएमजी, 5 एके-56 राइफलें, एम-155.56 एम एम राइफल शामिल हैं; उसने यह भी बताया कि इन सबका इस्तेमाल आत्मरक्षा के लिए किया जाता

है। गवाह ने यह उल्लेख किया कि संघर्षों की प्रस्तुत सूची उन्हें दिए गए पदनाम के अनुसार नहीं थी। उसने इस बात से इंकार किया कि सूची में पाई गई संघर्षों भिन्नता निरंतर भर्ती के कारण थी। उसने यह कहा कि यह भिन्नता शांति बातों के जरिए प्राप्त प्रगति के कारण थी। गवाह ने यह बताया कि उसे प्रत्येक शिविर में संघर्षों की संख्या के बारे में जानकारी नहीं है। गवाह को तीन दिन बाद दोबारा जिरह की गई, जब उसने यह बताया कि उसे एएनवीसी के निकाले गए या छोड़े चुके सदस्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसने यह भी बताया कि हथियारों का कोई प्रशिक्षक नहीं है और सभी संघर्षों ने स्वयं प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उसने बताया कि संगठन के शीर्ष नेता गारो हिल्स में रहते हैं और गैर-जनजातीय लोग बैरिकेड तौर पर एएनवीसी का समर्थन कर रहे हैं। गवाह ने यह उल्लेख किया कि एएनवीसी कोई साहित्य प्रकाशित नहीं करता।

53. गवाह ने एडीशन्सल सीपीसीएर जनरल द्वारा की गई उसकी जिरह में यह भी बताया कि मजबूत सुरक्षा के लिए कोई चुनना नहीं कराया गया था और उसे उनके नेता श्री दिलाश रम, मास्कर दसा चुना गया था। उसने बताया कि उसे संगठन में शामिल होने के लिए कभी भी आर्म्ड नहीं किया गया बल्कि वह स्वेच्छा से इसमें शामिल हुआ है। गवाह ने यह बताया कि एएनवीसी का कार्यालय नूरा सुवा होस्टल में है और वह अर्वास सरकार द्वारा आर्बेटिड किया गया है। गवाह ने यह उल्लेख किया कि एएनवीसी का कोई लिखित संविधान नहीं है, इसके लक्ष्य एवं उद्देश्य सामूहिक निर्णयों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। निर्णय बैठक में लिए जाते हैं। गवाह ने यह भी बताया कि एएनवीसी के सदस्यों की निश्चित संख्या 202 है। उसने बताया कि केन्द्रीय सरकार को दिए गए ज्ञापन में तिरंगा तथा एएनवीसी की झंडी चिह्न है, जो संगठन का झंडा है केवल एक ही झंडा है और इसे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं किया जाता, इसे कार्यालय में रखा जाता है। गवाह ने बताया कि एएनवीसी अपना मुख्यालय (चेरम) बैसा कि कहा जाता है) बदलता रहता है क्योंकि पुलिस द्वारा मुठभेड़ की जाती है और इससे इसके कई संघर्ष मारे जा चुके हैं। गवाह ने बताया कि संघर्षों की सदस्यों के अलावा एएनवीसी के मुख्यालय के बारे में कोई नहीं जानता। उसने यह भी बताया कि एएनवीसी का एक अध्यक्ष, एक संयुक्त सचिव है जो वित्त विभाग को देखता है; चेयरमैन-इन-चार्ज संघर्षों को संचालित है। श्री एरिस्ट सेंगसरांग एएनवीसी के प्रचार का काम देखते हैं और वह प्रचार सचिव हैं। एक आभोजक सचिव भी है लेकिन कोई रक्षा या विदेश सचिव नहीं है।

54. गवाह ने बताया कि उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्रकाशित नहीं किया गया था क्योंकि वह पहले से ही ज्ञापन में था। उसने कहा कि गारो लैण्ड का सृजन किसी भी तरह नहीं बल्कि राजनीतिक बातचीत के जरिए होगा। हथियार और गोलाबारूद आत्मरक्षा के लिए जरूरी है। उसने यह भी कहा कि एएनवीसी के लिए दो निर्धारित शिविर स्थापित किए गए थे और एक संपर्क अधिकारी बनाया गया तथा काइरों को निर्धारित शिविरों में कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता राजनीतिक बातचीत के कारण इसकी कोई जरूरत नहीं है। गवाह ने बताया कि एएनवीसी कोई सार्वजनिक सभा आयोजित नहीं करता और इसके सदस्यों की गतिविधियों के बारे में इसके

संवर्गों को जानकारी होती है। उसने यह भी कहा कि एएनवीसी का एक टेबल कैलेण्डर है जिसे प्रचार सचिव द्वारा बनाया जाता है। उसने यह भी बताया कि एएनवीसी को कोई बैंक खाता नहीं है क्योंकि इसके पास धन नहीं है। धन शुभचिन्तकों से प्राप्त किया जाता है। अंत में उसने कहा कि एएनवीसी के संवर्ग सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष से कम है। ऐसा इस तथ्य के कारण है कि युवा लोग शारीरिक रूप से ज्यादा सक्रिय और लड़ने में सक्षम होते हैं।

55. श्री तोरिक जांगनिंग माराक, एएनवीसी के आयोजक सचिव आर डब्ल्यू-5 के रूप में पेश हुए। उन्होंने ई एक्स आर डब्ल्यू 5/1 के रूप में 13-4-2007 का अपना शपथ-पत्र दिया। गवाह ने यह बताया कि एएनवीसी का लक्ष्य और उद्देश्य है 'पृथक गारो लैंड' का सृजन करना। उसने बताया कि एएनवीसी का उद्देश्य कभी भी भारत के भू-भाग के किसी भी हिस्से को अलग करना नहीं है। उसने बताया कि एएनवीसी किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं है और वर्तमान में इसके पास कोई हथियार नहीं है। उसने कहा कि कोयला पट्टी क्षेत्र में जबरन धन वसूली करने वाले लोग एएनवीसी से संबंध नहीं है बल्कि वे अन्य एजेंसियों से जुड़े हैं जो सरकार की ओर से धन एकत्रित करते हैं। गवाह ने बताया कि एएनवीसी के बारे में जबरन धन वसूली करने, परेशान करने, गारो हिल्स में व्यवसाय पर कब्जा जमाने, लोगों के बीच दहशत फैलाने और उनके मन में भय पैदा करने के झूठे आरोप गढ़े गए हैं। उसने बताया कि एएनवीसी के सभी संवर्ग सदस्य निर्धारित शिविरों में रहते हैं और शिविरों के बाहर उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाती है। उनका पास आत्मरक्षा के लिए हथियार भी संयुक्त अभिरक्षा में रखे जाते हैं।

56. गवाह ने बताया कि एएनवीसी गारो हिल्स के लोगों द्वारा लंबे समय से महसूस की जा रही निराशा की प्रतिक्रिया है जो पिछड़े हुए हैं तथा जिन्हें विकास वंचित रखा जाता है। एएनवीसी उचित दर्जा न दिए जाने के कारण लोगों के हित के लिए संघर्ष कर रहा है। गारो लोग मेघालय की अन्य दो जनजातियों की तुलना में शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े रहे हैं। गवाह ने कहा कि अन्य जनजातियों के मुकाबले उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। गवाह ने मुख्य जांच में कहा कि वर्ष 2004 में एएनवीसी ने अपने हथियार डाल दिए थे। उसने बताया कि एएनवीसी की योजना है कि यदि प्रतिबंध हटा लिया जाता है तो वह चुनाव लड़ेगा। एएनवीसी की बैठकें निर्धारित शिविरों और युवा होस्टलों में की जाती हैं। उसने यह भी बताया कि महिन्द्रा फाइनंस ने उससे संपर्क किया कि वह गारो हिल्स में उन दोषी व्यक्तियों के वाहनों को पुनः अपने कब्जे में लेने के लिए वसूली एजेंट के रूप में कार्य करे जो वाहन अग्रिम का भुगतान नहीं करते हैं।

57. गवाह ने अपनी जिरह में कहा कि एएनवीसी का प्रमुख उद्देश्य है पृथक गारो लैंड राज्य प्राप्त करना क्योंकि गारों लोगों की अपेक्षा की जाती है। उसने बताया कि एएनवीसी का लिखित संविधान नहीं है। गवाह ने बताया कि एएनवीसी के पदधिकारियों के लिए विभिन्न पदनामों जैसे के अध्यक्ष, संयुक्त सचिव और प्रचार सचिव का उपयोग किया जाता है। उसने आगे बताया कि नामांकन की कोई

प्रक्रिया नहीं है और उसे मौखिक रूप से संगठन सचिव के रूप में नामित किया गया था। उसने यह भी बताया कि युद्ध विराम से पहले एएनवीसी के संवर्ग इधर-उधर घूमकर अपने संगठन का प्रचार किया करते थे और युद्ध विराम के पश्चात ऐसी कोई गतिविधि नहीं है। उसने कहा कि संवर्ग को सेना के रूप में जाना जाता था। जब गवाह से एएनवीसी के उन सदस्यों के बारे में पूछा गया जो कई मामलों में संलिप्त थे तो उसने नकारात्मक उत्तर दिया। गवाह एएनवीसी को छोड़ने वाले व्यक्तियों के बारे में जानता था; उसने कहा कि उनमें से तीन व्यक्तियों को संपर्क अधिकारी के पद से हटाया गया क्योंकि वे कठोर बुनियादी नियमों का पालन नहीं कर सके थे। उसने यह उल्लेख किया कि युद्ध विराम से पहले संवर्ग के सदस्यों को हथियारों का प्रशिक्षण दिया गया था। जिसमें ए. के. श्रृंखला के हथियारों और पिस्तौलों के चलाने का प्रशिक्षण शामिल है।

58. गवाह ने यह माना कि उसका ईसाई नाम बर्नार्ड माराक था जिसे परिवर्तित करके अधिकारिक नाम तोरिक जेंगनिंग माराक कर दिया गया था। गवाह ने इससे इनकार किया कि महिन्द्रा फाइनंस नामक कोई कम्पनी है तथा उन्होंने यह स्वीकार किया कि उन्हें महिन्द्रा फाइनंस, रि-भोई जिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के मामले में अग्रिम जमानत प्रदान की गई थी। गवाह ने यह स्वीकार किया कि सी डब्ल्यू-12/2 दीवार कैलेण्डर सी डब्ल्यू 12/3 और टेबल कैलेण्डर एएनवीसी द्वारा तैयार किए गए थे परन्तु यह स्पष्ट किया कि कैलेण्डर में दिए गए फोटो युद्ध विराम से पहले खींचे गए थे। उन्होंने यह स्वीकार किया कि श्री दिलाश एम. मारक एएनवीसी के अध्यक्ष थे तथा उनका नाम संयुक्त मानीटरिंग ग्रुप या सरकार को प्रस्तुत की गई सूची में नहीं था क्योंकि वह कैंप में नहीं रहते थे। केवल उन्हीं के नाम थे जो उन कैम्पों में रहते हैं। गवाह ने बताया कि एएनवीसी राष्ट्रीय समारोहों में भाग नहीं लेती परन्तु उसके व्यक्तिगत सदस्य भाग लेते हैं। उन्होंने बताया कि एएनवीसी संगठन का स्थापना दिवस या उसके गठन का दिवस मनाती है। उन्होंने बताया कि खासी और जनतिया गारो हिल्स में रहते हैं तथा रोजगार संबंधी नीतियां विभिन्न समुदायों के अनुपात के आधार पर बनाई जाती थीं। गवाह ने बताया कि कैलेण्डर और टेबल डायरी के सिवाय एएनवीसी के पास संयुक्त मानीटरिंग ग्रुप को प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के अलावा कोई लिखित रिकार्ड नहीं था।

59. गवाह ने बताया कि एएनवीसी को प्राप्त हुए धन का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता। खर्च का भी कोई रिकार्ड नहीं है। इसका कोई रिकार्ड नहीं है कि हथियार कहां से आते थे तथा उनका प्रयोग कैसे होता था? आर डब्ल्यू-5 ने बताया कि एएनवीसी के पदाधिकारियों और काडर के बारे में लोगों आपस में बातचीत के जरिए जानते हैं। तथा वे उन्हें अपना स्थानीय संरक्षक समझते हैं। गवाह ने बताया कि एएनवीसी कांडर को उनकी सेना के रूप में जाना जाता है तथा कोई कमांडर-इन-चीफ नहीं है। उन्होंने बताया कि जबरन धन वसूली जैसी अवैध गतिविधियां गारो हिल्स में अन्य संगठनों द्वारा की जाती हैं, अभी भी अर्थात् युद्ध विराम के बाद भी ये जारी थीं। उन्होंने बताया कि एएनवीसी के लक्ष्य और उद्देश्य चेयरमैन द्वारा तय किए जाते हैं तथा संगठन में आने के लिए किसी को आमंत्रित नहीं किया

जाता, लोग स्वयं आते हैं। अधिकारण के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ-पत्र पर उन्होंने चेरमैन की अनुमति से हस्ताक्षर किए थे परन्तु इसे उन्हें नहीं दिखाया गया था।

धारा 3 (1) के तहत अधिसूचना की पुष्टि के समर्थन में मेघालय राज्य एवं केन्द्र सरकार की ओर से की गई स्वीकारावृत्तियाँ

60. मेघालय राज्य की ओर से विद्वान वकील श्री रंजन मुखर्जी ने कहा कि न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों एवं सामग्री को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम की धारा 3(1) के तहत जारी अधिसूचना की धारा 4(3) के तहत पुष्टि की जानी चाहिए। विद्वान वकील ने अधिनियम के प्रावधानों का संक्षेप में वर्णन किया तथा यह उल्लेख किया कि इसे 1963 से संविधान में संशोधन के पश्चात् वर्ष 1967 में लागू किया गया था जिसके कारण सन्त्य भारत की प्रभुसत्ता एवं अखंडता की रक्षा के लिए उपयुक्त प्रतिबंध लगाने में सक्षम हो सका। यह उल्लेख किया गया कि मूल रूप से लागू अधिनियम में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप को कुछ भिन्न तरीके से परिभाषित किया गया था तथा कभी-कभी कुछ विशेष प्रकार की गतिविधियों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करते समय कठिनाईयाँ अनुभव की गईं। तथापि, वर्ष 2004 के संशोधन के पश्चात् अधिनियम के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर दिया गया जिसमें धारा 2(पी) के तहत "विधिविरुद्ध संगम" को एक ऐसे संगम के रूप में परिभाषित किया गया है जो अपने उद्देश्य के लिए किसी विधिविरुद्ध क्रियाकलाप का प्रयोग करता है अथवा जो व्यक्तियों को कोई विधिविरुद्ध कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करता है अथवा सहायता करता है अथवा जिसके सदस्य ऐसी गतिविधि में संलिप्त होते हैं। यह उल्लेख किया गया कि "प्रोत्साहित" एवं "सहायता" जैसी अभिव्यक्तियों का उद्देश्य अधिनियम के सीमा क्षेत्र में विस्तार करना था। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि धारा 2 (ओ) में विधिविरुद्ध गतिविधि को विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया है, इसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय सू-भाग के किसी हिस्से अथवा भारतीय संघ के किसी हिस्से के अलग-अलग को समर्थन अथवा ऐसे स्थानान्तरण अथवा पृथक्वाद को अंजाम देने की मंशा सहित व्यक्तियों एवं संगठनों की गतिविधियाँ जिनमें कहे गये शब्द या लिखे गये शब्द अथवा अभ्यावेदन के माध्यम से की गई गतिविधियाँ शामिल हैं। उप-धारा (ii) में दी गई परिभाषा के अनुसार भी इसमें ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियों को शामिल किया गया है जो भारत की प्रभुसत्ता एवं क्षेत्रीय अखंडता को अस्वीकार करता है, उसे चुनौती देता है, भंग करता है अथवा इसे भंग करने का प्रयास करता है अथवा भारत के खिलाफ घृणा पैदा करता है अथवा पैदा करने का प्रयास करता है। विद्वान वकील ने उल्लेख किया कि अधिनियम के उद्देश्य अर्थात् संगठनों, व्यक्तियों की प्रवृत्तता के अधिकार पर अंकुश लगाने का ध्यान रखते हुए "प्रभुसत्ता", "अखंडता" एवं अन्य प्रतिबंधक शब्दावली को एक साधारण एवं व्याकरणिक अर्थ दिए जाने की आवश्यकता है। मूलभूत रूप से जोर देकर यह कहा गया था कि सामान्य शब्दावली में भी प्रभुसत्ता एवं अखंडता वृहद शब्द हैं। अतः सुव्यवस्थित समाज के लिए स्वतंत्रा उत्पन्न करने वाली विधिविरुद्ध एवं तर्कविरुद्ध बाधाओं का अधिनियम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अनुमान लगाने की आवश्यकता है।

61. विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि 16-11-2006 को जारी अधिसूचना जिसमें एचएमएलसी तथा एएनवीसी नामक दो संगठनों पर प्रतिबंध लगाए जाने संबंधी प्रस्ताव किया गया था को रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री तथा दलों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अनुसमर्थित किए जाने की आवश्यकता है। इस बात पर बल दिया गया कि निर्णायक होने के बावजूद भी यह आशा नहीं की जाती कि अभिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पूर्ण रूपेण न्यायालय प्रक्रिया के समान ही हो। वकील ने यह कहने के लिए कि अभिकरण के पास धारा 9 के अध्याधीन अपनी क्रियाविधियों को विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है, धारा 5(5) का सहारा लिया। इसके विपरीत धारा 9 में यह उल्लेख है कि अभिकरण को वही प्रक्रिया अपनानी होगी जो न्यायालय को दावों की छानबीन के लिए अपनानी पड़ती है। वकील ने विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) नियमवली 1698 के नियम 3(1) में भी विश्वास जताया तथा उल्लेख किया कि अभिकरण भारतीय साक्ष्य अधिनियम से बाध्य नहीं है किन्तु इससे व्यावहारिक स्तर तक इसका अनुपालन करना अपेक्षित है।

62. यह तर्क दिया गया कि अभिकरण के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों का संक्षिप्त विवरण यह दर्शाता है कि दोनों संगठनों अर्थात् एचएमएलसी तथा एएनवीसी पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक था। वकील ने कहा कि निश्चित रूप से यह सत्य था कि एक समझौते के द्वारा दिनांक 27-3-2004 को केन्द्र सरकार, एएनवीसी तथा मेघालय राज्य सरकार द्वारा आपरेशनों को निलंबित कर दिया गया था। समझौते के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य जिसे निसंदेह विस्तृत कर दिया गया था वह यह था कि दल को निःशस्त्र कर दिया जाएगा तथा कांडरों गतिविधि को जबाबदेह बनाया जाए। वकील ने यह कहने के लिए कि एएनवीसी कांडर शस्त्रों के साथ अथवा वर्दी में नहीं घूमेंगे, समझौते की धारा 6 का उल्लेख किया। यह उल्लेख किया गया कि अभिकरण अर्थात् सीडब्ल्यू-10 से सीडब्ल्यू-16 के समक्ष गवाहों के बयान से यह स्पष्ट है कि मेघालय के विभिन्न जिलों में एएनवीसी कांडरों से संबंधित 16 घटनाएँ दर्ज की गई थीं, इनमें दोषी व्यक्ति, हत्या, लूट-पाट, फिरौती, अपहरण तथा शस्त्र अधिनियम से जुड़े अपराधों में शामिल पाए गए। अधिवक्ता ने दावा किया कि मई 2005 की अवधि के पश्चात् की प्राथमिकियाँ तथा विशेष रूप से संबंधित जिलों के पुलिस उप-अधीक्षकों के शपथपत्रों की प्रतियाँ सत्यापित प्रतियों की मूल प्रतियाँ थीं। वे प्रतियों की छायाप्रतियाँ थीं तथा इन दस्तावेजों की मूल प्रतियाँ भी उपलब्ध थीं किन्तु चूंकि मामलों की अभी जांच चल रही थी अतः इन्हें अभिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका। वकील ने दावा किया कि इन दस्तावेजों द्वारा उन गवाहों के बयानों जिनमें एएनवीसी के लिए वकील द्वारा पूर्ण रूप से पूछताछ की गई थी, से एकरूप निम्नलिखित बातें समाने आईं :

- (1) एएनवीसी के उन कांडरों की उनमुक्त गतिविधि जिन्होंने अपने सारे हथियारों का समर्पण नहीं किया था;

- (2) जबरन धन वसूली, फिरौती, अपहरण, अभिवास इत्यादि के माध्यम से एएनवीसी काडरों द्वारा आतंक का माहौल बनाना ।
- (3) आम जनता को निरंतर अभिवास्त करने संबंधी कार्य वकील ने सी डब्ल्यू-11 तथा सी डब्ल्यू-12 के बयानों का हवाला देते हुए कुछ विशेष घटनाओं पर प्रकाश डाला जिनमें "टोल वसूली" के रूप में हाट एवं बाजारों से धन एकत्रित किया गया था । अधिवक्ता ने तुरा में सूखी मछली की बिक्री पर 5 रु. प्रति किलो के हिसाब से लगाए जाने वाले अवैध कर का हवाला दिया जिसका उल्लेख सी डब्ल्यू-12 द्वारा किया गया था । इसी प्रकार वकील ने एएनवीसी द्वारा तुरा में दुकानदारों द्वारा नगरपालिका क्षेत्र के निवासियों को डीटीएच उपकरणों की बिक्री करने से रोकने संबंधी घटना का भी हवाला दिया ।
- (4) गवाहों के बयान से यह स्पष्ट है कि एएनवीसी काडर नोट जारी करके, अवैध मांगे करके तथा आम जनता को घटनाओं के संबंध में रिपोर्ट करने से रोककर तथा उन्हें राष्ट्रदिवस समारोहों में भाग लेने से रोककर खौफ का माहौल पैदा करके मुख्य रूप से व्यवसायी समुदाय को निशाना बनाते हैं ।
- (5) कानून के द्वारा प्रतिबंधित हथियारों को जप्त करना;
- (6) एएनवीसी काडरों द्वारा उल्फा, एनएससीएन (आईएम) तथा एनडीएफबी जैसे प्रतिबंधित समूहों एवं संगठनों से संपर्क बनाए रखने संबंधी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं । अधिवक्ता ने सी डब्ल्यू-10, सी डब्ल्यू-13 तथा सी डब्ल्यू-16 के बयानों का हवाला दिया ।
- (7) सरकार को गुमराह करने के लिए एएनवीसी की सूची समझी चाल तथा युद्धविराम के पश्चात् संयुक्त अनुवीक्षण दल की स्थापना/समझौते के अनुसार एएनवीसी काडरों की एक सूची मुहैया करवानी थी । तथापि, एएनवीसी ने अलग-अलग नामों वाली विभिन्न सूचियां मुहैया करवाई । इसने हथियारों को अभ्यर्पित करने तथा उन्हें संयुक्त अभिरक्षा में रखने संबंधी अपने उत्तरदायित्व को पूरा नहीं किया अपितु इन्हें तुरा स्थित अपने संपर्क कार्यालय में रखा ।

63. विद्वान अधिवक्ता ने यह उल्लेख किया कि हालांकि गतिविधियों के निलंबन संबंधी समझौते का उद्देश्य एएनवीसी के साथ बातचीत के लिए तैयार करना, आत्मविश्वास निर्माण उपायों को शुरू करना तथा इसे मुख्यधारा में शामिल करने योग्य बनाना था किंतु इसने गारोलैंड राज्य की प्राप्ति के लिए देश की क्षेत्रीय अखंडता को भंग करने के उद्देश्य से कार्य करना जारी रखा । अधिवक्ता ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीकों के माध्यम से गारोलैंड की प्राप्ति संबंधी एएनवीसी की प्रतिज्ञा का इसकी गतिविधियों ने मिथ्या साबित कर दिया । हथियार समर्पित करने संबंधी इसकी प्रतिज्ञा के विपरीत इसके काडरों

ने विभिन्न जिलों में निरंकुश रूप से अपनी गतिविधियों को जारी रखा जिसमें विशेषकर व्यवसायी समुदाय के लोगों को भयभीत करना तथा उनसे जबरन धन वसूल करना, छिपकर घूमना तथा बैठल फाइटिंग एवं गंभीर अपराधों को अंजाम देना भी शामिल है । अधिकारिक तौर पर दर्ज घटनाओं की संख्या वास्तविक रूप से घटित हुई घटनाओं से बहुत कम है क्योंकि लोगों में व्याप्त भय के कारण घटनाओं की पूरी रिपोर्ट नहीं दी जाती । विद्वान वकील ने दावा किया कि हर बार जब भी एएनवीसी काडरों से संबंधित कोई घटना होती है तो यह कहा जाता है कि संबंधित व्यक्ति या तो इसके सदस्य नहीं है अथवा ऐसे भगोड़े हैं जिनके ऊपर इसका कोई नियंत्रण नहीं है । परिणामस्वरूप यह जोर देकर कहा गया कि अभिकरण को धारा 4(3) के तहत प्रतिबंध की पुष्टि करनी चाहिए ।

64. विद्वान अधिवक्ता ने आगे दावा किया कि जहां तक एचएनएलसी की गतिविधियों के संबंध में अभिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों का संबंध है तो इनसे पता चलता है कि विगत प्रतिबंध अर्थात् मई 2005 से आज तक की अवधि के दौरान कम से कम 12 घटनाओं की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं । सी डब्ल्यू-1, सी डब्ल्यू-9 द्वारा इनका उल्लेख किया गया था । प्राथमिकी रिपोर्ट की प्रतियां भी रिकार्ड के तौर पर रखी गई हैं ।

64. विद्वान अधिवक्ता ने यह कहने के लिए कि एचएनएलसी काडर पुलिस तथा सशस्त्र बलों के लिए चुनौतियां पैदा करने सहित लूट, अपहरण, हत्या इत्यादि जैसे कार्यों में निरंतर संलग्न रहे, सी डब्ल्यू-2, सी डब्ल्यू-3 तथा सी डब्ल्यू-5 के बयानों पर भरोसा किया अधिवक्ता ने यह उल्लेख करने के लिए कि गोलीबारी की घटनाओं में एचएनएलसी काडरों की मृत्यु हुई, सी डब्ल्यू-6 के बयान पर भरोसा जताया । अधिवक्ता ने एचएनएलसी द्वारा फिरौती के लिए नोट जारी करने संबंधी अनेक घटनाओं का उल्लेख करने के लिए सी डब्ल्यू-3 के बयान का सहारा लिया । एचएनएलसी बैंक डकैती इत्यादि जैसे हिंसक अपराधों में भी शामिल रहा ।

65. विद्वान वकील ने दावा किया कि एचएनएलसी की गतिविधियों का मुख्य ध्येय भारत संघ से अलग होने संबंधी अपने उद्देश्य को पूरा करना तथा भारत की प्रभुसत्ता एवं अखंडता को चुनौती देना है । यह उल्लेख किया गया कि राज्य के लिए गवाही देने वाले गवाहों ने एचएनएलसी द्वारा गणतंत्र दिवस तथा स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय दिवसों पर बंद की घोषणा किए जाने तथा धमकियों के माध्यम से धन एकत्र करने के लिए व्यापारियों को लक्ष्य बनाए जाने की बात कही । यह कहने के लिए कि एचएनएलसी काडर 10 ए.के.-47 हथियारों जैसे अत्याधुनिक एवं प्रतिबंधित हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं जिसके लिए आधुनिकतम गोलाबारूद बरामद किया गया, गवाह अर्थात् सी डब्ल्यू-2 के बयान पर भी भरोसा जताया गया । इसी प्रकार अन्य गवाहों तथा सी डब्ल्यू-4 ने भी चाइना मेड पिस्तौल जैसे प्रतिबंधित हथियारों के विषय में बताया । अधिवक्ता ने दावा किया कि एचएनएलसी के एनएससीएन तथा एनडीएफबी जैसे प्रतिबंधित संगठनों के साथ भी संबंध थे । अधिवक्ता ने सी डब्ल्यू-1, सी डब्ल्यू-2 तथा सी डब्ल्यू-8 के बयानों पर भरोसा जताया । यह उल्लेख किया गया कि सीडब्ल्यू-8

के केएनवी (करवी नेशनल वालंटियर) तथा अन्य प्रतिबंधित संगठनों के विषय में भी बताया।

66. विद्वान वकील ने दावा किया कि भारत की प्रभुसत्ता एवं अखंडता को विघटित करने, भंग करने तथा उसे खतरा पैदा करने के अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एएनवीसी द्वारा की जा रही हिंसक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए तथा इस तथ्य के मद्देनजर कि सुनवाई के संबंध में व्यापक प्रचार के बावजूद न तो एएनएलसी अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत हुआ न ही इसने अपनी आपत्ति जताई और न ही रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री अधिकरण को मुहैया करवाई अतः अधिकरण द्वारा इसके समक्ष प्रस्तुत सामग्री एवं साक्ष्यों के आधार पर इस संगठन को प्रतिबंधित करने की सिफारिश करनी चाहिए।

67. भारत के अपर सोलिसिटर जनरल श्री पी. पी. मल्होत्रा द्वारा तथा भारत संघ के जाने माने अधिवक्ता श्री संजय कलयाल ने दावा किया कि दिनांक 16-11-2006 की अधिसूचना की पुष्टि की जानी चाहिए क्योंकि यह एएनवीसी तथा एएनएलसी के प्रस्तावों से संबंधित है। यह उल्लेख किया गया कि एएनवीसी कांडर अपने संगठन के लिए निधियां एकत्रित करने हेतु लूट, जबरन धन वसूली जैसे कार्यों में संलग्न है तथा यह जबरन धन वसूली जैसे अपने कार्यों को अंजाम देने के लिए अन्य विद्रोही समूहों से संपर्क बनाए हुए है तथा अपने कांडरों के प्रशिक्षण के लिए यह देश में तथा देश के बाहर स्थित समूहों से भी संबंध बनाए हुए है। अधिवक्ता ने दावा किया कि आसूचना अनुमान के अनुसार संगठन के पास कुल 150 हथियारों का जखीरा है जिसमें ए. के. शृंगला की 50 राष्ट्रिय तथा अन्य प्रतिबंधित हथियार शामिल हैं। वकील ने दावा किया कि एएनवीसी का मुख्यालय "चेरम" में स्थित है जो एक जाना माना स्थान तो नहीं है किन्तु छुपने का एक गुप्त अड्डा है। यह उल्लेख किया गया कि अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से पता चलता है कि हालांकि गवाहों ने लिखित संविधान का उल्लेख नहीं किया किन्तु इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि एएनवीसी के उद्देश्यों को परिभाषित करने वाला एक संविधान मौजूद है तथा उनके पास व्यक्तियों का एक ऐसा समूह या दस्ता है जिसमें व्यक्तियों को इस ढंग से पदवियां प्रदान की गई हैं जैसे कि किसी सशस्त्र बल में प्रदान की जाती हैं। यह उल्लेख किया गया कि अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत गवाहों ने एएनवीसी कांडरों द्वारा भेद्य बदलकर तथा युद्ध की वेशभूषा में घूमने की भी बात कही है। अधिवक्ता ने एएनवीसी द्वारा प्रकाशित कैलेण्डर तथा इसमें प्रयुक्त रंगों एवं भारत सरकार को प्रस्तुत ज्ञापन का इवाला दिया।

68. विद्वान वकील ने दावा किया कि राज्य के बयान के अलावा संघ द्वारा सी डब्ल्यू-17 के बयान के माध्यम से एएनवीसी की गतिविधियों का उल्लेख मिलता है जो न केवल गारा पहाड़ियों के तीन जिलों तक सीमित है अपितु पश्चिमी खासी पहाड़ियों में भी इसकी गतिविधियां चल रही हैं। अधिवक्ता ने उल्लेख किया कि सीडब्ल्यू-17 ने अपने बयान में यह भी कहा था कि एएनवीसी के प्रतिबंधित संगठनों के साथ संबंध थे तथा 2005-2006 में एएनवीसी कांडर कम से कम सात हिंसक घटनाओं में शामिल थे जिनमें से 2 में हनले करना शामिल था। वकील ने 28 जून, 2005 की एक घटना पर भरोसा जताया जिसमें सेकामुक्ता एएनवीसी कांडरों ने हैड ग्रिनेड के साथ

पुलिस पर हमला किया तथा मुठभेड़ में मारे गए। अधिवक्ता ने 4 नवम्बर, 2005 की घटना तथा 7-11-2005 की घटना पर भी भरोसा जताया जिसमें एएनवीसी कांडर मुठभेड़ में शामिल थे तथा जिसके परिणामस्वरूप दो कांडरों की मृत्यु हो गई। विद्वान वकील ने इसके अलावा 15 नवम्बर, 2005 की एक घटना पर विश्वास किया जब पुलिस ने नोनग्रोड ग्राम में एएनवीसी कांडरों को थकड़ा तथा उनसे प्रतिबंधित हथियार बरामद किए तथा इस मुठभेड़ में एएनवीसी कांडर मारे गए। अंत में 9 फरवरी, 2006 को डोबु पुलिस थाना विलियम्स नगर में हुई घटना संबंधी साक्ष्य पर भरोसा जताया गया जहां 30 लोगों ने कुष्ठ आम लोगों पर हमला किया तथा इसके परिणामस्वरूप उनमें से एक की मृत्यु हो गई, 7 लाख रु. लूट लिए गए एवं उस स्थल को अग्नि लगा दी गई।

69. विद्वान वकील ने आर डब्ल्यू-4 एएनवीसी के महासचिव से की गई पूछताछ में सामने आए साक्ष्य पर भरोसा जताया जिसमें एएनवीसी के महासचिव ने यह स्वीकार किया था कि संगठन को तस्करों से लाइट मशीनगनों सहित अन्य हथियार प्राप्त होते थे। यह उल्लेख किया गया कि यदि एएनवीसी की मंशा वैध राजनैतिक व्यवस्था में भाग लेने की है तो उसे अपने सभी सदस्यों का पूर्ण व्यौरा देने तथा अपने मुख्यालय अथवा अपने नेताओं के ठिकानों की सही स्थिति को बताने में कोई बाधा महसूस नहीं करनी चाहिए। इसके विपरीत इसकी मंशा संदेहास्पद है क्योंकि एएनवीसी ने हमेशा गलत सूचना दी - इसके कांडरों की सूची कभी सही नहीं थी तथा इनमें हमेशा भिन्नता पाई गई। अधिवक्ता ने यह भी दावा किया कि रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री से पता चलता है कि सभी हथियारों का पूर्ण व्यौरा कभी भी नहीं दिया गया अथवा उन्हें सांझी हिरासत में रखा गया किन्तु ये हथियार एएनवीसी के पास ही बने रहे तथा इसके कांडरों द्वारा ही इन हथियारों का उपयोग किया गया। एएनवीसी न तो अपने कांडरों का विवरण मुहैया करवा सका और न ही उन्हें नियंत्रित कर पाया जिससे इसकी भिरकुरा प्रकृति तथा अपनी विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के माध्यम से लोक अधिकरणों को गुमराह करने के इसके जानबूझकर किए गए प्रयास का भी पता चलता है। एएनवीसी का कैलेण्डर तथा इस पर छपी तस्वीरें एवं उसका संविधान जिसकी एक प्रति गवाह सी डब्ल्यू-17 द्वारा प्रस्तुत की गई थी तथा इससे सैन्य संगठन की एक प्रति जो सी डब्ल्यू-12 द्वारा प्रस्तुत की गई थी से तथा जैसा कि सी डब्ल्यू-12/3 द्वारा उल्लेख किया गया है, से पता चलता है कि एएनवीसी ने एक समान्तर प्रशासनिक एवं सैन्य ढांचा खड़ा कर रखा है जो शांतिपूर्ण तरीकों से गारोलैंड की प्राप्ति संबंधी इसके प्राथमिक उद्देश्य के अनुरूप नहीं हो सकता।

70. विद्वान वकील ने दावा किया कि यदि एएनवीसी की इच्छा विधि सम्पन्न तरीकों से गारोलैंड अथवा राज्य का दर्जा प्राप्त करने की है तो सैन्य अवस्थापना जैसे ढांचे की कोई आवश्यकता ही नहीं है जिसमें कांडर-इन-चीफ कहे जाने वाले नेता तथा सैन्य उपाधियों के समान उपाधियों वाले विभिन्न कार्मिकों को नामोदिष्ट किया गया हो। उसके अलावा उनसे हथियार भी बरामद हुए हैं जो इसकी शांतिपूर्ण तरीकों को अपनाने संबंधी मंशा को मिथ्या साबित करता है।

71. विद्वान वकील ने जोर देकर कहा कि संयुक्त अनुवीक्षण दल की बैठकों में इसके अटूट विश्वास तथा अपने काइरों के दुराचार संबंधी किसी भी सामग्री के तथाकथित रहस्योद्घाटन न करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि प्राथमिकी तथा अन्य दस्तावेज सार्वजनिक रिकार्ड के मामले हैं। इसके अलावा, यह एक तथ्य है कि निलंबन प्रस्ताव पर विचार किया गया था तथापि संगठन को पूर्व में ही विधिविरुद्ध घोषित किया जा चुका है। अतः वह सामग्री जिस पर इस अधिकरण द्वारा विचार किया जाना है, मई, 2005 के बाद की है। इससे एनवीसी काइरों के विषय में विरोधाभासी बातों इसके झूठे वायदों (यह भरोसा दिलाना कि काइरों को शिविरों में रखा गया है) तथा हथियारों को अस्थपित करने में इससे होने वाली लगातार चूक जिन्हें इसने अपने सम्पर्क कार्यालय में अपने नियंत्राधीन रखा हुआ है, का पता चलता है। कोई भी प्रजातांत्रिक संस्था अथवा संगठन जो वैध अथवा विधि सम्मत राजनैतिक व्यवस्था में भाग लेना चाहती है, के गुप्त एवं निरंतर बदलते मुख्यालय, गुप्त बैठकें नहीं हो सकतीं तथा वह अपने नेताओं के विषय में भी अनभिज्ञ नहीं हो सकता। गवाह द्वारा किए गए उल्लेख से स्पष्ट पता चलता है कि एनवीसी के पास न केवल प्रचुर मात्रा में हथियार हैं अपितु विपुल धन भी एकत्रित कर लिया है फिर भी कोई बैंक खाते नहीं खोले गए और न ही यह एक पंजीकृत संगठन था। इन अकादमिक सामग्रियों के प्रकाश में अधिकरण द्वारा एकमात्र निष्कर्ष यही निकाला जा सकता है कि हालांकि एनवीसी यह दावा करती है कि उसका गठन शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए किया गया है किन्तु वास्तव में यह संयुक्त-सशस्त्र विद्रोह तथा हथियारों के प्रयोग द्वारा अंग्लो-इंडी की प्राप्ति संबंधी अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है। अतः यह भारत की क्षेत्रीय अखंडता के लिए एक प्रत्यक्ष खतरा है।

72. विद्वान वकील ने कहा कि जमाएते इस्लामिया हिन्दू बनाम भारत संघ 1995 (1) एससीसी के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में यह घोषणा की गई थी कि अधिकरण को एक निष्पक्ष प्रक्रिया अपनानी होगी जिसका अर्थ है कि प्राकृतिक न्याय की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो। यह दावा किया गया कि न्यायालय के अनुसार ऐसे मामले जो अधिकरण के निर्णयधीन हैं में सामग्री विधिक समझौते तक ही सीमित नहीं होती इसलिए मुकदमों की छानबीन नहीं की जाती। अतः अधिकरण को अपने समक्ष प्रस्तुत सामग्री की विश्वसनीयता का स्वमूल्यांकन करके फिदावास्पद मुद्दों के संबंध में अपनी राय देनी है चाहे कभी-कभी ऐसी सामग्री के बारे में संगठन को भी न बताया गया हो। इस परिप्रेक्ष्य में अधिकरण ने उल्लेख किया कि हालांकि अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत सक्षम शपथ लेकर शपथ पत्रों के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं किन्तु फिर भी कार्रवाई के लिए प्राथमिकी की प्रतियां ही पर्याप्त हैं। अधिकरण ने 9 मई 2007 को नियम 3 (1) के तहत गुप्त रूप से अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत आसूचना रिपोर्ट पर भी भरोसा जताया।

73. वकील ने मेघालय राज्य सरकार की ओर से दिए गए बयान का समर्थन किया तथा कहा कि अधिनियम के प्रावधानों को उसके नैसर्गिक एवं साधारण अर्थों में समझा जाना चाहिए जिससे कि "प्रभुसत्ता" एवं "अखंडता" जैसी अभिव्यक्तियों को वृहद् आयाम प्रदान किया जा सके।

74. जहां तक एचएनएलसी पर प्रतिबंध का संबंध था वकील ने मेघालय राज्य सरकार की ओर से दिए गए बयान का समर्थन किया तथा इसे स्वीकार किया। यह दावा किया गया कि इसके अलावा सी डब्ल्यू-17 के बयान से यह स्पष्ट है कि एचएनएलसी के शीर्ष नेता बंगलादेश में रहते हैं तथा वे प्रशिक्षण शिविरों सहित अन्य शिविरों को भी नियंत्रित करते हैं। एचएनएलसी व्यवसायियों तथा आम जनता से जबरन धन वसूल करती है। उसने उल्लेख किया कि साक्ष्य के अनुसार एचएनएलसी लोगों को डराती है तथा उन्हें शिलांग नगरपालिका बोर्ड चुनावों के लिए नामांकन पत्र भरने से रोककर चुनावों में भाग लेने से रोकती है तथा अलगाववादी बयान जारी करती है जैसा कि 25-5-2006 को किया गया जिससे पता चलता है कि जब तक सरकार तथा पुलिस इसके सदस्यों को गिरफ्तार करना जारी रखेगी तब तक सशस्त्र विद्रोह को समाप्त करने का इनका कोई इरादा नहीं है। अधिवक्ता ने अनुलग्नक पर यथाचिन्हित एवं सी डब्ल्यू-17/1 द्वारा बताए गए एचएनएलसी के पदाधिकारियों के नामों पर भरोसा किया। यह उल्लेख किया गया कि एचएनएलसी के अन्य प्रतिबंधित संगठनों के साथ भी संबंध है तथा इसने भारत से मेघालय के पृथक्करण संबंधी अपने उद्देश्य की खुले तौर पर घोषणा कर दी है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह हिंसा एवं शस्त्रों का उपयोग कर रहा है।

एनवीसी की ओर से स्वीकारोक्ति

75. एनवीसी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अमित कुमार ने पहले यह उल्लेख किया कि अधिनियम का कड़ाई से प्रवर्तन किया जाना चाहिए क्योंकि यह गंभीर प्रकृति के उन अपराधों से जुड़ा है जिनके बारे में ऐसा माना जाता है कि इन्हें सामान्य या असाधारण आपराधिक कानून के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अधिवक्ता ने उल्लेख किया कि जहां तक अधिनियम के द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने तथा संबंधित अपराधों के होने का संबंध है, अधिनियम में प्रयुक्त अभिव्यक्तियों के अर्थ को निहितार्थों के माध्यम से व्यापक नहीं बनाया जाना चाहिए और न ही इन्हें इसके अर्थों के तहत सामान्य तौर पर शामिल नहीं हो सकने वाली स्थितियों को शामिल करने के लिए भी इसे विस्तृत रूप प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। यह उल्लेख करने के लिए कि जबरन धन वसूली तथा इसी प्रकार की अन्य अवैध गतिविधियों जिनसे शस्त्र अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता जैसे सामान्य अधिनियमों के तहत निपटा जा सकता है, को शामिल किए जाने के लिए अधिनियम का विस्तार नहीं किया जा सकता, अधिवक्ता ने निरंजन सिंह, कर्म सिंह पंजाबी, बनाम महाराष्ट्र राज्य सरकार, 1990 (4) एससीसी 76 तथा विजय कुमार अग्रवाल बनाम उड़ीसा राज्य (1996) 5 एससीसी 1 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर विश्वास किया। यह भी जोर देकर कहा गया कि अधिनियम को कानून एवं व्यवस्था से जुड़ी सामान्य समस्याओं के उपचार स्वरूप भी प्रयोग में नहीं लाया जा सकता।

76. इसके पश्चात् यह तर्क दिया गया कि स्वीकृत योजना अर्थात् धारा 3(1) के आलोक में दिनांक 16-11-2006 की अधिसूचना, जहां तक इसका उद्देश्य एनवीसी पर प्रतिबंध लगाना है का

कोई विधिक प्रभाव नहीं है तथा इसे लागू नहीं किया जा सकता। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि केन्द्र सरकार का मत यह होना चाहिए कि एक संगठन विधिविरुद्ध संगम है अथवा विधिविरुद्ध संगम बन गया है। धारा 2(पी) के तहत विधिविरुद्ध संगम का अर्थ है एक ऐसा संगठन जिसने अपने उद्देश्य के लिए कोई विधिविरुद्ध गतिविधि की है अथवा जिसने अपने उद्देश्य के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए अथवा 153-बी के तहत कोई दण्डनीय कार्य किया है। धारा 2(ओ) के तहत विधिविरुद्ध क्रियाकलापों का परिभाषा दी गई है। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि राज्य एवं भारत संघ की ओर से दिए गए तर्कों के अधिप्राय से यह स्पष्ट है कि एएनवीसी को विधिविरुद्ध घोषित करने के उद्देश्य से धारा 2(ओ) (ii) तथा (iii) का सहारा लेना पड़ा। उन्होंने तर्क दिया कि अधिसूचना में कहीं भी यह नहीं कहा गया था कि एएनवीसी की गतिविधियाँ भारत की प्रभुसत्ता एवं क्षेत्रीय अखंडता को भंग करती हैं अथवा समाज के विभिन्न वर्गों के बीच घृणा की भावना पैदा करती हैं। ऐसी परिस्थितियों में, एएनवीसी की तथाकथित विधिविरुद्ध गतिविधियों के संबंध में मूलपाठ विषयक प्रकटीकरण अथवा मत निर्माण की अनुपस्थिति में प्रस्तावित प्रतिबंध की पुष्टि नहीं की जा सकती।

77. विद्वान वकील ने तर्क दिया कि केन्द्रीय या राज्य सरकार, अधिसूचना में दी गई दोषपूर्ण राय के समर्थन में किसी नये या अतिरिक्त आधार पर निर्भर नहीं रह सकती। यह कहा गया कि एएनवीसी की विधिविरुद्ध गतिविधियों के बारे में व्यक्त मत का आधार तथा यह निष्कर्ष निकाला जाना कि यह "हानिकर" है सरकार को इस बात के लिए बाध्य कर है कि इसके बाद से वह नयी सामग्री या हलफनामे प्रस्तुत करके अपने मत को नहीं बदल सकती। उन्होंने इस कथन का हवाला दिया कि एक सांविधिक आदेश पर न्याय-निर्णय उसमें किए गए उल्लेख के आधार पर ही किया जाना चाहिए तथा इसे और हलफनामों तथा दलीलों के माध्यम से स्पष्ट नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने मोहिन्द्र सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त, 1978 (1) एससीसी 405 में दिए गए निर्णय का हवाला दिया। विद्वान वकील ने आगे यह भी कहा कि अधिनियम का इस्तेमाल एक निवारक नजरबंदी विधायन के रूप में नहीं किया जा सकता है। यह अधिसूचना में उल्लिखित निम्नलिखित कथन के संदर्भ में था—

"अगर इन गतिविधियों को तत्काल रोका एवं नियंत्रित नहीं किया गया तो एएनवीसी अपने को पुनः एकजुट तथा अस्त्र-शस्त्र से लैस करेगी, अपने काहर को बढ़ाएगी, अत्याधुनिक हथियारों की खरीद करेगी, नागरिकों एवं सुरक्षा बलों के जान-माल को काफी नुकसान पहुंचावेगी तथा अपनी राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में तेजी लाएगी।"

यह कहा गया कि इस कथन से स्पष्ट होता है कि केन्द्रीय सरकार के अनुसार वास्तविक रूप में कोई विधिविरुद्ध गतिविधियाँ नहीं थीं परन्तु इस अधिनियम का इस्तेमाल एक निवारक उपाय के रूप में करने के लिए ऐसा दृष्टिकोण अपनाया गया है। उन्होंने इसके लिए मद्रास राज्य बनाम बी. जी. रो. एआईआर 1952 एससी 196 तथा जमात-ए-इस्लामी हिंद बनाम भारत संघ, 1995 (1) एससीसी 428

में की गई टिप्पणियों को आधार बनाया। उन्होंने मो. जफर बनाम भारत संघ, 1994 (अनुपूरक 2) एससीसी 1 को भी आधार बनाया गया तथा कहा कि सरकार, संगम या संगठन को विधिविरुद्ध गतिविधियों में संलिप्त होने के बारे में धारणा कायम करने के लिए पुरानी सामग्री पर निर्भर नहीं कर सकती।

78. इसके बाद विद्वान वकील ने अधिसूचना को आधार बनाया तथा उल्लेख किया कि इसे पूरा पढ़ने पर तथा पूर्व में किए गए उल्लेख के आलोक में, अधिकरण को यह निष्कर्ष देना होगा कि केन्द्रीय सरकार के अनुसार भी एएनवीसी का उद्देश्य बातचीत करना और अंततोगत्वा राजनीतिक मुख्यधारा में शामिल होने के लिए हिंसा का त्याग कर एक शांतिपूर्ण वार्ता करना था। उन्होंने अधिसूचना में किए गए वर्णन को आधार बनाया कि एएनवीसी हिंसा को त्यागने हेतु सहमत हो गया था। यह भी कहा गया कि केन्द्रीय सरकार द्वारा एएनवीसी को एएनएलसी के साथ जोड़ा जाना तथ्यों के बारे में बुद्धि का प्रयोग न किए जाने को दर्शाता है। बाद के संगम ने खुलआम और स्पष्ट रूप से भारत के भू-भाग से अलग होना चाहा है। यह कहा गया कि इस तरीके से जोड़े जाने से एएनवीसी को नुकसान पहुंचा है क्योंकि बासी एवं पुराने कार्यों के आधार पर यह धारणा बना ली गई है।

79. इसके बाद विद्वान वकील ने यह तर्क दिया कि सीडब्ल्यू-1 तथा सीडब्ल्यू-17 के हलफनामे तथा साक्ष्य रिकार्ड आधारित हैं न कि व्यक्तिगत जानकारी पर। इन दस्तावेजों के रचयिता या जिन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई उन्हें बतौर गवाह पेश नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त मूल दस्तावेज विचार के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए। यह कहा गया कि ये सभी सरकारी मामले के लिए घातक सिद्ध हुए क्योंकि कथित गतिविधियों के बारे में प्राथमिक साक्ष्य अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए। उन्होंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 64 तथा 65 और जे. यशोधा बनाम श्रीमती के. शोभा रानी, 2007 (6) एससीएलई 6 में दिए गए निर्णय का भी हवाला दिया। जांच में प्रस्तुत सामग्री सुने सुनाए साक्ष्य हैं क्योंकि इसमें स्रोत का खुलासा नहीं किया गया है तथा यह कोई विधिक सामग्री नहीं है जिसे प्रतिबंध की संस्तुति के प्रयोजन से इस्तेमाल किया जा सके या आधार बनाया जा सके। यह कहा गया कि नियम 3(1) में यह अधिदेश दिया गया है कि अधिकरण को जहां तक संभव हो सके भारतीय साक्ष्य अधिनियम का अनुसरण करना चाहिए और इससे अलग तभी हुआ जाए जब वह लोकहित में आवश्यक हो। यह कहा गया कि दावों की सत्यता जांचने के लिए (जिसकी जिम्मेवारी मुख्यतः सरकार पर है कि वह विधिसम्मत साक्ष्यों के माध्यम से एएनवीसी द्वारा विधिविरुद्ध गतिविधियों में संलिप्त होना सिद्ध करे) अधिकरण में या कैमरा कार्यवाहियों में पीड़ितों की या दस्तावेजों के रचयिताओं की राय या प्रथम सूचना रिपोर्टें प्रस्तुत नहीं की गईं और न ही उन्हें आधार बनाया गया। अतः अधिकरण को चाहिए कि वह प्रतिबंध की पुष्टि करने की बजाय अधिसूचना को रद्द करे।

80. विद्वान वकील ने एएनवीसी की ओर से अर्थात् आरडब्ल्यू-1 में दिए गए साक्ष्य को आधार बनाया तथा कहा कि एएनवीसी विधि

विरुद्ध या हिंसक गतिविधियों में शामिल नहीं है और न ही इसने किसी को धमकी दी है या धन मांगा है। यह कहा गया कि गवाह, जिसके एएनवीसी के साथ कोई संबंध नहीं थे, ने कहा है कि गारो लोगों को विकास में यथोचित रूप से हिस्सा नहीं दिया गया है। यह गवाह एएनवीसी से किसी भी प्रकार से संबद्ध नहीं था। इसी प्रकार से आरडब्ल्यू-2, कामगार संघ के नेता द्वारा दी गई गवाही के साथ-साथ आरडब्ल्यू-3, छात्रागरी संघ, जिसमें 50% गैर-जनजातीय लोग शामिल हैं, के अध्यक्ष द्वारा दी गई गवाही को आधार बनाया गया।

81. विद्वान वकील ने यह भी कहा कि आरडब्ल्यू-4, महासचिव ने अपनी गवाही में यह विशेष रूप से स्पष्ट किया था कि एएनवीसी शांतिपूर्ण माध्यमों से राज्य के दर्जे की मांग करती है और वह जबरन धन कसौली या बैंड-कानूनी गतिविधियों में शामिल नहीं है। यह कहा गया कि गवाह यह तथ्य प्रकाश में लाया है कि जुलाई, 2007 तक सरकार तथा केन्द्रीय बलों ने युद्धविराम समझौते के मद्देनजर अपनी गतिविधियां रोक रखी थीं। विद्वान वकील ने जिरह के दौरान गवाह के बयान के भाग को आधार बनाया और कहा कि हथियार रखे जाने का तर्क खारिज हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि एएनवीसी द्वारा राजनीतिक मुख्यधारा में शामिल होने की मंशा को उसके द्वारा 1999 में प्रधानमंत्री को दिए गए एक जापान से समझा जाना चाहिए। उन्होंने यह कहने के लिए आरडब्ल्यू-5 की गवाही को भी आधार बनाया कि इस गवाह ने स्पष्ट रूप से दर्शाया है कि किसी प्रकार से गारो लोगों को वंचित किया गया और उन्होंने अपनी उपेक्षा महसूस की। इन परिस्थितियों में, एएनवीसी ने अपनी मांग उठाई और भारत के संविधान के दायरे में एक अलग गारोलैंड की अवधारणा को सामने रखा।

82. आगे विद्वान वकील ने कहा कि हालांकि राज्य तथा केन्द्रीय सरकार ने सरकारी गवाहों को आधार बनाया है तथा कुछ एक दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत की हैं फिर भी इन गवाहों की गवाही विश्वसनीय नहीं है क्योंकि उन्हें तथाकथित घटनाओं की कोई प्राथमिक जानकारी नहीं है। वकील ने कहा कि संयुक्त निगरानी दल की बैठकों के कार्यवृत्त संबंधी सामग्री के बारे में गवाहों से सवाल-जवाब करने पर उन्होंने स्वीकार किया कि हथियार लौटा दिए गए थे और एएनवीसी काडर तीन नामोहिष्ट शिविरों में रहते थे। वस्तुतः अगर राज्य तथा केन्द्रीय प्राधिकार ने यह महसूस किया कि एएनवीसी या इसके काडर विध्वंसक या विधिविरुद्ध गतिविधियों में संलिप्त हैं तब उन्हें बैठक के ऐसे कार्यवृत्तों में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख या रिकार्ड किया जाना चाहिए था। ऐसे किसी भी उल्लेख के अभाव में यह एक अकादमिक निष्कर्ष है कि युद्धविराम समझौते तथा इसकी शर्तों को सभी पक्षकारों ने आपसी संतुष्टि से स्वीकार किया था तथा उसका अनुसरण किया था। यह निष्कर्ष एएनवीसी के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण है क्योंकि संघ सरकार के साथ इसकी विधिक रूप से स्वीकार्य साक्ष्य के माध्यम से इसकी विधिक प्रकृति को दर्शाने में असफल रहा है कि युद्धविराम समझौते की अपनी प्रतिबद्धता से पीछे हटा है।

83. वकील ने कहा कि जिन कथित वस्तुओं के बारे में कहा गया है, इसके समर्थन में कोई अन्य सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई तथा गवाहों के द्वारा उल्लिखित हिंसक घटनाएँ पुरानी हैं और ज्यादा से

ज्यादा 20 जुलाई, 2004 से पूर्व की हैं। विद्वान वकील ने कहा कि किसी भी तरीके से कुछ एक ऐसी घटनाओं को इसके द्वारा प्राधिकृत नहीं माना जा सकता जिनमें एएनवीसी को छोड़ने वाले लोग या इसके शिविरों से बेदखल किए गए काडर सम्मिलित थे। ऐसे व्यक्तिगत कृत्य, समझौते के उद्देश्य और भावना के विपरीत हैं और यह उन्होंने अपनी इच्छा से किया, जिसके लिए, एएनवीसी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। वकील ने आगे यह भी कहा कि तथाकथित भयपूर्ण माहौल तथा खतरा बिलकुल ही आधारहीन है। अधिनियम के अर्थों के तहत एएनवीसी या इसके काडरों द्वारा विधिविरुद्ध गतिविधियों में शामिल होने संबंधी दावे के समर्थन में एक भी गवाह की स्वतंत्र गवाही प्रस्तुत करने से किसी ने भी राज्य या केन्द्रीय प्राधिकारियों को नहीं रोका था।

विधिक मामलों का विश्लेषण

84. इससे पहले की अधिकरण अधिसूचना के सही होने पर विचार करे और अधिसूचना की पुष्टि करने या उसे निरस्त करने के रूप में अपने निष्कर्ष दे, विचार हेतु निम्नलिखित विधिक प्रश्न उठते हैं:

- (1) अधिकरण के सामने कार्यवाही की प्रकृति तथा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया;
- (2) क्या साक्ष्य के सख्त नियमों का पालन किया गया;
- (3) क्या अधिसूचना को शब्दशः लागू नहीं किया जा सकता।

मुद्दा संख्या 1 के संदर्भ में :

85. उच्चतम न्यायालय ने जमात-ए-इस्लामी हिंद बनाम भारत संघ 1995(1) एससीसी 428 में इस अधिनियम की रूपरेखा, इसके उद्देश्यों तथा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का विस्तार से उल्लेख किया है। न्यायालय ने यह महसूस किया कि निवारक नजरबंदी के मामले में तथ्यों की जांच या "न्याय-निर्णयन" की प्रक्रिया, आकलन से अलग है; संगम की स्वतंत्रता के अधिकार को काफी महत्व दिया जाना तथा इस बात पर बल देना कि न्याय-निर्णय हेतु उच्च न्यायालय के किसी पीठासीन न्यायाधीश की तैनाती हो, यह इंगित करते हैं कि मूल अधिकारों के प्राधिकृत उल्लंघनों के लिए केवल ये ही शर्तें थीं। न्यायालय ने कहा कि अधिकरण को अपने कार्य करते समय ऐसी प्रक्रिया को अपनाना होगा जिससे विपरीत दावों की सत्यता एवं विश्वसनीयता की जांच हो सके। न्यायालय की टिप्पणी निम्नलिखित थी :

"किया गया न्यायनिर्णय एक यथार्थ निर्णय नहीं रहेगा तथा यह निरर्थक हो जाएगा तथा इससे इसे केन्द्र सरकार के बयान को स्वीकार किए जाने की प्रक्रिया मात्र माना जाएगा। अधिनियम के अंतर्गत परिकल्पित अधिकरण द्वारा न्यायनिर्णय किए जाने की आवश्यकता से अधिकरण को, केन्द्र सरकार की राय पर मात्र अपने अनुमोदन की मुहर लगाते हुए अपने कार्य केन्द्र सरकार को सौंपने की अनुमति नहीं मिल जाती है। अतः अधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिससे अधिकरण किसी विवादित मुद्दे से संबंधित सामग्री की

विश्वसनीयता का स्वयं का आकलन कर सके तथा एक ऐसी प्रक्रिया विकसित कर सके जिसके द्वारा अधिकरण यह निर्णय ले सके कि क्या केन्द्र सरकार के बयान को स्वीकार किया जाए अथवा एसोसिएशन द्वारा व्यक्त किए गए विरोधी विचार के आलोक में इसे नार्मल कर दिया जाए”

बाद में न्यायालय ने एक तरफ निष्पक्षता (तथा पारदर्शिता) तथा दूसरी तरफ गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए लोकहित के मद्देनजर अधिनियम के तहत अधिकरण द्वारा किए जाने वाले तथ्यों के संग्रहण तथा विश्लेषण की प्रक्रिया पर विचार-विमर्श किया।

86. धारा 4(3) अधिकरण को प्रतिबंध की पुष्टि करने या उसे रद्द करने के बारे में “निर्णय” लेने का अधिकार प्रदान करती है। स्पष्टतया यह संबंधित संगमों को यह कारण बताओ नोटिस जारी करने के पश्चात् ही होगा कि क्यों न संगम को विधिविरुद्ध घोषित किया जाए। 12-02-07 तक उत्तर वापस मिल जाने वाले नोटिस जारी किए गए; उन्हें केन्द्रीय सरकार की जानकारी में उनके पतों पर भेजा गया तथा उस क्षेत्र में अधिक पढ़े जाने वाले समाचार पत्रों में अंग्रेजी के साथ-साथ गारो तथा खासी भाषाओं में प्रकाशित कराया गया। इसके अतिरिक्त, ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से सूचना भी प्रसारित की गई। नोटिस के अनुसरण में एएनवीसी प्रस्तुत हुआ और अधिसूचना की वैधता को चुनौती दी। एचएनएलसी ने प्रक्रिया से दूर रहना स्वीकार किया हालांकि उसे भी एएनवीसी की तरह नोटिस दिया गया था।

87. उच्चतम न्यायालय के अनुसार “निर्णय” निर्माण प्रक्रिया भी न्याय-निर्णय ही होता है। इस अधिनियम में कुछ प्रावधान हैं जिनमें यह उपबंध है कि न्याय-निर्णय प्रक्रिया का सार क्या होना चाहिए। धारा 9 में असंदिग्ध रूप से आवेदनों के निपटारे संबंधी प्रक्रिया की रूपरेखा उल्लिखित है, परन्तु इसमें महत्वपूर्ण रूप से अन्य बातों के साथ-साथ यह भी अधिनियमित है कि:

“धारा 4 की उप-धारा (3) के तहत जांच हेतु अधिकरण द्वारा अथवा धारा 7 की उप-धारा (4) या धारा 8 की उप-धारा (8) के तहत किसी जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा किसी आवेदन के निपटान में अपनायी जाने वाले प्रक्रिया यथासंभव वही होगी जो दावों की जांच के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में निर्धारित है तथा अधिकरण या जिला न्यायाधीश के न्यायालय जैसा भी मामला हो, का निर्णय अंतिम होगा।”

(जोर दिया गया)

धारा 2(ग) के द्वारा “संहिता” को “दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)” के रूप में परिभाषित किया गया है। धारा 9 प्रक्रिया से संबंधित है, जो कि नियमों के अध्वधीन है। 1968 में बने नियमों के नियम 3(1) में प्रावधान है कि “जहां तक व्यवहारिक हो” भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का अनुसरण किया जाएगा। उदाहरण स्वरूप, संहिता की धारा 202 के तहत जांच एक “विचारण” नहीं है। यह स्थिति न्यायालय द्वारा अभियोजन या शिकायतकर्ता के साक्ष्य पर विचार किए जाने तथा सम्मन जारी किए जाने के पश्चात्

ही उत्पन्न होती है। हालांकि अभियुक्त कार्यवाही के प्रारंभ की संकल्पना है लेकिन ऐसा वह जमाना के सदस्य के माते को कहा जाता है न कि एक अभियुक्त के रूप में। (संदर्भ चाडीलाल पंचाल बनाम बराबरी बुलाजी घडीगांवकर (एआईआर 1960 एससी 1113 : 1960 सीआरआई एलजे 1499) चन्द्र देव सिंह बनाम प्रकाश चन्द्र बंस (एआईआर 1963 एससी 1430 : 1963 (2) सीआरआई एलजे 397)। एच.एस. खन्ना बनाम मुख्य सचिव, पटना एआईआर 1963 एससी 595; जरनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य 2003 (109) सीआरआई एलजे 2307 (एससी)। अतः विचारण की प्रकृति में कार्यवाही की प्रकृति नहीं है और यहां तक कि न्यायालय भी इसी बात की व्याख्या नहीं करता है कि क्या शिकायतकर्ता का मामला प्रथमदृष्टया सम्मन जारी करने का बनता है। (संदर्भ केवल कृष्ण बनाम सूरजभान 1980 (86) सीआर एलजे 1271 (एससी)।

88. उपर्युक्त विश्लेषण का निवल निष्कर्ष यह है कि धारा 4(2) के तहत अधिकरण की भूमिका न्याय निर्णयक की है; यह उनके कार्य को उन सलाहकारी निकायों के कार्य से बिल्कुल अलग करती है जो निवारक नजरबंदी कानूनों के तहत गठित किए गए हैं। न्याय निर्णायक की भूमिका में आवश्यक रूप से साक्ष्यों, सामग्रियों तथा निर्णय निर्माण प्रक्रिया की गहराई में व्यापक रूप से जाना शामिल है जिससे इस धारणा का निर्धारण किया जा सके कि क्या किसी संगम को विधिविरुद्ध घोषित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जमात में दिए गए निर्णय में इस बात पर बल दिया गया है कि अधिकरण की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए और तर्कसंगत भी क्योंकि इसके कार्य में एक सीमित अवधि के लिए ही सही किसी संगम के मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाने की संभावना शामिल होती है। तथापि यह न्याय निर्णायक प्रक्रिया विचारण नहीं है; इसकी प्रक्रिया जांच की तरह होनी चाहिए जिसका लक्ष्य निष्कर्ष निर्धारण के लिए सामग्रियों का संग्रहण है। इसी प्रकार से, यह बलपूर्वक स्वीकार्य नहीं है कि अधिनियम के प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि अधिनियम में दंड दिया जाना शामिल नहीं है अगर ऐसा होता तो विचारण की प्रक्रिया, प्रकृति तथा मानक बैसे ही होते जैसे किसी आपराधिक मामले के विचारण में होते हैं।

मुद्दा सं. 2 के संदर्भ में :

89. उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए जमात के निर्णय में भी इस प्रश्न पर विचार किया गया है। न्यायालय ने धारा 4, 9 तथा नियमों पर विचार करने के बाद निर्णय दिया था कि :

“22. यह स्पष्ट है कि किसी संग की विधिविरुद्ध गतिविधियां कभी-कभी गुप्त रूप में हो सकती हैं तथा इसलिए लोकहित में विधिविरुद्ध गतिविधियों के साक्ष्यों के स्रोतों की निरन्तर गोपनीयता बनाए रखना जाना आवश्यक हो सकता है। ऐसी स्थिति में ऐसी सूचना के स्रोत का तथा कभी-कभी उस सूचना के सम्पूर्ण विवरण का खुलासा करना लोकहित में होगा। अधिनियम की रूपरेखा तथा उसके तहत निर्धारित नियमों के अनुसार जब कभी भी लोकहित में आवश्यक हो जांच की

प्रक्रिया में भोपनीयता बनाए रखने का प्रावधान किया गया है। तथापि संवेदनशील सूचना तथा साक्ष्यों का संगम तथा उसके पदाधिकारियों के समक्ष खुलासा न करने का अर्थ यह नहीं है कि इसका खुलासा अधिकरण के समक्ष न किया जाए। ऐसे मामलों में जिनमें अधिकरण संतुष्ट हो कि ऐसी सूचना का संगम या इसके पदाधिकारियों के समक्ष खुलासा न करना लोकहित में है तो वह संगम या इसके पदाधिकारियों के समक्ष इसका खुलासा न करने की अनुमति दे सकता है लेकिन न्याय निर्णय के अपने कार्य, जैसा कि अधिनियम में कहा गया है कि को पूरा करने के लिए सूचना की विश्वसनीयता के आकलन के उद्देश्य से इसे देख सकता है और इस बात से संतुष्ट हो सकता है कि वह उस पर सावधानीपूर्वक कार्य कर सकता है। ऐसी किसी परिस्थिति में अधिकरण एक उचित प्रक्रिया विकसित कर सकता है जिसमें वह संगम को विधि विरुद्ध घोषित करने के लिए पर्याप्त कारणों के रूप में ऐसी सामग्री को स्वीकार करने से पूर्व स्वयं उसकी जांच, परीक्षण तथा विश्वनीयता परख सके। सही अर्थों में ऐसी सामग्री केवल विधिक साक्ष्य तक ही सीमित नहीं है। ऐसी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करेगी कि अधिकरण का निर्णय केवल केन्द्रीय सरकार के तथ्यों पर ही कार्य न करते हुए अपने कार्यकरण का परित्याग किए बिना ऐसी सामग्रियों जिसे उसने स्वीकार किया है कि विश्वसनीयता का आकलन करने के पश्चात् विवादास्पद मुद्दों के संबंध में किया गया न्याय निर्णय है। ऐसी प्रक्रिया से संगम तथा इसके सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करते हुए तथा लोकहित को खतरे में डाले बिना प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में प्राकृतिक न्याय की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि न्याय निर्णय की प्रक्रिया अपने सही अर्थ से विलग न हो तथा अधिकरण का अंततः दिया गया निर्णय उसके द्वारा न्याय निर्णय विवाद में शामिल सभी मुद्दों पर गौर करने के पश्चात् दिया गया है और यह केन्द्रीय सरकार द्वारा पहले से ही बनाई गई धारणा की स्वीकारोक्ति मात्र नहीं है।" (जोर दिया गया)

धारा 5(5) में अधिकरण को अपनी प्रक्रिया को नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान किया गया है; धारा 5(6) उसे गवाहों को सम्मन जारी करने तथा उनकी उपस्थिति, साक्ष्यों को पता लगाने और प्रस्तुत करने, हलफनामों के माध्यमों से साक्ष्यों की स्वीकृति; किसी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक रिकार्ड को मंगाने तथा गवाहों की जांच के लिए वारंट जारी करने के उद्देश्य से सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत एक दीवानी न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग का अधिकार प्रदान करती है। धारा 9(3) का शीर्षक "अधिनियम के तहत आवेदनों को निपटाए जाने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया" संभवतः भ्रमवश रखा गया है। जैसा कि पूर्व की चर्चा में देखा गया है, संहिता में अधि नियमित किए गए अनुसार ही प्रक्रिया लागू की गई। यह धारा नियमों के अधधीन है; नियम 3(1) में स्पष्ट उल्लेख है कि जहां

तक व्यवहारिक हो अधिकरण को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों का अनुसरण करना चाहिए। इन प्रावधानों, जमात में दिए गए निर्णय तथा इस अधिनियम के प्रावधानों का मिला जुला निचोड़ यह है कि अधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए तथा संगठन को प्रतिबंधित किए जाने संबंधी ओषणा की पुष्टि के लिए अपने दावे के समर्थन में राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा खुलासा किए गए साक्ष्य या सामग्री का खंडन करने के लिए संबंधित व्यक्ति या संगम को पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। अधिकरण को चाहिए कि वह जहां संभव हो (जैसा कि अभिव्यक्ति "व्यवहारिक" से स्पष्ट है) भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों का पालन करे। तथापि कार्यवाही की प्रकृति (दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किसी मामले की जांच जैसी एक विचारण के लिए की जाती है) तथा इसके समक्ष कार्यवाही के दौरान संवेदनशील सूचनाओं के खुलासे की संभावना को देखते हुए अधिकरण साक्ष्य के नियमों से नहीं बंधी है; उसने उसकी भावनाओं का तथा साक्ष्य अधिनियम के सिद्धांतों का पालन करना है।

मुद्दा सं. 3 के संदर्भ में

90. इस मुद्दे पर निर्णय देने की आवश्यकता है चूंकि एएनवीसी के वकील ने यह दलील दी कि दिनांक 16-11-2006 की अधिसूचना का आश्रय नहीं लिया जा सकता क्योंकि इसमें उस संगठन के विरुद्ध कुछ भी नहीं है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि केन्द्र सरकार एएनवीसी को विधिविरुद्ध संगठन कहने के लिए अधिसूचना के आधारों या तथ्यों से परे नहीं जा सकती है और इस सीमा तक उल्लिखित आधारों तथा हलफनामों के तथ्यों में कोई समानता नहीं है, हलफनामों को अधिकरण ने देखा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि एएनवीसी को एचएनएलसी के साथ जोड़ा जाना तथा एक ही अधिसूचना जारी करना इस बात का द्योतक है कि इस पर बुद्धिमता से विचार नहीं किया गया क्योंकि दोनों के आधार समान नहीं हो सकते।

91. पहली आपत्ति धारा 2(ण) के अंतर्गत अभिव्यक्ति के संदर्भ के अभाव से संबंधित है जिसमें विधिविरुद्ध गतिविधि को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि कोई संगम विधिविरुद्ध संगम वह है जो "भारत की संप्रभुता तथा भू-भागीय अखंडता को नहीं मानता उस पर प्रश्न उठाता है, उसका विरूपण करता है या विरूपित करने की मंशा रखता है"; या "जो भारत के प्रति वैमनस्य पैदा करता है या ऐसा इरादा रखता है" जैसा कि अधिसूचना में कहा गया है। वकील ने कहा कि अधिसूचना में केवल इस बात को दुहराया गया है कि केन्द्रीय सरकार का "यह मत है कि एएनवीसी तथा एचएनएलसी ऊपर उल्लिखित गतिविधियां भारत की संप्रभुता तथा अखंडता के लिए हानिकर हैं"। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रावधान में उन कृत्यों के बारे में स्पष्ट राय दिया जाना आवश्यक है जिनसे भारत की संप्रभुता तथा भू-भागीय अखंडता पर सवाल उठाए गए हों, उसे विरूपित किया गया हो या विरूपित करने की मंशा हो या भारत के प्रति वैमनस्य पैदा किया गया हो या पैदा करने की मंशा रही हो। अधिसूचना में इनमें से किसी भी का उल्लेख नहीं किया गया और "हानिकर" शब्द का इस्तेमाल कर दिया गया है।

92. मेडिसैन्स लेक्चरर, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय (13-05-07 को भारतीय मानक संभव 13:41 पर देखे गए www.oxford.com/dictionary/detrimental) के अनुसार "डेट्रीमेंटल" का अर्थ "स्पष्ट रूप से घातक"; अर्थात् बहुत बड़े नुकसान; हानिकारक है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी (13-05-2007 को भारतीय मानक समय 13:44 पर देखे गए <http://www.oxford.com> / www.oxford.com) के अनुसार डेट्रीमेंटल का अर्थ नुकसान का अर्थ है। इससे स्पष्ट है कि "डेट्रीमेंटल" अभिव्यक्ति का अर्थ हानिकारक या चोट पहुंचाना है। विधिविरुद्ध गतिविधियों को परिभाषित करने वाली अधिसूचना में यह अभिव्यक्ति भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को तोड़ने के लिए इस्तेमाल की गयी है। हालांकि प्रश्नगत अधिसूचना में इसी अभिव्यक्ति का इस्तेमाल नहीं किया गया है और मेरी राय में इससे घातक नुकसान नहीं हुआ फिर भी अधिसूचना में स्पष्ट कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार की यह धारणा है कि ये संगम विधिविरुद्ध हैं और विधिविरुद्ध गतिविधियों में लिप्त हैं। अगर संप्रभुता या संप्रभुता अखंडता को विखिन्न करने के उद्देश्य से की गई गतिविधियों पर विचार किया जाए तो यह निष्कर्ष स्वतः निकलता है कि "विरूपण" शब्द के प्रयोग में हुई चूक या प्रयोग न किए जाने से अधिसूचना अमान्य नहीं हो जाती। इसके अतिरिक्त अधिकरण द्वारा न्याय निर्णय की प्रक्रिया का उद्देश्य अर्धपूर्ण सुनवाई तथा संबंधित गुट या संगम को यह सिद्ध करने का अवसर देना है कि उनकी गतिविधियाँ विधिविरुद्ध नहीं हैं। यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि साविधिक शर्तों के यंत्रिक निरूपण का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि अभी वास्तविक तथ्य मौजूद हैं। ये अधिकरण के द्वारा जल्द किए जाने के मामले हैं जैसा कि इस मामले में है।

93. अगला प्रश्न है कि क्या केन्द्रीय सरकार उन तथ्यों पर निर्भर रह सकती है जो अधिसूचना में प्रकाशित आधारों में उल्लिखित नहीं थे। यह कहने के लिए कि साविधिक आदेश में उल्लिखित आधारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता मोहिन्दर सिंह गिल मामले में दिए गए निर्णय का सहारा लिया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह तय किया जा चुका है साविधिक आदेश की जांच उसमें उल्लिखित तथ्यों के आधार पर ही की जानी चाहिए तथा इसके अलावा न्यायालय द्वारा कोई और सुनवाई नहीं की जानी चाहिए या साक्ष्य नहीं लिए जाने चाहिए। तथापि अधिनियम के तहत आदेश तथा अन्य साविधिक आदेशों में अन्तर यह है कि इस आदेश से एक निष्पक्ष अधिकरण के समक्ष सामग्री तथा साक्ष्यों के माध्यम से एक निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है जिससे अधिकरण को अपने समक्ष प्रस्तुत सामग्री के आधार पर संतुष्ट होना होता है। दूसरे मामले में, आदेश में सरकार की राय या निर्णय को दर्शाया जाता है। अधिसूचना तथा अधिनियम के तहत प्रक्रिया मिलकर एक प्रतिकूल प्रक्रिया का निर्धारण करती है जहाँ संगम के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार तथा अन्य संबंधित पक्षकारों को सुनवाई तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है। अतः इस धारणा से साम्यता रखना या यह आधार बनाना कि प्राधिकारी साविधिक आदेश की घोषणा या किए गए उल्लेख से बंधा हुआ है, अधिनियम के तहत एक अधिकरण के मामले में सही नहीं है।

94. तीसरा पहलू यह है कि जहाँ तक एनवीसी का संबंध है, केन्द्रीय सरकार ने बिना सोचे-विचारे अधिसूचना जारी कर दी। आरम्भिक प्रस्तुति, जो एनवीसी द्वारा हिंसा को छोड़ने के आश्वासन के बारे में है पर भरोसा किया गया है। वह अनुरोध किया गया था कि इससे पता चलता है कि दोनों संगठनों के विरुद्ध आरोपों की प्रकृति अलग है और जहाँ तक एनवीसी का संबंध है अधिसूचना जारी करने के लिए कोई आधार नहीं है। अधिसूचना में निम्नानुसार उल्लेख किया गया है :

"जबकि मेघालय की अधिक नेशनल वॉलेंटियर कॉन्सिल ('जिसे इसके पश्चात एनवीसी' कहा जाएगा) ने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए भारत के संविधान के बांधे के भीतर कार्रवाई करने के लिए अपनी तत्परता और हिंसा का त्याग करने पर सहमति के बावजूद धन एकत्र करना और जबरन वसूली करना जारी रखा है।"

इसमें बाद में, केन्द्र सरकार के विचारों के बारे में उल्लेख किया गया है कि एनवीसी और एचएनएससी दोनों ही—

- (i) अपने संगठनों के लिए धन एकत्र करने के लिए जनता को धमकाने, जबरन वसूली और लूटने के कार्यों में लिप्त हैं;
- (ii) वे जबरन वसूली और डराने धमकाने के कार्यों के लिए पूर्वोक्त क्षेत्र के अन्य विद्रोही दलों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं;
- (iii) वे शरण स्थल और अपने सदस्यों के प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए कुछ पड़ोसी देशों में बाँप चल रहे हैं।

और जबकि केन्द्र सरकार का यह विचार है कि :—

- (i) एनवीसी वर्ष 2004 में त्रितीय हिंसक घटनाओं, 2005 में द्वितीय हिंसक घटनाओं में और वर्ष 2006 (31 अगस्त, 2006 तक) में एक हिंसक घटना में शामिल था।
- (ii) एनवीसी द्वारा की गई इन हिंसक घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्ष 2004 में 12 व्यक्ति सुरक्षा बलों की 4 कर्मियों सहित) और वर्ष 2005 में एक व्यक्ति मरा गया।

इन प्रस्तुतियों के पश्चात् यह विचार बना कि एनवीसी एक गैर-कानूनी एसोसिएशन है। प्रत्यक्ष रूप से, मेरा यह विचार है कि ये दोनों संगठन, अधिसूचना या इस विचार को खारिज नहीं करते कि एनवीसी एक गैर-कानूनी एसोसिएशन है। हिंसा को परित्याग करने की सहमति के उल्लेख से कवल इस बात का पता चलता है कि आश्वासन के बावजूद यह जबरन वसूली और धन एकत्र करने के कार्यों में लिप्त रहा। पूरी अधिसूचना का तात्पर्य यह प्रकट करता है कि केन्द्र सरकार को, दोनों एसोसिएशनों की गतिविधियों की प्रकृति में विभिन्नता के बारे में जानकारी थी; उसने इनसे अलग दृष्टि से निपटा।

साक्ष्य और निष्कर्षों पर विचार विमर्श

95. सी. डब्ल्यू.-1 और सी. डब्ल्यू.-2 जेन्तिया हिल्स जिला, जोवाई के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक हैं। उन्होंने एच. एन. एल. सी. के सदस्यों द्वारा हिंसा और लूट-पाट के कार्य जारी रखने के मामले में गवाही दी। सी. डब्ल्यू.-2 ने 25 जनवरी, 2005 और 25 मार्च, 2005 को हुई लूट-पाट और अपहरण की घटनाओं का वर्णन किया है। तथापि, मेरे विचार में, इस प्राधिकरण द्वारा उन घटनाओं पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये घटनाएँ उन अवधियों से संबंधित हैं जिन पर पहले प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया था, अतः वे पुराने आधार हैं। सी. डब्ल्यू.-2 ने दिनांक 25 मई, 2005 की एक अपहरण की घटना के बारे में और जोवाई में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने और अपहृत व्यक्ति की हत्या के बारे में भी कहा है। उन्होंने दिनांक 8-1-2006 को बासीमभा पाथव नामक व्यक्ति की गिरफ्तारी के बारे में और चीन निर्मित 10 ए. के.-47 सक्रिय कारतूसों की बरामदगी और मई एवं जुलाई के बीच एवं 8 मई, 2005 एवं 16 जुलाई, 2006 के बीच जेन्तिया पहाड़ियों में एच. एन. एल. सी. के छः सदस्यों के आत्मसमर्पण के बारे में बताया है। इन सदस्यों ने हथियारों का समर्पण भी किया है। सी. डब्ल्यू.-2 ने अभिसाक्ष्य दिया है कि दोनों एच. एन. एल. सी. जिले में सक्रिय हैं परंतु एच. एन. एल. सी. अधिक सक्रिय है और एन. एस. सी. एन. (आई. एम.) उस संगठन का मुख्य अनुपेक्षक है।

96. सी. डब्ल्यू.-3 और सी. डब्ल्यू.-4 पूर्वी खासी पहाड़ी जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक हैं। उपायुक्त ने एच. एन. एल. सी. उत्फा, एन. डी. एफ. बी., एन. एल. एफ. टी. और एन. एस. सी. एन. के बीच संबंधों के बारे में कहा। उसने कहा है कि एच. एन. एल. सी. का मुख्य निशाना व्यथसाही समुदाय है। सी. डब्ल्यू.-4 ने पूर्वी खासी पहाड़ी, जिले में अनेक घटनाओं के बारे में अभिसाक्ष्य दिया है, जिसमें अपहरण, दिनांक 10-7-2005 को पीड़ित को बचाने के लिए चलाया गया अभियान, मासीनराम पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाना शामिल है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति प्राधिकरण की फाइल में रखी गई थी। इसमें, 9 मि. मी. सक्रिय गोलाबारूद के तीन खोखों, चीन निर्मित एक हथगोले, डी. बी. बी. एल. बन्दूक इत्यादि की बरामदगी के बारे में भी कहा गया है। सी. डब्ल्यू.-4 ने दिनांक 14-8-2005 को बंद के लिए एच. एन. एल. सी. के आह्वान का और बाद में प्रतुल चन्ना डेका के बारे में इसके द्वारा दिनांक 22-9-2005 को की गई मांग, एच. एन. एल. सी. के सदस्यों की गिरफ्तारी और पुलिस स्टेशन लबान में मामला सं. 53 (2005 का 09) दर्ज करने का उल्लेख किया। उन्होंने अन्य घटनाओं का भी उल्लेख किया है, नामतः दिनांक 23-12-2005 की घटना जिसके कारण दिनांक 6-7-2006 को आरोप पत्र दाखिल किया गया जिस मामले में मैगजीन सहित 7 चक्र-गोलाबारूद से भरी हुई मैगजीन के साथ 9 मि. मी. पिस्टन बरामद किए गए। उन्होंने 26 जनवरी, 2006 को गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर दिए गए एक बंद के आह्वान और 26-3-2006 को आइबोर मारवीन की हत्या, पुलिस मामला सं. 16(3) 06 दर्ज किए जाने के बारे में भी अभिसाक्ष्य दिया। प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति प्राधिकरण को दिखाई गई और यह रिपोर्ट

रिकार्ड का हिस्सा है। उन्होंने दिनांक 6-7-2006 को कम्पेर फ्रेंकली सियम की गिरफ्तारी और अभिर्शासी दस्तावेजों की बरामदगी का उल्लेख किया जिससे शिलांग सदर पुलिस स्टेशन मामला 2006 को सं. 128(07) दर्ज किया गया। अभिसाक्ष्य में आगे 15 अगस्त, 2006 को स्वतंत्रता दिवस के बहिष्कार के बारे में बयान और दिनांक 28-9-2006 को राहुल जसारांरिआ से 10 लाख रु. की मांग भी शामिल है। उन्होंने दिनांक 20-9-2006 की सुबह घटित एक और घटना और उस दिन उमक्रम गांव में घटित एक मुठभेड़ जिसमें एच. एन. एल. सी. के दो सदस्यों की गिरफ्तारी की गई और एक अन्य व्यक्ति की हत्या के बारे में बताया। उन्होंने पूर्वी खासी पहाड़ियों जिसकी बांग्लादेश के साथ एक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जहां उनके शीर्ष नेता तथाकथित रूप से छुपते हैं, में होने वाली एच. एन. एल. सी. की गतिविधियों के बारे में उल्लेख किया।

97. सी. डब्ल्यू.-5 और सी. डब्ल्यू.-6 पश्चिम खासी पहाड़ी जिला नानगसट-वाइन के क्रमशः उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक हैं। उन्होंने एच. एन. एल. सी. और ए. एन. वी. सी. दोनों के बारे में कहा परंतु मुख्यतः एच. एन. एल. सी. के बारे में कहा। सी. डब्ल्यू.-6 के अनुसार एच. एन. एल. सी. की गतिविधियों का उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष के जरिए भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को तोड़ना है। उन्होंने कहा कि इसके सदस्य नानगजरी, अम्बर, नानबोलाम, पोरमावदार और मावेत क्षेत्रों में सक्रिय हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एच. एन. एल. सी. के सदस्य व्यापारी वर्ग से जबरन बसुली करते हैं और डकैतियों, चोरी और पुलिस दलों पर हमले करने में लिप्त हैं, उनके अनुसार एच. एन. एल. सी. का एन. एस. सी. एन. (आई. एम.) और एन. एल. एफ. टी. के साथ सीधा संबंध है। यह प्रतिबंधित संगठन सदस्यों को प्रशिक्षण देकर एच. एन. एल. सी. की सहायता करते हैं और अन्य सहायता देते हैं जो राज्य की सुख और सामान्य जीवन की जड़ों को खोदते हैं। उन्होंने एच. एन. एल. सी. के साथ हुई एक मुठभेड़ के बारे में बताया जिसमें होनबीलाम गांव में दिनांक 22-6-2006 को उनके सदस्य की मौत हो गई, छः चक्र गोलाबारूद के साथ कारबाइन, एक रिवाल्वर जिसके साथ 32 गोलाबारूद के 5 राउंड और अन्य अभिर्शासी दस्तावेज बरामद किए गए। यह भी इस मामले सं. 13 (6) 06 की विषयवस्तु है। गवाह ने एक अन्य घटना के बारे में बताया जब दिनांक 18-11-2006 को छापा मारा गया था, जिसके फलस्वरूप एच. एन. एल. सी. के वित्त सचिव द्वारा हस्ताक्षरित मांग पत्र बरामद हुए।

98. सी. डब्ल्यू.-7 और सी. डब्ल्यू.-8 उपायुक्त री-बॉय और पुलिस अधीक्षक री-बॉय ने लगभग इसी प्रकार से अभिसाक्ष्य दिया। सी. डब्ल्यू.-7 ने एच. एन. एल. सी. और अन्य प्रतिबंधित गुटों जैसे उत्फा, एन. डी. एफ. बी. और के. एन. वी. के बीच संबंध के बारे में कहा। सी. डब्ल्यू.-8 ने विशेष घटनाओं के बारे में बताते हुए एक सूची के जरिए सामग्री प्रस्तुत की। उनके अनुसार एच. एन. एल. सी. के वित्त स्कंध के एक व्यक्ति कैलेन्डर सन वैनियांग को गिरफ्तार किया गया और एच. एन. एल. सी. वित्त सचिव द्वारा हस्ताक्षरित एक मांग-पत्र बरामद किया गया। इस गिरफ्तारी से व्यापारियों को वितरित किए गए कई मांग-पत्रों के बारे में पता चला और पी एस मामला सं. 45 (6) 03 दायर किया गया।

99. सी. डब्ल्यू-9, मेघालय सरकार के आयुक्त और सचिव ने मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ियों, मणिमरी खासी पहाड़ियों, जयंतिया पहाड़ियों और री-बॉय जिलों में एच. एन. एल. सी. की गैर-कानूनी, जघन्य और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि एच. एन. एल. सी. का मुख्य उद्देश्य एक अलग राज्य बनाना है जो भारत का हिस्सा नहीं हो। उन्होंने अभिसाध्य दिया कि एच. एन. एल. सी. बंद का आह्वान करता है और लोगों को राष्ट्र दिवस समारोह में उपस्थित न होने के लिए धमकी देता है। उनके अनुसार एच. एन. एल. सी. खासी और जयंतिया पहाड़ियों में सक्रिय है। चूंकि इन पहाड़ियों के साथ लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है; इसके अन्य प्रतिबंधित जिले गुटो जैसे एन. एस. सी. एन. डब्ल्यू. एन. डी. एफ. डी. और एन. एल. एफ. टी के साथ अच्छे संबंध हैं; वे एच. एन. एल. सी. के सदस्यों को प्रशिक्षण देते हैं। उन्होंने कहा कि एच. एन. एस. सी. मुख्य रूप से व्यापारिक समुदाय को निरुत्साहित करता है और उनसे जबरन धन वसूली करता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 में कई हथियार जैसे एक ए. के. राइफल, एक 303 राइफल, 2 शॉट गन, 1 पिस्तौल, 1 रिवाल्वर, 30 गोला-बारूद, 1 खाली मैगजीन, 1 हथगोला बरामद किया गया और वर्ष 2006 में तीन कारबाइन, 1 पिस्तौल, 3 रिवाल्वर, 31 गोला-बारूद, 2 खाली मैगजीन बरामद किए गए। उन्होंने यह सूचना देते हुए कि दो संगठन नामतः ए. एन. वी. सी. और एच. एन. एल. सी. गैर-कानूनी थे, के समर्थन में समाचार-पत्रों की प्रतियां दायर की हैं जिनमें कारण बताओ नोटिस प्रकाशित किए गए थे।

100. सी. डब्ल्यू. 17, श्री आर. आर. झा, निदेशक भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने अभिसाध्य दिया कि एच. एन. एल. सी. का उद्देश्य हैन्यूट्रेप लोगों को भारत सरकार के तथाकथित सत्तावादी शासन से स्वतंत्र कराना, खासी और अन्य मेघालय जन-जातियों की शोषण से रक्षा करना और अपनी संस्कृति का संरक्षण करना है। उन्होंने अभिसाध्य दिया कि एच. एन. एल. सी. लोगों को राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग न लेने के लिए धमकी देता है और बंद का आह्वान करता है। उन्होंने एच. एन. एल. सी. की गैर-कानूनी गतिविधियों जैसे जबरन वसूली करना, विशेषकर खासी जयंतिया क्षेत्रों में कोयला सेक्टर में व्यापारी समुदाय से जबरन वसूली करना, धन एकत्र करने के लिए नागरिकों को लुटाना, डराना-धमकाना और अपहरण के बारे में बताया। उन्होंने यह भी बताया कि एच. एन. एल. सी. के बांग्लादेश स्थित गैर-कानूनी प्रतिबंधित एसोसिएशनों के साथ संपर्क हैं। उन्होंने साक्ष्य दिया कि प्रतिबंध को आगे बढ़ाया जाना चाहिए चूंकि पहले लगाए गए प्रतिबंधों ने कुछ हद तक संगठन और इसकी गतिविधियों को नियंत्रित नहीं किया था।

101. सी. डब्ल्यू. 18, श्री आर. आर. झा, निदेशक भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने अभिसाध्य दिया कि एच. एन. एल. सी. का उद्देश्य हैन्यूट्रेप लोगों को भारत सरकार के तथाकथित सत्तावादी शासन से स्वतंत्र कराना, खासी और अन्य मेघालय जन-जातियों की शोषण से रक्षा करना और अपनी संस्कृति का संरक्षण करना है। उन्होंने अभिसाध्य दिया कि एच. एन. एल. सी. लोगों को राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग न लेने के लिए धमकी देता है और बंद का आह्वान करता है। उन्होंने एच. एन. एल. सी. की गैर-कानूनी गतिविधियों जैसे जबरन वसूली करना, विशेषकर खासी जयंतिया क्षेत्रों में कोयला सेक्टर में व्यापारी समुदाय से जबरन वसूली करना, धन एकत्र करने के लिए नागरिकों को लुटाना, डराना-धमकाना और अपहरण के बारे में बताया। उन्होंने यह भी बताया कि एच. एन. एल. सी. के बांग्लादेश स्थित गैर-कानूनी प्रतिबंधित एसोसिएशनों के साथ संपर्क हैं। उन्होंने साक्ष्य दिया कि प्रतिबंध को आगे बढ़ाया जाना चाहिए चूंकि पहले लगाए गए प्रतिबंधों ने कुछ हद तक संगठन और इसकी गतिविधियों को नियंत्रित नहीं किया था।

एन. एल. सी. के सदस्यों से अवैध हथियार जब्त करते हैं आरोपों से संबंधित हैं।

102. मेघालय राज्य की ओर से सभी गवाहों के अभिसाध्य यह दर्शाते हैं कि एच. एन. एल. सी. सक्रिय है और पूर्वी एवं पश्चिमी खासी पहाड़ी जिलों, जयंतिया पहाड़ी जिले और री-बॉय जिले में कार्य करता है। मेघालय राज्य की ओर से गवाहों के अनुसार इसके प्रतिबंधित संगठनों जैसे एन. एस. सी. एन. डब्ल्यू. एन. डी. एफ. डी. के एन. वी. और एन. एल. एफ. टी. इत्यादि के साथ भी सक्रिय संबंध हैं। ऐसी कुछ घटनाएं हुई जिसमें एच. एन. एल. सी. के सदस्य मुठभेड़ में मारे गए और गिरफ्तार किए गए, जिससे हथियार बरामद हुए। यह साक्ष्य यह भी दर्शाता है कि वर्ष 2005 और 2006 में एच. एन. एल. सी. ने लोगों की धमकियां दीं और उन्हें गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय समारोहों में भाग लेने से रोका। इसके अतिरिक्त गवाहों ने अभिसाध्य दिया कि एच. एन. एल. सी. हैन्यूट्रेप लोगों के लिए भारत से अलग एक राज्य चाहती है। इन गवाहों, जिनमें चार जिलों के पुलिस अधीक्षक शामिल हैं, के अनुसार एच. एन. एल. सी. का शीर्ष नेता भारतीय सीमा से बाहर बांग्लादेश में रहता है। एच. एन. एल. सी. प्रशिक्षण और संसाधन इत्यादि एकत्र करने हेतु गैर-कानूनी घोषित अन्य एसोसिएशनों से भी सहायता लेता है।

103. प्राधिकरण ने कारण बताओ नोटिस जो दिनांक 12-2-2007 को वापस भेजे जाने से जारी किए, जिन्हें शिलांग और सभी जिला मुख्यालयों के स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया गया। एच. एन. एल. सी. ने उपस्थित होना या अपना उत्तर दायर करना ठीक नहीं समझा। दो अलग अवसरों अर्थात् 12-4-2007 से 14-4-2007 और 6-5-2007 को शिलांग में कार्यवाहियों की गईं और सार्वजनिक सुनवाई हुई। अंग्रेजी भाषा के समाचार-पत्रों और पत्रों एवं खासी में स्थानीय भाषा के समाचार-पत्रों में सुनवाई का व्यापक प्रचार किया गया। इन समाचार-पत्रों के प्रकाशन की प्रतियां रिकार्ड का हिस्सा हैं। इसके बावजूद एच. एन. एल. सी. ने कार्रवाई में उपस्थित न होने और इसका विरोध करने का निर्णय लिया।

104. अभिसाध्य का विश्लेषण यह दर्शाता है कि एच. एन. एल. सी. एक ऐसा संगठन है जो हैन्यूट्रेप लोगों के लिए भारत से बाहर एक अलग और स्वतंत्र राज्य लेने के लिए प्रतिबद्ध है और वह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यह हिस्सा के कार्यों के माध्यम से अपना उद्देश्य प्राप्त करना चाहता है। हिस्सा के इन कार्यों में पुलिस कार्रमा पर आक्रमण, अत्याधुनिक और अवैध हथियारों का प्रयोग, लोगों को राष्ट्रीय दिवस समारोहों में भाग न लेने के लिए धमकी देना, लोगों को वैधानिक प्रक्रिया में भाग लेने से रोकना (जैसा कि शिलांग म्युनिसिपल बोर्ड के चुनावों के लिए जायकन पत्र न भरने के लिए उम्मीदवारों को धमकियां देने का मामला) इत्यादि शामिल हैं। साक्ष्य में यह भी दर्शाया गया है कि एच. एन. एल. सी. गैर-कानूनी घोषित किए गए चार अन्य संगठनों के साथ संबंध और संपर्क बनाए हुए हैं। उनके नेता बांग्लादेश में हैं, जहां सदस्यों को प्रशिक्षण देने के लिए उनके कैम्प हैं। वे अपहरण, जबरन धन एकत्र करने और हिंसा के अन्य कार्य करने के उपरांत यहां चले जाते हैं।

105. दो वर्षों की अवधि में दर्ज 12 प्रथम सूचना रिपोर्टें गंभीर प्रकृति की नहीं लगती। तथापि, उनकी गतिविधियों का पैटर्न ध्यान देने योग्य है। इन सभी में एक सांझी बात यह दिखाई देती है कि इनका उद्देश्य लोगों को डराना-धमकाना, सामान्य कार्यकरण को रोकना और जबरन वसूली और अपहरण के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को क्षति पहुंचाना है। ऐसी घटनाओं से, जिनमें एच.एन.एल.सी. ने बार-बार लोगों को राष्ट्रीय दिवस उत्सवों में भाग लेने से रोका है और उन्हें डराया-धमकाया है और इसके साथ-साथ लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भागीदारी की इच्छा रखने वाले लोगों को धमकाया है, सशस्त्र संघर्ष और हिंसा के जरिए अलग राज्य का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हिंसा का प्रयास अपनाने की उसकी प्रतिबद्धता का पता चलता है। इससे स्पष्टतः पता चलता है कि इसकी गतिविधियां किसी विधिपूर्ण उद्देश्यों के लिए नहीं बल्कि भारत की सार्वभौमिकता और प्रांतीय एकता को नुकसान पहुंचाने और उसे छिन्न-भिन्न करने से संबंधित हैं। उभरते चर्चा को ध्यान में रखते हुए एवं रिकार्ड में उपलब्ध सभी विचार करने के पश्चात् इस न्यायाधिकरण का यह मत है कि संघ और मेघालय राज्य द्वारा (इसके द्वारा की गई जांच में) (1) के अंतर्गत अधिसूचना की पुष्टि में प्रयाप्त तथ्य प्रदर्शित किए गए हैं।

106. जहाँ तक ए. एन. वी. सी. का संबंध है, केन्द्र सरकार ने श्री आर.आर. झा, सी.डब्ल्यू.-17 के अभिसाक्ष्य और उसके शपथपत्र पर विश्वास किया है। इसका समर्थन मेघालय राज्य की ओर से प्रस्तुत गवाहों मुख्यतः सी.डब्ल्यू.-10 से सी.डब्ल्यू.-16 द्वारा किया गया है। सी.डब्ल्यू.-10, मेघालय सरकार के राजनैतिक विभाग के आयुक्त और सचिव ने अपने शपथ-पत्र में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने उन स्थानीय समाचार पत्रों, स्थानीय सामाचार पत्रों की प्रेस कतरन दिनांक 12-12-2006 के शिलांग टाइम्स का अंक, उसी तारीख का यू-माफोर और दिनांक 13-12-2006 को सतातिनी जनेरा की कतरन संलग्न की हैं जिसमें अधिसूचना के बारे में जानकारी दी गई है। समाचार पत्रों के प्रकाशनों, जिसमें न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 30-12-2006 और 4-1-2007 के उन समाचार पत्रों के साथ-साथ दिनांक 30-12-2006 का "द टेलीग्राफ" कोलकाता में, कारण ब्रताओ नोटिस प्रकाशित किया गया, की कतरन संलग्न की गई हैं। गवाह ने आकाशवाणी और दूरदर्शन शिलांग से प्रसारण किए जाने के साक्ष्यों के दस्तावेज संलग्न किए।

107. उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि ए.एन.वी.सी., गैर जन-जातीय व्यवसायियों विशेषकर तुरा और गारो पहाड़ियों के अन्य कस्बों में डराने धमकाने और जबरन वसूली के कार्य में संलिप्त है। उसने ए.एन.वी.सी. के नेताओं के बारे में यह साक्ष्य दिया कि वे कोयला व्यापारियों पर बगैर विधिक प्राधिकार के उनके एजेंटों से अत्याधिक ऊँची दरों पर फार्म खरीदने के लिए दबाव डालते हैं। इस गवाह ने जुलाई, 2004 के त्रिपक्षीय समझौते का उल्लेख भी किया जो युद्ध विराम की मॉनीटरिंग करने और शिविरों की स्थापना करने के संबंध में संयुक्त मॉनीटरिंग समूह की स्थापना करने के संबंध में है। उसके अनुसार ए.एन.वी.सी. ने हथियारों और गोला-बारूद का समर्पण करने से मना कर दिया जो तुरा स्थित ए.एन.वी.सी. के संपर्क कार्यालय

में रखे हुए थे। उसने यह बताने के लिए असूचना रिपोर्ट का उल्लेख किया कि ए.एन.वी.सी. बांग्लादेश के अन्य संगठनों के साथ संपर्क बनाए हुए है और वहाँ इसने सुरक्षित स्थान बना रखा है। उसके अनुसार ए.एन.वी.सी. के सदस्य मई, 2005 और अप्रैल, 2006 के बीच हथियारों के साथ अपने शिविरों से भाग गए थे। उन्होंने पूर्व और दक्षिण की गारो पहाड़ियों में आधिक नेशनल लिबरेशन फ्रंट (ए.एन.एफ.) और पश्चिमी खासी की पहाड़ियों में आधिक नेशनल यूथ (ए.एन.वाई) नामक दो संगठन बना लिए हैं। उसने ए.एन.वी.सी. सदस्यों की गिरफ्तारी के बारे में अभिसाक्ष्य दिया जिसमें भगौड़ और ए.के. सीरीज दो राइफलों और अनेक प्रतिबंधित हथियारों की बरामदगी शामिल है। ए.एन.वी.सी. के सदस्य जो 2005-2007 के दौरान सक्रिय रहे थे, के नामों की सूची और अलग-अलग पुलिस मामलों में उनकी संलिप्तता को शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है, हथियारों और गोला-बारूद की बरामदगी से संबंधित सांभान्य सूची भी प्रस्तुत की गई।

108. ए.एन.वी.सी. के वकील ने उनसे विस्तृत रूप से प्रतिपरीक्षा की। गवाह ने यह साक्ष्य दिया कि मेघालय सरकार को समझौता को आगे बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं थी परंतु साथ ही साथ इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया कि संयुक्त मॉनीटरिंग समूह ने किसी स्वर पर ए.एन.वी.सी. द्वारा स्थापित नियमों के अनुपालन के बारे में अपनी संतुष्टि व्यक्त की। उसने इस बयान को बरकरार रखा कि ए.एन.वी.सी. का उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से राज्य का दर्जा प्राप्त करना है। उसने बताया कि ए.एन.वी.सी. के सदस्यों की सूची सूचना सरकार के पास थी और न्यायाधिकरण के समक्ष स्वेच्छा से यह भी स्वीकार किया कि इस प्रकार की सूची को पूर्ण नहीं माना जा सकता है क्योंकि ए.एन.वी.सी. दूसरे संगठन बना लेता है। ए.एन.वी.सी. के प्रमुख का नाम सूची में उल्लिखित नहीं है। उसने सूची में मौजूद विस्तारितियों का भी उल्लेख किया। उसने प्रतिपरीक्षा के दौरान ए.एन.वी.सी. के बारे में पुनः यह उल्लेख किया कि ए.एन.वी.सी. हथियारों का समर्पण नहीं कर रही है और उन्हें किसी एकान्त स्थान पर रख रहीं हैं। उनके अनुसार शांतिवार्ता को आगे चलाने के उद्देश्य से मेघालय राज्य द्वारा युद्ध विराम को बढ़ाये जाने का विरोध नहीं किया गया।

109. सी.डब्ल्यू.-11 और सी.डब्ल्यू.-12 उपयुक्त पश्चिमी गारो पहाड़ियां और जिले के पुलिस अधीक्षक ने शपथ पत्र द्वारा अपने अभिसाक्ष्य की पुष्टि की और यह अभिसाक्ष्य दिया कि ए.एन.वी.सी. जिले में गैर-कानूनी गतिविधियां चलाता है। और हथियारों और गोला-बारूद की आपूर्ति के लिए इसका एन.एस.सी.एल., उल्फा और एन.डी.एफ.डी. के साथ संपर्क है। उनके अनुसार गैर-कानूनी गतिविधियों में जबरन वसूली, हत्या और डराना-धमकाना शामिल है। सी.डब्ल्यू.-11 ने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया कि गारो समुदाय के कुछेक वर्ग को कतिपय मुद्दों पर शासन से नाराजगी है जिसमें उन्होंने बंद आदि के माध्यम से व्यक्त किया था किंतु इस बात से इंकार किया कि ए.एन.वी.सी. को गारो लोगों के किसी वर्ग का समर्थन प्राप्त है। उसने यह भी बताया कि वहाँ स्थापित नियमों का अनेक बार उल्लंघन हुआ था। वे दिनांक 8-2-2005 को हुई मौसिक समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त को दिखाने पर इस बात पर सहमत हुए हैं कि उन्होंने समझौते की शर्तों के उल्लंघन को रिकार्ड नहीं किया था। उनके

अनुसार बैठक का उद्देश्य हिंसा का रास्ता छोड़ देने के लोगों को प्रोत्साहित करना था। उन्होंने प्रतिपरीक्षा के दौरान उस बैठक के बारे में स्पष्टता से बताया कि जो 25-8-2003 को उस समय हुई जब ए.एन.वी.सी. के समुक्त सचिव अपने संगठन के सदस्यों के साथ खिला मजिस्ट्रेट के काराखाने जबरन वसूली घुस गए जिसकी रिपोर्ट की गई थी। उन्होंने स्वीकार किया कि इनमें ए.एन.वी.सी. के कैदों से भागे कुछ लोग भी थे। सी.डब्ल्यू-12 ने अपने शपथ-पत्र में दिनांक 15-2-2006, 17-2-2005, 5-4-2006 और 14-4-2006 की विभिन्न घटनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि वे बटनाई जिले में हुई उन अनेक घटनाओं में से कुछ के थीं जिनमें से अधिकांश घटनाओं की रिपोर्ट आम जनता में फैले डर के कारण नहीं की गई। सी.डब्ल्यू-12 के अनुसार ए.एन.वी.सी. का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर जबरन वसूली, जनता को अपराधिक तौर पर डराना-धमकाना, लूटना और गरीब पहाड़ियों में व्यवसाय को अपने अधिकार में रखने के माध्यम से वास्तविक प्राप्त करना है। उन्होंने यह भी अभिसाध्य दिया कि लोगों के क्षेत्रों से ए.एन.वी.सी. संगठन के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। उनके अनुसार व्यवसायी समुदाय को निराशा प्रभावित गया और उनके प्रतिबंधित संगठनों के साथ संपर्क है। उन्होंने वर्ष 2007 की सी.डब्ल्यू-12/2 वाला कैलेंडर, सी.डब्ल्यू-12/3 टेबल कैलेंडर और सी.डब्ल्यू-12/4 विभिन्न प्रिंटिंग प्रेस में मुद्रित गारों में "अधिकृत बॉलटिम्बर कॉन्सिडर के आर्मी फार्मेशन" नामक हस्ताक्षर की और इसकी अनुमति प्रिंट, सी.डब्ल्यू-12/5 प्रस्तुत की।

110. प्रतिपरीक्षा में सी.डब्ल्यू-12 ने यह स्वीकार किया कि ए.एन.वी.सी. प्रमुखों को छोड़ बांग्लादेश से जाने की अनुमति थी किंतु उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर धारण करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने अन्य संगठनों से संबंधित मिलने के बारे में इंकार किया और यह स्वीकार किया कि कुछ विराम की सहमतियों के खंड 5 के अनुसार ए.एन.वी.सी. प्रमुखों को मेजालस पुलिस से पी.एस.ओ. मुहैया नहीं कराए जा सके। तथापि, उन्होंने यह बताया कि किसी भी नेता ने ऐसी सुरक्षा की मांग नहीं की थी। उन्होंने यह भी बताया कि ए.एन.वी.सी. ने पुलिस और अन्य संगठनों के साथ सहयोग नहीं किया। उन्होंने स्वीकार किया कि बड़ा ए.एन.वी.सी. कैदों से भागे व्यक्ति आगे हुए थे और इस बात से इंकार किया कि ए.एन.वी.सी. किसी अन्य प्रतिबंधित या गैर-कानूनी संगठन से संपर्क नहीं रखता। अपनी प्रतिपरीक्षा में उन्होंने बताया कि ए.एन.वी.सी. ने तुरा में सूखी मछली के विक्रय पर प्रति किलो 5 रु. का टैक्स लगा रखा था और यह अभिसाध्य भी दिया कि ए.एन.वी.सी. ने डी.टी.एच. प्रौद्योगिकी के विक्रय पर प्रतिबंध लगा रखा था जिससे तुरा में व्यवसाय प्रभावित हुआ। उनके अनुसार ए.एन.वी.सी. केवल व्यवसाय संभालने पर नियंत्रण रखता है। उन्होंने यह स्वीकार किया कि हालांकि उसे ऐसी घटनाओं की एफ.आई.आर. दर्ज करने की क्षमता प्राप्त है परंतु उनके स्तुति होने के असार कम हो जाते हैं क्योंकि लोग डर की वजह से लगीए गए बोबाचेयन के समर्थन में अभिसाध्य देना नहीं चाहेंगे। उन्होंने इस बात से इंकार किया कि ए.एन.वी.सी. को राजनैतिक विचारधाराओं की मुख्य धारा में भाग देने से बचत करने के लिए अलग-अलग रखा जा रहा था।

111. सी.डब्ल्यू-13 और सी.डब्ल्यू-14 ने दक्षिणी गारो पहाड़ी जिलों के बारे में अभिसाध्य दिए और अपने शपथ-पत्र सी.डब्ल्यू-13/1

और सी.डब्ल्यू-13/2 प्रस्तुत की। सी.डब्ल्यू-13 दक्षिणी गारो पहाड़ियों, बांगमारा के उपायुक्त हैं और सी.डब्ल्यू-14 दक्षिणी गारो पहाड़ियों के पुलिस अधीक्षक हैं। उनके अनुसार बांगमारा पुलिस स्टेशन मामला सं. 20(5)/2005 वाली एक घटना की रिपोर्ट की गई थी और अन्य घटनाओं की रिपोर्ट डर की वजह से नहीं की गई। मुख्यतः गैर-जनजातीय लोगों से जबरन वसूली की जाती है और कुछ के मामलों में स्थानीय व्यवसायियों से भी जबरन वसूली की जाती है। सी.डब्ल्यू-13 ने बताया कि तुरा में दुकानदार निवासियों की डी.टी.एच. उपकरण नहीं बेचते हैं क्योंकि ए.एन.वी.सी. का इसमें एकाधिकार है और केवल व्यवसाय पर उनका नियंत्रण है। अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने इस बात से इंकार किया कि ए.एन.वी.सी. जबरन वसूली या संबंधित गतिविधियों में संलिप्त नहीं है और इस बात से भी इंकार किया कि ए.एन.वी.सी. प्रतिबंधित संगठनों से संपर्क नहीं रखता। प्रतिपरीक्षा में उसने ए.एन.वी.सी. और उसके सदस्यों द्वारा नांगल बिन्ना में कोयला व्यापारियों से की जाने वाली जबरन वसूली की घटनाओं के बारे में बताया।

112. दक्षिणी गारो पहाड़ियों के पुलिस अधीक्षक सी.डब्ल्यू-14 ने दिनांक 2-5-2005 की घटना का उल्लेख किया जिसमें ए.एन.वी.सी. संगठनों द्वारा की गई गोली-बारी के कारण कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, हथियार बरामद हुए और बांगमारा पुलिस स्टेशन में मामला सं. 20(5)/2005 के तहत एफ.आई.आर. दर्ज की गई। उनके अनुसार ए.एन.वी.सी. के प्रतिबंधित उपायुक्त समूहों यथा एन.एस.सी.एन., उल्फा, एन.डी.एफ.बी. आदि के साथ संबंध और संपर्क हैं और इसका मुख्यतः बांग्ला देश में है। उन्होंने बताया कि पिछली घोषणा से संगठन की गतिविधियों को रोकने में सहायता मिली थी। अपनी मुख्य परीक्षा में उन्होंने बताया कि ए.एन.वी.सी. द्वारा तुरा के व्यवसायी समुदाय के लोगों के संस्पर्शों के अलावा गांव प्रमुखों और सरकारी कर्मचारियों को भी डराना-धमकाना जाता है। उन्होंने बताया कि ए.एन.वी.सी. के सदस्य नांगल बिन्ना कोयला-बट्टी क्षेत्र में संकेन्द्रित हैं। प्रतिपरीक्षा के दौरान उन्होंने इस बात से अनभिज्ञता प्रकट की जिसमें दक्षिणी गारो पहाड़ियों के पुलिस अधीक्षक ने ए.एन.वी.सी. छोड़ चुके 6 लोगों के संबंध में पुलिस को जानकारी देने के लिए ए.एन.वी.सी. से अनुरोध किया। उन्होंने इस बात से इंकार किया कि ए.एन.वी.सी. किसी तरह की अवैध गतिविधियों में संलिप्त नहीं थी अथवा इसका अन्य प्रतिबंधित संगठनों के साथ संबंध नहीं था। उन्होंने प्रतिपरीक्षा में बताया कि ए.एन.वी.सी. की स्थापित नियमों के अनुसार हथियार लेकर नहीं चलना चाहिए था फिर भी उनसे हथियार बरामद किए गए हैं।

113. पूर्वी गारो पहाड़ियों के पुलिस अधीक्षक और पूर्वी गारो पहाड़ियों, विलियम्स नगर के उपायुक्त सी.डब्ल्यू-15 और 16 ने अभिसाध्य दिया और सी.डब्ल्यू-15/1 और सी.डब्ल्यू-16/1 के रूप में अपने शपथ-पत्र प्रस्तुत किए। सी.डब्ल्यू-15 ने अभिसाध्य दिया और एफ.आई.आर. की प्रतियां प्रस्तुत की। ये विभिन्न प्रकार की घटनाओं से संबंधित हैं जिसमें अपहरण और हत्या शामिल हैं। सी.डब्ल्यू-15 ने यह उल्लेख किया कि ए.एन.वी.सी. के सदस्य जबरन तौर पर गारो

पहाड़ियों के तीन जिलों के अधिकांश जिला परिषद् गेटों पर नियंत्रण रखते थे और सहानुभूति प्राप्त करने के लिए इसने एंबुलेंस और वाहन आदि भी खरीद रखे थे और उन्हें लोगों को दान में दे रहा था। उन्होंने उल्लेख किया कि ऐसे वाहन को जब्त करने के बाद में यह पता चला कि यह वाहन ए.एन.वी.सी. संगठनों द्वारा अवैध गतिविधियां चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उन्होंने 8-8-2006 की घटना का भी उल्लेख किया जब ए.एन.वी.सी. संगठन के लोगों को डबास में सैनिक कार्मिकों द्वारा पकड़ा गया और 9 एम एम पिस्टल सक्रिय कारतूसों के साथ जब्त की गई। उनके अनुसार ए.एन.वी.सी. के सदस्य संरक्षित वनों से पेड़ों को काटने के कार्य में भी संलिप्त थे और लोगों में डर व्याप्त होने के कारण इन गतिविधियों की सूचना कम संख्या में दी जा रही है। पूर्वी गारो पहाड़ियों में प्रतिबंधित संगठनों के मुख्य समर्थकों में उल्फा, एन.डी.एफ.डी., एन.एस.सी.एन. आदि शामिल हैं। सी.डब्ल्यू.-15 के अनुसार ए.एन.वी.सी. का मुख्य उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से एक अलग सार्वभौम राज्य प्राप्त करना है और ए.एन.वी.सी. संगठन प्रतिबंधित हथियार लेकर चलते हैं और वे राष्ट्रीय त्योहारों, स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस को मनाने से रोकते हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि ए.एन.वी.सी. संगठन के तीन-तीन निर्धारित कैंप अस्तित्व में हैं और उनमें से एक उनके जिले में स्थित है। हालांकि, उन्होंने बताया कि इस स्थिति के बावजूद अधिकांश संगठन के सदस्य कभी भी इस कैंप में वास्तव में नहीं ठहरते। उसने इस बात से इंकार नहीं किया कि कुछेक पूर्ववर्ती मामलों में कैंप छोड़कर गए हुए लोग शामिल थे।

114. सी.डब्ल्यू.-16 ने यह अधिसाक्ष्य दिया कि ए.एन.वी.सी. पूर्वी गारो पहाड़ियों में गैर-कानूनी गतिविधियों में सक्रिय रूप से संलिप्त हैं और इसके शीर्षस्थ प्रमुख भूमिगत रहते हैं। इसके सदस्य जबरन वसूली द्वारा धन एकत्र करते हैं। गवाह ने यह साक्ष्य दिया कि ए.एन.वी.सी. का प्रतिबंधित संगठनों यथा उल्फा, एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) और एन.डी.एफ.बी. के साथ संपर्क है। उनके अनुसार इसको अवैध घोषित करने से इसकी गतिविधियों को रोकने में पहले सहायता मिली थी। प्रतिपरीक्षा में उन्होंने बताया कि ए.एन.वी.सी. ने पिछली बार वर्ष 2004 में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस समारोह पर बंद का आह्वान किया था।

115. सी.डब्ल्यू.-17 ने दो शपथ-पत्र सी.डब्ल्यू.-17/2 एवं सी.डब्ल्यू.-17/3 प्रस्तुत किए। ये भारत सरकार गृह मंत्रालय में निदेशक है। उनके अनुसार ए.एन.वी.सी. का उद्देश्य एक अलग गारोलैंड राज्य का सृजन करना है और यह कि यह 24-9-1996 को बना लिया गया था। इसका मुख्यालय एक अज्ञात स्थान धिरम में है। इसके संविधान में कैबिनेट, मुख्य कमांडर, आर्मी स्टाफ, आर्मी विभाग, कैबिनेट द्वारा विधेयक पारित करने का उल्लेख है, जिन सबसे यह पता चलता है कि भारतीय संविधान के दायरे के अंतर्गत कार्य नहीं करता है। इसके संविधान में यह भी अपेक्षा है कि भावी सदस्यों के शारीरिक स्वास्थ्य की जांच संगठन के आसूचना और अन्वेषण इकाई द्वारा की जाए और यह कि सदस्यों को पार्टी की योजना और गोपनीयता को बताने के लिए प्रतिपिद्ध किया गया है। ए.एन.वी.सी.

का उद्देश्य एक अलग गारोलैंड राज्य का सृजन करना है जिसमें मेघालय के तीन गारो पहाड़ी जिले और गारो लोगों की बसावट वाले समीपवर्ती क्षेत्र, मेघालय की पश्चिमी गारो पहाड़ियां और रि-भोई जिलों के साथ-साथ असम के गोलपाड़ा और कामरूप जिले शामिल हैं। इसके कारण इन क्षेत्रों में विद्रोह पैदा हुआ है। इस मांग से खासी के साथ-साथ गारों और अन्य लोगों के बीच दुश्मनी बढ़ गई है। गवाह के अनुसार इस मांग से वैमनस्य और घृणा और दुर्भावना पैदा करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने बताया ए.एन.वी.सी. की गतिविधियों से विभिन्न वर्गों के बीच दुर्भावना पैदा हो गई है।

116. सी.डब्ल्यू.-17 ने यह भी बताया कि अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ए.एन.वी.सी. राज्य के कार्यकारिणों तथा जनता को डराता धमकाता है, जबरन वसूली, अपहरण लूट-पाट के द्वारा धन एकत्रित करता है, दूरदराज के क्षेत्रों में शाखा स्थापित करता है तथा अन्य भूमिगत गुटों अथवा प्रतिबंधित संगठनों के साथ भी संपर्क बनाए हुए है। अपने शपथ-पत्र में सी.डब्ल्यू.-17/2 ने तीन विवरणियां संलग्न की हैं जिसमें ए.एन.वी.सी. द्वारा 2004-2005 तथा 2006 में की गई हिंसक वारदातों का विस्तृत विवरण है। सी.डब्ल्यू.-17 ने बताया कि ए.एन.वी.सी. ने दिनांक 23-7-2004 को शुरुआत में छह महीने के लिए भारत सरकार और मेघालय सरकार के साथ अपने ऑपरेशन्स स्थगित करने के लिए एक समझौता किया। इसे समय-समय पर बढ़ाया गया और अब यह दिनांक 23-7-2007 तक वैध है। ए.एन.वी.सी. हिंसा को त्यागने के लिए और संविधान के दायरे के भीतर रहकर बातचीत करने के लिए तैयार हो गया। सेना, अर्ध-सैनिक बलों, मेघालय सरकार तथा केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों से गठित एक संयुक्त मॉनीटरिंग ग्रुप, युद्ध विराम की मॉनीटरिंग का रहा है। गवाह ने बताया कि यथास्थिति को अंग्रे बनाए रखने के लिए ए.एन.वी.सी. के सदस्यों को दक्षिण गारो हिल्स जिले में जेटरेज चोकपोट में तथा मेघालय के पूर्वी गारो हिल्स जिले के ब्रम्दा कैम्प में रखा गया है और तुरा में एक जनसंपर्क कार्यालय स्थापित किया गया है। ए.एन.वी.सी. द्वारा 202 सदस्यों की सूची मेघालय सरकार को प्रस्तुत की गई थी किंतु निर्धारित कैंपों में केवल 120 सदस्य ही ठहरे थे। उपलब्ध कराई गई सूची में महत्वपूर्ण व्यक्तियों जैसे कि अभ्यक्त, दिलाश मारक, जेरोम सी. मोनिन (स्वयंभू कम्पेंडर-इन-चीफ) जो कि वहां नहीं रह रहे हैं, के नाम शामिल नहीं हैं।

117. सी.डब्ल्यू.-17 ने बताया कि ए.एन.वी.सी. ने केवल 16 हथियार जमा कराए और कई अन्य हथियार अभी भी उनके पास हैं जो कानून एवं व्यवस्था के लिए खतरा हैं। उसने बताया कि ए.एन.वी.सी. के सदस्य कैम्पों को छोड़कर जा रहे हैं और अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त हो रहे हैं। कुछ ऐसे भगोड़े सदस्यों ने कैबिनेट के मकान के नेतृत्व में अधिक नेशनल लिबरेशन फ्रंट (ए.एन.एल.एफ.) गठित किया और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं। सी.डब्ल्यू.-17 ने बताया कि रिपोर्टों के अनुसार कैम्पों में ठहरे हुए लोग भी ने सदस्य बड़े पैमाने पर जबरन वसूली, कोयला व्यापारियों तथा अन्य लोगों को उनके निशाने पर हैं; से "दान" आदि लेने जैसी गतिविधियों में लिप्त हैं। उसने दिनांक 30 मई, 2005, 07 अक्टूबर, 2005 तथा

121. आर. डब्ल्यू.-4 ने दिनांक 13-4-2007 को आर. डब्ल्यू.-4/1 के रूप में अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया वह वर्ष 1998 से ए.एन.वी.सी. का महासचिव है। उसके अनुसार ए.एन. वी.सी. का डेरेल अपने पवित्र को नई दिशा देने के लिए पृथक गतोलैंड की स्थापना करमा है। उसने ऑपरेशन स्थगित करने संबंधी समझौते तथा विभिन्न अवसरों पर आबोधित बैठकों के बारे में साक्ष्य दिया। उसने दिनांक 17-1-2005 को हुई बैठक के बारे में विशेष रूप से साक्ष्य दिया जिसमें ए.एन.वी.सी. ने दावा किया कि उसके सदस्य विधिविरुद्ध गतिविधियों में शामिल नहीं है तथा पुलिस उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जो अबरन वसूली में ए.एन.वी.सी. के नाम का प्रयोग कर रहे हैं। उसने साक्ष्य दिया कि ए.एन.वी.सी. ने सदस्यों की पत्नी नहीं कर रही थी। उसने बताया कि चक्रान्ति कैम्पों में रह रहे सदस्यों की पूरी सूची फोटोग्राफ, पते इत्यादि सहित निर्णय के अनुसरण में दिनांक 18-7-2005 को प्रस्तुत की जाती थी। उसने यह भी बताया कि ए.एन.वी.सी. के पास जो इधियाए हैं वे आत्मरक्षा के लिए हैं। उसने दावा किया कि ए.एन.वी.सी. गैर-कानूनी संगठन नहीं है और यह ठलफा (यू.एल. एफ.ए.) या इस तरह के अन्य-ग्रुपों के साथ लिप्त नहीं है। उसने दावा किया कि इस तरह के अन्य ग्रुप जैसे कि अधिक नेशनल लिबरेशन फ्रंट अबरन वसूली, इत्यादि में लिप्त अपहरण हैं। उसने इस बात पर जोर दिया कि ए.एन.वी.सी. का कोई भी शीर्ष नेता बांग्लादेश में नहीं रहता है और वे कोई गैर-कानूनी गतिविधियां नहीं कर रहे हैं। उसने बताया कि ए.एन.वी.सी. ने अपने सदस्यों से स्वीच्छक रूप से लिए गए अंशदान से बड़े स्तर पर सुनामी रिलीफ फंड जैसी सामाजिक गतिविधियां संचालित की और गांव वालों को दो एम्बलेंस भी दान की।

122. प्रति-परीक्षा में आर. डब्ल्यू.-4 ने साक्ष्य दिया कि गारो लोगों के साथ हुए भेदभाव के कारण गारो लोगों के लिए एक पृथक गारोलेण्ड वांछनीय है। उसने बताया कि ए.एन.वी.सी. ने अपने 202 सदस्यों की सूची प्रस्तुत की है जिसका रखरखाव शुभ चिंतकों तथा गारो लोगों द्वारा किया जाता है। ए.एन.वी.सी. की आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है अपितु यह लोगों द्वारा नियमित आधार पर किए जा रहे अंशदान पर आधारित है। आर. डब्ल्यू.-4 के अनुसार ए.एन.वी.सी. के पास बड़ी संख्या में हथियार नहीं हैं परंतु जो कुछ भी उनके पास है उसे संयुक्त अभिरक्षा में रखा जाता है। हथियारों की आवश्यकता आत्मरक्षा के लिए होती है तथा यह सब हथियार तस्करों से प्राप्त किए गए थे। उसने इस बात से इन्कार किया कि यह हथियार बांग्लादेश से प्राप्त किए गए या पुलिस, अर्द्ध-सैनिक बलों और सशस्त्र बलों से छीने गए हैं। उसने स्वीकार किया कि राज्य सरकार को भेजी गई हथियारों की सूची में पांच एल.एम.जी., ए.के.-47 राईफलें तथा 155.56 एम.एम की राईफलें आदि शामिल हैं। उसने स्पष्ट किया कि इन सब का प्रयोग आत्मरक्षा के लिए किया गया था। उसने बताया कि उसे प्रत्येक कैम्प में रहने वाले सदस्यों की संख्या के बारे में जानकारी नहीं है और कहा कि सदस्यों की सूची ए.एन.वी.सी. द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले पदनामों के अनुसार तैयार की गई थी। वह इस बात से सहमत नहीं हुआ कि ए.एन.वी.सी. निरंतर सदस्यों की भर्ती कर रहा है और कहा कि सदस्यों की सूची में आया अंतर शांतिवार्ता में हुई प्रगति के कारण है। उसने कहा कि ए.एन.वी.सी. किसी प्रकार का साहित्य प्रकाशित नहीं करता है।

123. भारत सरकार की ओर से प्रति परीक्षा में गवाह ने कहा कि महासचिव चुनने के लिए ए.एन.वी.सी. ने कोई आंतरिक चुनाव नहीं करवाया है और उसका चुनाव नेता दिलाश एम. मराक द्वारा किया गया था। उसने बताया कि ए.एन.वी.सी. का कार्यालय सरकार द्वारा आवंटित एक मकान, तुरा यूथ होस्टल में है। उसने बताया कि ए.एन.वी.सी. का कोई लिखित संविधान नहीं है तथा इसके लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निर्णय बैठकों में सामूहिक निर्णय से लिया जाता है। उसने बताया कि ए.एन.वी.सी. के कुल 202 सदस्य हैं। उसने यह साक्ष्य दिया कि भारत सरकार को अस्तुत ज्ञापन में तिरंगे के साथ-साथ ए.एन.वी.सी. के झण्डे का प्रतीक अर्थात् ए.एन.वी.सी. का झण्डा दर्शाया गया है और इसे जनता के बीच प्रदर्शित नहीं किया जाता है। गवाह ने बताया कि पुलिस मुठभेड़ों, जिनमें ए.एन.वी.सी. के कई सदस्यों की मृत्यु हो चुकी है, के कारण ए.एन.वी.सी. अपने मुख्यालयों को बदलता रहता है जिसे 'चिराम' कहते हैं। उसने बताया कि ए.एन.वी.सी. का एक अध्यक्ष है, ए.एन.वी.सी. का महासचिव वित्त विभाग देखता है, कमांडर-इन-चीफ केडर को देखता है तथा मिस्टर अरिस्त सेनगसरंग प्रचार एवं संचालन सचिव के रूप में ए.एन.वी.सी. के प्रचार कार्यों को देखता है। प्रति परीक्षा में उसने साक्ष्य दिया कि ए.एन.वी.सी. किसी प्रकार की जनसभाएं आयोजित नहीं करता है तथा इसकी गतिविधियां केवल इसके सदस्यों को ही पता होती हैं। उसने यह भी माना कि ए.एन.वी.सी. ने प्रचार सचिव द्वारा डिजाइन किए गए टेबल कलेंडर को प्रकाशित किया और यह कि इसका कोई बैंक खाता नहीं है क्योंकि यह शुभचिंतकों से प्राप्त धन को नहीं रखता है। ए.एन.वी.

सी. के सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष से कम है क्योंकि इस आयु वर्ग के लोग शारीरिक रूप से चुस्त-दुरुस्त होते हैं तथा लड़ने में सक्षम होते हैं।

124. आर. डब्ल्यू.-5 ने अपना आर. डब्ल्यू.-5/1 रापथ पत्र प्रस्तुत किया और भारतीय क्षेत्र में ही एक पृथक राज्य स्थापित करने के रूप में ए.एन.वी.सी. के लक्ष्यों और उद्देश्यों के बारे में बताया। उसने दावा किया कि ए.एन.वी.सी. किसी गैर-कानूनी गतिविधि में शामिल नहीं है और इसके पास कोई हथियार नहीं है। उसके अनुसार कोयला क्षेत्र में की जा रही जबरन वसूली ए.एन.वी.सी. द्वारा नहीं बल्कि अन्य एजेंसियों द्वारा की जा रही है। उसने दावा किया कि जबरन वसूली, प्रताड़नाएं गारो हिल्स में व्यापार पर कब्जा, भय का वातावरण तैयार करना जैसे सभी आरोप गलत हैं तथा ए.एन.वी.सी. के सदस्य पदनामित कैम्पों में रहते थे जहां उनकी गतिविधियां सख्ती से विनियमित होती हैं। इसके सदस्यों के पास जो हथियार थे वे आत्मरक्षा के लिए थे और संयुक्त अभिरक्षा में रखे गए थे। उसने दावा किया कि ए.एन.वी.सी. उन गारो के लिए लड़ रही थी जिन्हें विकास और अधिकारों से भी वंचित रखा गया। शिक्षा के मामले में गारो लोग अन्य दो जनजातियों से काफी पीछे हैं।

125. उसने मुख्य परीक्षक के सामने साक्ष्य दिया कि ए.एन.वी.सी. ने 2004 में हथियार डाल दिए थे और यदि उसकी गतिविधियों पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया जाता है तो उसकी मंशा चुनकर लड़ने की है। आर. डब्ल्यू.-5 के अनुसार ए.एन.वी.सी. की बैठकें पदनामित कैम्पों तथा यूथ होस्टल में होती हैं। उसने साक्ष्य दिया कि महिन्द्रा फाईनंस कंपनी ने गारो हिल्स में उन चूककर्ताओं के वाहनों को जब्त करने के लिए रिकवरी एजेंट के रूप में कार्य करने की बात की थी जो वाहनों हेतु लिए गए अग्रिम को वापिस नहीं कर रहे हैं। प्रति परीक्षा में उसने कहा कि ए.एन.वी.सी. का लिखित संविधान नहीं है परंतु उसने स्वीकार किया कि इसकी संरचना में अध्यक्ष, संयुक्त सचिव, प्रचार सचिव आदि जैसे विभिन्न पदनाम हैं। उसने बताया कि ए.एन.वी.सी. के केडर को आर्मी के रूप में जाना जाता है। गवाह ने अनेक मामलों में ए.एन.वी.सी. की सलिप्तता के बारे में अनभिज्ञता जाहिर की है किन्तु यह बताया है कि वह भगौड़ों से अवगत है। तीन भगौड़े कैम्प छोड़कर चले गए थे क्योंकि वे स्थापित नियमों का अनुपालन नहीं कर सकते थे। उसने स्वीकार किया कि उसको ईसाई नाम बनाई मराक है। उसने स्वीकार किया कि रि-भोई जिले में महिन्द्रा फाईनंस द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में उसे अग्रिम जमानत मिल गई थी।

126. प्रति परीक्षा में आर. डब्ल्यू.-5 ने ऑफेशन स्थापित करने संबंधी सरकारी समझौते के अंतर्गत स्थापित नियमों का ए.एन.वी.सी. द्वारा उल्लंघन किए जाने का खंडन किया। उसने यह भी स्वीकार किया कि ए.एन.वी.सी. गणतंत्र दिवस, स्वातंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्वों में भाग नहीं लेता है और यह कोई जनसभा या सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं करता है। उसने स्वीकार किया कि जे.बी. ग्रेगिन, ए.एन.वी.सी. का संयुक्त सचिव है। उसने उल्लेख किया कि कलेंडर तथा टेबल डायरी के अलावा संयुक्त मॉनीटरिंग पुस्तक को भेजे गए

दस्तावेजों को छोड़कर कोई अन्य लिखित रिकार्ड विद्यमान नहीं है। उसके अनुसार ए.एन.वी.सी. उसे प्राप्त धन या उसके द्वारा व्यय किए गए धन का कोई रिकार्ड नहीं रखता है। ए.एन.वी.सी. अपने सदस्यों के पास हथियारों के बारे में या उसके प्रयोग का भी कोई रिकार्ड नहीं रखता है। उसने बताया कि यद्यपि ए.एन.वी.सी. अपने पदाधिकारियों की पहचान का खुलासा नहीं करता है फिर भी लोग इससे अवगत हैं। उसने साक्ष्य दिया कि युद्धविराम के बाद ए.एन.वी.सी. के सदस्य गैर-कानूनी गतिविधियां नहीं करते हैं और अब वे कोई औपचारिक सैन्य पदनाम का प्रयोग नहीं करते हैं। उसने बताया कि जब कभी भी उन्हें किसी अन्य ग्रुप द्वारा की जा रही गैर-कानूनी गतिविधियों का पता चलता है तो पुलिस को इसकी सूचना देते हैं जो उनकी मदद भी करती है। उसने कहा कि लोगों को ए.एन.वी.सी. में शामिल होने के लिए कोई भी आमन्त्रित नहीं करता अपितु वे स्वयं इसमें शामिल होते हैं। उसने यह भी कहा ए.एन.वी.सी. के पदाधिकारी इकट्ठे नहीं होते और नेता को अध्यक्ष, जो संगठन के प्रमुख हैं, द्वारा मौखिक निर्देश दिए जाते हैं और ए.एन.वी.सी. के पदाधिकारी अध्यक्ष की सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही कोई कार्रवाई कर सकते हैं। गवाह को सी. डब्ल्यू-12/2 कैलेन्डर और सी. डब्ल्यू-12/3 टेबल कैलेन्डर दिखाया गया; उसने कहा कि ये कैलेन्डर ए.एन.वी.सी. के प्रचार सचिव द्वारा जारी किए गए थे। उसने कहा कि अधिकांश फोटोग्राफ युद्धविराम से पहले लिए गए थे। उसने इस बात से इन्कार किया कि सी. डब्ल्यू-12/4 और उसका अनुवाद सी. डब्ल्यू-12/5 ए.एन.वी.सी. द्वारा जारी किए गए थे।

127. सरकार की ओर से प्रस्तुत सारे साक्ष्य यह इंगित करते हैं कि ए.एन.वी.सी. या इसके सदस्य जबरन वसूली, अपहरण, फिरौती की कार्रवाईयों में संलिप्त हैं। सी. डब्ल्यू-10 से 16 और सी. डब्ल्यू-17 के अनुसार ए.एन.वी.सी. की गतिविधियां अधिकांशतः मेघालय के गारो हिल्स जिलों में हो रही थीं। सी. डब्ल्यू-7 में इसकी गतिविधियां दो अन्य जिलों में और खासी तथा जयन्तिया लोगों के बीच असन्तोष व्याप्त होने के बारे में भी कहा गया है। इन शपथ-पत्रों में लगाए गए आराधों, साक्ष्यों और प्रति-परीक्षा का सार निम्नानुसार है :-

1. वर्ष 2005 और 2007 के बीच 16 ऐसी घटनाएं हुईं जिनके बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। कुछ प्रथम सूचना रिपोर्टों की प्रतियां सी. डब्ल्यू-10 से सी. डब्ल्यू-16 पर रखे गए शपथ-पत्रों के साथ लगाई भी हैं।
2. इसमें कोई सन्देह नहीं कि न्यायाधिकरण की भूमिका न्यायनिर्णयक की है उस रूप में इसे दो विरोधाभासी कथनों की सम्भाव्यताओं का आकलन करना होता है। यहां पर सी. डब्ल्यू-6, से सी. डब्ल्यू-10 से सी. डब्ल्यू-16 और सी. डब्ल्यू-17 के माध्यम से भी राज्य की ओर से यह कहा गया है कि बड़ी संख्या में घटनाएं

सूचित की गई हैं और प्रथम सूचना रिपोर्टें दर्ज की गई हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उन प्रथम सूचना रिपोर्टों की मूल प्रतियां प्रस्तुत नहीं की गई हैं तथापि, शपथ-पत्रों के साथ प्रस्तुत अधिकांश प्रतियां, सत्यापित प्रतियों की छायाप्रतियां हैं। ए.एन.वी.सी. ने गवाह की प्रति-परीक्षा का पूर्ण अवसर लिया है। गहनता से की गई प्रति-परीक्षा के दौरान किसी भी समय ऐसी कोई आपत्ति नहीं उठाई गई कि ऐसे दस्तावेजों की प्रतियों को मूल प्रतियों के अभाव में साक्ष्य के रूप में चिह्नित नहीं किया जा सका; दूसरा यह कि अधिवक्ता ने भी सम्बन्धित गवाह से विशिष्ट रूप से ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा कि वे दस्तावेज असली नहीं थे और मूल प्रतियां नहीं हैं। इस प्रकार की घटनाएं नहीं हुई हैं, इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछने का कोई सुझाव नहीं दिया गया है।

कार्यवाही की प्रकृति न्यायनिर्णयन की है तथापि संहिता के तहत प्रक्रियात्मक रूप से जांच के रूप में है, को ध्यान में रखते हुए न्यायधिकरण द्वारा दिया जाने वाला निष्कर्ष अनिवार्यतः सम्भाव्यताओं पर ही आधारित होगा। अतः उपर्युक्त चर्चा के परिप्रेक्ष्य में यह निष्कर्ष निकलना स्वाभाविक है कि प्रथम सूचना रिपोर्टों की प्रतियों पर विचार किया जाए। उनसे निम्नलिखित बातों का पता चलता है :-

1. ए.के. श्रेणी, 9 एम.एम. पिस्टलों, मैगजीनों, हथगोलों सहित हथियारों की बरामदगी;
2. हमले और हत्याएं, (विलियमनगर पुलिस स्टेशन मामले सं. 52 (11) 2006, विलियमनगर पुलिस स्टेशन मामले सं. 56 (12) 2006, 57 (12) 2006, 58 (12) 2006, 59 (12) 2006 तथा 60 (12) 2006 और तूरा पुलिस स्टेशन मामले सं. 39(4) 2006 तथा दिनांक 29-1-2006 और दिनांक 2-7-2006 के बीच विभिन्न तारीखों के मामले);
3. सशस्त्र बलों के कार्मिकों पर गोलीबारी (शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1) (क) के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 307/326 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 20(5)/2005) जिसके कारण पिस्टल और गोला-बारूद की बरामदगी की गई;
4. लोगों और व्यापारी वर्ग को डराना-धमकाना और मुक्त व्यापार को निषिद्ध करना। इसमें डी.टी.एच. तकनीक को बेचने, सूखी मछली पर 5 रुपये प्रति किलो की दर से लगाए जाने वाले कर जैसे अवैध कर लगाने, अनाधिकृत और अवैध टोल/करों की वसूली करने, हाटों में बिक्री के अधिकारों को हथियाने, मेघालय के विभिन्न

जिलों में कोयला क्षेत्र के व्यापारियों को डराने-धमकाने इत्यादि पर प्रतिबन्ध लगाया जाना शामिल है।

5. राज्य और भारत सरकार के गवाहों ने समान रूप से कहा है कि ए.एन.वी.सी. के नेता बांग्लादेश में सुरक्षित रूप से छुपे हुए हैं। ए.एन.वी.सी. का कोई भी गवाह अपने नेताओं के पते ठिकाने को उजागर करने का इच्छुक नहीं था। यह भी रिकार्ड करने योग्य मामला है कि ए.एन.वी.सी. के सदस्यों की सूची जो केन्द्र सरकार और संयुक्त मॉनीटरिंग समूह को उपलब्ध कराई गई थी, में किसी नेता का उल्लेख नहीं किया गया है।
6. ए.एन.वी.सी. के सदस्य हथियारों के साथ चलते हैं। सी. डब्ल्यू-17 ने उल्लेख किया कि केवल 16 हथियार ही सुपुर्द किए गए थे। सी.डब्ल्यू-10 ने भी इसी प्रकार का बयान दिया है और यह कहा है कि सभी हथियार किसी एकान्त स्थान पर नहीं रखे गए थे अपितु उन्हें ए.एन.वी.सी. के सम्पर्क कार्यालय में रखा गया था।
7. ए.एन.वी.सी. के सदस्य अपनी गतिविधियों के लिए सेना जैसी वस्त्रियाँ और युद्ध के समय प्रयोग में आने वाले छाद्यावरणों का प्रयोग जारी रखे हुए हैं।
8. व्यापारी वर्ग को विशेषरूप से निशाना बनाना और जबरन वसूली, अपहरण इत्यादि में संलिप्त होना।

128. ए.एन.वी.सी. ने अपने गवाहों के साक्ष्यों के माध्यम से और जिरह के दौरान निरन्तर यह साबित करने का प्रयास किया कि चाहे पहले इसकी गतिविधियाँ जो भी रही हों परन्तु अब इसे विधि विरुद्ध घोषित करने का कोई नया आधार नहीं है। इसने इस बात पर जोर दिया कि जुलाई, 2004 के युद्ध विराम या स्थगन समझौते के बाद सब कुछ बबल गया है और यह कि स्थापित नियमों का समग्र और मुख्य रूप से अनुसरण किया जा रहा था। एक ठोस तर्क यह भी था कि केन्द्र सरकार ने समझौते की अवधि को जुलाई 2007 तक बढ़ा दिया है। सुनवाई के दौरान, यह सिद्ध करने का भरसक प्रयास किया गया कि संयुक्त मॉनीटरिंग समूह की प्रासंगिक बैठकों में, डराने धमकाने, विधि-विरुद्ध गतिविधियाँ चलाने या जबरन वसूली करने, हत्या करने इत्यादि जैसी किसी भी गम्भीर कृत्य को उजागर नहीं किया गया। इसका आशय यह था कि ऐसी गतिविधियों के उल्लेख के अभाव में राज्य और केन्द्र सरकार अब प्रतिबन्ध लगाए जाने के लिए नहीं कह सकते। दूसरे शब्दों में, जब शान्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का विवेकपूर्ण निर्णय लिया जाता है और समझौते की अवधि को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया जाता है तो संगठन को विधि-विरुद्ध घोषित करने का कोई औचित्य नहीं है। यह कहने का एक प्रयास किया गया कि यदि हिंसा या जबरन वसूली, लूटने इत्यादि के कृत्य होते हैं तो

उनके लिए ए.एन.वी.सी. को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि इसने अपने हथियारों का खुलासा कर दिया है और उन्हें सुपुर्द कर दिया है और इसके सदस्य पदनामित शिविरों में रह रहे हैं।

129. इसमें कोई सन्देह नहीं है कि केन्द्र सरकार ने अपनी दूरदर्शिता से युद्ध विराम या संचालनों के स्थगन के समझौते की अवधि को बढ़ा दिया है। फिर भी यह अपने आप में निर्णायक नहीं हो सकता; न्यायाधिकरण, उस निर्णय के आधार पर तथ्यात्मक रूप से इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता कि ए.एन.वी.सी. की गतिविधियाँ विधि-विरुद्ध नहीं हैं; और न ही प्रतिबन्ध हटाने का तर्क दिया जा सकता है चूँकि धारा 3(1) के अन्तर्गत जारी की जा चुकी अधि-सूचना की पुष्टि करने या उसे रद्द करने का निर्णय रिकार्ड पर रखे गए दस्तावेजों के आधार पर किया जाना होता है न कि राजनीतिक मानसिकता से लिए गए निर्णय के आधार पर, जैसा कि वस्तुतः संचालनों को स्थगित करने के समझौते में किया गया है। दूसरे शब्दों में, न्यायाधिकरण का कार्य, इसके समक्ष प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के आधार पर और संगठन, जो यह बताना चाहता है कि उसकी गतिविधियाँ विधिसंगत हैं न कि विधि-विरुद्ध, द्वारा की गई प्रतिक्रिया की जांच के माध्यम से, निष्पक्ष रूप से सम्पन्न किया जाना होता है।

130. आर.डब्ल्यू-4, सी.डब्ल्यू-17 और सी. डब्ल्यू-10 के साक्ष्यों के सावधानीपूर्वक विश्लेषण से यह प्रकट होता है कि ए.एन.वी.सी. संयुक्त मॉनीटरिंग समूह को अपने सदस्यों की अलग-अलग सूची प्रस्तुत करती रही है। हालाँकि, विश्वास पैदा करने और युद्ध विराम की अवधि को बढ़ाए जाने से हुई प्रगति के बारे में एक स्पष्टीकरण दिया गया है परन्तु यह तथ्य शेष रह जाता है कि ऐसे मूलभूत विवरणों में असमानता के साथ-साथ शिविरों (ए.एन.वी.सी. के गवाह ने दावा किया है कि जो लोग शिविर छोड़ चुके हैं उन पर ए.एन.वी.सी. का कोई नियन्त्रण नहीं है) से जाने वालों का अनुपात यह दर्शाता है कि समझौते के भाग के रूप में इसके कई सदस्य उन शिविरों को छोड़ चुके हैं, जहाँ उनके रहने की आशा की जाती थी। इसी प्रकार, इन गवाहों ने यह साक्ष्य दिया कि सभी हथियार कभी भी संयुक्त अभिरक्षा में, किसी एकान्त स्थान पर नहीं रखे गए अपितु इन्हें ए.एन.वी.सी. के तुरा स्थित सम्पर्क कार्यालय में ए.एन.वी.सी. के नियन्त्रण में ही रखा गया। इसके अतिरिक्त, केवल 16 हथियार ही सुपुर्द किए गए। इससे यह दावा गलत सिद्ध होता है कि ए.एन.वी.सी. ने हमेशा स्थापित नियमों का अक्षरशः अनुपालन किया है। इससे, सरकार के इस कथन में भी विश्वास और दृढ़ हो जाता है कि ऐसे सदस्य आजाद घूमते रहते हैं और अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित हैं।

131. इन कार्रवाईयों में यथाप्रदर्शित के अनुसार ए.एन.वी.सी. संगठन की एक विस्मयकारी तस्वीर उभरती है। इस संगठन की ओर से पेश किए गए गवाहों के अनुसार इसका कोई लिखित संविधान नहीं है परन्तु यह संगठन शान्तिपूर्ण ढंग से गारोलैंड राज्य के गठन की

वकालत कर रहा है। यदि इसका वास्तविक उद्देश्य यही है तो इसके नेता को खुलकर सामने आने और केन्द्र तथा राज्य सरकारों के साथ बात करने से कोई नहीं रोकता है। इसकी बजाए, ए.एन.वी.सी. का गुप्त व्यवहार अधिक सन्देशास्पद है; यह संगठन पूर्व सूचना दिए बिना चेराम में बैठकें आयोजित करता है; इसके पदाधिकारी, इसके अध्यक्ष दिलाश मारक द्वारा चुने जाते हैं, जो कहीं दूर रहता है और अपने पता-ठिकाना नहीं बताता। हालाँकि यह संगठन दावा करता है कि यह अनेकों गारों लोग उसके अनुयायी है परन्तु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह एक गैर-पंजीकृत संगठन है; यह पर्याप्त निधियाँ और धन प्राप्त करता है परन्तु इसने एक भी बैंक खाता नहीं खोल रखा। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रदर्श सी.डब्ल्यू.-12/2 और 12/3 इसी संगठन द्वारा प्रकाशित किए गए हैं; ये प्रदर्श वर्ष 2007 के कैलेंडर हैं; इनमें से एक में, भगोड़े के रूप में स्पष्ट उल्लिखित सदस्यों सहित अनेक कैडर सदस्यों की तस्वीरें और फोटोग्राफ्स हैं। कई तस्वीरों में सदस्यों को युद्ध की वर्दी में दिखाया गया है मानो वे नियमित सेना के सदस्य हों; उन्हें हथियार उठाए हुए और सक्रिय प्रशिक्षण में दिखाया गया है। आर.डब्ल्यू.-5, जिसने यह स्वीकार किया था कि ये कैलेंडर वास्तव में 2007 के लिए प्रकाशित किए गए हैं, द्वारा वर्ष 2004 में लिए गए फोटोग्राफ्स के बारे में कहा कि ये फोटोग्राफ्स नकली हैं क्योंकि युद्ध विराम समझौते से पहले, “भगोड़े” शब्द के विशेष उल्लेख का कोई अर्थ नहीं है। वस्तुतः आर.डब्ल्यू.-5 ने सी. डब्ल्यू.-17 को जोड़ने का समर्थन किया है और केन्द्र सरकार की ओर से यह तर्क दिया है कि ए.एन.वी.सी. की एक सेना है जिसके नेता को कमान्डर-इन-चीफ कहा जाता है और इसके सदस्यों के सेना जैसे पदनाम हैं। वास्तव में, आर.डब्ल्यू.-4 के साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत की गई सूची से भी यह प्रकट होता है।

132. अत्याधुनिक और प्रतिबंधित हथियार रखने का मामला, जो कि समुचित हस्तक्षेप का मामला बनता है, मेघालय राज्य और भारत संघ के गवाहों द्वारा कही गई विभिन्न बातों के साथ-साथ सी.डब्ल्यू.-10 और सी.डब्ल्यू.-17 के इस अकादमिक साक्ष्य मिलता है कि केवल 16 हथियार ही सुपुर्द किए गए थे जबकि अन्य हथियारों को ए.एन.वी.सी. के नियन्त्रण में रखा गया, इसके साथ-साथ स्वीकार न करने योग्य अप्रत्यक्ष रूप से दिए गए इस स्पष्टीकरण कि वे आत्मरक्षा के उद्देश्य से प्रयोग करते हैं, पुनः यह दर्शाता है कि ए.एन.वी.सी. के सदस्य कानून से परे हैं और वे हथियारों से सुसज्जित हो रहे हैं। इसका कोई कारण नजर नहीं आता है कि कोई केवल मात्र आत्मरक्षा के लिए ऐसे प्रतिबंधित हथियार रखे। हथियारों की किस्में, अर्थात् एस.एल.आर., ए.के.-47 बन्दूकें, राईफलें, 9 एम.एम. चार्जनीज पिस्टल, हथगोले, सक्रिय गोलाबारूद ए.एन.वी.सी. के शान्तिपूर्ण उद्देश्य को गलत साबित करती हैं; वे अहिंसा द्वारा गारोलैण्ड प्राप्त करने के अपने शान्तिपूर्ण उद्देश्य के विरोधाभासी हैं।

133. सी.डब्ल्यू.-13 ने ए.एन.वी.सी. के सदस्यों के बारे में बताया, जिनकी अनेकों पहचान हैं; उनमें से कुछ व्यक्तियों, जिनकी कार्यवाही में उल्लिखित प्रथम सूचना रिपोर्ट में कई नाम थे; वास्तव में आर.डब्ल्यू.-5 का भी एक और नाम था। इससे यह पता चलता है

कि भगोड़े या संगठन से निकाले गए व्यक्ति संगठन से बाहर रहकर, चोरी-छुपे अथवा छद्मवरण युक्त होकर संगठन के लिए कार्य कर रहे हैं, यह सच्चाई है और इसे नकारा नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त, अलग-अलग समय पर सदस्यों की अलग-अलग सूचियाँ दिखाई गई हैं और हथियारों या उन सदस्यों जो तीन पदनामित शिविरों में नहीं ठहरते हैं, की पूरी सूची प्रस्तुत करने में हुई देरी यह दर्शाती है कि ए.एन.वी.सी. या तो जानबूझ कर स्थापित नियमों का अनुपालन नहीं कर रहा, जिससे इस मत को बल मिलता है कि यह संगठन निरन्तर पुनर्गठित होता रहता है, अथवा यह कि यह संगठन अपने सदस्यों पर नियन्त्रण करने में विफल है और अराजक है। यह संगठन, हर रूप में, शान्ति और सुरक्षा के लिए खतरा है और इस प्रकार से क्षेत्रीय अखंडता को छिन्न-भिन्न कर रहा है।

134. उपर्युक्त चर्चा के परिप्रेक्ष्य में और इसके समक्ष प्रस्तुत किए गए सारे दस्तावेजों, साक्ष्यों और पक्षों की ओर से प्रस्तुत वादों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त न्यायाधिकरण का यह मत है कि ए.एन.वी.सी., विधि-विरुद्ध गतिविधियाँ चला रहा है, जिनका उद्देश्य, शान्तिपूर्ण ढंग से गारों राज्य के संगठन के घोषित प्रत्यक्ष उद्देश्य की बजाए, भारत की क्षेत्रीय अखंडता को नुकसान पहुँचाना और उसे छिन्न-भिन्न करना है। इसने हिंसा नहीं छोड़ी है और अपनी उन कार्यवाहियों में संलिप्त है जो विध्यवसंकारी, विनाशक और विघटनकारी हैं अथवा इसे भारत की क्षेत्रीय अखंडता को छिन्न-भिन्न करने के आशय से किया जाता है। अतः न्यायाधिकरण का यह मत है कि यह एक विधि-विरुद्ध संगठन है और जहाँ तक इसे धारा 3 (1) के अन्तर्गत घोषित करने का सम्बन्ध है, इसकी पुष्टि की जाती है।

न्यायाधिकरण का आदेश

उपर्युक्त चर्चा और निष्कर्षों के परिप्रेक्ष्य में, यह न्यायाधिकरण, विधि-विरुद्ध गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4 (3) के अनुसरण में, विधि-विरुद्ध गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम, 1976 की धारा 3 (1) के उपबन्धों के तहत, अधिक नेशनल वालन्टियर काउंसिल ऑफ मेघालय और हैन्द्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल ऑफ मेघालय को विधि-विरुद्ध संगठन घोषित करने के सम्बन्ध में, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 16-11-2006 को जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1974(अ) की एतद्द्वारा पुष्टि करता है।

नई दिल्ली

दिनांक 14 मई, 2007

(एस. रवीन्द्र भट्ट)

न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय, पीठासीन अधिकारी, विधि-विरुद्ध गतिविधियाँ (निवारण) न्यायाधिकरण

[फा.सं. 11011/49/2006-एन.ई.-III]

नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 2007

S.O. 789 (E).— In terms of Section 4 (4) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the order, dated 14-5-2007, of the Tribunal presided over by Hon'ble Justice Raviandra Bhat, Judge, Delhi High Court, to whom a reference was made under Section 4(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the associations, namely the Achik National Volunteer Council (ANVC) and the Hynniewtre National Liberation Council (HNLC) organizations of Meghalaya as unlawful is published for general information :

REPORT OF THE UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) TRIBUNAL CONSISTING OF HON'BLE MR. JUSTICE S. RAVINDRA BHAT, JUDGE, DELHI HIGH COURT, NEW DELHI.

Ref: Ministry of Home Affairs Notification No. S.O.1974(E)
New Delhi, dated 16TH NOVEMBER, 2006

1. By a Notification dated 16-11-2006, the Central Government declared that it was, inter alia, of the opinion that for the specified reasons the Achik National Volunteer Council (hereafter called "ANVC") and Hynniewtre National Liberation Council (hereinafter called "HNLC") and the other bodies set up by them, are unlawful associations. The Central Government was also of the opinion that the activities of the ANVC and the HNLC are detrimental to the sovereignty and integrity of India, and if these are not immediately curbed and controlled, they would regroup and rearm themselves, expand their cadres, procure sophisticated weapons, cause heavy loss of lives of civilians and Security Forces, and accelerate their anti-national activities. Accordingly, this tribunal was set up under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (hereafter "the Act").

2. This Tribunal, constituted in terms of Section 3 of that Act, received the reference on 19-12-2006. Exercising its powers under Section 4(2), the Tribunal issued notice to show cause to the Achik National Volunteer Council (hereafter called "ANVC") and Hynniewtre National Liberation Council (hereinafter called "HNLC"), returnable on 12-2-2007. The Central Government was directed to serve notices upon those organizations at their addresses and also publish the notice in national and vernacular publications and newspapers with wide circulation in the area. The Central Government was directed to additionally give appropriate publicity in the electronic media. The Director, Ministry of Home Affairs, Central Government filed an affidavit indicating compliance with regard to the service of its notices and its publication for both ANVC and HNLC. According to the affidavit, notices were served through publication in four different newspapers including local vernacular newspaper on 30-12-2006 and 4-1-2007.

Notices were also broadcasted by All India Radio on three successive dates i.e. 29th, 30th and 31st December, 2006 in different languages i.e. Khasi, Garo, Jaintia and English. The notices were also fixed on the notice board of the Deputy Commissioners Offices in all the Districts of Meghalaya. The Court took on record the compliance report filed by Registrar to the Tribunal, evidencing that the notice was served and published in the different modes on 12-2-2007. On the same date, the ANVC entered appearance before the Tribunal through its counsel.

3. The Tribunal had required the various parties to file their affidavits and documents. The ANVC filed its objections; however, there was no objection or representation on behalf of the HNLC. These facts were noticed in the proceedings on 28th March, 2007 and counsel for Central Government sought time for filing affidavit. The State of Meghalaya had filed affidavits. The matter was thereafter fixed for further proceedings at Shillong on 12th, 13th and 14th April, 2007. By then, the State of Meghalaya and the Central Government had placed their affidavits, on record.

4. After the sittings in New Delhi on 28th, 29th March, 2007, and 2nd April, 2007, the Tribunal held sittings at Shillong, on 12th, 13th and 14th April, 2007, to facilitate recording of evidence of witnesses. Due publicity was given in "*Shillong Times*" and the local language newspapers; copies of those newspaper clippings are part of the record. Depositions of witnesses on behalf of the State of Meghalaya i.e. CW-1 to CW-16 and the depositions of some witnesses of objector, ANVC, namely, RW-1 to RW-3 were recorded at Shillong between 12th April, 2007 to 14th April, 2007. Affidavits of these witnesses were tendered during the proceedings at Shillong. The Tribunal recorded the evidence on behalf of the Central Government and the cross-examination of its witnesses on 19th April, 2007 in New Delhi. The further evidence on behalf of the ANVC i.e. RW-4 and RW-5 were recorded on 20th and 23rd April, 2007. The evidence and cross-examination of RW-5 was recorded on 24th, 25th and 26th April, 2007.

5. The matter was listed for final hearing on behalf of the interested parties at Shillong on two days i.e. 6th May, 2007 and 7th May, 2007. Arguments were concluded on 9th May, 2007, at New Delhi. The ANVC was represented; throughout the proceedings, HNLC did not chose to present itself before the tribunal.

The reference from the Central Government

6. The reference received from the Central Government reads as follows :

"GAZETTE NOTIFICATION

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, 16th November, 2006

S.O. 1974(E).—Whereas the Achik National Volunteer Council (hereinafter referred to as the "ANVC")

of Meghalaya have continued collection of funds and extortion despite having agreed to adjure violence and having expressed their willingness to hold talks within the framework of the Constitution of India for fulfilling their demands;

And whereas, the Central Government is of the opinion that the Hynniewtre National Liberation Council (hereinafter referred to as the HNLC) of Meghalaya have been openly declaring as their objective the secession of the State of Meghalaya from Indian Union.

And whereas, the Central Government is further of the opinion that both ANVC and HNLC have been,—

- (i) indulging in acts of intimidation, extortion and looting of civilian population for collection of funds for their organization;
- (ii) maintaining links with the other insurgent groups of the North Eastern Region for carrying out acts of extortion and intimidation;
- (iii) maintaining camps in some neighbouring countries for the purpose of sanctuary and training of their cadres. And whereas the Central Government is also of the opinion that—
 - (i) the ANVC was involved in twenty four violent incidents in 2004, six violent incidents in 2005 and one violent incident in 2006 (upto 31st August, 2006);
 - (ii) These violent incidents by ANVC resulted in killing of 12 persons (including 4 Security Forces) in 2004 and one person in 2005;
 - (iii) the HNLC was involved in one violent incident in 2004, four violent incidents in 2005 and two violent incidents in 2006 (upto 31st August, 2006);

And whereas, the Central Government is also of the opinion that for the reasons aforesaid, the ANVC and the HNLC and other bodies set up by them, are unlawful associations;

And whereas, the Central Government is also of the opinion that the aforesaid activities of the ANVC and the HNLC are detrimental to the sovereignty and integrity of India, and if these are not immediately curbed and controlled, the said ANVC and the HNLC would regroup and rearm themselves, expand their cadres, procure sophisticated weapons, cause heavy loss of lives of civilians and Security Forces, and accelerate their anti-national activities;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the Achik National Volunteer Council (ANVC) and the Hynniewtre National Liberation Council

(HNLC) alongwith all their factions, wings and front organizations as unlawful associations;

The Central Government is of further opinion that it is necessary to declare the ANVC and the HNLC alongwith all their factions, wings and front organizations as unlawful with immediate effect and accordingly, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3, the Central Government hereby directs that this notification shall, subject to any order that may be made under Section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 11011/49/2006-NE. III]

NAVEEN VERMA, Jr. Secy."

The brief resume forwarded along with the reference reads as follows :

"A BRIEF RESUME REGARDING THE AIMS/OBJECTIVES AND VIOLENT ACTIVITIES OF ACHIK NATIONAL VOLUNTEER COUNCIL (ANVC) AND HYNNEWTRSEP NATIONAL LIBERATION COUNCIL (HNLC) FURNISHED TO THE TRIBUNAL CONSTITUTED UNDER SECTION 5 OF THE UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) ACT, 1967

1. The Achik National Volunteer (hereinafter referred to as the "ANVC") and the Hynniewtre National Liberation Council (Hereinafter referred to as the "HNLC") were declared as 'unlawful association' under the provisions of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 *vide* notification number S.O. 1974 (E) dated 16th November, 2006. Previously, a reference under sub-section (1) of Section 4 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was made to the Unlawful Activities (Prevention) Tribunal consisting of Hon'ble Justice Swatanter Kumar, Judge, Delhi High Court and the learned Tribunal *vide* its order dated 12-05-2005 had confirmed the Notification dated 16-11-2004 issued by the Government of India.

2. The ANVC was formed in December 1995 with the aim of, among other things, liberation of Garo Hills to achieve a new State of 'Achik Land' to prevent the influx of non-tribals and exploitation of Garos, to improve the living conditions and preserve the customs and traditions of Garos, to bring unity among the Garos and to strengthen Garo Hills Autonomous District Council under the Sixth Schedule of the Constitution. The outfit entered into an agreement for 'Suspension of Operation' with Government of India and Government of Meghalaya w.e.f. the 23rd July, 2004 initially for six months which has been extended periodically and is at present valid upto the 23rd July, 2007. With the signing of this Agreement, the outfit has agreed to abjure violence and has expressed its willingness to hold talks within the framework of Constitution of India for fulfilling their demands. Although law and order situation in Garo Hills of Meghalaya has improved significantly since

signing of this Agreement and the ANVC leadership in Meghalaya appears to be eager to have talks with Government, ANVC cadres continue to indulge in extortion and 'tax' collection. Self-styled Chairman Dilash Marak and Self-styled Commander-in-chief Jerome Momin of ANVC have not directly involved themselves in peace process. Dilash Marak continues to stay and do business in Bangladesh along with his supporters. ANVC is also reported to maintaining links with United Liberation Front of Assam (ULFA).

3. The HNLC was formed in 1992 with the aim of liberation of Hynniewtrep People from the authoritarian rule of the Indian Government, protect the Khasis and other Meghalaya tribes from exploitation, retain the indigenous culture and to eradicate social evils. It also vows to fight against any attempt to divide Khasi society. Though the HNLC has not resorted to any major violent activity in the recent past and the violence by the outfit had declined significantly since the year 2004, it continues to indulge in extortion, kidnappings and abductions, especially in the Shillong Valley. The outfit has also given threat to non-tribals to move out of the State. The HNLC is also maintaining links with National Democratic Front of Bodoland (NDFB) and National Socialist Council of Nagaland (Issac/Muviah) (NSCN IM). The nexus of HNLC with NDFB expertise in carrying out explosions. The HNLC has been regularly giving calls for boycott of the Republic Day and Independence Day. It has also been asking people to observe Bandh on these days to mark protest against National days.

4. The area of influence of ANVC is spread over three districts of Garo Hills and coal belt areas of West Khasi Hills District. Its present strength is estimated at 250, out of which 150 are lodged in Tura, West Garo Hills District and two designated camps at Samanda and Jetra in East Garo Hills District and South Garo Hills District respectively. The total weaponry of the outfit is estimated at 150 including 50-60 AK series rifles, 3 Light Machine guns, 5 Stenguns, 50 Pistols/Revolvers, 35 Rifles and 25 Shot guns, besides 200 grenades.

3.2 The HNLC is primarily operating in Khasi Hills of Meghalaya. It also maintains some camps in Bangladesh. The cadre of HNLC estimated at 100. The total weaponry of the outfit at present is estimated at 75 including around 30 AK series rifles, 2 Light Machine guns, 20 Carbines and Stenguns and 20 Rifles, besides around 80 hand grenades.

4. VIOLENCE PROFILE

4.1 During 2004, 2005 and 2006 (upto 31-8-06), the ANVC was involved in twenty four, six and one violent incidents. These violent incidents by ANVC resulted in killing of 12 persons (including 4 Security Forces) and 1 persons in the year 2004 and 2005 respectively. In the years 2004, 2005 and 2006 (upto 31/8/06), the HNLC was involved in one, four and two violent incidents respectively. In these incidents no one was killed.

5. JUSTIFICATION FOR CONTINUATION OF DECLARATION OF ANVC AND HNLC AS 'UNLAWFUL ASSOCIATION'

5.1 The background of activities of the ANVC and the HNLC as given in preceding paragraphs, the proposal for declaration of ANVC and HNLC as 'unlawful association' under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for a period of two years beyond 15th November, 2006 so that these two outfits do not get opportunity to rejuvenate themselves is being proposed :

- (i) Continued extortion and collection of taxes from businessmen of Meghalaya by ANVC despite the outfit having agreed to abjure violence and having expressed their willingness to hold talks within the framework of Constitution of India for fulfilling their demands;
- (ii) Openly declared objective of HNLC for secession of Meghalaya from India;
- (iii) Continued intimidation and extortion of civilian population by HNLC for collection of funds for their organization;
- (iv) Maintaining links with other insurgent groups of the North Eastern Region by both HNLC and ANVC for carrying out acts of extortion and intimidation;
- (v) Maintenance of camps by both ANVC and HNLC in Bangladesh for the purpose of sanctuary and training of their cadres.

5.2 Under the proviso to sub-section (3) Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, if the Central Government is of the opinion that circumstances exist which render it necessary to extend the notification declaring these associations as 'unlawful', it may direct for reasons to be stated in writing that the notification shall have effect from the date of its publication in the Official Gazette. The activities of the ANVC and the HNLC are continuing and it is felt that if there is any delay in extension of the notification, these organizations may take undue advantage of the situation and mobilize their cadres for escalating secessionist, subversive and violent activities. It may also provide an opportunity to the leadership of these organizations to openly propagate anti-national activities in collusion with foreign powers inimical to India's security concerns. The Police and the Security Forces in such an eventuality will find it difficult to detain and prosecute those militants apprehended by them. It is, therefore, considered necessary to extend the notification banning them for a further period of two years from the date of its publication in the Official Gazette. Accordingly a Notification S.O. 1974(E) was issued by the Ministry of Home Affairs on 16th November, 2006 declaring ANVC and HNLC along with their factions, wings and front organizations as 'unlawful associations'.

Relevant provisions of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967

7. The Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (hereafter called "the Act") defines, through Sections 2(o) and 2(p) as to what are "Unlawful Associations" and "Unlawful Activities". "Unlawful activity" has been defined as follows :

"2(0) "Unlawful activity", in relation to an individual or association, means any action taken by such individual or association (whether by committing an act or by words, either spoken or written, or by signs or by visible representation or otherwise),—

- (i) which is intended, or support any claim, to bring about, on any ground whatsoever, the cession of a part of the territory of India or the secession of a part of the territory of India from the Union, or which incites any individual or group of individuals to bring about such cessation or secession; or
- (ii) which disclaims, questions, disrupts or is intended to disrupt the sovereignty and territorial integrity of India; or
- (iii) which causes or is intended to cause disaffection against India;"

Unlawful association has been defined as follows :

"2(p) "unlawful association" means any association,—

- (i) which has for its object any unlawful activity, or which encourages or aids persons to undertake any unlawful activity, or of which the members undertake such activity; or
- (ii) which has for its object any activity which is punishable under section 153 A or Section 153 B of the Indian Penal Code (45 of 1860), or which encourages or aids persons to undertake any such activity; or of which the members undertake any such activity :

Provided that nothing contained in sub-clause (ii) shall apply to the state of Jammu and Kashmir;"

8. Section 3(1) of the Act empowers the Central Government, if it is of the opinion that any association is or has become an unlawful association, declare it to be unlawful through Notification in the Official Gazette. The Central Government, has to specify the grounds why the Association is unlawful Section 3(2). Section 3(3) indicates that a Notification issued under Section 3(1) would not have effect until the Tribunal constituted under Section 5, confirms the declaration and the order is published in the Official Gazette. The proviso to Section 3(3) enacts that the Central Government, if it is of the opinion that circumstances exists which render it necessary to declare

an association to be unlawful with immediate effect, it may, for reasons, to be stated in writing that the Notification shall, subject to any order which may be made under Section 4, have the effect from the date of its publication in the Official Gazette.

9. The Central Government, simultaneous by with issuance of the Notification under Section 3 (1) has to refer the Notification to the Tribunal for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the association as unlawful. The Tribunal, constituted under the Act, is required to be comprised of a High Court Judge, according to the mandate of Section 5. According to the provisions of Section 4 (3) the Tribunal has to hold an inquiry, and decide whether or not there is cause for declaring the association concerned to be unlawful and make a report as expeditiously as possible and in any case within six months from the date of issue of the Notification under Section 3(1). The Tribunal can either confirm the declaration under Section 3(1) or cancel the declaration. Section 9 of the Act indicates that subject to rules framed under the Act, the procedure to be followed by the Tribunal shall be as so far as made the procedure laid down by the Code of Civil Procedure, 1908 for the investigation of claims.

Evidence and Materials concerning HNLC

10. The State of Meghalaya produced Affidavits of 9 witnesses besides documentary evidence. The 9 deponents were also examined before the Tribunal in support of the Notification issued by the Central Government under Section 3 (1) concerning, the declaration that HNLC is an unlawful association. This evidence is supportive of the Central Government's evidence in that regard. The Central Government relied upon the deposition of CW-17, Sh. R. R. Jha, Director, North East, Ministry of Home Affairs.

11. CW-1, Shri. Fredrick Roy Kharkongor, Deputy Commissioner, Jaintia Hills District and working as such since 10-5-2005, exhibited the affidavit executed by him on 17-3-2007, as CW-1/1. He deposed that the HNLC was actively operating in Jaintia Hills District; members of HNLC in the district were indulging in unlawful activities, in spite of ban imposed by previous Notifications. The top ranking leaders of HNLC are in hiding in Bangladesh and running their activities from across the border. This includes intimidation and kidnapping against the public at large and also, particularly, directed against the business community. He further deposed that due to fear psychosis victim do not report cases. The witness further stated that HNLC has relationship and links with other banned groups of North Eastern States like the National Socialist Council of Nagaland (NSCN(IM), National Democratic Front of Bodoland (NDFB) etc. The witness deposed that the ban has to a certain extent helped in curbing the activities of HNLC.

12. The second witness to depose was CW-2 Shri Heimonlang Nongphuh Superintendent of Police, Jaintia Hills District, Jowai; he identified his signatures on the affidavit, tendered on record as EX.CW-2/1 dated 17-3-2007. He mentioned about an incident of 25th January, 2005 when Rs. 93 lakhs was looted involving HNLC cadres from Apex Bank, Khliehriat and lodging of a P.S. Case No. 7(1)05 Under Sections 395/397 IPC. He deposed about a incident on 25th March, 2005 where one Mon Bah Pradhan was kidnapped from Umlawang War Passah Coal Quarry and was released after ransom money was paid to HNLC. He produced a copy of the FIR being P.S. Case No. 24(3)05 U/S 364/34 IPC. The witness further deposed about an incident of kidnapping of one Raju Sharma on 25th May, 2005. This led to lodging of an FIR, Jowai P.S. Case No. 65(5)05 U/S 448/364/326/34 IPC. According to the witness since ransom money was not paid, the kidnapped person was killed. The witness further mentioned about arrest on 8-1-2006, of one Bashembha Pathaw @ Commando @ Bahduh @ Bahnah Pathaw from Moolber and recovery of 10 Chinese made AK-47 live ammunition. Apparently, he was found to be involved in 4 other cases concerning various cases under IPC as well as the Arms Act. The witness further deposed about surrender of six HNLC cadres in Jaintia Hills Districts during 2005-2006 i.e. Pherlok Syngkrem @ Pher on 10-5-2005 at Jowai P.S. without arms; Tarson Lymba surrendered at P.S. Dawki P.S. on 10-5-2005, Hopeborn Shangpliang @ Bahrit on 20.1.2006 before Jowai P.S. with one Chinese made 9mm pistol, two magazines and 10 rounds of ammunitions; Hambad Biam on 4-2-2006 at Jowai P.S. with one country made revolver; Nilan Sten on 4-2-2006 at Jowai P.S. along with one country made revolver and Diamsalon Manner on 16-7-2006 at Jowai P.S. without any weapon.

13. The witness deposed that HNLC and ANVC operate in the district but HNLC is more active. He alleges that NSCN(IM), the main supporter of the unlawful organizations is based in Bangladesh and it supplies arms and ammunition to train the cadres whose basic objective is to threaten the sovereignty and integrity of India and seek an independent state. Copies of a letter from the Meghalaya Co-operative Apex Bank Ltd and copy of an order dated 20-3-2006 directing the Preventive Detention of Bashembha Pathaw under the Meghalaya Preventive Detention Act, 1995, were exhibited as part of his affidavit.

14. The CW-3, Sh. Bhalang Dhar, Deputy Commissioner, East Khasi Hills District deposed next. He tendered his affidavit dated 17th March, 2007 as Ex. CW-3/1. In the affidavit he reiterated the nature of the activities of HNLC to be much the same as was deposed to by CW-1 and CW-2. He further stated that HNLC is active in the East Khasi Hills District and its top ranking leaders are hiding in Bangladesh. According to him, HNLC has established good relationship with other banned, insurgent groups like United Liberation Front of Assam (ULFA), National Democratic Front of Bodoland (NDFB),

NLFT, NSCN etc. The witness, in his deposition recorded by the Tribunal spoke about fear psychosis among the people and that HNLC was indulging in illegal arms activities, extortion, kidnapping and in one case, killing. The witness also stated the main target of the HNLC is the business community of the district. He reiterated about the links of HNLC with other banned organizations.

15. Sh. Addison Roy Mawthoh, Superintendent of Police, East Khasi Hills District deposed as CW -4. He exhibited the affidavit executed by him on 17th March, 2007 as CW -4/1. This witness mentioned details of several incidents. He mentioned about kidnapping of one Manik Dey on 9-7-2005 his being kept in Tyllaw village under Mawsynram Police Station and raiding of house at Lawbah village on 10-7-2005 for rescue of the victim, firing by HNLC militants, exchange of cross fire and death of one cadre. He deposed that another cadre member escaped even though the kidnapped person was rescued. He mentioned about Mawsynram Police Station Case No. 12(07) of 2005 and placed a copy of that First Information Report on the record of the Tribunal. The witness stated that recoveries of weapons such as revolver, three rounds of 9 mm live ammunition, one hand grenade of Chinese make, DBBL gun (modified), a Rifle Barrel No. 405WCF and a Stainless Steel Draggar were made. The witness also deposed that HNLC had given a call for 24 hours Bandh on 14-8-2005 and also on 15-8-2005 asking the people not to participate in celebrations of the Independence Day. Copies of the news reports were also filed. The witness mentioned about an incident dated 22-9-2005 where one Pratul Chandra Deka received a note demanding Rs. 3 lakhs along with a bullet leading to ambush somewhere at Barik and an arrest of HNLC cadre named Peaceful Ricky Sohtun. This led to filing of FIR being P.S. Laban Case No. 53(09) of 2005 under Sections 384/506/34 IPC and filing of a charge sheet on 28-11-2005. A copy of the charge sheet has been produced on the record. Similarly he mentioned about an incident of 23-12-2005 involving one Teilang Thangkhiew and his arrest, recovery of one 9 mm pistol with magazine loaded with 7 rounds of ammunition, leading to registration of the Rynjah Police Station Case No. 75(12) of 2005 for offences under Sections 121 (A)/120 IPC, Sections 25(1A) of the Arms Act and Sections 10/13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act. This led to filing of charge sheet on 6-7-2006. A copy of that charge sheet had been produced on the record of the Tribunal. The witness further deposed about a Bandh call for boycott of Republic Day celebration for 24 hours from 25-1-2006 to 26-1-2006, given by HNLC. He deposed that on 14-2-2006 HNLC in a press release stated that it would not accept the Constitution of India. According to the witness, on 26-3-2006 one Aibor Marwein of Mawlai, Shillong was shot dead by suspected HNLC cadre. It led to registration of Police Case No. 16(3)/06 under Section 302 IPC and Sections 25 (1A)/27(2) Arms Act. A copy of that FIR had

been produced on the file of the Tribunal. It was stated that HNLC had issued a press release stating that it would continue with its armed struggle and that it had on 1-6-2006 issued warning through a press release that it would take deterrent action against any person participating in the election to the Shillong Municipality. The witness deposed that on 6-7-2006 the police arrested from the Hill Star Hotel, Police Bazar, Shillong, one HNLC cadre named Kampher Frankly Syiem who had been working as a cook in the HNLC camp, and from his possession, some incriminating documents relating to the banned HNLC were recovered and seized, leading to the registration of the Shillong Sadar Police Station Case No. 128(07) of 2006 under Section 10/13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act 1967.

16. CW -4 deposed that on the eve of the Independence Day celebration of 2006, the HNLC gave a call for 24-hours bandh effective from 6 PM on 14-8-2006 to 6.00 P.M. on 15-8-2006, to protest against the celebrations of the Indian Independence Day in the Hynniewtrep land and asked the people not to participate in such celebrations. This call given, resulted in the general people suffering from fear psychosis, as in turn the normal lives of the people during the celebration got disturbed. On 1-9-2006 an information was received by the police from Shri Rahul Jasararia of M/S. Radio Electrical, Mawkhair, Shillong, that on 29-8-2006, at about 3.30 PM, he received a telephonic call from one person who identified himself as an HNLC cadre, directing him to pay Rs. 10,00,000 (Rupees ten lakhs) by 5-9-2006, leading to the registration of the Lumdingiri Police Station Case No. 109(9) of 2006 under Section 384/511 IPC.

17. The witness deposed that a group of HNLC cadres were taking shelter in Umkrem village and therefore a raid was conducted on 20-9-2006 at about 5.00 AM by the Police in the village. In this operation, according to witness, an encounter took place due to firing from inside a house at the Police force. The Police retaliated in self defence and an encounter ensued. During the encounter, one of the cadre were killed and another, namely Shri Wanpysnshngain Dympep @ Bah Jop (19 years), of Mawlai Iewrynghep, Shillong, was arrested. Shri Westmorland Lamin (35 years), was also arrested for harbouring the HNLC militants. The HNLC cadre killed in the encounter was identified as Shri Bankit Khongjee @ Leit. He was earlier arrested on 27.9.2001 and 23.1.2002 for illegal arms possession. From the place of occurrence and from the possession of the militants arrested, the following seizures were made, namely:—

- (i) One number modified Stengun with magazine;
- (ii) One number carbine with magazine;
- (iii) Forty rounds of 9 mm live ammunition; and
- (iv) Eight numbers of empty cases of assorted ammunition.

Consequently the Pynursla Police Station Case No. 14(09) of 2006, under Section 353/307/120(B)/121/121(A)/123 IPC read with Section 25(l-a)(l-b)/27 Arms Act was registered.

18. CW-4 also mentioned that on 25.9.2006, at about 9.00 AM, the Police raided the house of one Shd Tom Jones Rynjah, a hardcore HNLC cadre at Mawlai Syllaikariah, Shillong, and arrested him. During the search in his residence, a demand note of the HNLC letter head addressed to Shri Bishan Nongrum, demanding Rs. 5,00,000 (Rupees five lakhs) was recovered, which led to registration of the Mawlai Police Station Case No. 44(9) of 2006 under Section 384/511 IPC read with Section 10/13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act. He stated that the HNLC is active in the East Khasi Hills District, which has a long international border line with Bangladesh, as the top cadres of HNLC are hiding in Bangladesh from where they operate their unlawful, nefarious and anti-national activities. The cadres of the organization are engaged in raising funds by issuing demand notes to members of the business community as per the instructions of their top leaders from across the international border. According to him, apart from the incidents mentioned specifically, there were at least 10 other un-reported incidents. People do not pursue and report all incidents due to fear psychosis. He stated that the illegal activities indulged in by the HNLC include extortion, kidnapping, murder and intimidation. He stated that the previous ban had led to curbing activities of HNLC to some extent.

19. The next witness examined by the Tribunal was CW-5, Freeman Kharlyhndoh, Deputy Commissioner, District West Khasi Hills. He identified and tendered his affidavit dated 17-3-2001 as Ex. CW-5/1. According to him, HNLC and ANVC are operational in West Khasi Hills and that they were reportedly keeping illegal arms and ammunitions in sizable quantity in various hide out to achieve the objective of subverting and disrupting of sovereignty and territorial integrity of India. It was also stated that members of both organizations collect funds illegally by use of threats which was continuing and that extortion of money from people including businessmen was still being carried on by ANVC and HNLC cadres. HNLC cadres are operating in Nongjri, Umbar, Nonghyllam, Pormawdar and Mawait areas. He reiterated the contents of his affidavit and also stated that the organizations are indulging in various illegal activities in coal rich areas and that the business community is the main target of the two organizations. The witness stated that cadres of both organizations take shelter outside India, in Bangladesh. According to him, the ban had resulted in effective control of the activities of the organizations. When cross examined, by counsel of ANVC, he admitted that he joined as Deputy Commissioner on 15th January, 2007.

20. CW -6, Dalton P. Marak, Superintendent of Police, West Khasi Hills District, Nongstoin deposed both in respect of ANVC and HNLC. He identified and tendered

his affidavit dated 17-3-2001 Ex. CW-6/1. The evidence as regards the ANVC was that its cadres were involved in six incidents leading to arrests. He mentioned about details of such incidents, and FIRs lodged. In his cross examination by counsel for ANVC, he admitted knowledge about the mechanism of joint monitoring group, under the ceasefire settlement, and denied that names of persons mentioned by him in the annexure to his affidavit were not ANVC members. He named three persons and said that according to their admission, they were ANVC members. As regards the HNLC, he alleged that it continues with its activity of arms struggle with a view to disrupt the sovereignty and territorial integrity of India and keeps sizable arms and ammunitions. He also stated that HNLC cadres operate in Nongjri, Umbar, Nonghyllam, Pormawdar and Mawait areas. He further stated that the two organizations extort money from the business class and indulge in dacoities, thefts, attack on police parties. HNLC has direct nexus and links with the NSCN(IM) and NLFT. Those organizations support HNLC by training the cadres and other support to it to undermine the security and peaceful living in the State. The witness in his deposition also mentioned about an incident where two cadre members died in an encounter and one was arrested in 2006. He deposed in support of two cases mentioned in a list filed along with his affidavit. The first case concerned an incident dated 22-6-2006 where HNLC cadres fired at the police party at Honghyllam village which led to exchange of fire and death of two unidentified HNLC's suspect cadres and escape of the rest. This incident led to recovery of one Carbine with six rounds of live ammunitions, one revolver with five rounds of .32 ammunitions and other incriminating documents. An FIR being Mawkyrwat PS Case No. 13(6)06 under Sections 333/307/353 IPC read with Sections 10/13 UA(P) Act and Section 27 of Arms Act, was filed. The second incident was related to Mawkyrwat PS Case No. 26 (11)06 under Sections 120(B)/387 IPC read with Section 10/11 UA(P) Act. A raid was conducted on the resident of Morning Hahshah of Nongjri Village on 18-11-2006 and recovery of two demand notes by the HNLC signed by the Finance Secretary of the HNLC. The witness reiterated all these allegations in his examination-in-chief before the Tribunal while tendering the affidavit on the record.

21. CW-7 Sankey Ford Khongwir, Deputy Commissioner, Ri-Bhoi District deposed next; he supported the affidavit dated 17-3-2007, produced as Ex. CW 7/1. Sh. Jainal Rymmai, Superintendent of Police, Ri-Bhoi District deposed as CW-8. He too supported his affidavit dated 17-3-2007 which is Ex. CW-8/1. Both these witnesses spoke that HNLC is active in Re-Bhoi District and its cadres carry on unlawful activities which go un-reported due to fear psychosis by its cadres. CW-7 mentioned about relationship of HNLC with other groups such as ULFA, NDFB, KNV (Karbi National Volunteer) etc.

22. CW-8 produced materials by way of list (Ex. CW-8/2) giving specific instances. On 8-6-2005, one

Kalenderson Wanniang @ Marmet @ Bat of the Finance wing of HNLC was arrested from a jungle near Umjarsi village and a demand note of HNLC signed by its Finance Secretary, demanding Rs. 50,000/- from Woodland Cafe was recovered. This led to his arrest and disclosure about distribution of demand notes to several other businessmen and filing of Nongpoh P.S. Case No. 45(6)03 under Sections 120B/121/121A IPC read with Sections 10/13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act. He also mentioned about another incident of 11-6-2005 of surrender by Sumarland Kharmujai @ Hep Jep, a finance wing cadre of HNLC to Superintendent of Police, Ri-Bhoi and handing over of a letter authorization dated 1-4-2005 on HNLC letter head signed by its Chairman Julius Dorphan and Finance Secretary Ianek Skhem Shylla authorising him to negotiate with persons against whom demand notices were issued. A list of all firms to whom demand notes had to be distributed and mention of amounts; receipt books of the Sohpetbneng Youth Sport Youth Club, were recovered. It was stated that HNLC had called for Bandh on National days including on 26th January, 2006, 15th August, 2006 and 26th January, 2007. This led to fear psychosis restraining freedom of movement of the people, for celebrating such occasions. The witness lastly stated in his list that according to intelligence reports, HNLC cadres seek garner support from other organizations in Assam in their bid to regroup and strengthen their weaponry.

23. Smt. Rebecca Vanessa Suchiang, Commissioner and Secretary to the Government of Meghalaya deposed as CW-9; She identified her affidavit dated 17-3-2007, as CW-9/1. The witness deposed that HNLC was actively involved in unlawful, nefarious and anti-national activities in the districts of East Khasi Hills, West Khasi hills, Jaintia hills and Ri-Bhoi, Meghalaya. The principal object of HNLC is to achieve a Separate state which will not be a part of Union of India. The Witness deposed about some incidents in which HNLC was actively involved. During the 2005, 2006 and 2007 Republic day and Independence day functions HNLC called for a 24 hour bandh and threatened people not to attend the functions. The general public did not attend the celebrations anticipating trouble. The witness deposed that HNLC is active in Khasi and Jaintia hills, which has a long international border with Bangladesh. She deposed that the top leaders of HNLC are hiding in operating from Bangladesh. The witness deposed that HNLC maintains good relations with other banned insurgent groups like NSCN, ULFA, NDFB and NLFT, and receives training from those groups.

24. The witness deposed that HNLC mainly targets the business community, they are involved in extortion. During the year 2005 HNLC cadres were arrested and in the year 2006, 21 of them were arrested. 1 AK Rifle, 1 303 Rifle, 2 shotgun, 1 pistol, 1 revolver, 30 ammunitions, 1 empty magazine, 1 hand grenade were recovered in the year 2005 and 3 carbine, 1 pistol, 3 revolvers, 31 ammunitions, 2 empty magazine were recovered in the year 2006. The witness

filed copies of the notifications in various news papers declaring the two organizations as unlawful. The notifications are dated 16-11-2006. She has also filed a list of violent/unlawful activities the ANVC cadres were involved in and the arrests made in the year 2005-2006.

25. Shri. R.R. Jha, Director to the Government of India in the Ministry of Home Affairs deposed as CW-17. He identified his affidavit dated 29-3-2007 tendered as Ex.CW -17/1. The witness deposed that HNLC's aim is to liberate the Hynniewtrep people from the authoritarian rule of Indian Government, protect the Khasis and other Meghalaya tribes from exploitation, retain the indigenous culture and to eradicate social evils. The outfit reiterated its right to armed struggle. The witness deposed that the organization threatens people not to participate in national celebrations, it calls for bandhs on these days. People anticipate trouble and do not attend them. The witness also stated that the organization is involved in unlawful activities like coercion, extortion, particularly from the coal sector in Khasi Jaintia areas. The organization indulges in extortion from the business community, looting civilians to collect funds for their outfit, intimidation and kidnappings. They have links with the other banned insurgent groups of North Eastern States for procurement of arms and ammunition. The top leaders of HNLC stay in Bangladesh; they run camps which include training camps. The witness, in the examination in chief, deposed that imposition of ban on HNLC by the previous notification enabled the Central Government to effectively take steps towards counter insurgency operations. The same is the case of a previous ban relating to ANVC. The ban was imposed with immediate effect to ensure that there was no gap in effectively curbing the operations of the organisations and also to prevent them from regrouping.

Evidence concerning ANVC, led by the State of Meghalaya and the Central Government

26. CW-10, Smt. Rebecca Vanessa Suchiang, Commissioner and Secretary to Govt. of Meghalaya, Political Department, Shillong deposed on behalf of the State of Meghalaya. She tendered her affidavit dated 17-3-2007, as Ex.CW-10/1. The witness deposed that the ANVC indulges in criminal activities by harassing people and engaging in acts of intimidation and extortion particularly from non-tribal businessmen. ANVC also uses power to extort money from the business community. It is attempting to capture business activities in Garo hills by intimidation. Their activities are not only confined to three districts of West, East & South Garo Hills, but its cadres are also active in West Khasi Hills. ANVC is extorts money from businessmen in Tura and other places in Garo Hills by criminal intimidation. Senior leaders of ANVC force coal dealers to buy P-forms and DMR challans in East Garo Hills at highly inflated rates from their agents without any authority from the Department. Some of the toll-gates in Garo Hills are indirectly controlled by ANVC. The

clandestine operations by members of the organisation for collecting funds through illegal use of veiled threats is still carried out. The witness deposed that an incident of January 14, 2005 illustrates that ANVC cadres terrorized people for their own vested interest. People are scared to report against them. According to the witness, following a Cease Fire agreement, the State Government urged the ANVC to give up its unlawful activities and surrender all arms and ammunition. They are presently kept at liaison office of ANVC at Tura. Intelligence reports reveal that top leaders of ANVC have links in Bangladesh and have established safe houses. They have concealed their arms and ammunition in Bangladesh. ANVC has forcefully taken control of many District Council gates in three districts of Garo Hills. They have made it mandatory for each coal dealer to donate truckloads of coal to them.

27. CW-10 deposed that ten members of ANVC Cadre deserted the camps with weapons in May and October 2005 and April 2006. The deserters formed two organisations, namely ACHIK National Liberation Front Army (ANLFA) in East & South Garo Hills & Achik National Youth (ANY) in West Khasi Hills. The witness also stated that 13 Cadres of ANVC including deserters were arrested in 2005-2006 and 2 AK Rifles, 1 SLR, 3 Pistols, 3 Revolvers, 139 ammunitions, 12 Grenade & 7 empty magazines was recovered. In the examination in chief, she stated that both HNLC as well as ANVC have links with banned/unlawful associations such as ULFA, NLF, NDFB and NSCN(IM). The ban imposed by the earlier notifications has impacted by restoring the confidence of people, restricting the movements of the organizations which are by and large confined to outside the territory of India.

28. The witness was cross examined. She stated that approval of the State Cabinet was not obtained before her affidavit was filed in the Tribunal; no approval required as it did not involve a policy decision by the Cabinet. There was a tripartite agreement, signed between the Government of Meghalaya, Government of India and ANVC for suspension of operations of ANVC. The initial suspension was for a period of 6 months; it was extended time and again. The extension of suspension of operation and the validity of the agreement were without consent of the State Govt. of Meghalaya. She clarified that there was no objection to it. The parties to the agreement expressed satisfaction at the observance of ground rules by ANVC. In the cross examination, the witness stated that the objective of ANVC is to achieve statehood through armed struggle and that any activity involving conflict and disruption of existing territorial integrity or affecting sovereignty and integrity of India is unlawful. The State of Meghalaya has a list of members of ANVC, the list is not an exclusive (sic exhaustive?) one. The initial list contained 105 names and a later list contained 202 names. In reply to a query, the witness stated that weapons possessed by ANVC ought to have been kept in a neutral place but they were kept at a ANVC liaison office, in Tura. She further

deposed that there were discrepancies regarding the weapons surrendered and kept in joint custody and details of the missing items. As per the ground rules governing suspension of operations ANVC cadres are to be unarmed; but few move around with weapons. There are also deserters from ANVC cadres. The missing weapons, which are supposed to be in the joint custody in the premises of ANVC and the existence of such deserters, speak about the unreliability of ANVC's intention.

29. CW-10 deposed further in cross-examination that ANVC cadres collect funds by extortion from businessmen, shopkeepers, industrialists and entrepreneurs of the three Districts of East Garo Hills, West Garo Hills and South Garo Hills. They indulge in kidnapping for ransom, which also include highprofile kidnapping. They create fear psychosis amongst the people. The targets of ANVC have been mostly non-tribals; they also imposed annual tax on all businessmen/traders ranging from Rs. 2,000 to Rs. 1 lakh and asked them to clear all payments by 15th December, 2006. The ANVC had submitted a list of 202 cadres out of which only 120 cadres stay in the designated camps; the top leaders never stay in the designated camps. The outfit deposited only 16 weapons. Rest of the weapons are still in their possession. ANVC is indulging in extortion by collecting donations from coal traders and other target groups. The deserters left the organisation with AK-47 rifles, self loading rifles, magazines and Chinese hand grenades. The deserters were two different groups; they formed different organisations namely ANLFA, ANY based in West Khasi Hills. ANVC does not have any control over these organisation. ANVC is active in Garo Hills and aims at enhancing its financial capabilities. Its cadres create fear psychosis amongst people. ANVC has been involved in social and cultural policing and also settling disputes.

30. Sh. Pamu Sampath Kumar, Deputy Commissioner, West Garo Hills Dist., Tura, Meghalaya, deposed as CW-11. He tendered his affidavit dated 17-3-2007, as Ex. CW-11/1. According to him, ANVC actively carries out its unlawful activities in West Garo Hills District. He stated that ANVC intends creation of a greater Garoland by armed struggle; the business community is its main target. It has links with other unlawful organisations including National Socialist Council of Nagaland (IM), [hereafter "NSCN (IM)"] United Liberation Front of Assam ("ULFA") and National Democratic Front of Bodoland ("NDFB") who supply arms and ammunitions to it. ANVC has its head quarters in Bangladesh from where it operates regularly. Its cadres are engaged in raising funds by issuing demand notes to the business community. The witness in his examination in chief deposed that ANVC is active in his district. Its objective is to achieve a separate Garoland through armed struggle. He stated that the cadres have good relations with the other banned organisations across the border. ANVC is involved in unlawful activities like kidnapping, extortion, killing and terrorizing people. They target people who do not support their point of view. The

witness further deposed that the ban had the beneficial effect of weaning away misguided youth from participating in such violent and unlawful activities.

31. The witness, in his cross-examination, deposed that the Garos inhabit the West Garo Hills. ANVC does not have support of any sections of Garo Community. There have been instances and cases of violation of ground rules involving violence after the agreement to suspend operations was entered into between various parties. Except five cases, many other cases were unreported due to fear psychosis. The witness deposed that the acts of violence are reported to the review committee to facilitate co-ordination for State's issuance of Identity Cards and ironing out other related issues concerning the ANVC Cadre who had to stay in the designated camps. The primary objective of the meeting is to counsel and bring home the benefits of abjuring violence and not to straight away point out the violation of ground rules agreed upon. He stated that this was the reason why demands for extortion etc. were not highlighted in the meetings. The witness narrated an incident dated 25-8-2005 where the Joint Secretary of ANVC along with some Cadre members forcibly entered the Chambers of District Magistrate, in violation of ground rules and its cadre members were wearing Camouflage dresses. The witness deposed that the possibility of some others using the name of ANVC to further their ends is remote, as they are afraid of the consequences. The witness also agreed that ANVC had deserters.

32. Mr. Jerry Fiscer K. Marak, Superintendent of Police, West Garo Hills, Tura, Meghalaya, deposed as CW-12. He tendered his Affidavit dated 17-3-2007, as Ex. CW-12/1. The witness stated that ANVC is a banned organization and carries out unlawful activities. He narrated a few incidents. On 15-2-2006 ANVC Cadres were seen at Kalaichar Bazar when they started demanding money from members of the business community. They demanded Rs. 3,000 from Teer Counter and took Rs. 1,000 that day. This led to lodging of FIR Mahendraganj P.S. Case No.6(2) 2005 U/s 384 IPC. The witness narrated about another incident which occurred on 17-2-2005, when an ANVC Cadre, i.e Sh. Kochol K. Marak @ Adam @ Rikson was arrested while he was collecting the remaining demanded money. This led to the lodging of an FIR Mahendraganj P. S. Case No.6 (2) 2005 u/s 384 IPC against him. The third incident narrated related to Shri. Tonang D. Sangma, a cadre member who came to Latrigre Tri junction on a scooter and asked the complainant Sh. Dukrant M. Sangma to collect Rs. 200 each from all Teer counters of Ampati Bazar. The complainant collected Rs. 200 from each counter and gave him Rs. 1,800. This led to lodging an FIR Mahendraganj PS Case No.8(2)05 u/s 384 IPC.

33. The witness narrated an incident where Sh. Wanding K. Marak, Gen. Secretary (ANVC) threatened Garo Hills District Council (GHADC) members for allotment of toll collection from hats/bazaar which are under GHADC

to their proxy candidates; he also coerced Tura Municipal Board Officers to secure toll collection contracts of the Municipality in the name of the ANVC candidates. On the day fixed for Auction ANVC members were present, and the general public returned, due to fear. The ANVC cadres create a fear psychosis in the minds of general public. The witness narrated an incident of 5-4-2006, when at 11PM, ANVC Cadres, namely Remke B. Marak, Chonbat Ch. Momin and Charlie Sangma assaulted their colleague Dambil C. Marak with a Wooden Stick at Youth Hostel, Tura as a result he sustained grievous injuries and succumbed into his injuries. The accused fled the place with small arms, they were arrested and an FIR dated 14-2-2006 at Tura police Station case No. 39(4)06, u/s 302/201 IPC was lodged. The witness narrated few other incidents to show the presence of ANVC cadres create psychosis and fear to the people. The locals do not give any statement out of fear. He also sums that in view of the prevailing circumstances it is important to impose further ban of the organisation at least for another term of two years for improving the prevailing situation in the District.

34. CW-12 deposed that in West Garo Hills both HNLC and ANVC are active; yet the latter is more active. The objective of ANVC is to achieve Garoland through armed rebellion. They are involved in unlawful activities like extortion, criminal intimidation and harassing the public; they are attempting to capture business of Garo Hills by intimidation. There are cases against the ANVC Cadres. Many go unreported due to fear psychosis. The witness deposed that during 2005—2007, 3 ANVC Cadres members were arrested but no arms were recovered from them. The business community is targeted by ANVC and they (ANVC) have links with banned associations. ANVC is involved in imparting arms training to its personnel and the Cadres wear camouflage uniform. During examination in chief, he produced Ex. CW-12/2 and CW-12/3 wall calendar and table calendar, published by ANVC; the former contained photographs and images of its cadres, with details of names, showing them in battle or combat dress, informations, and also being trained. CW-12/3 was marked; it is a copy of a document titled "Army Formation Achik National Volunteer Council" in Garo; its English translation was produced and marked by the witness as CW-12/4. These were marked without objections on behalf of ANVC.

35. The witness deposed that a Nodal Officer maintains contacts with the leaders of ANVC. The Nodal Officer is Inspector General of Police level. The senior leaders of ANVC are permitted to carry small fire arms, but they cannot carry them in public places, they are permitted to do so for personal safety. ANVC is not co-operating with the police in tackling other banned organisations. ANVC makes demands from the business community and imposes tax on the sale of a very commodity in Garo Hills. ANVC has imposed a ban on the sale of DTH (Direct to Home) Technology which affected all people in Tura. ANVC controls cable operation business in the district.

ANVC also imposed a tax of Rs. 5 per kilo on the sale of dried fish in Tura. People are scared to report the incidents due to fear psychosis.

36. Smt. Renilla D. Marak, IAS, Deputy Commissioner South Garo Hills deposed as CW-13 she tendered her Affidavit dated 17-3-2007 as Ex. CW-13/1. She stated that ANVC is a unlawful organisation with its top leaders hiding in Bangladesh and operating from there. The cadres of the organisation are used for raising of funds by issuing demand notes to the business community; fund raising by way of extortion is one their major activities. ANVC has established good relations with other banned insurgent groups of other North Eastern States like NSCN-(IM), ULFA, NDFB. The witness deposed in her chief examination that in South Garo Hills both HNLC and ANVC are active, but ANVC is more active. Their objective is to create a Garoland through armed struggle. The ANVC is involved in unlawful activities like extortion, killing and intimidation of members of public. Non-tribals and local businessmen are targeted for extortion. People are scared to report all the incidents. The witness also deposed that due to intimidation by ANVC, shopkeepers in Tura do not sell DTH equipment to the residents in municipal area of Tura. ANVC has a control over the cable business also but the shopkeeper do not openly divulge this threat but agree that there is a problem by account. The witness deposed in her cross-examination that in 2006 there were some violent incidents, reports of extortions to coal traders in Nongalbibra were made. She also stated that the FIR in her affidavit, relates to a deserter from ANVC.

37. Shri Heimond Toi, MPS, Superintendent of Police, South Garo Hills District, Baghmara deposed as CW-14. He tendered his affidavit dated 17-3-2007 as Ex. CW-14/1. He narrated an incident of 2-5-2005 where cadres of ANVC fired with their pistols. M/s Wasa D. Sangma and three others fired at Shri Chipson Marak and Johurul Islam with 9 mm pistol, seriously injuring the victims. Later on, police raided their hide out and live 9 mm ammunition and 3 Chinese made hand grenade were recovered from their possession. This led to the filing of Baghmara PS Case No. 20(5)2005 u/s 307/326 IPC read with Section 25(1)(A) Arms Act. The witness deposed that ANVC cadres terrorise people, who are scared to report to the police as the militants still have their weapons with money. He deposed that ANVC continues to extort money from the business community by involving 3rd parties. The outfit is trying to capture all business activities in Garo Hills. The cadre members commit various crimes like kidnapping, murder and encounter with police; their main object is to extort money. People do not report to the police due to fear. The witness deposed that ANVC has links with other North Eastern banned insurgent groups. ANVC has its headquarters in Bangladesh and the organisation is operated from there. The witness deposed that in South Garo Hills, Bagmara District with HNLC & ANVC are active, ANVC is more active. ANVC is involved in extortion, intimidation and

creation of terror amongst the people. People do not report incidents due to fear. Four cadres members of ANVC were arrested as they were indulging in unlawful activities, further there has been no arrest and there has been no recoveries of arms from any other Cadres of ANVC persons. ANVC threatens the business class and also Nokma ie. Headman of the village. The witness further deposed that ANVC also threatens Government officials. Its cadres are largely concentrated in coal areas of Nangalbibra. ANVC has contacts with HNLC; it is also based in Bangladesh. ANVC Cadres have identity Cards, copies of those were placed on record. ANVC Cadres maintain multiple identities and they change their names frequently. They make new recruits often. The witness deposed that the cadres of ANVC are kept in designated camps. The witness on being confronted with the documents of (monthly review meeting dated 8-12-2005) stated that he is unaware whether previous S.P. South Garo Hills requested ANVC to assist the police by submitting information of whereabouts of six ANVC deserters from the designated camps. He deposed that ANVC and its cadres are not supposed to carry arms, yet recoveries of arms were made.

38. Shri Onesimus Pasi, MPS, Superintendent of Police, East Garo Hills, William Nagar deposed as CW -15 and tendered his affidavit dated 17-3-2007 as Ex.CW -15/1. The witness deposed that ANVC cadres indulge in extortion; they demand money from coal traders, gate operators and other businessmen. They forcefully took control of many District council gates in three districts of Garo Hills. In order to gain sympathy of the people they purchase vehicles, ambulance, by using extorted money and donate them to the people. In one instance a Maruti Van ambulance was donated to the Mothers Care Society of Rongjeng and the vehicle was handed over to Smt. Surdha M. Sangma, an executive member of the Society. The vehicle, purchased in the name of Pes at A. Sangma of Tura was subsequently seized by Police, when it was found that it was used by cadres of ANVC for carrying on their nefarious and unlawful activities. This led to Rongjeng PS Case No. 11(4)05 u/s 11/13 ULA (P) Act. The ANVC cadres on 8-8-2006 were apprehended by the Army personnel at Damas Village and two 9 MM pistols with live ammunitions were seized from their possession. A case was registered in Mendipathar PS case No. 34(8)06 u/s 25(1-A)(1-B) Arms Act. The witness further deposed that ANVC cadres are involved in illegal felling of trees from reserve forest and removing them through Samanda Prapgra Road. They are also involved in a lot of killings and people do not report them as they are scared. The witness deposed that in east Garo Hills ANVC and HNLC are active, but of the two ANVC is more active. It is involved in kidnapping, murder, abduction and all these have caused fear psychosis amongst the public at large. The cadres are involved in killings and various FIR's have been lodged at PS Williamnagar U/s 302/201 IPC. The main supporters of these banned organisations in East Garo Hills are ULFA, NDFB,

{VSCN (IM)}, Arms training and supply is the main help of these organizations. He stated in his examination in chief that the basic objective of ANVC is to achieve a separate sovereign state outside the Indian Union through armed struggle. There are cases involving ANVC and its personnel. All instances are not reported due to fear. The unlawful activities of ANVC include extortion, kidnapping and murder. They carry banned weapons and impose ban on the celebrations, observance of national festivals such as Independence day and Republic day. They target the business community and public who do not fall in the line with their dictates.

39. The witness deposed, in his cross examination, that there are three designated camps of ANVC and one such is located in his District. Many Cadres do not actually stay in the camp. There are deserters from the camps. The witness further deposed that the Cadre targets business community, boycotts several occasions and has links with several banned insurgent groups.

40. Mr. Synrem, IAS, Deputy Commissioner, East Garo Hills, William Nagar, Meghalaya deposed as CW-16. He tendered his affidavit dated 17-3-2007 as Ex.CW -16/1. The witness deposed that ANVC is actively involved in unlawful activities in East Garo Hills. Its top leaders hide in Bangladesh. They carry their activities from across the border. Cadres of the organisation are engaged in fund raising activities, by issuing demand notes to the business community. They have good relations with other banned groups of North Eastern States like ULFA, NSCN(IM), NDFB. The witness deposed in his Chief Examination that in East Garo Hills, William Nagar both HNLC and ANVC are active but ANVC is more active. The main aim of the organization is to achieve a separate state through armed struggle. They are involved in extortion, kidnapping, murder and other anti-social activities; these activities restrict people from actively participating in national festivals. Most of the incidents go unreported due to fear and adverse consequences. The witness further deposed the ANVC Cadres operate in the district but their top leaders are across International border, in Bangladesh. ANVC targets business community, police and general public.

41. The witness deposed in his cross examination that the last time ANVC called for bandh and boycott of Independence Day and Republic Day celebrations was in the year 2004. The witness further deposed that he is unaware and unable to state where joint meetings were held with ANVC Cadres. The witness disagreed that the real motive or objective of banning ANVC is to prevent it from joining and participating in mainstream political activities.

42. R.R. Jha, Director to Govt. of India in the Ministry of Home Affairs, CW 17, also spoke about ANVC; he tendered his affidavit dated 29-3-2007 as Ex.CW 17/2. The witness deposed that ANVC was formed on 24th September, 1996 from its fore runner Achik liberation

Matgrik Army (ALMA). The objective of ANVC is creation of separate state of Garoland comprising of three districts of Garo Hills of Meghalaya, West Khasi Hills & Ri-Bhoi districts. The demand has prompted enmity between Khasis and Garo's. For achieving its objective, the outfit has been intimidating state functionaries of public, raising funds through extortions; kidnappings, robberies, indulging in establishing bases in remote areas and also have been maintaining good relations with other banned groups. The witness deposed in his Chief Examination conducted by the Addl. Solicitor General that the imposition of ban on HNLC by the previous notification enabled the Central Government to effectively take steps towards counter insurgency operations. The same is the case of a previous ban relating to ANVC. The ban was imposed with immediate effect to ensure that there was no gap in effectively curbing the operations of the organisations and also to prevent them from regrouping. The witness also identified another affidavit tendered as Ex-CW-17/3 which enclosed a copy of the ANVC constitution, framed in 1996.

43. The witness deposed in his cross examination that he does not speak, write/read or understand Garo language. He deposed that he went through the English translation of the ANVC Constitution. ANVC has a constitution of its own. The witness deposed that in a meeting of 11-7-06, the Central Government asked the ANVC to furnish a complete list of its Cadres. The ANVC provided a list of 202; out of these 120 stayed in the camps. The list of weapons according to Central Govt's estimation exceeds 150; a list of only 16 weapons was provided.

Evidence on behalf of ANVC

44. Mr. Raphael Ch. Mārak deposed as RW -1. He identified his affidavit dated 12-04-2007 tendered as Ex. RW-1/1. The witness deposed that he is a Joint Secretary of United Achik Peace Forum (hereafter referred to as "UAPF") which represents almost all church leaders of Garo Hills. The witness deposed that the membership of UAPF comprises of ten members. He stated that the main objective of the Organization is to promote peace in Garo Hills by conducting regular meetings of the leaders of the Society. The witness further deposed that that ANVC has been trying to ensure that the peace should return back to the region. He further stated that his organization played an important role in continuing the truce between ANVC and Government. According to his knowledge, ANVC never threatened anyone or demanded money by way of extortion. He further stated that ANVC is trying to achieve its objective by peaceful negotiations. The witness deposed in his chief examination that the objective of ANVC is achieving statehood for Garo people and the objective of United Achik Peace Forum is to promote peace between the Government of Meghalaya and ANVC. He further stated that ANVC has not threatened or demanded money from anyone. The witness deposed that if the Garos have a separate state for themselves it will promote peace because

the present composite state comprises of different tribes and people, and is not conducive to the nature of the Garo people who are not securing a fair share of development in the existing set up. The ban on ANVC should be lifted for the benefit of Garo people.

45. In cross examination, the witness deposed that he was aware of an incident involving police firing in Garo Hills on 30-09-2005; after that incident efforts were made to resolve the differences between the Government and all the factions. This involved participation by various denominations of the Church groups such as Roman Catholics, the Pentecostal Church and the American Baptist denominations. He stated that Church and related services try hard to achieve peace between ANVC and members of other communities. He deposed that ANVC does not threaten and extort money from people; that ANVC and UAPF have met on three occasions at the Auditorium of Garo Hills, Tura as a part of peace initiative and the main objective of his organization is to promote peace. The witness further in his cross examination deposed that ANVC is not active in his region, i.e. Bishop Campus Area, Tura, Garo Hills. He stated that the incident dated 30-09-2005 which led to the death of some children, was due to police firing. He stated that ANVC cadres do not possess any weapons and he is not aware as to where they have hidden their arms.

46. Mr. Raknang S. Sangma deposed as RW -2. He tendered his affidavit dated 16-11-2006 as Ex. RW-2/1. The witness deposed that he is a Secretary of Garo Hills Labour Union, headquartered at Tura and the Labour Union consists thousand members. The witness stated that he has close interaction with members of the Labour Union who are mostly non-tribals and those people have no complaints against ANVC for threatening or intimidating them for any cause. He further deposed that ANVC is promoting the interest of people living in Garo Hills and they seek a separate state to improve the conditions of the people living in Garo Hills.

47. The witness deposed in his cross examination that the Union members are around thousand in number. Registration fee of Rs.100 is obtained from new members at the time of their joining the Union. The Union is a registered association, the voting for office bearers is by raising hands and not by secret ballot. The problems faced by workers and labourers in Garo Hills include disputes relating to wage fixation, abuse and conflict with members of public, interse disputes and influx of workers from outside areas particularly from across the border. The majority of members are non tribals; if there is any threat by the ANVC to the non tribal members of the Union then it is forwarded to the Union by the concerned members. ANVC's involvement has resulted in reduction on incidents of looting, gambling and drunkenness. The witness further deposed that he is not aware about the activities of ANVC. Cadre members of ANVC visit the region where he resides often and they do

not carry any weapons. He is not aware about the sources of funds to ANVC.

48. Mr. Parman R. Marak deposed as RW-3. He tendered his affidavit dated 16-11-2006 as Ex. RW3/1. The witness deposed that he is President of the Garo Hills Traders Union, Tura which has its objective to promote and safeguard the interest of the traders of the region. He stated that the association represents both tribals and non tribals. The ANVC has not been indulging in any activity which is directed against traders living in Garo Hills. The witness deposed the cadres of ANVC have not demanded money nor have threatened or harassed traders. The witness deposed that he was selected as President of the Union in a process where members raised their hands and there was no secret ballot. The activities of the Union are mainly ensuring welfare of the Traders and its members. The Union collects Rs. 200 per membership as registration fee and there are about thousand members. The activities of the Traders Union is to assist its members during times of difficulty and also extend financial help to the family members in case of any distress or emergency. The membership of the Union comprises of approximately 50% of Garo's and balance are non tribals. The witness deposed that the traders do not face to many problems; some times they are faced with troubles by drunken youth. Whenever such information is received, the Union visits the spot and tries to counsel such trouble makers. The witness deposed that he is unaware whether ANVC lodged any objections to the notification proposing a ban.

49. The witness deposed in his cross examination that he is not aware of the day to day activities of ANVC. He is not even aware of the office bearers; he has not seen ANVC cadres in his area for long. No members of the Association have mentioned about demand of money or threats or harassment by ANVC.

50. Mr. Wanding K. Marak, General Secretary, ANVC, deposed as RW-4. He tendered his affidavit dated 13-04-2007 as Ex. RW-4/1. The witness deposed that ANVC was formed on the 20-12-1995 and he has been the General Secretary since 1998. The objective of the organization is creation of separate state of Garo land comprising the district of Garo Hills of Meghalaya and the areas predominantly inhabited by the Garo (West Khasi Hills and Ribhoi Districts of Meghalaya, Goalpara and Kamrup District of Assam). The witness deposed that Garo's must have a separate state for shaping their own destiny in respect of political, social cultural, ethnicity, education spheres. The witness deposed that ANVC entered into an agreement for suspension of operation with Government of India and Government of Meghalaya initially for six months. Meetings were held on several occasions; in the meeting dated 17-1-2005 ANVC clarified that none of its cadre member were indulging in unlawful activities and the police should take action against anybody using ANVC's name for extortion. The witness deposed that they were

not recruiting any new cadres. It was decided in one of the meetings dated 18-7-2005 that a complete list of cadre members in designated camps, photographs and address would be submitted alongwith list of weapons possessed. The weapons were possessed for self defence. The cease fire was extended for six months and subsequently for another year. The list was provided and the weapons are kept in joint custody.

51. The witness deposed that both HNLC and ANVC are not illegal organizations, ANVC is not involved with ULFA and other smaller groups like ANLF, LAEF. The witness deposed that these smaller groups are involved in killing extortion, kidnapping, serving demand notes, etc., in Garo Hills. He further deposed that none of its top leaders reside in Bangladesh, and they are not carrying on illegal activities. In fact ANVC carries out large number of social activities like voluntarily contributing to the Tsunami relief fund it has even donated 2 ambulances to the villagers.

52. The witness deposed, in his cross-examination, that the Garos deserve a separate state because they have been discriminated against in comparison to other tribes in Meghalaya. ANVC submitted a list of 202 members of its Cadre to the Central Government and the State Government. The Cadre are maintained through the assistance of well-wishers and the Garo people who wish to have a separate State of Garoland. The ANVC does not have a separate source of income; it is supported by contributions of people/well-wishers on regular basis. The witness denied that ANVC used to maintain large number of weapons and the weapons possessed by them are kept in joint custody. The weapons were maintained for self defence and all of them were obtained from smugglers; RW-4 denied that the weapons were obtained from Bangladesh or were snatched from the Police, Paramilitary or the Army. The witnesses agreed that a list of weapons were given to the State Government which included a list of weapons including LMG's, 5 AK-56 rifles, M-155.56MM rifle; he stated that all these were used for self-defence. The witness deposed that the list of cadres furnished was according to the designation assigned to them. He denied that the variance in the list was due to ongoing recruitment of the cadres but stated that this was due to the progress achieved through to peace talks. The witness stated that he was not aware of the number of cadres in each camp. The witness was again cross-examined after three days, when he deposed that he was not aware of the discharged members or the deserters of ANVC. He further stated that there is no weapon-instructor, and all the cadres are self-trained. He stated that the top leaders of the association live in Garo hills and the non tribals are supporting ANVC morally. The witness deposed that ANVC does not publish any literature.

53. The witness further deposed in his Cross Examination conducted by the Addl. Solicitor General that no elections were held to choose the General Secretary and he was chosen by their leader Mr. Dilash. M. Marak.

He stated that he was never invited to join the organisation but he volunteered to do so. The witness deposed that ANVC has its office at Tura Youth hostel, and the house was allotted by the Government. The witness deposed that ANVC does not have any Written Constitution, its aims and objectives are decided through collective decisions. The decisions are taken in meetings. The witness further deposed the specific number of membership of ANVC is 202. He deposed that the Memorandum submitted to the Central Government displayed a tricolour alongwith the symbol of ANVC, which is the flag of the organisation. There is only one flag and it is not displayed in public, it is kept in the office. The witness deposed that ANVC keeps changing its head quarter (Cheram as it is called) because of police encounters that has taken many lives of its cadres. The witness deposed that other than the cadre members no one is aware of ANVC headquarters. He further stated that ANVC has a Chairman, a Joint Secretary who looks after the Finance Department. The Commander-in-Chief looks after the cadre. Mr. Arist Sengsrang looks after the publicity of ANVC and he is the Publicity Secretary there is also an Organizing Secretary but there are no defence and foreign secretaries.

54. The witness deposed that the aims and objectives were not published as it was already in the memorandum. He said that creation of Garoland was not through any means but through political dialogue. The arms and ammunitions were necessary for self-defence. He also stated that two designated Camps were established for ANVC and one liaison office has been established and there is no training imparted to Cadres in designated Camps; due to the political dialogue, that is unnecessary. The witness deposed that ANVC does not hold any public meetings and the activities of its members are known to its Cadres. He further deposed that ANVC has a table calender, which is designed by the Publicity Secretary. He also states that ANVC does not have a bank account as it does not have any money. The money is obtained from the well wishes. He lastly deposed that the average age of ANVC Cadre members is below 30 years due to the fact that young people are physically more active and capable of fighting.

55. Mr. Torik Jangning Marak Organising Secretary of ANVC deposed as RW-5. He tendered his affidavit dated 13-4-2007 as Ex. RW-5/1. The witness deposed that the aims and objectives of ANVC are creation of a separate state of 'Garoland'. He stated that ANVC never aims at cessation of any part of territory of India. He deposed that ANVC is not involved in any kind of criminal activity and at present it does not possess any weapons. He stated that the extortionists of the coal belt areas are not connected to the ANVC but other agencies that collect money on behalf of the Government. The witness deposed that false allegations relating to ANVC about extortion, harassment, capturing business in Garo Hills, terrorizing and creating fear psychosis amongst the people have been made. He stated that all ANVC cadre members live in designated Camps and their movements outside Camps are strictly

regulated. The weapons they possess for self defence are also in joint custody.

56. The witness deposed that ANVC is the response to an age old deprivation felt by the people of Garo Hills, who are deprived of development and are backward. ANVC is fighting for the cause of the people for having been denied the right status. The Garos are lagging behind in education compared with the other two tribes in Meghalaya. The witness deposed that they gets step-motherly treatment in comparison with the other tribes. The witness deposed in chief examination that in the year 2004 ANVC surrendered its weapons. He stated that ANVC plans to contest elections if the ban is lifted. The meetings of ANVC are held in designated camps and the Youth hostel. He further deposed that Mahindra Finance approached him to act as a recovery agent to re-possess vehicles of defaulters who do not pay vehicles advances, in Garo Hills.

57. The witness deposed, in his cross examination that the principal objective of ANVC is achieving separate state of Garoland because the Garos are neglected. He stated that ANVC does not have a written Constitution. The witness deposed that various designations of ANVC office bearers like the Chairman, Joint Secretary and Publicity Secretary, are used. He stated that there is no process of nomination and he was nominated as Organisation Secretary verbally. He further stated that before the cease fire the ANVC cadre used to move around, giving publicity to their organisation and since the cease fire there is no such activity. He stated that the Cadre was known as the Army. When the witness was asked about few ANVC members who were involved in several cases, he responded in the negative. The witness was aware about the deserters of ANVC; he stated that three of them deserted from the liaison office as they could not comply with the strict ground rules. He deposed that before the cease fire, weapons training was provided to the cadre members which included training to handle weapons of A.K.series and Pistols.

58. The witness admitted that his Christian name is Bernard Marak was changed to his official name Torik Jangning Marak. The witness denied there being a company called Mahindra Finance and he agreed that he was granted anticipatory bail in a complaint registered by Mahindra Finance, Ri-Bhoi District. The witness accepted that CW-12/2 wall calender CW12/3 and table calender were prepared by ANVC, but explained that the photographs in the calendar were taken before the cease fire. He accepted that Mr. Dilash M. Marak was Chairman of the ANVC and his name was not mentioned in the list submitted to the Joint Monitoring Group or to the Government, because he did not reside in the Camp. The names were only of those who reside in Camps. The witness deposed that ANVC does not participate in national celebrations, but individual members do so. He deposed that ANVC celebrates the foundation day of the organization, or its raising day. He stated that Khasis and Jaintias live in Garo Hills and employment policies were formulated on the basis of

proportion of different communities. The witness stated that other than calendar and table dairy no written records except the documents furnished to the Joint Monitoring Group, exist with ANVC.

59. The witness deposed that no records are maintained about the money received by ANVC. There is no record of expenses either. There are no records from where the weapons came and how they were utilized. RW -5 stated that people come to know about the office bearers and cadres of ANVC by interaction and they consider them as their local guardians. The witness deposed that ANVC cadres are known as their Army and there is no commander-in-chief. He stated that illegal activities like extortion are carried out in Garo Hills by other organizations; even now they continued i.e. after the cease fire. He deposed that the aims and objects of ANVC are decided by the Chairman and there is no invitation to join the organization, people volunteer to join. The affidavit signed to be produced before the Tribunal was with Chairman's permission but it was not shown to him.

Submissions on behalf of the State of Meghalaya and Central Government, in support of confirmation of the notification under Section 3(1)

60. Mr. Ranjan Mukerjee, learned counsel for the State of Meghalaya, submitted that the notification issued under Section 3(1) of the Act should be confirmed under Section 4(3), having regard to the evidence and materials led before the Tribunal. Counsel briefly dealt with the provisions of the Act, and submitted that it was enacted in 1967 after the Constitution was amended, in 1963, enabling the State to impose reasonable restrictions to protect the sovereignty and integrity of India. It was submitted that the Act as originally enacted, defined unlawful activity slightly differently and at times difficulties were experienced in invoking the powers in relation to certain kinds of activities. However, the scope of the Act was broadened after the amendment of 2004 which defined "unlawful association", under Section 2(p) to mean an association which has for its object any unlawful activity, or which encourages or aids persons to undertake any unlawful activity or of which the members undertake such activity. It was submitted that the expressions "encouraged" and "aid" were intended to broaden the coverage of the Act. Learned counsel contended that unlawful activity was defined in the widest terms by Section 2(o); it includes activities of individuals or associations, including words spoken or written or through representation, disclosing, *inter alia*, support to cession of a part of the territory of India or part of the territory of the Indian Union, or intention to bring about such cession or secession. The definition by sub-clause(ii) also includes activities by such persons, which disclaims, questions, disrupts or is intended to disrupt the sovereignty and territorial integrity of India or also causes or is intended to cause dis-affection against India. Counsel submitted that having regard to the object of the enactment namely

placing curbs on the freedom of right of association, of individuals, the expressions "sovereignty" "integrity" and the other qualifying terms have to be given the plain and grammatical meaning. Sovereignty and integrity, it was contended intrinsically are wide terms, even in common parlance. Therefore, impediments which are unlawful and illegitimate, posing threats to such concepts, essential for orderly society, have to be construed having regard to the object of the enactment.

61. Learned counsel next contended that the notification issued on 16-11-2006, proposing a ban on the two organizations, i.e. HNLC and ANVC, is to be confirmed having regard to the materials placed on record and evidence led by the parties. It is contended that the procedure followed by the Tribunal though adjudicatory is not expected to be strictly like that of a Court. Counsel relied upon Section 5(5) to say that the Tribunal has the power to regulate its own procedure, subject to Section 9. Section 9 in turn states that the procedure to be followed by the Tribunal would be that which Court has to adopt in holding an enquiry for investigation of claims. Counsel also relied upon Rule 3(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Rules, 1968 and submitted that the Tribunal is not strictly bound by the Indian Evidence Act but has to follow it as far as it is practicable.

62. It was contended that the conspectus of evidence led before the Tribunal showed that the ban had to be imposed against both organizations i.e. HNLC and ANVC. Counsel submitted that it was no doubt true that by an agreement, suspending operations was entered into between the Central Government, ANVC and the State of Meghalaya on 27.3.2004. One of the cardinal objectives of the agreement which was undoubtedly extended, was to disarm the group and make the movement of the cadres accountable. Counsel relied upon Clause 6 of the agreement to say that the ANVC cadres would not move with anTIS or in uniform. It was submitted that the deposition of witnesses led before the Tribunal, i.e. CW 10 to CW-16 showed that there were about at least 16 recorded incidents concerning ANVC cadres, in various Districts of Meghalaya. These implicated the accused of offences such as murder, robbery, kidnapping, extortion and widespread Arms Act. Counsel contended that copies of the FIRs produced for the post may 2005 period, and the affidavit of Dupty Superintendents of Police of the Districts concerned, particularly, were true copies of certified copies. They were photocopies of the copies and the originals of these documents were available but since cases were still under investigation, they could not be presented to the Tribunal. Counsel contended that the cumulative effect of these documents and the depositions of the witnesses, who were duly cross-examined by counsel for the ANVC, disclosed the following uniform pattern :

- (1) The open movement of ANVC cadres, who had not surrendered all their arms;

- (2) creation of terror by the ANVC cadres through acts of extortion, ransom, kidnapping, intimidation etc.
- (3) repeated acts of intimidation of general public. Counsel highlighted particular instances, by relying on depositions of CW-11 and CW-12 where money was collected "toll collections" from Hats and Bazars. Counsel also relied upon imposition of an illegal, so-called tax of Rs.5/- per kilo on sale of dry fish in Tura, spoken to by CW-12; likewise ANVC preventing shopkeepers in Tura from sale of DTH equipment to the residents of Municipal area was also cited.
- (4) Deposition of witnesses showing that ANVC cadres target the business community specifically, making illegal demands by issuing notes and also creation of an atmosphere of terror in the general public, inhibiting them from reporting incidents due to scare or retaliation and also preventing them from participating in National Day celebrations.
- (5) Seizure of weapons which are banned by law;
- (6) Reports of ANVC cadres maintaining links with groups and organizations that are banned, like the ULFA, NSCN (IM) and NDFB. Counsel relied upon the depositions of CW-10, CW-13 and CW-16.
- (7) Deliberate act of ANVC to mislead the Government and the Joint Monitoring Group set up pursuant to the ceasefire. According to the agreement, a list of ANVC cadres had to be furnished. However, the ANVC furnished different lists containing different names. It also did not fulfil its obligation to surrender arms and keep them in joint custody but kept them in its Liaison office at Tura.

63. Learned counsel submitted that even though the objective of suspension of operations agreement was to bring ANVC to the negotiating table, initiate confidence building measures and enable it to eventually to join the main stream, it continue to function with the objective of disrupting the territorial integrity of the country, for achieving the State of Garoland. Counsel submitted that the protestation about the ANVC, wishing to achieve Garoland through peaceful means is belied by its activities. Contrary to its obligation to lay down arms, its cadres continued to move freely throughout various Districts, intimidate and extort people, particularly the business community, move around in camouflage and battle fatigues and also commit serious offences. The number of incidents officially recorded is far less than what actually occurs as there is widespread under reporting, due to fear psychosis

amongst the people. Learned counsel contended that each time there is an incident concerning ANVC cadres, it is held out by of that the persons concerned are not its members or are deserters over whom it cannot exercise any control. All these point to its persistence with the stand of achieving whatever objectives it professes, through violent means and by force of arms, which was impermissible and amounts to an unlawful activity under Section 2(o) of the Act. As a result, the Tribunal, it was contended, should confirm the ban under Section 4(3).

64. It was next contended by the learned that the evidence led before the Tribunal as regards activities of HNLC showed that between the period of the previous ban i.e. May, 2005 and till date, no less than 12 reported incidents took place. These were spoken about by CWs 1 - CW-9. Copies of the FIRs are also part of the record.

64. Learned counsel relied upon depositions of CW-2, CW-3 and CW-5 to say that the HNLC cadres were indulging in repeated and persistent acts of ransacking, kidnapping, murder and also challenge the police and armed forces. Counsel relied upon the deposition of CW-6 to state that in firing incidents the HNLC cadres had died. He relied upon the deposition of CW-3 to say that there were several incidents concerning HNLC issuing extortion notes. It also indulged in higher scale acts of violent crimes such as bank robbery etc.

65. Learned counsel contended that the activities of HNLC are aimed towards its objective of seceding from the Union of India and also challenge its sovereignty and integrity. It was submitted that the witnesses for the State have spoken about bandhs on National Days such as Republic Day and Independence Day declared by the HNLC and its targeting businessmen for collection of funds, through threats. Reliance was also placed upon depositions of a witness i.e CW-2 to say that HNLC cadres were using sophisticated and banned weapons such as 10 AK-47 weapons for which live ammunitions were recovered. Similarly, other banned weapons like Chinese made pistols etc. were spoken to by that witnesses as well as CW-4. Counsel contended that HNLC had links with banned organizations such as NSCN and NDFB. He relied upon depositions of CW-1, CW-2 and CW-8. CW-8 it was submitted had also spoken about KNV (Karvi National Volunteers) and other banned organizations.

66. Learned counsel contended that having regard to the violent activities of the HNLC, aimed at achieving the objective of ceding disrupting and threatening the sovereignty and integrity of India, in view of the fact that it did not approach the Tribunal in spite of wide publicity about the hearings, or choose to file its objections or place the materials placed on record, the Tribunal should return a finding recommending the ban, on the strength of the materials and evidence placed before it.

67. The Additional Solicitor General of India Mr. P.P. Malhotra and Mr. Sanjay Katyal, learned Counsel for the Union of India argued that the Notification dated 16-11-2006, so far as they concern both the proposal of ANVC and HNLC ought to be confirmed. It was submitted that ANVC and its cadres, have been shown to indulge in acts of intimidation, extortion, leading to collection of funds for their organization, maintaining links with other insurgents groups for carrying out acts of extortion and also maintaining relations with groups in outside the country for the purposes of training of their cadres. Counsel contended that according to intelligence estimates the total weaponry of the outfit was about 150 including 50 AK-series rifles and other banned weapons. Counsel contended that headquarters of ANVC is at "Cheram" which is not a known place, but a secret hideout. It was submitted that the evidence placed before the Tribunal showed that though witnesses avoided mention of a written Constitution, there was no denial that a Constitution with objects of the ANVC existed and that it had a group or band of people, given designations as if they were an armed force. It was submitted that the evidence led before the Tribunal also point to the cadres of ANVC moving around in camouflage and battle uniform. Counsel relied upon the calendar published by the ANVC and the colours admitted by it, the Memorandum submitted to the Government of India.

68. Learned counsel contended that apart from the deposition of the State, the Union had through the evidence of CW-17 spoken about activities of ANVC not being confined to three districts in Garo hills but also in West Khasi Hills. Counsel submitted that CW-17 had also deposed that ANVC had links with banned organizations and that in 2005-2006 ANVC cadres were involved in not less than seven violent incidents, two of which involved attacks. Counsel relied upon an incidents of 28th June, 2005, whereby discharged ANVC cadres had attacked the police with hand grenades and were killed in the encounter. He also relied upon the incident of 4th November, 2005 where an encounter involving ANVC cadres leading to death of two and another incident of 7-11-2005. Learned counsel further relied upon the incident of 15th November, 2005 when the police apprehended ANVC cadres in Nongroundu Village and recovered banned weapons as also encounter and killing of ANVC cadre. Lastly, reliance was placed on evidence about an incident of 9th February, 2006 at Dobu, P.S. Williamsnagar where 30 persons had attacked some members of the public which ultimately led to the death of one of them and looting of Rs.7 lakhs and burning of the place.

69. Learned counsel relied upon the testimony in cross-examination of RW-4, General Secretary of ANVC, who admitted that the organization got weapons including light machine guns from smugglers. It was submitted that if the real intention of the ANVC is to participate in legitimate political activity, there is no impediment to full disclosure

of all its members, and about revealing location of its headquarters or location of its leadership. Its intentions on the contrary were suspect as ANVC always gave wrong information the - list of its cadres were never correct and they always varied. Counsel also contended that the materials on record showed that all weapons were never disclosed or kept in joint custody but continued with ANVC and were used by its cadres. The ANVC was unable to furnish details of its cadres or even control them which pointed to its anarchic nature or its deliberate attempt to mislead the public agencies and continue with its unlawful activities. The calendars and the images on it and the Constitution, a copy of which was produced by the witness CW -17 and copy of its army formation, produced by CW-12, as CW-12/3 point to the ANVC's maintaining a parallel administrative and military set up, that cannot be consistent with its preferred goal of achieving Garoland through peaceful means.

70. Counsel contended that if indeed the ANVC is intends to achieve Garoland or statehood through lawful means, there is no need to have a military like set up with leaders called the Commander-in-Chief and the designation of various personnel with military titles. These coupled with the recovery of arms spoken to belie its assertions about its peaceful intentions.

71. Learned counsel contended that the ANVC's consistent reliance on the Joint Monitoring Group Meetings and the so-called non-disclosure of any material about its cadres', misconduct, is of no avail because the FIRs and other documents are matter of public record. Moreover, it is a fact that the suspension agreement was considered and yet the association was declared unlawful, presiously. Therefore, the material which has to be considered by this Tribunal is what existed after May, 2005. These show conflicting versions about the ANVC's cadres, about its broken promises (to ensure that cadres are kept in Camps) and its repeated default in surrendering all the arms—it continued to keep them its Liaison Office, under its control. No democratic organization or association intending to have legitimate or lawful political activity can afford to have secret and shifting headquarters, clandestine meetings and un-known location of its leaders. The evidence, it was submitted clearly showed that ANVC has possession of large quantities of arms and also has amassed wealth - yet no bank accounts were opened; nor it was a registered organization. On the face of these irrefutable materials, the only conclusion that can and should be drawn by the Tribunal is that though professing to be formed for a peaceful purpose, ANVC in reality wants to achieve the objective of Garoland, through armed struggle and use of arms and therefore, it is a direct threat to the territorial integrity of India.

72. Learned counsel contended that the judgment of the Supreme Court in Jamait-E-Islamia Hind Vs. Union of

India 1995(1) SCC had declared that the Tribunal has to follow a fair procedure which would mean that the minimum requirements of natural justice should be followed. It was contended that according to the Court, the materials in such matters as are subject to the assessment of the tribunal are not confined to legal evidence in the strict sense and that scrutiny is not that of a trial. Therefore, the Tribunal has to form an opinion on the points in controversy, by assessing for itself, the credibility of materials presented to it and even if at times such materials are not disclosed to the association. In this context he submitted that the evidence led before the Tribunal though in the form of affidavits and under oath, as well as the copies of the FIRs for the purposes of proceedings are sufficient material. He also sought to place reliance upon the intelligence report disclosed to the Tribunal, in confidence under Rule 3(1) on 9th of May, 2007.

73. Counsel supported the submission on behalf of the State Government of Meghalaya and stated that the provisions of the Act have to be construed in their natural and plain meaning, giving wide amplitude to the expression "sovereignty" and "integrity".

74. Learned Counsel supported and adopted the submissions on behalf of the State of Meghalaya so far as the ban on HNLC was concerned. It was contended that the deposition of CW-17, in addition, showed that top leaders of HNLC live in Bangladesh and also control camps including training camps. The HNLC indulges in extortion from business men and people in general. He submitted that according to the evidence, HNLC intimidates people and prevents them from taking part in elections such as filing nominations for polls to the Shillong Municipal Board, and issues secessionist statements, such as the one on 25-5-2006, indicating that it did not intend no intention to stop its armed struggle as long as the Government and the police continued to arrest its members. Counsel relied upon names and office bearers of HNLC, marked as Annexure to CW-17/I. It was submitted that HNLC maintains links with other banned organizations and has openly declared the objective of cessation of Meghalaya from India and is using violence and arms to achieve its purposes.

Submissions on behalf of ANVC

75. Mr. Amit Kumar, Learned Counsel for the ANVC first submitted that the Act has to be construed strictly, as it deals with crimes of an aggravated nature that were not perceived to be controlled by the normal or the ordinary criminal law. He submitted that in as much the enactment imposes restrictions and also creates related offences, the meaning of the expressions in it should not be enlarged by implication, or extended to cover situations that do not obviously fall within the terms. He relied upon the judgments of the Supreme Court reported as *Niranjan Singh Karam Singh Punjabi V/s. State of Maharashtra*, 1990(4)

SCC 76 and *Vijay Kumar Aggarwala V/s. State of Orissa*, (1996) 5 SCC 1 to say that the Act cannot be enlarged to cover alleged activities such as extortion and so on which can be sufficiently dealt with through the normal law of the land such as the Arms Act and the Indian Penal Code. The Act cannot also, it was contended, be invoked the remedy general problems associated with law and order.

76. It was next contended that having regard to the statutory scheme i.e. Section 3(1), the Notification dated 16-11-2006, as far as it purported to impose the ban on ANVC has no lawful effect and could not be acted upon. Learned counsel contended that the opinion of the Central Government has to be that an association is or has become an unlawful association. An unlawful association under Section 2(p) means any association which has for its object done any unlawful activity or which for its object has done any activity punishable under Sections 153-A or 153 B, IPC. Unlawful activity is defined by Section 2(0). Learned Counsel contended that the tenor of arguments on behalf of the State and Union of India indicated that Section 2(0) (ii) and (iii) were sought to be invoked for the purpose of saying that ANVC is unlawful and carrying on unlawful activity. He contended that the notification nowhere stated that activities of ANVC disrupt sovereignty or territorial integrity of India or that it causes any dis-affection among sections of the people. In these circumstances, in the absence of a textual disclosure, or formation of opinion about the alleged unlawful activity of ANVC, the proposed ban cannot be confirmed.

77. Learned counsel urged that the Central or State Government could not rely on any new or further ground in support of a flawed opinion shown on the face of the Notification. It was submitted that the basis of opinion about the unlawful nature of activities of ANVC and the conclusion drawn i.e. its being "detrimental", bind the Government which cannot thereafter seek to improve on that opinion by adducing fresh materials or affidavits. He relied on the proposition that a statutory order should be judged on the basis of what is disclosed on its face and it cannot be explained through further affidavits or pleadings and cited the decision in *Mohinder Singh Gill V/s. The Chief Election Commissioner*, 1978(1) SCC 405. Learned Counsel further submitted that the Act cannot be used as a preventive detention legislation. This was in the context of the statement contained in the Notification that —

"If these activities are not immediately curbed and controlled, the ANVC would re-group and re-armed themselves, expand their cadres, procure sophisticated weapons, caused heavy loss of life of civilians and security force and accelerate their anti-national activities"

It was submitted that this statement showed clearly that according to the Central Government there really was no unlawful activity but it formed the opinion to use the Act, as a preventive measure. He relied upon observations in *State of Madras Vs. V. G. Row*, AIR 1952 SC 196 and *Jamat-e-Islami Hind Vs. Union of India*, 1995 (1) SCC 428. He also relied on *Mohd. Zafar Vs. Union of India*, 1994 (Supp. 2) SCC 1 and stated that Government cannot rely upon stale material to form an opinion that the association or organisation was involved in unlawful activity.

78. Learned counsel further relied upon the notification and submitted that an overall reading and in the context of the previous submissions, the Tribunal has to return a finding that even according to the Central Government the object of ANVC was to hold talks and enter into a peaceful dialogue to abjure violence with the view of ultimately joining the political mainstream. He relied upon the recitation in the notification that ANVC agreed to abjure violence. This, it was submitted, disclosed non-application of mind to the facts since the Central Government clubbed the ANVC with the HNLC. The latter expressly and avowedly wanted to secede from the territory of India. It was submitted that this clubbing has acted to the detriment of ANVC as stale and old actions were made part of the opinion formation.

79. Learned counsel next urged that the affidavits and depositions of CW-1 and CW-17 are based on the records and not on personal knowledge. The authors of the documents or those who recorded the FIRs were not produced as witnesses. Further, the original documents were not produced for consideration. These, it was submitted, were fatal to the official case as primary evidence about the alleged activities were not produced, before the tribunal. He relied upon Section 64 and 65 of the Indian Evidence Act and also the judgment reported as *J. Yasodha Vs. Smt. K. Shobha Rani*, 2007(6) SCALE 6. The material produced in the enquiry at is, best hearsay evidence without disclosing the source and is not legal material which can be used or acted upon for the purpose of recommending a ban. It was submitted that Rule 3(1), mandated that the Tribunal should, as far as practicable, follow the Indian Evidence Act and that a departure should be made only if public interest so require it. It was submitted that opinion of the victims or authors of the documents or the FIRs produced before the Tribunal or even in Camera proceedings for testing the veracity of the claims, (the onus which lies primarily on the Government of satisfying through legally sustainable evidence about ANVC indulging in an unlawful activities) has not been produced or resorted to. Therefore, the Tribunal ought not to confirm the ban but ought to cancel the notification.

80. Learned counsel relied upon the evidence led on behalf of the ANVC i.e. deposition of RW-1 and submitted that ANVC is not indulging in any illegal or violent activity

or that it did not threaten or demand money from anyone. It was contended that the witness, who had no concern with ANVC, stated that Garo people were not having a fair share of development. This witness, was independent of any affiliation with the ANVC. Likewise, counsel relied upon deposition of RW-2, leader of the Labour Union, as well as evidence of RW-3, the President of the Traders Union which comprised of 50% non-tribal members.

81. Learned counsel also contended that RW-4, the General Secretary had in his deposition categorically affirmed that ANVC seeks statehood by peaceful means and that it has not indulged in extortion or illegal activity. It was contended that the witness had brought out the fact that till July 2007, the Government and central forces had suspended their activities, pursuant to a cease fire agreement. Learned counsel relied upon the portions of cross-examination of the witness to say that the suggestion that weapons were being kept have been denied. He also submitted that the desire of ANVC to join political mainstream has to be underscored by its submission of a memorandum as far back in 1999 to the Prime Minister. He also relied upon the deposition of RW-5 to say that this witness graphically brought out how the Garo people were deprived and felt justifiably neglected. In these circumstances, ANVC took up their cause and espoused the concept of a separate Garoland but within the framework of the Constitution of India.

82. Learned counsel next contended that although the State and the Central Government placed reliance on official witnesses and filed copies of certain documents, the depositions of these witnesses are unreliable because they have no primary knowledge of the so-called incidents. Counsel contended that the witnesses on being confronted with the materials by way of Minutes of Meeting of the Joint Monitoring Group, admitted that arms were surrendered and ANVC cadres lived in the three designated camps. If, in fact the State and the Central Authorities felt that ANVC or its cadres were indulging in subversive or unlawful activities, that would have been clearly mentioned or recorded in such Minutes of Meetings. In absence of such mention, the inescapable conclusion is that the cease fire agreement and its terms were accepted and followed, to the mutual satisfaction of all the parties. This inference, was essential and important for the ANVC because the Union Government as well as the State were unable to show any specific incident through legally acceptable evidence that the ANVC had gone back from its commitment to abjure violence.

83. Counsel contended that the so-called recoveries spoken of were not supported by any other material and that incidents of violence mentioned during the course of evidence were of stale and in any case prior to 20th July, 2004. Learned counsel submitted that in any case some-stray incidents involving deserters of ANVC or those

cadres who had been discharged from its camps could not be treated as authorized by it. Such individual acts contrary to the intent and the spirit of the agreement, were done at their volition for which ANVC could not be responsible. Counsel further submitted that the so-called fear psychosis and threat mentioned is absolutely baseless. Nothing prevented the State or Central Authorities from adducing independent evidence of even one witness to support the claim of ANVC or its cadres indulging in unlawful activities within the meaning of the Act.

Analysis of Legal issues

84. The following legal questions arise for determination, before the Tribunal can proceed to consider the correctness of the notification and return its findings either confirming the notification or cancelling it :

- (1) Nature of proceedings before the tribunal and the procedure to be followed;
- (2) Whether strict rules of evidence are to be followed;
- (3) Whether the notification ex-facie cannot be acted upon.

Re Point No. 1 :

85. The Supreme Court elaborately dealt with the scheme of the Act, its objectives, and the nature of the procedure to be followed, in *Jamaat-e-Islami Hind-Vs. Union of India* 1995 (1) SCC 428. The court felt that the exercise of fact sifting or "adjudication" was qualitatively different from assessment in the case of preventive detention; that the high value placed on the right to freedom of association, and the insistence of a sitting Judge of a High Court, having to man it, indicate that these were conditions for authorised infractions into the fundamental right. The court stated that the Tribunal, while undertaking its task, has to follow a procedure that would enable testing the veracity and credibility of conflicting claims. It was held as follows :

"The adjudication made would cease to be an objective determination and be meaningless, equating the process with mere acceptance of the ipse dixit of the Central Government. The requirement of adjudication by the Tribunal contemplated under the Act does not permit abdication of its function by the Tribunal to the Central Government providing merely its stamp of approval to the opinion of the Central Government. The procedure to be followed by the Tribunal must, therefore, be such which enables the Tribunal to itself assess the credibility of conflicting material on any point in controversy and evolve a process by which it can decide whether to accept the version of the Central Government or to reject it in the light of the other view asserted by the association..."

The court later discussed the fact gathering and sifting process which can be performed by the Tribunal, under the Act, having regard to the public interest in ensuring fairness (and transparency) on the one hand, and the other public interest in confidentiality, on the other.

86. Section 4(3), enables the Tribunal to "decide" whether to confirm a ban, or cancel it. This is, of course, after following the mandate of issuing a show cause notice to the associations concerned as to why the association should not be declared unlawful. Notices returnable on 12-2-2007 were issued; they were served at the address known to the Central Government, and also published in the newspapers having wide circulation in the area, both in English as well as in Garo and Khasi language. Additionally, notice by way of information was broadcast in the All India Radio. Pursuant to the notice, ANVC appeared, and contested the legality of the notification; the HNLC chose not to appear in the proceedings; though it was also served, in the same manner as the ANVC.

87. According to the Supreme Court, the process of "decision" making amounts to adjudication. The Act contains certain provisions providing a clue as to what should be the content of the adjudicatory process. The Section 9 no doubt outlines the procedure for disposal of applications; but significantly, it enacts, *inter alia*, that

"the procedure to be followed by the Tribunal in holding any inquiry under sub-section (3) of Section 4 or by a court of a District Judge in disposing of any application under sub-section (4) of Section 7 or sub-section (8) of Section 8 shall, so far as may be, be the procedure laid down in the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), for the investigation of claims and the decision of the Tribunal or the Court of the District Judge, as the case may be, shall be final."

(emphasis supplied)

"Code" has been defined as "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)" by Section 2(c). Section 9 which talks of the procedure, is subject to rules. Rule 3(1) of the Rules, framed in 1968 prescribes that the Indian Evidence Act, 1872, "as far as practicable" shall be followed. An inquiry, as for instance, under Section 202 of the Code, is not a "trial". That stage arises only after the court considers the evidence of the prosecution or the complainant, and issues process. Even though the accused might participate in the proceedings, he would be doing so as a member of the public, not as an accused. [Ref. *Vadilal Panchal Vs. Dattatraya Dulaji Ghadigaonkar* (AIR 1960 SC 1113 : 1960 Cri LJ 1499), *Chandra Deo Singh Vs. Prokash Chandra Bose* (AIR 1963 SC 1430 : 1963 (2) Cri LJ 397); *S. S. Khanna Vs. Chief Secretary, Patna* AIR 1983 SC 595; *Jarnail Singh Vs. State of Haryana* 2003 (109) Cr. LJ 2307 (SC)]. Therefore, inherently, the proceedings are not in the nature of a trial, and even the court only inquires broadly whether the

complainant has made out a case for issuance of process, on a prima facie basis [Ref. Kewal Krishan Vs. Suraj Bhan 1980 (86) Cr. LJ 1271 (SC)].

88. The net result of the above analysis is that the Tribunal's role, under Section 4(2) is adjudicatory; this delineates its task as radically different from the work of Advisory Boards set up under preventive detention laws. The adjudicatory role necessarily affords greater intrusion into the evidence, materials and decision making process that goes into formation of opinion of whether an association has to be declared as unlawful. Further, the decision in Jamaat had emphasized that the tribunal's procedure should be fair and one may add, reasonable—because its task comprehends likelihood of restricting the fundamental right to association, though for a limited period. However, this adjudicatory process is not a trial; its procedure is to be like an inquiry, aimed at gathering materials needed to form conclusions. Likewise, the argument that the provisions of the Act have to be construed strictly, are unacceptable, because the statute does not involve penal consequences; if it were so, the procedure, nature of trial and standards would have been as in the criminal case of a trial.

Re Point No. 2

89. This question too was addressed and dealt with by the Supreme Court in the Jamaat decision. The court, after considering Sections 4, 9 and the Rules, held that :

"22. It is obvious that the unlawful activities of an association may quite often be clandestine in nature and, therefore, the source of evidence of the unlawful activities may require continued confidentiality in public interest. In such a situation, disclosure of the source of such information, and, may be, also full particulars thereof is likely to be against the public interest. The scheme of the Act and the procedure for inquiry indicated by the Rules framed thereunder provide for maintenance of confidentiality, whenever required in public interest. However, the non-disclosure of sensitive information and evidence to the association and its office-bearers, whenever justified in public interest, does not necessarily imply its non-disclosure to the Tribunal as well. In such cases where the Tribunal is satisfied that non-disclosure of such information to the association or its office-bearers is in public interest, it may permit its non-disclosure to the association or its office-bearers, but in order to perform its task of adjudication as required by the Act, the Tribunal can look into the same for the purpose of assessing the credibility of the information and satisfying itself that it can safely act on the same. In such a situation, the Tribunal can devise a suitable procedure whereby it can itself examine and test and the credibility of such material before it decides to accept the same for determining

the existence of sufficient cause for declaring the association to be unlawful. The materials need not be confined only to legal evidence in the strict sense. Such a procedure would ensure that the decision of the Tribunal is an adjudication made on the points in controversy after assessing the credibility of the material it has chosen to accept, without abdication of its function by merely acting on the ipse dixit of the Central Government. Such a course would satisfy the minimum requirement of natural justice tailored to suit the circumstances of each case, while protecting the rights of the association and its members, without jeopardising the public interest. This would also ensure that the process of adjudication is not denuded of its content and the decision ultimately rendered by the Tribunal is reached by it on all points in controversy after adjudication and not by mere acceptance of the opinion already formed by the Central Government."

(emphasis supplied)

Section 5(5) enables the Tribunal to regulate its own procedure; Section 5(6) enables it to use powers vested in a civil court, under the Code of Civil Procedure, for the purpose of summoning and attendance of witness, discovery and production of evidence; reception of evidence through affidavits; requisitioning of public record from any court or office, and issuance of commission for examination of witnesses. Section 9(3) is titled, perhaps misleadingly as "Procedure to be followed in the disposal of applications under the Act". As noticed in the previous discussion, the procedure is as enacted in the Code. The section is subject to the rules; Rule 3(1) expressly states that the tribunal's should follow, as far as practicable, provisions of the Indian Evidence Act. The cumulative effect of these provisions, and the discussion in Jamaat and the provisions of the Act are that the procedure to be followed by the tribunal should be fair, affording the concerned individual or association a proper opportunity of confronting and meeting the evidence or materials disclosed by the State of Central Government in support of the claim for confirmation of the declaration that the organization should be banned. The tribunal should, wherever possible (as is evident from the expression "practicable") follow the provisions of the Indian Evidence Act. However, having regard to the nature of the proceeding (inquiry akin to one under the Code of Criminal Procedure, as juxtaposed to a trial) and likelihood of sensitive nature of material likely to be disclosed during the proceeding before it, the tribunal is not hidebound by rules of evidence; it has to follow them in the spirit, and the principles of Evidence Act.

Re Point No. 3

90. A decision on this point is called for, since the counsel for ANVC took the position that the notification

dated 16-11-2006 is not sustainable, as it nowhere recited anything adversarial to that organization. He also urged that the Central Government could not traverse beyond the grounds or contents of the notification to say that the ANVC was an unlawful organization, and to the extent there is dichotomy between the grounds mentioned expressly and the contents of the affidavits, the latter should not be seen by the tribunal. He also urged that the clubbing of ANVC with HNLC and issuance of a common notification showed non-application of mind, since the grounds could not be common.

91. The first objection raised pertains to absence of any reference to the expressions under Section 2(o) which define unlawful activity, such as any association acting so as to "disclaims, questions, disrupts or is intended to disrupt the sovereignty and territorial integrity of India; or "which causes or is intended to cause disaffection against India;" in the notification. The counsel urged that the notification had merely recited that Central Government is "of the opinion that the aforesaid activities of the ANVC and the HNLC are detrimental to the sovereignty and integrity of India;". The submission was that the provision required specific opinion about acts questioning, disrupting, or intention to disrupt the sovereignty and territorial integrity of India, or cause of intended to cause disaffection against India; the notification did not mention any of these, and used "detrimental".

92. According to the Merriman Webster Online Dictionary (www.m.w.com/dictionary/detrimental accessed on 13-5-07 at 18 : 41 IST) "detrimental" means "obviously harmful"; damaging; pernicious. The Oxford dictionary (<http://www.askoxford.com/> accessed on 13-5-2007, at 18 : 44 IST) detrimental means harm or damage. These show that the expression "detrimental" bears the same meaning as harming or causing injury. The expressions used in the Act, defining unlawful activities are "disrupt" the territorial integrity or sovereignty of India. Although the notification in question does not use the same expression, that, in my opinion, has not resulted in a fatal infirmity; the notification expressly recites that the Central Government has formed the opinion that the associations are unlawful, and indulge in unlawful activities. If these, and the aim of the activities, undermining the sovereignty or the territorial integrity are taken into consideration, the conclusion which has to inevitably follow is that the lapse or omission in the use of the expression "disruption" cannot invalidate the notification. Furthermore, the process of adjudication by the tribunal is meant to assure meaningful hearing, and opportunity to the concerned group or association to show that its activities are not unlawful. It is well settled that a mechanical incantation of the statutory conditions by themselves do not imply that the requisite objective facts exist; those are matter of inquiry, as in this case, by the Tribunal.

93. The next question is whether the Central Government can rely on instances that were not mentioned in the grounds published in the notification. Reliance had been placed upon the decision in Mohinder Singh Gill to say that the grounds mentioned in a statutory order cannot be improved upon. No doubt, the proposition that a statutory order has to be tested on the basis of the contents appearing on its face, and no other pleadings or evidence can be seen by the court, is well settled. However, the distinction between the order under the Act, and other statutory orders, is that this order sets into motion the mechanism of a decision making process, through materials and evidence before an impartial tribunal, which has to be satisfied on the basis of what is placed before it; in other cases, orders reflect the opinion or decision of the Government. The notification and process under the Act assimilates an adversarial procedure where the association as well as the Central Government and others interested, are afforded opportunity of hearing and adducing evidence. Therefore, the analogy, and reliance on the proposition that the authority is bound by the declaration or recitals in a statutory order, is inapt in the case of a tribunal under the Act.

94. The third facet raised is that the Central Government issued the notification, as far as ANVC was concerned, without application of mind. The opening recital, which mentions about the assurance of ANVC to abjure violence, has been relied upon. It was urged that this shows that the nature of allegations against both organizations are different, and that there were no grounds to issue the notification as far as ANVC was concerned.

The notification states as follows :

"Whereas the Achik National Volunteer Council (hereinafter referred to as the 'ANVC') of Meghalaya have continued collection of funds and extortion despite having agreed to adjure violence and having expressed their willingness to hold talks within the framework of the Constitution of India for fulfilling their demands."

It later mentions that about opinion of the Central Government that both ANVC and HNLC have been:

- (i) indulging in acts of intimidation, extortion and looting of civilian population for collection of funds for their organization;
- (ii) maintaining links with the other insurgent groups of the North Eastern Region for carrying out acts of extortion and intimidation;
- (iii) maintaining camps in some neighbouring countries for the purpose of sanctuary and training of their cadres.

And whereas the Central Government is also of the opinion that—

- (i) the ANVC was involved in twenty four violent incidents in 2004, six violent incidents in 2005 and one violent incident in 2006 (upto 31st August, 2006),
- (ii) These violent incidents by ANVC resulted in killing of 12 persons (including 4 security Forces) in 2004 and one person in 2005;...”

These recitals were later followed by the opinion that ANVC was an unlawful association. Facially, I am of the opinion that the mention of two organizations do not vitiate the notification or opinion formation that ANVC is an unlawful association. The mention of its agreement to abjure violence is only to show that despite assurance, it continued to indulge in acts of extortion, and collection of funds. The tenor of the entire notification shows that the Central Government was conscious about the difference in the nature of the activities of the two associations; it dealt with them separately.

Discussion of Evidence and Findings

95. CW-1 and CW-2 are the Deputy Commissioner and Superintendent of Police of Jaintia Hills District, Jowai. They deposed about continued acts of violence and looting by the HNLC cadres. CW-2 has narrated incidents of 25th January, 2005 and 25th March, 2005, concerning looting and kidnapping. However, in my opinion, those incidents cannot be taken into consideration by this Tribunal because they relate to periods that were considered by an earlier Tribunal, as such they are stale grounds. CW-2 has also spoken of a kidnapping incident dated 25th May, 2005 and lodging of an FIR at Jowai and the kidnapped person being killed. He narrated about arrest of one Bashembha Pathaw on 8-1-2006 and recovery of 10 Chinese made AK-47 live ammunition and surrender of six HNLC cadres in Jaintia Hills between May and July and between 8th May, 2005 and 16th July, 2006. The cadres also surrendered weapons. CW-2 deposed that both HNLC operates in the District but HNLC is more active and that NSCN(IM) is the main supporter of that organisation.

96. CW-3 and CW-4 are the Deputy Commissioner and Superintendent of Police of East Khasi Hills District. The former mentioned about links between HNLC, ULFA, NDFB, NLFT and NSCN. He stated that the main target of HNLC is business community. CW-4 deposed about several incidents in the East Khasi Hills District, including kidnapping, operation for rescue of the victim on 10-7-2005, lodging of an FIR before Mawsynram Police Station. A copy of the FIR was placed in the file of the Tribunal. It also spoke of recovery of three rounds of 9 mm live ammunition, one hand grenade of Chinese make, DBBL gun etc. CW-4 mentioned about HNLC's call for Bandh on 14-8-2005 and later as well as a demand by it from

Pratul Chandra Deka on 22-9-2005, arrest of HNLC cadre and filing of PS. Laban Case No. 53 (09) of 2005. He mentioned about other incidents, namely, dated 23-12-2005, leading to charge sheet dated 6-7-2006 where 9 mm piston with magazine loaded with 7 rounds of ammunition were recovered. He also deposed about a Bandh call in respect of the Republic Day Celebration on 26th January, 2006 and the killing of Aibor Marwein on 26-3-2006, registration of Police Case No. 16(3)06. A copy of that FIR was shown to the Tribunal and is part of the record. He further mentioned about arrest of Kampher Frankly Syiem on 6-7-2006 and recovery of incriminating documents, leading to registration of Shillong Sadar Police Station Case No. 128(07) of 2006. The deposition further included statement about boycott of Independence Day on 15th August, 2006 and a demand on 28-9-2006 for Rs. 10 lakhs from Rahul Jasararia. He spoke about another incident on 20-9-2006 in the morning and an encounter which took place that day in Umkrem village leading to arrest of two HNLC cadres and the death of another person. He mentioned about activities of HNLC in East Khasi Hills which has a long International Border, Bangladesh where its top leadership is allegedly hide.

97. CW-5 and CW-6 are Deputy Commissioner and Superintendent of Police respectively of West Khasi Hills District Nongstoin. They spoke about both HNLC and ANVC but mainly about HNLC. According to CW -6, the HNLC's activities are aimed at disruption of sovereignty and territorial integrity of India through arm struggle. He stated that its cadres operated in Nongiri, Umbar, Nonghyllam, Ponnawdar and Maweit areas. He also stated that HNLC cadres extort money from the business class and indulge in dacoities, theft and attack on police parties; according to him HNLC has direct links with the NSCN(IM) and NLFT. These banned organisations help HNLC by training the cadres and giving other supports which undermines the security and peaceful life in the State. He spoke about an encounter with HNLC leading to death of its cadres on 22-6-2006, at Honghyllam village, recovery of carbine with six round of live ammunitions, one revolver with five rounds of .32 ammunitions and other incriminating documents. This is subject-matter of PS case No. 13(6)06. The witness spoke about another incident when a raid was conducted on 18-11-2006, leading to recovery of two demand notes by HNLC signed by its Finance Secretary.

98. CW-7 and CW-8, Deputy Commissioner, Ri-Bhoi and Superintendent of Police, Ri-Bhoi more or less deposed in the same manner. CW-7 spoke of relationship between HNLC and other banned groups such as ULFA, NDFB and KNV. CW-8 produced materials through a list giving specific instances. According to him one Kalenderson Wanniang of the finance wing of HNLC was arrested and a demand note of HNLC signed by its Finance Secretary was recovered. This arrest led to disclosure about distribution of several demand notes to business men and the filing of P.S. Case No. 45 (6)03.

99. CW-9, Commissioner and Secretary to Government of Meghalaya spoke about unlawful, nefarious and anti-national activities of HNLC in the District of East Khasi Hills, West Khasi Hills, Jaintia Hills and Ri-Bhoi of Meghalaya. She stated that the principal object of HNLC is to achieve a separate state that would not be part of India. She deposed that HNLC calls for Bandh and threatens people not to attend national day celebrations. According to her HNLC is active in Khasi and Jaintia hills since they have a long International Border; it maintains good relations with other banned insurgent groups like NSCN, ULFA, NDFB and NLFT; they train the cadres of HNLC. She submitted that HNLC mainly targets the business community and extorts money from them. She stated detailed recoveries of weapons such as 1 AK Rifles, one 303 Rifle, 2 Shotgun, one Pistol, 1 Revolver, 30 ammunitions, 1 empty magazine, 1 hand grenade were recovered in 2005 and three carbines, 1 pistol, 3 revolvers, 31 ammunitions, 2 empty magazine were recovered in the year 2006. She also filed a copy of the newspapers intimating that the two organisations, namely, ANVC and HNLC were unlawful as proof of publication of the show cause notices.

100. CW-17, Sh. R. R. Jha, Director to the Government of India, Ministry of Home Affairs deposed that the HNLC's aim is to liberate the Hynniewtrep people from the so called authoritarian rule of the Indian government, protect the Khasis and other Meghalaya tribes from exploitation and preserve the indigenous culture. He deposed that HNLC threatens people not to participate in the national day celebration and calls for Bandhs. He spoke about HNLC's involvement in unlawful activities like extortions, particularly in the coal sector in Khasi-Jaintia areas, extortion from business community, looting civilians to collect funds, intimidation and kidnappings. He too stated that the HNLC has links with banned associations declared as unlawful based at Bangladesh. He deposed that the ban should be extended since the previous ban had to a certain extent helped in curbing the organisation and its activities.

101. The above discloses that for the relevant period, namely, between May/June 2005 and December 2006, the evidence led on behalf of the Union of India through affidavits and the depositions and the stand of the State of Meghalaya (which also supported the Central Government's opinion that HNLC is unlawful), have shown about 12 incidents that led to lodging of FIRs. These incidents concerned allegations related to murder, kidnapping, extortion and seizure of illegal weapons from the cadres/members of HNLC.

102. The depositions of all the witnesses on behalf of State of Meghalaya show that HNLC is active and functions in East and West Khasi Hills Districts, Jaintia Hills District and Ri-Bhoi District. According to the witnesses on behalf of the State of Meghalaya, it also

maintains active links with banned organisations such as NSCN, ULFA, NDFB, KNV and NLFT etc. There have been some incidents where HNLC's cadres died in encounter and were arrested, which led to recovery of weapons. The evidence further points to HNLC holding out threats to the people in 2005 and 2006 and preventing them from participating in national celebrations for Republic Day and Independence Day. Additionally, the witnesses deposed that HNLC wants a separate State for Hynniewtrep people outside the territory of India. According to these witnesses, who include the Superintendent of Police of the four Districts, the top leadership of HNLC is based outside the Indian border, in Bangladesh. HNLC also seeks the help of other associations declared unlawful for training and resource building etc.

103. The Tribunal had issued show cause notice, which was published in the local newspapers at Shillong and all the District Headquarters, returnable on 12-2-2007. The HNLC did not choose to appear or file its response. Proceedings and public hearings held in Shillong on two separate occasions, namely, 12-4-2007 to 14-4-2007 and on 6-5-2007. Wide publicity about the hearings was given in the English language newspapers as well as the local newspapers such as in Garo and Khasi. Copies of those newspapers' publication are part of the record. Despite these HNLC has chosen not to appear and contest the proceedings.

104. The analysis of unrebutted evidence shows that HNLC is an organisation committed to achieving a separate or independent State for the Hynniewtrep people outside India and to that end it seeks to achieve the objective through acts of violence. These acts of violence include attacks on police personnel, use of sophisticated and illegal weapons, repeated acts exhorting the people not to attend national day celebrations, preventing people from participating in the democratic process (as in the case of holding out threats against candidates from filing nominations for the elections in the Shillong Municipal board) etc. The evidence also points to HNLC maintaining contacts and link with four other organisations that have been declared unlawful. Its leadership is in Bangladesh where they have camps to train cadres and where apparently they flee after committing acts of kidnapping, extortion and other acts of violence.

105. Individually the 12 FIRs spanning a period of two years may not seem to be serious. However, what is to be considered is the pattern of activities. A common thread appears to run through all these - the objective appears to be to intimidate people, disrupt normal functioning and undermine economic activity through extortions and kidnapping. The incidents where repeatedly HNLC has held out threats against people to prevent and intimidate them from participating in national day celebrations coupled with the threat held out against people wanting to participate in

the democratic process, display its commitment to pursue the path of violence to achieve the end of a separate State through armed struggle and violence. This clearly establishes that its activities do not have any lawful aim but are meant to undermine and disrupt the sovereignty and territorial integrity of India. In view of the above discussion and after considering all the materials on record, this Tribunal is of the opinion that sufficient materials have been shown (in the enquiry held by it) by the Union of India and the State of Meghalaya to confirm the Notification under Section 3(1).

106. As regards the ANVC, the Central Government has relied upon deposition of Sh. R. R. Jha, CW-17 and his affidavit; it is supported by the witnesses on behalf of the State of Meghalaya, primarily, CW-10 to CW-16. CW-10, the Commissioner and Secretary to the Government of Meghalaya, Political Department in her affidavit deposed that she enclosed press clippings of local newspapers intimating in Shillong Times dated 12-12-2006, 'U-Mawphor' of the same date and Satantini Janera dated 13-12-2006 intimating about the Notification. The publication through newspaper clippings, containing the show cause notice issued by this Tribunal in those newspapers dated 30-12-2006 and 4-1-2007 as well as in respect of "The Telegraph" Kolkata dated 30-12-2006 have been enclosed. The witness enclosed documents evidencing broadcast of notices in the All India Radio and Doordarshan, Shillong.

107. She deposed that ANVC engages in acts of intimidation and extortion from non-tribal businessmen, particularly in Tura and other towns of Garo Hills. She deposed about leaders of the ANVC forcing Coal Traders to buy forms at highly inflated rates from their agents without lawful authority. This witness mentioned about the Tripartite Settlement of July, 2004, establishment of a Joint Monitoring Group to monitor the ceasefire and setting up of camps. According to her ANVC refused to hand over arms and ammunitions which, were kept in a Liaison Office of ANVC at Tura. She mentioned about intelligence reports to say that ANVC continues its links with other organisations in Bangladesh and has established safe havens there. According to her ANVC cadres deserted camps with weapons between May 2005 and April, 2006. They formed two Organizations, Achik National Liberation Front (ANLF) in East and South Garo Hills and Achik National Youth (ANY) in West Khasi Hills. She deposed about arrest of ANVC cadres including deserters and recovery of two AK series rifles and several banned weapons. A list of ANVC cadres said to have been involved during 2005—2007 with their names and involvement in different police cases has been produced with the affidavit; a common list containing the recoveries of arms and ammunition has also been filed.

108. Counsel for the ANVC had extensively cross-examined her. The witness deposed that the Government

of Meghalaya had no objection to extension of agreement but at the same time denied the suggestion that the Joint Monitoring Group at any stage expressed satisfaction about adherence to ground rules by the ANVC. She maintained that the objective of ANVC is to achieve Statehood through armed struggle. She stated that list of all ANVC members were with the Government but also volunteered to the Tribunal that such a list cannot be considered as exclusive because the ANVC re-groups. The name of the Chairman of ANVC does not find mention in the list. She also mentioned about the differences in the list. She again highlighted, during the cross-examination about the ANVC not surrendering arms and keeping them at a neutral place. According to her the extension of ceasefire was not objected to by the State of Meghalaya to facilitate the on-going peace process.

109. CWs-11 & CW-12, Deputy Commissioner West Garo Hills and Superintendent of Police, of the district, supported their depositions on affidavit and deposed that ANVC carried out its unlawful activities in the district and it has links with NSCN, ULFA & NDFB to supply arms and ammunition. According to them the unlawful activities include extortion, killing and intimidation. CW-11 admitted in the cross-examination that some sections of the Garo community have resentment on certain issues of governance which were expressed through bandhs etc. but denied that ANVC has the support of any section of the Garos. He also stated that there were several violation of the ground rules. He agreed, upon being shown Minutes of Monthly Review Meeting on 8-12-2005 that they did not record violation of terms of the agreement. According to him the objective of the meeting was to bring home the benefits of abjuring violence. He volunteered in his cross examination about the incident which took place on 25-8-2005 when the Joint Secretary of ANVC along with some cadre members forcibly entered the chambers of the District Magistrate which was reported. He admitted that there were some deserters from ANVC camps. CW-12 submitted his affidavit, which described different incidents, on 15-2-2006, 17-2-2005, 5-4-2006 and 14-4-2006. He affirmed that these incidents were a few of the many in the district, most of which were unreported due to fear psychosis in the general public. According to CW-12 the objective of ANVC is to achieve Garoland through armed rebellion i.e indulging in activities like extortion, criminal intimidation, looting, the public and attempts to capture business in Garo Hills. He also deposed that in the two areas three ANVC cadre members were arrested. According to him the business community is targeted and that they have links with banned organizations. He produced CWs-12/2 wall calendar, CW-12/3 table calendar for 2007 and CW-12/4 copy of a document entitled "Army formation of Achik National Volunteer Council" in Garo printed at Chiram Printing Press and its translated copy, CW-12/5.

110. In cross-examination, CW-12 admitted that ANVC leaders were permitted to carry small fire arms but not allowed to wear them in public places. He denied about threats from other organizations and admitted that according to clause 5 of the agreed terms of ceasefire, ANVC leaders could be provided PSO's from the Meghalaya police. He, however, stated that none of the leaders sought such protection. He also stated that ANVC had not been cooperating with the police and other organizations. He admitted that there were deserters from ANVC camps and denied the suggestion that ANVC did not maintain links with any other banned or unlawful organization. In his cross-examination he stated that ANVC imposed a tax of Rs.5 per kilo on the sale of dry fish in Tura and deposed also that ANVC had imposed a ban on the sale of DTH technology, which affected business in Tura. According to him ANVC controls the cable business operations. He admitted that though he is empowered to register an FIR into such incidents, chances of their success would be bleak since people would be unwilling to depose in support of the allegations on account of fear. He denied that ANVC was being singled out, to deprive it from participating in mainstream political activities.

111. CW-13 & CW-14 deposed about the South Garo Hills district and tendered their affidavits CW-13/1 and CW-13/2. CW-13 is the Deputy Commissioner, South Garo Hills, Baghmara and CW-14 is the Superintendent of Police, South Garo Hills. According to them one incident being Baghmara Police Station Case No.20(5)/2005 was reported and other incidents were not reported due to fear. Mainly non-tribals are targeted for extortion and in some cases local businessmen are also subjected to extortion. CW-13 stated that shopkeepers in Tura do not sell DTH equipments to residents since ANVC has a monopoly and controls the cable business. In her cross-examination she denied the suggestion that ANVC had not indulged in extortion or related activities and also denied the suggestion that ANVC does not maintain links with banned organizations. In the cross examination she mentioned about the incidents of extortion by ANVC and its cadres from coal traders in Nongal Bibra.

112. CW-14 the Superintendent of Police of South Garo Hills mentioned about the incident dated 2-5-2005 where firing by ANVC cadres lead to arrest of some people, recovery of weapons and the lodging of an FIR being Baghmara P.S. Case No.20(5)/2005. According to him ANVC has relationship and links with banned insurgent groups like NSCN, ULFA, NDFB etc. and has its headquarters at Bangladesh. He stated that the previous declaration had helped in curbing the activities of the organization. In his examination-in-chief he stated that apart from members of the business community headman of villages were also threatened by ANVC as also Government officials. He stated that ANVC cadres are concentrated in coal belt area of Nangal Bibra. In cross-examination he expressed lack of

knowledge where the previous S.P. of South Garo Hills requested to ANVC to arrest the police about information regarding 6 ANVC deserters. He denied the suggestion that ANVC had not indulged in illegal activities or that it had no links with banned organizations. He stated in the cross-examination that ANVC was not supposed to carry arms as per the ground rules yet recoveries of arms were made.

113. CWs-15 & 16 the Superintendent of Police, East Garo Hills, and Deputy Commissioner, East Garo Hills, Williamsnagar deposed and tendered their affidavits as CW-15/1 and CW-16/1. CW-15 deposed and tendered copies of the FIRs. They relate to several incidents, involving kidnapping, and murder. CW-15 mentioned that ANVC cadres forcefully controlled many district councils gates in three districts of Garo hills and in order to gain sympathy it purchased ambulances and vehicles etc., and donated them to the people. He mentioned that seizure of one such vehicle later revealed that it was used by ANVC cadres for carrying on illegal activities. He mentioned about the incident of 8-8-2006 where ANVC cadres were nabbed by any personnel at Dabas and 9 mm pistol with of live ammunitions were seized. According to him ANVC cadres also indulged in felling of trees from preserved forest and there is under reporting of the activities due to scare among the people. The main supporters of banned organizations in East Garo Hills include ULFA, NDFB, NSCN etc. According to CW-15 the basic objective of ANVC is to achieve a separate sovereign State through armed struggle and the ANVC cadres carry banned weapons; they also prohibit celebrations and observance of National festivals, Independence and Republic Day. He admitted that three designated camps of ANVC cadres are supposed to reside and one of them is located in his District. He however stated that in spite of that condition many cadre members never actually stayed in the camp. He did not deny that in some previous cases there were deserters from the camps.

114. CW-16 deposed that ANVC is actively involved in unlawful activities in East Garo Hills and that its top linking leaders are in hiding. Its cadres raise funds by extortion. The witness deposed that ANVC has links with banned organizations such as ULFA, NSCN(IM) and NDFB. According to him the declaration of its being unlawful had helped earlier to curb its activities. In the cross-examination he stated that the last time ANVC called for bandh on Independence Day and Republic Day celebrations were in 2004.

115. CW-17 tendered two affidavits CW-17/2 & CW-17/3, he is the Director to Government of India, Ministry of Home Affairs. According to him the ANVCs objective is creation of a separate State of Garoland and that it was formed on 24-9-1996. Its headquarters is at Chiram, an unknown place. Its Constitution refers to existence of Cabinet, Commander-in-Chief, Army Staff, Army Department,

passing of bill by the Cabinet, all of which indicate that it does not function within the framework of the Indian Constitution. Its Constitution also requires physical health check of the prospective members, by the intelligence and investigation unit of the organization and also that the members are prohibited to disclose the plan and secrecy of the party. The objective of ANVC is creation of a separate State of Garoland comprising of three Garo hills districts of Meghalaya and contiguous areas inhabiting of Garo's, West Garo Hills and Ri-Bhoi Districts of Meghalaya as well as Golpara and Kamrup Districts of Assam, which has led to resentment in those areas. The demand has prompted enmity between Khasi's as well as Garos and other people. According to the witness the demand attempts to create disharmony and spread of hatred and ill-will. He stated that the activities of ANVC has led to ill-will between different people.

116. CW-17 also stated that to achieve its objective, ANVC intimidates State functionaries and the public, raises funds through extortion, kidnappings, robberies, indulges in establishment of bases in remote areas and also maintaining links with other underground outfits or banned organizations. In his affidavit CW-17 enclosed three statements detailing incidents of violence by ANVC in 2004-2005 and 2006. CW-17 stated that ANVC had entered into an agreement for suspension of operation with Government of India and Government of Meghalaya on 23-7-2004, initially for six months. It was extended periodically and is now valid upto 23-7-2007. The ANVC agreed to abjure violence and expressed willingness to talk within the framework of the Constitution. A Joint Monitoring Group comprising representatives of army, paramilitary forces, Government of Meghalaya and Central Government is monitoring the ceasefire. The witness stated that further to the ground rules ANVC cadres were accommodated at Jetrage Chokpot Camp in South Garo Hills, District and Samanda Camp in East Garo Hills District of Meghalaya and a liaison office was established at Tura. A list of 202 cadre members were submitted by ANVC to Government of Meghalaya but only 120 cadres stayed in the designated camps. The list provided does not contain names of important persons like the Chairman, Dilash Marak, Jerome C. Monin (Self Styled Commander-in-Chief) who are not staying there.

117. CW-17 stated that the ANVC deposited only 16 weapons and that many other weapons continue in their possession which posed a threat to law and order. He stated that cadres of ANVC have been deserting the camps and indulging in undesirable activities. Some such deserted cadres, under the leadership of Nobin K. Makak floated Achik National Liberation Front (ANLF) and indulged in criminal activities. CW-17 stated that according to reports even after staying in the camps the cadres indulge in large scale extortions, collecting "donations" from coal traders and other target groups. He mentioned about incidents of

30th May, 2005, 7th October, 2005 and 5th April, 2006 where specifically named persons deserted the camps with arms like 3 AK-47 rifles, magazines and three Chinese handgrenades, two self-loading rifles etc. He stated that the incidents point to ANVC not having control over its cadres and being an anarchic organization. The witness stated that even after suspension of operations ANVC is active in Garo hills and engages in activities aimed at acquiring and enhancing financial capabilities and acquiring legitimacy; its cadres continued to carry illegal arms and ammunitions in sizeable quantities and are in various hideouts. ANVC according to CW-17 acquired rights for weekly haats and taxes businessmen in Tura for their transactions. They terrorize people who are scared to report against them.

118. CW-17/3, the encloses a copy of the ANVC Constitution drafted on 26-6-1996. The witness was mainly cross-examined regarding violation of ground rules and whether they were reported. He was confronted with the Minutes of the Joint Monitoring Group Meeting of 17-1-2005 and asked whether the Central Government took any action. In reply he stated that the State Government took action not only in respect of such incidents but also others. In cross-examination he stated that in the Meeting of 11-7-2006 ANVC was asked to furnish a complete list of its cadres. A list of 202 cadres was provided in August, 2006. Out of these only 120 stayed in the Camps. He also stated in the cross-examination that only a list of 16 weapons was provided further to the understanding.

119. The evidence led on behalf of ANVC were depositions of five witnesses. RW-1 is a functionary of the Achik Peace Foundation; he supported the ANVC and stated that the organization never threatened anyone or demanded money through extortion. According to him an incident took place on 30-9-2005 after which various denominations of Church groups became active in promoting peace. RW-2 a trade Union leader supported his affidavit RW-2/1 and claimed that he has close relations with non-tribals who were in substantial numbers, and were members of the Union. According to him ANVC never indulged in threats or intimidation; it promotes interests of the Garo people with a view to support Statehood. In the cross-examination he stated that there are a thousand members of the Union and for subscription, a Registration Fee is Rs. 100 each is charged from new members. He stated that majority of the members of the Union are non-tribals and that if there is any threat by ANVC to them, it is forwarded to the Union. He maintained that ANVC's involvement resulted in reduction of incidents in looting, gambling and drinking. He expressed lack of knowledge about activities of ANVC. He also stated that cadre members of ANVC visit the region where he resides and they do not carry any weapons. He is also not aware about the source of funds of ANVC.

120. RW-3 tendered his affidavit as RW-3/1. He claimed to be President of the Garo Hills Traders Union formed with the objective to promoting and safeguarding the interests of the region. He mentioned about the activities of the Union, comprising of about 1000 members of whom about 50% are non-Garos. He expressed lack of awareness about ANVC's lodging any objection to the notification proposing that it should be declared as unlawful. He also deposed that he was never made aware of any member of the Association being asked to pay any money to ANVC or any threat or harassment to any traders.

121. RW-4 tendered his affidavit dated 13-4-2007 as RW-4/1. He is the General Secretary of ANVC 'since 1998. According to him the objective of ANVC is a creation of separate Garoland to shape their destiny. He deposed about agreement of suspension of operations and about meetings held on separate occasions. He specifically deposed about a meeting on 17-1-2005 where ANVC qualified that its cadres were not indulging in unlawful activities and that police should take action against those using ANVC's name in extortions. He deposed that ANVC was not recruiting any new cadres. He stated that a complete list of cadre members in designated camps with photographs, address etc. was to be submitted in accordance with the decision on 18-7-2005. He also stated that the weapons possessed by ANVC cadres were for self-defence. He claimed that ANVC is not an illegal organization and is also not involved with ULFA, or other similar groups. He claimed that other similar groups such as Achik National Liberation Front are involved in extortion, kidnapping etc. He asserted that none of ANVC's top leaders reside in Bangladesh and they are not carrying out any illegal activities. He stated that ANVC carried out large substantial social activities like Tsunami Relief Fund from contributions made by its members voluntarily and it also donated two ambulances to villagers.

122. In the cross-examination RW-4 deposed that Garos deserve a separate State due to discrimination against them. He stated that ANVC submitted a list of 202 members of its cadres which are maintained by well-wishers and the Garo people. ANVC does not have a separate source of income but is supported by the contributions of the people on regular basis. According to RW-4 ANVC does not maintain large number of weapons but those possessed by it were kept in joint custody. The weapons were needed for self-defence and all of them were obtained from smugglers. He denied that the weapons were obtained from Bangladesh or snatched from police, paramilitary and armed forces. He admitted that the list of weapons given to the State Government included five LMGs, AK-56 rifles and 155.56 MM rifle etc. He clarified that all these were used for self-defence. He expressed lack of knowledge about the number of cadres in each camp and stated that list of cadres were furnished according to the designations used by the ANVC. He denied the suggestion that ANVC was recruiting cadres continuously and stated that the

difference in the list of members was due to progress achieved in the peace talks. He stated that ANVC does not publish any literature.

123. In cross-examination on behalf of the Government of India the witness stated that the ANVC does not hold internal elections to choose the General Secretary and he was chosen by the leader Dilash M. Marak. He stated that the ANVC has its office at Tura Youth Hostel, in a house allotted by the Government. He stated that ANVC does not have any written Constitution and its aims and objects are decided by collective decisions, in meetings. He stated that total membership of the ANVC is 202. He deposed that the Memorandum submitted to the Government of India displayed a tri-colour along with the symbol of the ANVC flag, i.e the flag of ANVC and it is not displayed in the public. The witness stated that ANVC keeps changing its headquarters which is called "Chiram" due to police encounters which has claimed many lives of its cadre members. He stated that ANVC has a Chairman, a General Secretary of the ANVC looks after the Finance Department, Commander-in-Chief who looks after the cadre and one Mr. Arist Sengsrang who looks after the publicity of ANVC as Publicity and Organizing Secretary. In cross-examination he deposed that ANVC does not hold any public meetings and its activities are known only to its cadres. He also admitted that ANVC has published a table calendar designed by the Publicity Secretary and that it does not have any bank account as it does not hold any money which is obtained from well-wishers. The average age of ANVC cadres is below 30 years; this is because people in that age group are physically active and capable of fighting.

124. RW-5 tendered his affidavit RW-5/1 and spoke about the aims and objectives of ANVC as creation of a separate State but within the Indian territory. He claimed that ANVC is not involved in any criminal activity and does not possess any weapons. According to him extortions in the coal belt areas were not by ANVC but other agencies. He claimed that the allegations of extortion, harassment, capturing business at Garo Hills, creation of fear psychosis were all false and that ANVC cadre members lived in designated camps where their activities were strictly regulated. The weapons possessed by its cadres were for self-defence and were in joint custody. He claimed that ANVC was fighting for the Garo people who were deprived of their development and also denied their right. Garo's lag behind in education compared with other two tribes.

125. He deposed in examination-in-chief that ANVC surrendered weapons in 2004 and that it plans to contest elections if the ban on its activities is lifted. According to RW-5 meetings of ANVC are held in designated camps and in Youth Hostel. He deposed that Mahindra Finance Company approached him to act as a recovery agent to repossess vehicles of defaulters who do not repay vehicle

advances in the Garo hills. In cross-examination he stated that ANVC does not have a written Constitution but admitted that its structure has various designations like Chairman, Joint Secretary, Publicity Secretary etc. He stated that ANVC cadre is known as the Army. The witness expressed lack of knowledge about involvement of ANVC members in several cases but stated that he was aware about deserters. Three deserters left camps as they did not comply with the stipulated ground rules. He admitted that his Christian name was Bernard Mara. He admitted that he was granted anticipatory bail in a complaint registered by Mohindra Finance in Ri-Bhoi District.

126. In cross-examination RW-5 denied about violation of the ground rules by ANVC, under the Government's agreements for suspension of operations. He also admitted that ANVC does not participate in National celebrations like Republic Day, Independence Day festivals and that it does not organize any public meetings or cultural functions. He admitted that J.G. Momin is the Joint Secretary of ANVC. He mentioned that besides the calendar and table diary no other written records exist, except documents furnished to the Joint Monitoring Group. ANVC according to him does not maintain any records about the sums of money received by it or of expenses incurred. ANVC also does not maintain records of weapons acquired by its cadre or about their utilization. He stated that though the ANVC does not declare the identities of the office bearers the people become aware of it. He deposed that the ANVC cadres stopped indulging in illegal activities after the ceasefire and that they no longer use the formal army designations. He stated that whenever they receive information about illegal activities by other groups, they pass it on to the police who even helps them. He stated that no one invites people to join ANVC but they volunteer to join it. He also stated that office bearers of ANVC do not meet and that directions are issued by the leader to the Chairman who is the supremo of the organization, verbally the ANVC Office bearers can act only after taking his consent. The witness was shown CW-12/2 calendar and CW-12/3 table calendar; he stated that they were issued by the Publicity Secretary of ANVC. He stated that the photographs were taken mostly before the ceasefire. He denied that CW-12/4 and its translation CW-12/5 were issued by ANVC.

127. The entire evidence led on behalf of the Government points to ANVC or its cadre members indulging in acts of extortion, kidnapping ransom etc. According to CWs 10 to 16 and CW-17, the activities of ANVC were mostly in the districts of Garo hills in Meghalaya. CW -7 also spoke about its activities in two other Districts and unrest among other peoples such as the Khasis and the Jaintias. The allegations in these affidavits, depositions and the cross-examination may be briefly summarized as follows :

- i. Between 2005 and 2007 16 incidents were reported leading to lodging of FIRs. Copies of some of FIRs had been produced along with the affidavits CW-10 to CW-16.

2. The Tribunal no doubt performs an adjudicatory role. In that sense it has to weigh the probabilities of two conflicting versions. Here it is asserted on behalf of the State through CW -6, CW -10 to CW -16 and also through CW-17 that a number of incidents were reported and FIRs recorded. No doubt originals of those FIRs were not produced. However, many of the copies produced along with the affidavits are true photocopies of the certified copies. ANVC availed of its full opportunity to cross-examine the witnesses. At no stage during the cross-examination, conducted exhaustively was any objection taken that copies of such documents could not be marked in evidence in the absence of originals; secondly counsel also did not specifically put any question to the witness concerned that those documents were not genuine are not copies of the original. No line of questioning to the effect that such incidents did not took place, were also not suggested.

Having regard to the nature of the proceeding which is adjudicatory but yet procedurally in the form of an enquiry under the code, the conclusion which the Tribunal has to draw is to be based necessarily to be founded on the probabilities. Therefore, in the light of the above discussion, the conclusion which has necessarily follow is that the copies of FIRs are to be considered. They indicate the following pattern :—

1. Recovery of weapons including AK series, 9 mm pistols, magazines, handgraneds;
2. Attacks and killings, (Williamnagar P.S. Case No.52(11)2006, Williamnagar P.S. Case No.56(12)/2006, 57(12)/2006, 58(12)/2006, 59(12)/2006 & 60(12)/2006 and Tura P.S. Case No.39(4)/2006 and on various dates between 29-1-2006 and 2-7-2006.
3. Firing at armed forces personnel [FIR No.20(5)/2005 under Section 307/326 IPC read with Section 25(1)(a) Arms Act] leading to recovery of pistol and ammunition;
4. Intimidation of people and the business community and preventing free trade. These include ban on sale of DTH technology, imposition of illegal taxes such as Rs.5/- per kilo on dry fish, collection of unauthorisrd and illegal tolls/taxes, capturing of rights for sale in haats, intimidation of traders in the coal belt in various districts of Meghalaya etc.
5. The witnesses of the State and Govt. of India have uniformly spoke about ANVCs leadership

hiding in Bangladesh in safe havens. None of the witnesses of ANVC were willing to disclose the whereabouts of their leaders. It is also a matter of record that the list of ANVC cadres provided to the Central Government and the Joint Monitoring Group never included the mention of any leader.

6. The ANVC cadres moving around with weapons. CW-17 mentioned that only 16 weapons were surrendered. CW-10 also made a similar statement and deposed that all weapons were not kept in a neutral place but kept in ANVCs liaison office;
7. The ANVC cadres continuing to use army style uniforms and battle camouflage for their activities.
8. Targetting the business community in particular, and indulging in extortion, kidnapping, etc.

128. The attempt of ANVC through depositions of its witnesses and during arguments was consistently to project that whatever be its actions in the past, no fresh grounds for declaring it unlawful were made out. Its emphasis was that after the ceasefire or suspension agreement, of July, 2004, all changed, and that the ground rules, in all the substantial and main particulars were being followed. One strong argument was that the Central Government has extended the agreement till July 2007. During the hearing, frequent endeavour was made to establish that in the relevant meetings of the joint monitoring group, no serious acts of intimidation, unlawful activities or extortion, killing, etc. were highlighted. The insinuation was that in the absence of mention of such activities, the State and Central Government cannot now complain that the ban has to be imposed. In other words, when conscious decision to further the peace process is made, and the agreement to extend it is taken, there is no ground to declare the organization as unlawful. An attempt was made to say that if there were acts of violence or extortion, looting etc., the ANVC cannot be held responsible, since it disclosed weaponry, surrendered it, and its cadres are in designated camps.

129. There is no doubt that the Central Government, in its wisdom, extended the ceasefire, or suspension of operations agreement. Yet, that cannot alone be conclusive; the Tribunal cannot *ipso facto*, on the basis of that decision, conclude that the activities of ANVC are not unlawful; nor can there be an argument of estoppel, since the decision to confirm or cancel the notification under Section 3 (1) has to be on the basis of materials placed on record, and not merely a decision taken on the basis of a political determination, as indeed the agreement to suspend operations is. In other words, the task of the tribunal has to be undertaken independently, on the basis of materials

placed before it, and tested through the adversarial process, by the association which seeks to show cause that its activities are lawful, and not unlawful.

130. A careful analysis of the testimony of RW-4, CW-17 and CW-10 would show that ANVC had been furnishing separate lists of its cadres to the Joint Monitoring group. Though an explanation about confidence building, and progress achieved through extension of ceasefire was given, the fact remains that inconsistency in such basic particulars, coupled with the admitted attrition ratio from the camps (the ANVC witnesses claiming those leaving the camps to be deserters over whom it has no control) shows that several members of its cadres left the camps where they were supposed to be housed, as part of the agreement. Similarly, these witnesses deposed that all weapons were never placed in joint custody, in a neutral place, but in the ANVC liaison office at Tura, under its control. Further, only 16 weapons were surrendered. These belie the contention that ANVC always intended to comply with terms of the ground rules, in letter and spirit. These also lend credence to the official version that such cadres are moving about freely, and are armed with sophisticated weapons.

131. The ANVC's organization as shown through these proceedings, presents a curious picture. According to the witnesses led on its behalf, it has no written constitution, but professes to achieve a state of Garoland through peaceful means. If that is the real objective, nothing prevents its leadership from coming out openly, and engaging with the Central and State Governments. Instead, the ANVC's secretive behaviour is all too writ large; it conducts meetings at Cheram, without prior intimation; its office bearers are hand-picked by its Chairman, Dilash Marak, who has chosen to stay away, not disclosing his whereabouts. Though it claims to have a wide following among the Garos, it is undeniably an unregistered organization; it secures substantial funds and amounts, but does not even open a bank account. Exhibits CW-12/2 and 12/3 were indisputably published by it; they are calendars of 2007; one of them contains pictures and photographs of several cadre members, including those clearly described as "deserters". Several photographs show the cadres in combat uniforms, as if they are members of the regular army; they are shown bearing arms, and in active training. The belated attempt of RW-5, who admitted that the calendars were indeed published for 2007, to explain the photos are those having been taken in 2004, rings hollow, because the specific mention of "deserter" cannot imply any meaning before the ceasefire agreement. RW-5 virtually supported the assertion of CW-17 and arguments on behalf of the Central Government, that ANVC maintains an army, whose leader is called the commander in chief, and its cadres have military designations. In fact, this is also borne out from the list filed along with the depositions of RW-4.

132. The possession of sophisticated and banned weapons, which is a matter of reasonable inference, drawn from the various recoveries spoken to by witnesses of the State of Meghalaya, and the Union of India, as well as the unchallenged testimony of CW-10 and CW-17 that only 16 weapons were surrendered, whereas the others were kept under control of ANVC, as well as the unacceptable explanation obliquely given, i.e. that they were used for self defence purposes, is again indicative of the ANVC cadres continuing to be at large and armed. There can be no reason why anyone would need such banned weapons, much less for purposes of self defence. The nature of weaponry, i.e. SLRs, AK-47 Guns, rifles, Chinese 9 mm Pistols, hand grenades, live ammunition, belie the peaceful intent of ANVC; they contradict its avowed peaceful objective of achieving Garoland by abjuring violence.

133. CW-13 had spoken about ANVC cadres having multiple identities; some of the persons named in the FIRs mentioned in the proceedings had several aliases; in fact, even RW-5 had an alias. These show that the possibility of deserters or those discharged from the organization, continuing to work for it, outside of its structure, in a concealed or camouflaged manner, is real, and cannot be ruled out. Further, the conflicting lists of members shown on different times, and the delay in furnishing full list of weapons, or members, all of whom do not stay in the three designated camps, show that ANVC is either deliberately not adhering to the ground rules, which in turn support the theory that it constantly regroups, or that it is unable to exercise control of its cadres, and is anarchic. Either way, this poses a threat to peace and security, in turn disrupting the territorial integrity.

134. In view of the above discussion, and after careful consideration of all the materials, evidence placed before it, and submissions on behalf of parties, the tribunal is of the opinion that the ANVC carries on unlawful activities, which are detrimental to, and intending to disrupt the territorial integrity of India, in spite of its ostensibly declared objective of achieving statehood for Garos through peaceful means. It has not abjured violence, and continues to engage in acts that are subversive, and disruptive of, detrimental to, or acts with intention to disrupt the territorial integrity of India. Therefore, the tribunal is of the opinion that it is an unlawful association, and the declaration, under Section 3(1), so far as it is concerned, has to be confirmed.

ORDER OF THE TRIBUNAL

In view of the above discussion and findings, the Tribunal, in accordance with Section 4(3) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, hereby confirms the Notification No. SO 1974(E) issued by the, Ministry of Home Affairs, Government of India, dated 16-11-2006 declaring the Achik National Volunteer Council of Meghalaya and the Hynniewtre National Liberation Council of Meghalaya, as unlawful associations, in terms of Section 3(1) of the said Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.

S. RAVINDRA BHAT

Judge, Delhi High Court, Presiding Officer,
Unlawful Activities (Prevention) Tribunal

New Delhi

Dated 14th May, 2007

[F. No. 11011/49/2006-NE-III]

NAVEEN VERMA, Jt. Secy.